

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजनीतिक-निबन्ध (POLITICAL ESSAYS)

सम्पा. ३

डॉ० प्रभुदत्त शर्मा

सम० १० सम० १०० १०० १०० १०० (१०० १०० १००)

राजनीति विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

नवीन सशोधित संस्करण

1966

प्रकाशक

पद्म बुक कम्पनी, जयपुर

प्रकाशक

पदम बुक कम्पनी

जयपुर

•

©

पूर्णतया समोधित सस्करण १९६६

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित

मूल्य : दस रुपये मात्र

•

मुद्रक

नवल प्रेस, जिनवाणी प्रिन्टर्स एवं
हिन्दुस्तान आर्ट कटिज, जयपुर मे मुद्रित

सम्पादकीय

प्रस्तुत पुस्तक में ये कुछ निबन्ध रचकनिन हैं जो मेरे नए और पुराने विद्यार्थियों ने मेरे निवेदन में संपादक किये हैं। एक सम्पादक के नाते मेरा यह प्रयास रहा है कि ये सभी युवक प्रतिभायें जैसी भी हैं उसी स्वरूप में प्रस्तुत हो सकें और बृहत्तर विद्यार्थी तथा शिक्षक-जगत उन्हें उसी रूप में देख सके, जैसी ये सचमुच हैं।

इन निबन्धों में—प्रणयन, सम्पादन तथा सज्जन-तभी में एक उपयोगितावादी, परोक्षानुसूयी दृष्टिकोण को अपनाते का प्रयास किया गया है, यत इनके अथवा पाठित्वपूर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी अपनी सीमाओं को स्पष्टतः पहचानते हुए, अपनी योग्यता, निष्ठा, अध्यवसाय तथा मन से कुछ विद्यार्थियों ने ईमानदारी से यह सम्भीर परिश्रम किया है उसे देखते हुए उनका यह प्रयास स्वागत्य है और मैं समझता हूँ सराहनीय भी।

छात्र-जगत को छात्र-जगत् प्राप्त सके तथा अपने व्यक्तिगत परिधम से मिल-जुल कर वे सामूहिक रूप से लाभान्वित हो सकें इसी विचार से यह रचना सज्जन की गई है। राजनीति-दर्शन, पंचायती-राज, विपत्तनाम-विवाद, पाकिस्तानी बुरासाम्राज्य का केन्द्र-फडमोर, पाक आक्रमण के परिवर्तित सदर्थ में भारत की विदेश नीति, अफ्रीकी राजनीति के नये क्षितिज तथा भारत की राज्यकीय राजनीति के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर अङ्गरेजी में उपलब्ध पाठ्य-सामग्री को निम्नचरारों में ढग से हिन्दी माध्यम द्वारा विवेचन एवं प्रस्तुत किया है। कोई भी निबन्ध यद्यपि में पूर्ण नहीं है पर उनके सम्पादन में मेरी अपनी यह चेष्टा रही है कि उन्हें बनाया जा सके कि उन्हें आपार-केन्द्र मानकर कोई भी परीक्षार्थी अपने समुचित सामग्री, अध्ययन-प्रणाली तथा शैली पा सके।

यह जानते हुए भी कि आज के विन्वविद्यार्थी के बुद्धि-जीवियों की दृष्टि में प्रकार के प्रयास सस्ते माने जाते हैं, मैंने अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए नया क्षेत्र दिया है। शोध के आकर्षण और चकाखीय में जहाँ शिक्षण और शिक्षक घुसते जा रहे हैं तथा अङ्गरेजी के उपासना भरे मोह को जहाँ संपादन स्तरों के नाम पर उभरती प्रतिभाओं पर बोया जा रहा हो, जिन्हें अङ्गरेजी के हर अक्षर के बर शब्द-बोझ देखना पड़ता हो। धागा है, मेरा यह प्रयास नये विद्यार्थियों होनता-परिमान से मुक्त कर कुछ स्वाभिमान की भावना दे सकेगा। प्रयास के पीछे न कोई प्रेरणा है, न कोई लोभ और न ही प्रत्यक्ष धनवा परोक्ष सहयोग। यत धन्यवाद की औपचारिकता को आवश्यक न समझते हुए उन सभी युवा-निबन्धकारों को बधाई पाहूँ जिनका यह अपना परिधम है।

प्रभुदत्त शर्मा

विषय-सूची

1.	जेटो और दलित दार्शनिक अधिनायकवाद	मेनका माहेश्वरी	1
2.	अस्तु के राजदर्शन में व्यावहारिकता एवं वैज्ञानिकता	श्रीम अंगेरा	12
3.	मध्ययुगीन विचारकों के मुख्य विचार	निर्मल कृष्णा	24
4.	धर्मसुधार आन्दोलन और आधुनिक राजदर्शन	लक्ष्मी कृष्ण	32
5.	हान्न हान्न के दर्शन में ईश्वर नीतिवाद	सुन्दर माहुर	42
6.	जॉन लॉक के दर्शन में धर्मवाद	गमि गिरी	54
7.	रुनो का राजदर्शन और मानव इच्छा-सिद्धान्त	प्रोफेसर भट्ट	67
8.	ग्रोन-एक देशर आदर्शवादी	गनदात कन्वा	80
9.	मार्क्सवाद के कुछ पहलू	इन्दु माहेश्वरी	89
10.	मार्क्सवाद के रुनो और चीनी सम्बन्ध	सुन्दर माहुर	110
11.	राजनीतिक बहुतेवाद	गोविन्दगन	120
12.	गांधीजी के राजनीतिक और धार्मिक विचार	हमा शाह	132
13.	नेहरू की विरासत	विद्यानाथ गर्मा	137
14.	शक्ति-संयुक्त	नरेन्द्र दत्त	156
15.	भारत की विदेश नीति : परिर्वर्तन संदर्भ में	हर्षिचन्द्र गर्मा	169
16.	अष्टादश राजनीति के नए सिद्धि	मोहनदास गर्मा	187
17.	चीनी-मार्क्सवादी दुरागाधों का केन्द्र-कम्पौर	प्रकाश दान्वा	200 F
18.	विप्लववाद	सुन्दर माहुर	200
19.	मविधानवाद-आचीन एवं अष्टादश	राजगन ऐर	209
20.	राजनीतिक इन-एक विनिर्णय	गोविन्दगन दान्वा	223
21.	पंचायती राज-एक आन्तर्व्यक्तिक अध्ययन	कमलदत्त गर्मा	235
22.	द्वितीय मदन-एक अध्ययन	गजेंद्र गर्मा	249
23.	आधुनिक सरकारें और न्यायिक पुनर्विचार	सुभाषचन्द्र दान्वा	263
24.	भारत में न्यायशासन	राजकुमार कृष्ण	274
25.	दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण	सुभाषचन्द्र दान्वा	293
26.	कम्पौर समन्वय-एक परिचय	अनन्त कन्वेंदी	307
27.	भारत में गणतन्त्र-राजनीति	गजेंद्र अंगेरा	317
28.	भारत-यु.एस. और संयुक्त राष्ट्र	विनेन्द्र गोदीका	331
29.			

प्लेटो और उसका दार्शनिक अधिनायकवाद (PLATO AND HIS PHILOSOPHICAL DICTATORSHIP)

—प्रेमलता महेस्वरी

साद्वार्थ्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो, वह पट्टा विचारक या चिंतक प्रभाव आज चौबीस सौ वर्ष बीत जाने के बाद भी पुग्गु है। वह राज्य-व्यवस्था दर्शन, सुधार और चिन्तन की सभी प्राविशारी मात्राओं का उत्कृष्ट माना जाता है। वर्तमान साम्यवाद, फासीवाद और आदर्शवाद उसके दर्शन में प्रेरित हुए हैं। प्लेटो की "रिपब्लिक (Republic)" के नमूने पर आदर्श राज्य स्थापित करने की प्रेरणा योजनार्थ राजनीति दर्शन के इतिहास में प्रस्तुत की गई है। शिक्षा और सुगुणन राज्य के कार्यक्षेत्रों द्वारा समाज को उत्तम बनाने की दिशा में उसके विचार दर्शन के प्रेरणा-स्रोत रहे हैं। मध्य युग में उसमें प्रेरणा पाकर सर थॉमस मूर ने अपना "यूटोपिया" लिखा। प्रारम्भिक सताब्दी में 'कॉमो और उनका दर्शन' प्लेटोवाद से अनुप्राणित है। उन्नीसवीं सताब्दी में अगस्ट कोम्ते (August Comte) ने प्लेटो से प्रभावित होकर इन बातों पर बत दिया कि समाज का शासन वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा ही होना चाहिये। फ्रेड रिडन के आदर्शवादी विचारक बीन तथा बोसक्वे (Bosanquet) भी प्लेटो के अनुयायी तथा उनके दार्शनिक सिद्धियों की गणना में आते हैं।

आधुनिक साम्यवाद तथा फासीवाद आदि की विचारधाराओं पर प्लेटो के विचारों की गहरी छाप देखी जा सकती है। राजनीतिक चिन्तन के कुछ शास्त्र प्रश्नों की सुन्दर सीमाओं करने के कारण वह आज तक राजदर्शन के इतिहास में अद्वितीय और जब तक मानव समाज में राज्य की सत्ता रहेगी, सम्भवता उसका यही स्थान होगा। पिछले चौबीस सौ वर्षों के इतिहास में विज्ञान राज्यों को बनाने वाले प्रजापीताओं, शक्तिशाली सम्राटों तथा बुद्धिमान राजनीतिज्ञों की सभी बनी बनी विस्तृत जगह से किसी का भी राजनीतिक विचारों पर इतना प्रसिद्ध प्रभाव नहीं पड़ सका जितना कि प्लेटो का। उसकी रचनाएँ, चौबीस सताब्दियाँ बीत जाने के कुछ साल भी बाद भी उत्तुङ्गता के साथ पढ़ी जाती हैं, उनमें प्रेरणा ग्रहण की जाती है और उनके आधार पर आज भी समूहवादी मताँ की पुष्टि की जाती है। प्लेटो की मार्गभूमिका का प्रमाण उसकी शिक्षा-व्यवस्था, धर्मशास्त्र की प्रभावशालिता, बौद्धिक वर्ग के शासन के नियमों से ज्ञेय जाने वाले मापदण्ड, राज्य दण्ड विधि (Criminal Law) तथा व्यवहार विधि (Civil Law) के बीच किये जाने वाले अन्तराधारे के विचारों से स्पष्ट है। आज के

यूनान के दिवार न माने जाकर अधिक मानवता के विचार माने जाने हैं। शिक्षा पर आज भी राज्य का नियन्त्रण अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। रूस और अमेरिका तक ही यह बात सीमित नहीं है, संसार का प्रत्येक प्रगतिशील देश शिक्षा को राष्ट्रीय आधार पर नियोजित कर उस दिशा में चरण दश रहा है। श्रियो को घर की बहारदीवारी से मुक्त कराके उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिये राग्यों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाने लगा है।

रिपब्लिक के मूल सिद्धान्त

विचारों की यह सार्वभौमिकता हमें प्लेटो की प्रमुख पुस्तक "रिपब्लिक" में देखने को मिलती है। "रिपब्लिक" का मूल विचार है मुक्तचित्त का वह सिद्धान्त कि "सद्गुण ही ज्ञान है (Virtue is knowledge)।" इसके अनुसार श्रेष्ठत्व का ज्ञान तात्त्विक आवश्यकताओं द्वारा हो सकता है और उसका शिक्षा भी दी जा सकती है। अतः "रिपब्लिक" की प्रमुख बात यह है कि दार्शनिक धर्मात् वह पुरुष जो कि ज्ञाता है, शासक भी होना चाहिये। उसका ज्ञान ही उसे शासन का अधिकारी बनाता है। प्लेटो का विचार है कि समाज पारस्परिक आवश्यकताओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान पर आधारित है। प्लेटो के सिद्धान्त के प्रमुख नियम दो हैं—प्रथम शासन एक वक्ता है जिसके लिये विगिष्ट एवं सदाय ज्ञान की आवश्यकता है और दूसरे समाज की स्थापना पारस्परिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के निमित्त हुई है और यह केवल तभी संभव है जबकि प्रत्येक सदस्य को वह स्थान प्रदान किया जाये जिससे उसे वह सबसे अधिक उपयुक्त है।

अयोग्यता की उपासना—जनतंत्र

प्लेटो की राजनीतिक प्रवृत्ति और ग्रन्थदृष्टि का दिग्दर्शन इसी उक्त्य द्वारा हो जाता है कि उसने यूनान के नगर राग्यों में प्रचलित प्रजातन्त्रीय कार्यप्रणाली के आत्मनिरीक्षण द्वारा यह अनुभव किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रजातन्त्र अयोग्यता की उपासना है और प्रत्येक राज्य की अधिकांश बुराइया राजनीतिज्ञों की अयोग्यता के कारण हैं। अतः उसके राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख निर्देश है कि राजनीतिज्ञों को शासनकता में प्रशिक्षित किया जाये। उसने अनुसार राज्य वैज्ञानिक व्यवस्था होने चाहिए और साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों की प्रवृत्ति एवं सीमाओं का सदाय ज्ञान भी रखना चाहिए। आदर्श राज्य की स्थापना तभी संभव हैगी जबकि उसका शासन राज्य-वैज्ञानिकों द्वारा संचालित होगा। प्लेटो का कथन है "जब तक राजा दार्शनिक न हों प्रसदा दार्शनिक राजा न हों, आदर्श राज्य की स्थापना कल्पित ही रहेगी।" प्रो० डॉक्टर

1. "Until philosophers become kings or the kings of the world have the spirit of philosophy, the city will never rest from ruin."

के सबसे से—'विशिष्टीकरण का मार्ग प्लेटो के लिए एकीकरण का मार्ग भी था। यदि सरकार के कार्यों के लिये एक पृथक्-वर्ग की नियुक्ति हो तो सरकार को निश्चय म लागने के लिये शायद ही संघर्ष के लिये कोई स्थान रहे। यदि प्रत्येक वर्ग अपनी ही सीमाओं में बद्ध रहे और अपने ही कार्यों में एकाग्रित हो तो वर्गों में संघर्ष नहीं होगा। विशिष्टता के प्रभाव के ही कारण नागरिकों में मतभेद संभव होता है। विशिष्टता में साथ साथ यह एक सच्चा और प्रत्येक वर्ग प्रसन्नतापूर्वक अपने लिये नियुक्त हुए कार्यों को करने लगेगा। स्वार्थ-रत्ना अर्थात्स्वार्थ ही जायेगी और राज्य में एकता का साम्राज्य होगा।¹

त्रिकोणात्मक व्यवस्था

प्लेटो आदर्श राज्य की समस्त जनसंख्या को तीन वर्गों में विभक्त करता है। उनमें सबसे पहले संरक्षक है जिसको पुन सैनिकों और शासकों में विभक्त किया गया है। दूसरे मजदूर हैं जो कि जनसंख्या का अधिकतम भाग है। उनका मुख्य कार्य उत्पादन करना है। इनमें से प्रत्येक वर्ग के अपने विशिष्ट गुण हैं जिनके द्वारा उन्हें अपने वर्गों से भिन्न किया जा सकता है। इस प्रकार दार्शनिक सामरा में बुद्धि (reason), सैनिक संरक्षकों में साहस (spirit) एवं जनता तथा मजदूरों में धृष्टि (appetite) अधिक मात्रा में होता ही उनके इन भेदों के प्रमुख लक्षण हैं।

न्याय और उसके स्वरूप

राज्य के नागरिकों के इन त्रिभुजों वर्गीकरण को तथा कार्यविभाजन को स्थिर करने के लिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया है। प्रत्येक को उसका अधिकृत प्रदान करना ही प्लेटो के सामाजिक न्याय के सिद्धांत की परिभाषा है। शिक्षा प्रत्येक के सामर्थ्य-नुसार होगी और पारम्परिक समाज को यह प्रभाव रहेगा कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य और जीवन में अपने पद के अनुरूप ही ईमानदारी से सामाजिक दायित्वों का अनुष्ठान करेगा। प्रो० बार्कर के शब्दों में "यह सामाजिक न्याय की उस समझ का सिद्धांत बद्ध करने है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा निर्मित हुआ हो और जो एक दूसरे के प्रति अपनी आवश्यकताओं की प्रकृति में संयुक्त हुए हैं—इस प्रकार एक समाज में समुचित और अपने पृथक् कर्तव्यों में एकाग्रित होकर एक संपूर्ण का निर्माण किया हो जो कि

1. "The way of specialisation was also to Plato the way of unification. If a separate class were appointed to the work of government, there would hardly be any room for the old struggle to capture the room. Civil dissension had been rendered possible by the want of specialisation. With specialisation these things would cease. Each class would work at its appointed function in contentment. Selfishness would disappear. The unity would pervade the state".

—Barker

विवेक अधिक माना म पाया जाता है। ऐसे लोग को प्लेटो ने राज्य के दार्शनिक शासक माना है। बाकी के शब्दों में "सरक्षक वर्ग को दो भागों में विभाजित किया गया है प्रथम सैनिक सरक्षक है जिसकी विशेषता साहस है और जिन्हें 'माथीलरीज' का नाम दिया गया है दूसरे दार्शनिक सरक्षक है जिसकी विशेषता विवेक अथवा बुद्धि है और जो अपनी श्रेष्ठता के कारण प्लेटो के राज्य के सरक्षक हैं।"¹ विवेक के प्लेटो ने दो गुण माने हैं प्रथम विवेक में व्यक्ति को ज्ञान (knowledge) हाता है तथा विवेक ही व्यक्ति को प्रेम (love) करना सिखाता है। अतः प्लेटो के विचारानुसार शासक विवेक-शील होना चाहिये एवं अपने पर्याप्त मात्रा में सहनशीलता होनी चाहिए। राज्य का निर्माण करने वाले तीन वर्गों में दार्शनिक-शासक का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि वह राज्य के शांति को एकता के सूत्र में बांधे रख सकता है तथा उन्हें परस्पर स्नेह करना सिखा सकता है। राज्य के प्रथम दो वर्गों की भाँति शासक वर्ग भी विशद समझ-समझ वर्ग होता चाहिए। जिसकी अधिक मात्रावत्ता कार्य विशिष्टीकरण (Functional Specialisation) की दृष्टि से है उनमें अन्य दो वर्गों के लिए नहीं। प्लेटो के विचारानुसार ही दार्शनिक ही सही व्यक्तियों में राज्य का शासन होना चाहिए। बाकी के शब्दों में "सभी व्यक्ति दार्शनिक वर्ग के नहीं हो सकते।"² अतः संख्या की दृष्टि से राज्य का एक सर्वोच्च सूक्ष्म भाग ही इस वर्ग की महत्त्वता प्राप्त कर लेगा।

"रिपब्लिक" में वर्णित आदर्श राज्य में सरकार नियमों द्वारा ही नहीं व्यक्तिगतों द्वारा होगी। प्लेटो के राज्य में सर्वाधिक शक्ति तथा शक्ति का स्थान दार्शनिक शासक को प्राप्त हुआ है। उनके ऊपर किसी प्रकार के कानून आदि का बंधन नहीं है। राज्य की शांति में पाये जाने वाले गुणों में दार्शनिक शासक विवेक (reason) गुण का प्रतिनिधि है। अतः अन्य नागरिकों की मर्यादा उसका विवेक प्रति है। यह शासक जहाँ विवेकशील है वहाँ अपने राज्य को पर्याप्त चाहने वाला भी। विवेक के दो उत्तम-ज्ञान तथा प्रेम से वह परिपूर्ण है। राज्य के प्रति उनकी उत्कट शक्ति एवं दृढ़ प्रेम है। प्लेटो उसे "विवेक का प्रेमी" और नगर का मन्त्र तथा मन्त्र सरक्षक मानता है।"³ दार्शनिक शासक उसे समस्त गुणों का आधार प्रतीत होता है। उसने

1. "The class of guardians bifurcated into two—the military guardians whose characteristic is spirit and who are now termed auxiliaries and the philosophic guardians whose characteristic is reason and who are the guardians par excellence of the Platonic state"

—Ibid

2. "A whole people can not be a people of philosophers"

—Ibid

3. "A lover of wisdom a good and true guardian of the city"—*Republic, Book II.*

अनुसार दार्शनिक शासक सर्वकाल तथा सर्वमता का द्रष्टा है (Spectator of all time and all existence)। प्रकृति की श्रेष्ठतम दन से वह युक्त है एवं इसका सर्वश्रेष्ठ ढंग से वह प्रयोग करता है। उसमें आत्मा के किना भी सुन्दर गुण का प्रभाव नहीं है।

महाशक्ति मानव और कानूनहीन राज्य

इस प्रकार के सर्वज्ञ, विवक्षीय, सर्वदृष्ट नया ममवशान दार्शनिक शासक को प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर बिना किसी बाधा के सौंप देना चाहता है। इस श्रेष्ठ और निरुपेक्ष सोचों के नष्ट होने में आदर्श राज्य की सीमा, आर्थी और नृपति के सम्भावना से बचती हुई अपनी मजिल तक अवश्य ही पहुँच जायेगी। प्लेटो का यह विस्तृत स्वीकार नहीं था कि इस दार्शनिक शासक के कार्य में किंचित मात्र भी रुकावट या बाधा उपस्थित की जाये। इसलिए इस महाशक्ति मानव द्वारा शासित आदर्श राज्य में प्लेटो ने कानून का कोई स्थान नहीं दिया है। आदर्श राज्य के लिए कानून आना-दमक ही नहीं अपितु हानिकारक भी हैं। उनकी यह मान्यता उनके दृष्टिकोण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भी प्रतीत होती है। शासन-मन्त्रालय में विषय साम्यता रखने वाले तथा अन्य सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त शासक के हाथ पैर कानून की बंधिया से जकड़ देने के आदर्श राज्य के नागरिकों का अहित ही होगा। प्लेटो यह सर्व प्रमाणित करता है कि जैसे किसी अच्छे चिकित्सक की चिकित्साशास्त्र की पुस्तक में से अपना उपचार पत्र (Prescription) बनाने का आग्रह करना उचित नहीं है, उसी प्रकार दार्शनिक शासक का भी कानून की सीमा खारजा में बाध कर रखना उचित नहीं होगा। कानून को दार्शनिक शासक पर बाधना वह इसलिए भी उचित नहीं मानता, क्योंकि कानून प्राकृतिक न हानर रुढ़िगत (Conventional) हैं। रुढ़िगत कानून का एक सर्वज्ञाता एवं शासन मन्त्रालय विनियम पर बाधना उचित नहीं कहा जा सकता। किसी श्रेष्ठ बन्धु का अनुशासन निष्कट बन्धु के अनुशासन में रखना प्रथम श्रेणी की भूत ही नहीं कहा जा सकती है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक कानूनी दमन नहीं है बल्कि सुख दुःख का मिल-जुलकर समान रूप से अनुभव करने के लिये मनावेनान्तिक आधार पर निर्मित एक पूर्ण समुदाय है। अतः उसके दार्शनिक राज्य में कानून का स्थान न हानर दार्शनिक शासन है।

अनुमान विवेक का रोमान्स

प्लेटो ने विवेक (reason) का इतना अधिक महत्त्व माना है कि वह विवेक ही दार्शनिक शासक मान बैठा है। प्लेटो ने कभी इस सम्भावना पर विचार ही नहीं किया कि उसका दार्शनिक शासक का भी पतन हो सकता है अथवा सत्ता उसे भी ग्रस्त कर सकती है। उसने तब किसी भी प्रकार की विधि व नियम की आवश्यकता प्लेटो को नहीं मानी। प्लेटो के अनुसार वे ऐसे ही स्थितप्रज्ञ और बुद्धिमान होंगे कि उन्हें न तो कुछ बताने की आवश्यकता होगी और न उनके आचरण का नियमित करने

की। ऐसे उत्तम पुरुष चुन लेने पर बिना किसी डर के राज्यमूर्त उनके हाथ में दिया जा सकता है। उनसे हाथा से राज्य की केवल भताई ही हमी, राज्य में भगड़े होने का नाम का भी डर नहीं रहेगा। दार्शनिक शासक की इतनी अधिक स्वतन्त्रता देकर प्रो० जॉनेट कहते हैं, "रिपब्लिक की रोमान्चवादी बल्पना उन्मुक्त ज्ञान का वह रोमान्स है, जिस पर न रीति रिवाज के दम्भन हैं और न मानवीय मूर्खता और स्वार्थ का हस्तक्षेप।"¹

एक आदर्श की वित्ता ही बुद्धिमान बनाया जाये लेकिन वह स्वयं विवेक (reason) नहीं बन सकता। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और रखता है लेकिन वह संपूर्ण ज्ञान नहीं बन सकता। विवेक गतन नहीं हो सकता लेकिन दार्शनिक शासक सामारिक जीव है और सामारिक जीव होने के कारण वह गमती कर सकता है। प्लेटो न गतती करने वाले विवेक की गतती करने वाले व्यक्ति से मिला देता है। उसकी (प्लेटो की) इस तुलना के विषय में प्रो० बार्कर ने कहा है "प्लेटो की गतती मस्तिष्क के पुन्यकरण करने में सभा विवेक के निरंकुश मित्रता में है।"²

फासीवादी-निरंकुशता

बुद्धि के नाम पर "रिपब्लिक" एक निरंकुश राज्य (Autocratic State) बन गया है। यदि प्लेटो की "रिपब्लिक" का अध्ययन गंभीरतापूर्वक किया जाये और उससे कोई निर्वर्ण निगता जाये तो वह बेजल सर्वाधिनायवाद (Totalitarianism) निकलेगा। प्लेटो द्वारा स्थापित किया हुआ आदर्श राज्य "प्रथम फासीवादी राज्य" कहलाता है। प्लेटो ने दार्शनिक रीति से और तांत्रिक रीति से स्वयं वही निर्वर्ण निगता है कि जो दार्शनिक शासक हमारे वही हैं। सब पर शासन करेंगे। उनसे ऊपर कोई कायद कातून नहीं हावे, उन्हें पूर्ण स्वायत्ता होगी। वे जेगा भा न भाये वेंगा शासन करेंगे। यही बातें भागे जाकर मुसलिनी ने बड़े स्पष्ट रूप में कही थी।

फासीवाद से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहाँ ज्ञानाशाही हो और जिसमें व्यक्ति को कोई स्थान न हो। फासीवाद में एक फासिस्ट दल में निरंकुश राज्य किसी दल का मस्तिष्क स्वीकार नहीं किया जाता। डॉ० फ्रांकोइस ने निगता है "सर्वाधिनायक का मतलब व्यक्ति के जीवन के सीमित होने से होता है। इसमें मनुष्य के व्यक्तिस्व की ज्ञान व योग्यता को पूर्ण रूप से इन्कार किया जाता है। राज्य स्वो पहिदे की मसीन

1. "The true romance of the Republic is the romance of free intelligence, unbounded by custom and untrammelled by human stupidity of self will."—Prof. Jos. H.

2. "The error of Plato lies in the separatist conception of mind and autocratic conception of reason."—Barker:

—Plato and his Predecessors.

मुसोलिनी का आध्यात्मिक पुर्वज

प्लेटो के दार्शनिक शासन सम्बन्धी विचार तथा फासीवादी राज्य के इन वर्णन में कई समानताएँ हैं। एक महत्वपूर्ण समानता प्लेटोवाद तथा फासीवाद में अपने देश को सुन्दर बनाने की है। प्रो जी मी बर्टलिन लिखते हैं—“प्लेटो नवयुवकों का यह पाठ पढ़ाना है कि उनके देश से सुन्दरतर देश दूसरा नहीं है। महा प्लेटो ऐसी विचार-धारा का कि इन्होंने सुन्दर और मुसोलिनी सदैव ठीक है, कम की गई समानता नहीं है और स्टालिन मही है, ब्रिटेन सत्र पर शासन करता है—पूर्णतया समर्थक तथा अनुमोदक प्रतीत होता है।”¹ फामिन्टा के अनुसार राज्य स्वयं में एक सत्य है, नागरिकों के बिनाक इसे अधिकार प्राप्त है। इसके प्रतिरिक्त नेता का उद्देश्य सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमान तथा सबसे अधिक बुद्धिमान माना है। नेता की भाषा का अक्षर-साधर पावन उनके लिए परम धर्म है। प्लेटो ने भी राज्य की व्यक्ति से सर्वोपरि माना है एवं राज्य के हितों के लिए व्यक्ति के हितों की प्राकृति देने की उसने भी उचित ठहराया है। इसी प्रकार राज्य के शासन संबंधित में दार्शनिक शासन के नेतृत्व की उसने निदिवाह एवं निरंकुश रूप में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है।

प्लेटोवाद तथा फासीवाद दोनों में समानता की उपेक्षा की गई है। न्याय-गन समानता की दोनों ने स्वीकार कर लिया है। यदि प्लेटो ने प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्त समानता को धृष्ट की दृष्टि से देखा है तो फामिन्टा की भी इन सिद्धान्तों के प्रति धृष्टा उसने तैयमात्र भी कम नहीं है। इसी प्रकार दोनों में प्रजातन्त्र के प्रति भी उपेक्षा का भाव पाया जाता है और व्यवसाय पर आपारिज बुनीतता के दावा समर्थक है। प्लेटोवाद तथा फासीवाद दोनों में समानता की उपेक्षा के साथ-साथ स्तुतनता की भी कोई स्थान नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों के छात्र, बड़े, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक आदि सभी प्रकार के कार्यों पर पूर्ण एवं कठोर नियंत्रण है। उसे क्या करना है, क्या नहीं। इसका निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है। लगभग इसी प्रकार की स्थिति फामिन्टावादी व्यवस्था में व्यक्ति की होती है।

प्लेटोवाद तथा फासीवाद दोनों का बुनीतनत्र में विश्वास है। प्लेटो बुद्धि का शासन (Rule of intellect) स्थापित करने के लिए बोले तो गलाका को ही गमूसा शासन गौतना चाहता है। फासीवाद फामिन्टा दूत को ही शासन बनाने का दम्प है। प्लेटोवाद तथा फासीवाद में इन्हीं समानताओं के कारण प्लेटो को प्रथम फामिन्टावादा जाता है। बार्बर ने प्लेटो के शासन की योग्य व्यक्ति की निरंकुशता (Enlightened despotism) बताया है। बर्टल रीन ने भी प्लेटो के शासन की स्तुतनता करने दूये

1. "Plato would have the young men all home taught that no country was finer than their country. Here Plato was the complete moral jingo—as it were Itaha finest and Mussolini right, Russia unexcelled and Stalin right, Britannia ruling the waves."—G. C. Collins.

कहा है कि वह एक तानाशाही अथवा सर्वाधिकारवादी शासक बन गया है।

बौद्धिक फासीवाद

उपरोक्त मूल समानताओं के दावदूद भी प्लेटो को मुनासिबों का पूर्वज कहना अन्यायपूर्ण होगा। फासीवाद जहां सर्ववाद तथा बुद्धिवाद के प्रति एक विरोध है वहां प्लेटो के बुद्धिवाद का फासिस्टों के प्रज्ञावाद (Intuitionism) से सीधा विरोध है। फासिस्टों के अनुसार बुद्धि (Reason) कभी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझ सकती जबकि प्लेटो के लिए यही एकमात्र मार्ग-प्रदर्शक है जो मनुष्य को सामाजिक बुध्दया से दूर हटा सकती है। फासीवाद नावनाओं तथा प्रवृत्तियों को बुद्धि से ऊंचा स्थान देता है जबकि प्लेटो ने नावनाओं भी बुद्धि का रूप ग्रहण करती प्रतीत होती हैं। यह धारणा कि फासिस्ट अपने खून से सोचते हैं (Fascists think with their blood) प्लेटो के दर्शन के विरुद्ध सर्वथा महत्वहीन वही जा सकती है।

इसके अलावा फासीवाद की सत्य एवं नैतिकता की धारणा व्यावहारिक है। नैतिक मानदंड तथा सत्य केवल सापेक्षिक सिद्धांत (Relative concepts) हैं और कार्य करने वाले अनुमान (Working hypothesis) के रूप में ही इनका मूल्य है प्रमाण जब तक वे मनुष्य के उद्देश्यों व कार्यों को प्राप्त करने में सहायता दें। उनकी मापन में निष्ठ है और वे स्थान से स्थान तथा पीढ़ी से पीढ़ी बदलने रहते हैं, हमारे मनो में वे कुछ समय के (Arbitrary) मानदंड हैं। परन्तु प्लेटो ने इन विचारधारा का अपनी पुस्तक "रिपब्लिक" में खंडन किया है। प्लेटो का कहना है सत्य व न्याय न तो मान्य है और न ही कुछ समय के लिये। वे अमर हैं तथा बुद्धि पर आधारित हैं। वे दाहरी छत्र कण्ट न होकर मनुष्य के बौद्धिक स्वर (Rational faculty) के प्राकृतिक ढांचे के रूप में मानने माने हैं। यानि कभी भी ठीक नहीं होती, सुख या मतलब ही आनन्द नहीं होता (Might is never the right, pleasure is not necessarily happiness)। यह मत है कि न्याय, नैतिकता तथा सत्य अमर रूप में सामनायक होते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पीढ़ी को सामनायक होंगे है वह न्यायमंत्र भी हो। इन प्रकार सत्य, नैतिकता तथा न्याय के द्वारे में प्लेटो का सिद्धांत फासीवाद की व्यावहारिकता के विरुद्ध सीधा आमत्य है।

फासीवाद के नैतिक राष्ट्रवाद के सिद्धान्त (Theory of Militant Nationalism) का प्लेटो के विचारों में कोई स्थान नहीं है। फासिस्ट लोगों के लिये साम्राज्यवादी विस्तार जीवन का स्फिर तथा सन्नातन नियम है। उनके लिये युद्ध तथा राष्ट्रीय झंडे उदारता तथा नाहन के परिवारक हैं, लेकिन प्लेटो के लिये युद्ध तथा साम्राज्यवाद राज्य (Polity) के लिये दोषाधिक हैं। उनके आदर्श-राज्य में साम्राज्य के अभाव कभी युद्ध नहीं होता। प्लेटो ने विस्तारवाद की मान्यता राज्य में प्राकृतिक पृष्ठ के संकेत के रूप में की है तथा कि स्पेन (Spain) के राज्य का दण्ड प्रतिक

विक्रम हो गया हो। दूसरे शब्दों में प्लेटो के लिये युद्ध एक शक्ति उद्धारता तथा साहस का साधन न होकर राजनीतिक बीमारी का एक चिह्न तथा राज्य के आन्तरिक कुप्रवृत्ति के लिये उत्तरदायी है। युद्ध के स्थान पर एकता प्लेटो के लिये मनुष्य तथा राज्य का भाग्य है। इसी प्रतिष्ठित प्लेटो नगर-राज्य की पूर्णता में विराम करता है जबकि मुमाविनी का आचार राष्ट्रीय राज्य है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि यह सब है कि फासिस्टों की तरह प्लेटो ने यह धारणा की थी कि राज्य एक नैतिक मत्ता है जिसके प्रति व्यक्ति का आन्तरिक व सेवा का प्रयत्न करना है लेकिन प्लेटो की एकता की सामाजिक नैतिकता युद्ध की फासिस्ट नैतिकता से पूर्णतया भिन्न थी। यह भी मत्व है कि फासिस्टों की तरह प्लेटो ने यह भी कहा था कि शासन करने का विद्याभ्यास कुछ विद्या बुद्धिमान व्यक्तियों का ही है लेकिन जबकि प्लेटो के कुछ बुद्धिमान व्यक्ति बड़े नैतिक तथा धार्मिक परिभाषा के पक्ष में सत्ता प्राप्त कर पहुँचते हैं। फासिवाद में कुछ व्यक्ति धन, शक्ति तथा भूत आदि के लोभ से सत्ता हथकने में विराम करते हैं। यह भी सब है कि न तो प्लेटो ने और न ही फासिवादियों ने सम्मति या इच्छा (Consent) के दर्शन का उल्लेख किया। लेकिन जबकि फासिस्ट सोचा है शक्ति के दर्शन को जग्य दिया तो प्लेटो ने बुद्धि के दर्शन को। प्लेटो का राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में योग्य है तथा जिसमें एकता है लेकिन फासिवादी राज्य बिगड़े हुए समाज (Disintegrated Society) का प्रतिनिधित्व करता है। सब स्पष्ट होता है कि प्लेटो बाद के फासिवाद में समानता बनाकर, तुल्य व बाहरी हैं लेकिन इन दोनों का अंतर न बरन पाती खाई (Unbridgeable Gulf) की तरह है। प्लेटो को प्रथम फासिस्ट बताना हिटर, मुमाविनी, मानाजार व फैंकी तथा माय ही प्लेटो के दार्शनिक राजा की भी कुर्सी से हटाना है जो अमान्य भी है और उपहासनीय भी। प्लेटो के दर्शन से फासिस्टों का दर्शन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि फासिस्टों का दर्शन से प्लेटो का दर्शन बनाया जा सकता है (It is not like making a Fascist out of Plato, but a Plato out of Fascist)।

BIBLIOGRAPHY

- (1) BARKER Plato and his Predecessors.
- (2) NETTLESHIP Lectures on Plato's Republic
- (3) KARL POPPER Open Societies and its Enemies
- (4) TAYLOR Plato the Man and his Work
- (5) FOESTER Masters of political Thought

अरस्तू के राजदर्शन में व्यावहारिकता एवं वैज्ञानिकता

THE PRACTICAL AND SCIENTIFIC CHARACTER OF
ARISTOTALIAN POLITICAL PHILOSOPHY

—प्रेम अरोड़ा

मुकरात, प्लेटा तथा अरस्तू के रूप में यूनान में विद्वानों को तीन बहुमूल्य रत्न प्रदान किये हैं। राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में मानव समाज को इन मनीषियों की दत्त कल्पना से परे की चीज है। किन्तु इनमें से भी प्लेटो का यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला सिद्ध अरस्तू अनासक्त प्रतिभा का धनी था। कहा जा सकता है कि मानव जीवन का शायद ही ऐसा कोई पहलू अछूता रहा हो जिस पर अरस्तू की दृष्टि नहीं गई। अरस्तू ने न केवल विभिन्न विषयों पर ही विचार व्यक्त किये हैं अपितु ऐसे मत भी प्रकट किये हैं जिन पर गहन मनन किये जाने की आवश्यकता है। हममें सन्देह नहीं कि कतिपय व्यक्तियाँ न ही इनके अधिकार के साथ, इन्हीं विविध विषयों पर विचार व्यक्त किये हों, जितने कि अरस्तू ने।

अरस्तू ने न केवल विभिन्न विषयों पर विचार करके अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किये बल्कि सामाजिक विज्ञान (Social Science) के कुछ नवीन विषयों को भी जन्म दिया। मैनसी ने उसे प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक (First Political Scientist) की संज्ञा दी है। उसके अनुसार राजनैतिक चिन्तन के इतिहास में अरस्तू का महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति को एक स्वतन्त्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। अरस्तू के महान् कार्य 'पॉलिटिक्स' को यदि राजनैतिक शास्त्र का प्रथम एवं प्राभाषिक ग्रन्थ माना जाय तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। डा० जैन्स तो इसकी प्रशंसा में यहाँ तक कह जाते हैं कि हमारे पास यह सबसे बड़ा प्राचीन खजाना है और आज तक के राजनैतिक दर्शन के लिए सबसे बड़ी देन है।¹ प्रो० वाइले का मत भी कुछ अधिक भिन्न नहीं, जब कि वे कहते हैं कि अपने विषय पर 'पॉलिटिक्स' सबसे अधिक प्रभावशाली और तटस्थ विचार

1 'The Politics of Aristotle, is the richest treasure that has come down to us from antiquity, and the greatest contribution to the field of Political Science that we possess'—E. Zeller, *Aristotle and the Earlier Peripatetics*, English Translation Vol. II, P. 288

गहरा ग्रन्थ है। प्रो० डॉनिंग भी राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अरस्तू का महत्व इस तथ्य से मानते हैं कि उसने राजनीति को एक स्वतन्त्र विज्ञान का रूप प्रदान किया।¹

विज्ञान और वैज्ञानिकता

अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में देखने से पूर्व यह जानना स्वाभाविक है कि विज्ञान से क्या अर्थप्राप्त है ? विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है सम्यक् ज्ञान (Systematic Knowledge)। किन्तु विज्ञान शब्द साधारणतया गणितीय, रसायन शास्त्र (Chemistry), भौतिक शास्त्र (Physics) जैसे अनेक भौतिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। अतः इसका अर्थ उच्च ज्ञान से लगाया जाता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान में सत्य एवं ठीक प्रमाणित हो। विज्ञान निरीक्षण (Observation), प्रयोग (Experiment) तथा अनुभवों के द्वारा अपने नियम बनाता है और फिर उनके आधार पर भविष्य वाणियों की जा सकती हैं। विज्ञान के नियम, जब भी निश्चित दशाएँ वर्तमान हों, सामान्य रूप से सभी जगह तथा प्रत्येक समय लागू होने हैं। विज्ञान के अध्ययन में जो रीति अपनाई जाती है वह है अनुसंधान (Investigation), निरीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण (Classification) तथा सहसंबन्ध (Correlation) इत्यादि। इस प्रकार व्यापकता अथवा पूर्णता, ठीक होना, समान रूप से लागू करने के लिए नियमों का वर्तमान होना तथा अधिकवाणियों करना अथवा निष्कर्ष निकालना ही विज्ञान के लक्षण हैं। सारांश में, यह कहा जा सकता है कि विज्ञान सम्पत्ता पर आधारित न होकर तथ्यों पर आधारित होता है।

एक राजनीतिक विगठन के रूप में अरस्तू की मौलिक विचारधारा होने का श्रेय वांछे प्राप्त हो अथवा न हो, किन्तु उन्हीं इस बात में भौतिक होने का गौरव अवश्य प्राप्त है कि उसने एक नवीन एवं वैज्ञानिक अध्ययन विधि (Scientific method) का विकास किया। प्लेटो के प्रभाव में आने से पूर्व ही, अरस्तू को एक भौतिक शास्त्री के समान शिक्षा प्राप्त थी और उसने अनेक भौतिकशास्त्रियों की भाँति ही घटनाओं के बार-बार किये गये निरीक्षणों पर अपने निष्कर्षों को आधारित करने की सामान्य प्रवृत्ति हो बनाली थी। यही कारण है कि अरस्तू की धारणानुसार वस्तुओं का सावधानीपूर्वक अन्वेषण और तुलना करने पर ही, उनके भीतर छिपी हुई वास्तविकताओं का पता लगाया जा सकता है एवं उपयुक्त तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

Inductive Method

अरस्तू ने निगमनात्मक अध्ययन विधि को प्रगीतार दिया है। प्रो० बारर

1. "The capital significance of Aristotle, in the history of political theories, lies in the fact that he gave to politics the character of an independent science."

के शब्दों में—'इन अध्ययन विधि का भार या निरीक्षण करना तथा सम्बन्धित आकृति
एकत्रित करना, और इनका स्वरूप या प्रदेष्टा विचार विषय का कोई सामान्य सिद्धान्त
सोच निकालना।' अरस्तू की यह अध्ययन विधि प्लेटो की अध्ययन विधि के प्रतिष्ठित
पहली है। प्लेटो के अनुसार सत्य और आदर्श पूर्ण वस्तुओं में नहीं, अस्तित्व, सामान्य
विचारों में पाये जाते हैं। इनके जगह में वास्तविकता में नहीं बल्कि आदर्श में। यही
कारण था कि वह समस्त सौन्दर्यपूर्ण वस्तुओं में परे एक पूर्ण सौन्दर्य की, समस्त शक्ति
वस्तुओं में परे एक पूर्ण शक्ति की खोज कर रहा था। प्लेटो ने सत्य सत्य (Abso-
lute Truth) के सम्बन्ध में एक पूर्ण धारणा बना ली थी। इसके प्रतिष्ठित अरस्तू की
मान्यता है कि वास्तविकता पूर्ण विचारों में दृष्टान्तिवृत्ति नहीं है। इसके अनुसार हम
जो कुछ भी देखने या अनुभव करने हैं, वह ध्वान्तिवृत्ति है। वास्तविकता को निरक्षर
की वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method), तुलना एवं निष्कर्ष के द्वारा ही जानी
जा सकती है। आदर्श राज्य (Ideal State) की रचना करने में प्लेटो ने व्यक्त-
प्रधान-पद्धति का आश्रय लिया। यही कारण है कि शासन संरचना के तैयार करने समय
वह मानव स्वभाव तथा प्रवृत्तियों में पाई जाने वाली मर्यादों पर अधिक ध्यान नहीं
दे सका। अरस्तू ने इसके विपरीत वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक तथ्य संकलन के
मार्ग पर ही बत नहीं दिया बल्कि तथ्यों का सूम्भाजन करने की चेष्टा भी की। हमने
लगभग 158 ग्रीक संविधानों का अध्ययन कर, सामग्री एकत्रित की—इस विद्वान के
आधार पर कि पूर्ण राजनैतिक अनुभव के अनुवर्तन के अध्ययन के द्वारा महान निष्कर्षों
पर जाना सम्भव होगा। इसमें यह स्पष्ट होता है कि अरस्तू ने मर्यादों का अध्ययन
इसके इतिहास तथा उनकी दृष्टान्तिवृत्ति के माध्यम से किया। यह विधि
निश्चय ही वैज्ञानिक एवं वस्तुगत (Objective) थी।

प्रो० दुरिंग यह मानकर बतते हैं कि अरस्तू के विचारों में प्लेटो के दृष्टान्त
निम्न नहीं सिद्धता कि विधि और स्वयं में। इनके विचार जो देखने में अरस्तू के ही
प्रतीत होते हैं वास्तव में प्लेटो में भी देखने की बातें जाते हैं।¹ प्लेटो के मन, अस्तित्व
हिए भी बहुत बड़े परिमाण तक अरस्तू अपने दर्शन की सन्तानों के लिए इन विचारों
पर निर्भर करता है जो समझाये गये ग्रीक विद्वान की विवेकता के हैं। वह आचार
सम्बन्धी अवधारणाओं (Ethical Concepts) को राजनैतिक अवधारणाओं (Political
Concepts) के दृष्टि करके राजनीति की स्वतन्त्र विज्ञान का रूप प्रदान करता है।
राजनीति विज्ञान ही केवल मात्र ऐसा विज्ञान है जो सर्वोच्च सुख (Supreme
good) की प्राप्ति करता है। इसका अर्थ है हमें पद जने वाली सम्पूर्ण

1. "He differs from his master. Plato, much more in the form
and method than in the Substance of his thought. Most of the ideas
which seem characteristically Aristotelean are to be found in Plato."

—Dunring, A History of Political Theories.

शक्तियों का विकास व्यक्ति के लिए ऐसा होना तब तक असम्भव है जब तक वह अपने साधियों के साथ न रहे। इस प्रकार व्यक्ति का शुभ राज्य के शुभ में मिल गया है। इसीलिए राज्य का विज्ञान राजनीति विज्ञान ही Architectonic है।

प्रादशवाद बनाम सामेअवाद

प्लेटो ने 'रिपब्लिक' में प्रादर्श राज्य का जो विषय उपस्थित किया है वह यथार्थ में कोमा दूर है। वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। सरमू ने भी सर्व प्रथम प्रादर्श राज्य की योजना का प्रयास किया किन्तु अन्त में उसने ऐसे राज्य की योजना की जो कि विशेष परिस्थितियों में सर्वोत्तम हो। दूसरे शब्दों में, सरमू के अनुसार यह निश्चित करने में कि कौन सा अधिधान सर्वश्रेष्ठ है, हमें न केवल यह देखना है कि कौन सा स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि देखना तो यह है कि कौन सा प्रकार की हुई परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ है।¹ अपने राज्य में कानून की सर्वोच्चता की घोषणा करते हुए अथ्य सार्वभौमिकता को सरमू ने अपने राजनीतिक चिन्तन में स्थान दिया है। वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता कि विवेकशील व्यक्ति के हाथ में राजनैतिक जीवन की वागडोर सौंप दी जाए एक अथ्य सब लोग मूक होकर उसके आदेशों का पालन करें। प्लेटो की इस मान्यता के विरुद्ध सरमू ने यह घोषणा की कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का मनमाना शासन किसी भी प्रकार कानून के शासन से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मैसादन के अध्या में कानून की मिलित शक्ति मजिस्ट्रेट का स्थान तो नहीं लेती किन्तु वह मजिस्ट्रेट के अधिकार को एक नैतिक गुण प्रदान करती है जो उसने अथ्यपा नहीं हो सकता।² वास्तव में विवेक सम्पन्न व्यक्ति का शासन भी सामिता के दृष्टि में नहीं हो सकता क्योंकि यह सामितों में हीनता की भावना का विकास करता है। प्राथमिकता शासन की तुलना में कानून का शासन सर्वोत्तम है।

राज्य

सरमू एक सच्चे राजनैतिक वैज्ञानिक के रूप में यह दिखाने का प्रयास करता है कि राज्य समुदाय का ही विस्तृत रूप नहीं है। इसने पूर्ण सम्मेलन और कोई विचार-एक दृग समस्या पर विचार नहीं कर सका। इस भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए वह राज्य का विशेषण इसके अंगों में एवं उसके प्रारम्भिक स्तर से करता है। मुख्य रूप से दो प्रवृत्तियाँ मनुष्य की एक दूसरे में जोड़ती हैं। प्रथम तो पुण्य एवं नारी को एक दूसरे के

1. "We must consider, Aristotle declares, not only what form is the best absolutely, but what is the best under given conditions"

—Quoted from *Durning's, A History of Political Theories*

2. "The passionless authority of law does not take the place of a magistrate, but it gives to the magistrate's authority a moral quality which it could not otherwise have"

—Sabin, *History of Political Theory*, P. 94-95.

मर्माप लाती है तथा दूसरी भौतिक एवं दास की पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे के निकट लाती है। इस प्रकार तीन व्यक्तियों का एक सबसे छोटा समाज बनता है। समाज जो कि प्रतिदिन की मांग को पूर्ण करने के लिए प्रकृति के द्वारा स्थापित की हुई एक संस्था है। प्रगती स्थिति एक गांव की है जो कि प्रतिदिन की मांगों से कुछ अधिक की पूर्ति के लिए, कुछ परिवारों द्वारा किया हुआ एक समूह है। तीसरी अवस्था है कुछ गांवों का एक पूर्ण समुदाय या समूह, जो कि आमनिर्भरता के लिए पर्याप्त बड़ा है तथा जो जीवन के लिए अस्तित्व में आया किन्तु अच्छे जीवन का बनाये रखने के लिए विद्यमान है। यही पर राज्य का अन्य समुदायों से भेद स्पष्ट हो जाता है। राज्य भी उसी कारण से अस्तित्व में आया जिस कारण से गांव पर्याप्त जीवन को बनाये रखने के लिए किन्तु राज्य को एक अन्य इच्छा की भी पूर्ति करनी है वह है अच्छे जीवन की इच्छा। राज्य अपने पूर्वगामियों की अपेक्षा नैतिक कार्यों के लिए अधिक पर्याप्त धन प्रदान करता है। राज्य का उद्देश्य विकास दिवाकर अरस्तू ने उसी प्रकृति (Nature) पर अच्छा प्रकाश डाला है। राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति (Origin) एवं कार्यों के विषय में विचार प्रकट कर अरस्तू ने राजनीति शास्त्र के कुछ ऐसे घटक सार्यों पर प्रकाश डाला है जिन पर प्राचीन काल से लेकर अब तक राजनीति शास्त्र के विद्वान् बराबर चिन्तन करने प्रारंभ हैं।

प्लेटोनिक साम्यवाद का विरोध

प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में साम्यवाद (Communism) की जिस व्यवस्था का समर्थन किया है, अरस्तू उसमें सहमत नहीं। वह तथ्यों में भुल नहीं मोड़ता और यह मानकर चलता है कि साम्यवाद की ऐसी व्यवस्था समाज का एक अंग बनकर नहीं रह सकती। अरस्तू के अनुसार बहुसंख्यता (Plurality) तो राज्य की प्रकृति में ही है और यह है असमानता की बहुसंख्यता (Plurality of Unequals)। इसके विपरीत प्लेटो की धारणा तो यह है कि राज्य में जितनी अधिक एकता होगी उतना ही अच्छा है। अरस्तू के अनुसार एक राज्य में कार्यों की विभक्तता होती है जिसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुछ का कार्य शासन चलाना है एवं कुछ लोगों का कार्य शासित होना। अगर एकता का आदर्श ठीक भी हो तो भी अरस्तू के अनुसार इसे प्लेटो के कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। समान वस्तुओं के लिए मेरी या मेरी नहीं कहने मात्र में ही एकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता जैसा कि प्लेटो मानकर चलता है। अरस्तू के अनुसार यद्यपि प्लेटो के राज्य में एक वाक्क मनी का ही वाक्क है वह इस अर्थ में कि उसे एक निश्चित उम्र के मंत्रियों द्वारा अपना लिया जाता है पर वह सभी का वधा नहीं हो सकता और वह इस अर्थ में कि वह हरेक का ही वधा है। किसी भी व्यक्ति में उस वाक्क के प्रति वे भावनाएँ नहीं होंगी, अथवा उनकी तरफ वेना ही ध्यान नहीं देगा जो कि वह स्वयं के अपने वच्चे पर दे सकता। हर नागरिक के हज़ारों लड़के एवं हर लड़के के हज़ारों पिता होंगे। ऐसी परिस्थितियों में पनपने वाली मित्रता

वाणिक होगी। सरन्तू शायद यह मानेगा कि "It is better to be a cousin than a Platonic son".

इसी प्रकार सरन्तू यह भी कभी स्वीकार नहीं करेगा कि व्यक्तिगत सम्पत्ति (Private property) की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय और इसके लिए वह जिन कारणों की खोज करता है उनमें वास्तव में सच्चाई है भी। इसमें सन्देह नहीं है कि आर्थिक साधना का राजनीतिक जीवन में संगठन पर समुचित रूप में प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह भानव जीवन में निरत ही श्रेष्ठ गुणों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करता है, सम्पत्ति के सम्भाव्य अपने जीवन का समुचित विकास नहीं कर सक्ता है। समान सम्पत्ति के बोझ पर दृष्टिपात करते हुए सरन्तू भी धारणा है कि इस व्यवस्था में जो व्यक्ति बठिन परिश्रम करने हैं तथा थोड़ा पास हैं उनके प्रति वे लोग प्रवक्ष्य बहुता का अनुभव करेंगे जो थोड़ा परिश्रम करने ही अधिक प्राप्त कर लेते हैं। इससे प्रतिरिक्त सम्पत्ति का समान स्वामित्व (Common ownership property) भगवें की जड़ है। फिर सम्पत्ति का विचार ही मानव का श्रोत है। व्यक्ति सब अधिक कार्य कुशल होने हैं, जब वे उस कार्य को सम्पन्न करते हैं जो उनका अपना ही होता है। श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन की स्थापना सभी सम्भव हो सकती है जब कि राज्य के नागरिकों की आर्थिक विषमता का कम से कम किया जाय एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था स्वीकृत की जाय। नागरिका के एक भाग का अपनी सम्पत्ति का विकास करने वाले जाना तथा दूसरे भाग का सम्भाव्य रहना राज्य के प्रतिष्ठित के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होगा। इसमें सन्देह नहीं है कि इस प्रश्न पर सरन्तू ने अत्यन्त व्यावहारिक विचार व्यक्त किये हैं। दर्शित की भी यही मांग्यता है जब व कहते हैं— "बहु एग्य नहीं है, जो व्यक्तियों की समस्त विभिन्नताओं को ही समाप्त कर दे। राज्य की एग्य ही उन व्यक्तियों के मध्ये सम्बन्धों से विकसित होगी जो शासक एवं शासित के रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं।"¹

परिवार और दास

प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में राज्य को एक विस्तृत परिवार एवं राज्य के शासन को परिवार के प्रमुख के रूप में प्रदर्शित किया है जिसकी सरन्तू ने तीव्र प्रशंसा की है। अपने विचारों का समर्थन यह सर्व की समीचीन करता है। राज्य और परिवार एक दूसरे से भिन्न हैं—मात्रा में ही नहीं बल्कि प्रकार में भी। परिवार उन व्यक्तियों से मिलकर बना होता है जो अपनी पत्नी, बच्चे, धन एवं साथ ही दासों पर स्वामित्व रखता है। किन्तु मातृत्व का इन तीनों के साथ सम्बन्ध एक ही प्रकार का नहीं है। बहु धर्मी

1. "It is not a unity which consists in the obliteration of all diversities in individuals. The unity of the state is that which arises out of the proper organisation of relations among individuals who differ from one another as rulers and ruled."

पत्नी पर एक पूर्ण निरंकुश के रूप में शासन नहीं करता बल्कि एक मर्यादित सहाय-कार के रूप में शासन करता है। अपने बच्चों पर भी वह एक निरंकुश (Despot) के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में शासन करता है जो कि अपने हित की तरफ न देखकर, उनके हित की परवाह करता है। दाना के साथ उसका व्यवहार एक पूर्ण निरंकुश शासक जैसा होता है। जबकि अरस्तू के अनुसार राज्य में शासक का प्रत्येक नागरिक के साथ सम्बन्ध एक ही प्रकार का होता है। टॉल्सू० डी० रोस के शब्दों में कहा जा सकता है कि "परिवार जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये विद्यमान है जबकि राज्य का अस्तित्व नैतिक एवं बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना हुआ है।"¹ अरस्तू ही प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने राज्य एवं परिवार के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचकर भ्रम का निवारण किया। अरस्तू इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि राज्य व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखे। यद्यपि निजी अधिकारों के विषय में उनके कोई दृष्टुं ही उच्च विचार नहीं हैं क्योंकि यह विचार तो ग्रीक चिन्तन के लिए ही विदेशी था। पर वह यह तो स्वीकार करता है कि व्यक्ति उस समय सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, जब कि उसका व्यक्तित्व राज्य में ही समाहित कर दिया जाय। इसके साथ ही नाय अरस्तू लिंगों (Sex) की असमानता में भी विद्वान् करता है। वह यह मानकर चलता है कि "पुरुष आदेश देने में, स्वाभाविक रूप में ही नारी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बड़े एवं पठित, छोटे एवं अपरिपक्व की अपेक्षा अधिक उच्च होते हैं।"²

सरकार और जनमत

अरस्तू ही प्रथम राजनीतिक विचारक था जिन्होंने जनमत की उत्पत्ति एवं उसके महत्व पर दल दिया। इसके पूर्व सुक्राट एवं प्लेटो ने तो बौद्धिक निरंकुशता (Intellectual Despotism) का समर्थन किया। राज्य की सर्वोच्च शक्ति का निशान एक व्यक्ति के हाथों में ही प्रथम जनमनुदाय के हाथों में, इस प्रश्न पर विचार प्रकट करते हुए उनमें कहा कि कुल मिलाकर जन मनुदाय का विवेक किसी व्यक्ति विशेष के विवेक से अधिक श्रेष्ठ होता है। जनमाधारण में चाहे एक विशेषण की भांति राजनीतिक प्रदनों का समाधान ढूंढने की क्षमता बने ही न हो किन्तु जिस प्रकार कारीगरों की अपेक्षा मकान के गुण दोषों का अधिक अच्छा ज्ञान मकान में निवास करने वालों को हो सकता है उसी प्रकार राजनीतिक प्रदना का अच्छा ज्ञान जनमाधारण को ही हो सकता है जो किन्हीं राजनीतिक व्यवस्था में निवास करने हैं। जनमाधारण के हाथ में

1 "The household exists for the sake of the physical needs of life, the state for the moral and intellectual needs"

—W. D. Ross, Aristotle.

2 "The male is by nature better fitted to command than the female, just as the elder and full-grown is superior to the younger and more immature."

—Aristotle's Politics, P. 22.

सर्वोच्च सत्ता का निवास होना राज्य के लिए हितकर ही सिद्ध होगा। मात्र किसी भी राजनैतिक समुदाय में सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति (Supreme Political Power) एवं सर्वोच्च राजनैतिक विज्ञान (Supreme Political Wisdom) की उपस्थिति हम जन-मायाराण में ही स्वीकार करके चलते हैं व्यक्ति विषय में नहीं। जनमत ही राज्य के प्रजातन्त्र का आधार है।

राज्य और व्यक्ति

व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक सम्बन्धों का स्वल्प किम प्रकार का हो इस पर जो विचार प्रकट किये गये हैं उनमें सर्वाधिक महत्व गरन्तू का ही है। सोफिस्ट विचारकों ने पूर्ण व्यक्तिवाद (Absolute Individualism) का पक्ष लिया। यहाँ राज्य का व्यक्ति के हितों का पूर्णता का एक माधन मान बना दिया गया है। प्लेटो ने राज्य की प्राकृतिक एकता (Organic unity) का कण्टन यहाँ तक बड़ा फटा कर दिया है कि 'व्यक्ति अपने प्रापका राज्य में पूरी तरह समा दता है। गरन्तू यह मानकर तो चलता है कि राज्य ही अन्तिम और पूर्ण मन्था है एवं जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ण करने के लिए इसका जन्म हुआ किन्तु यह जीवन को पूर्ण बनाने के लिए बना हुआ है'। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएँ हैं। जहाँ गरन्तू राज्य का व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य प्राकृतिक एवं सर्वोच्च समुदाय के रूप में दर्शना है वहाँ उसने व्यक्तिवाद विचारक (Individualistic Thinker) की भाँति यह धोखला भी की है कि राज्य के प्रतिरिति भी व्यक्ति की धर्म प्राकृतिक एवं अनिवार्य मन्थाएँ हैं। राज्य को गरन्तू ने अपने प्राय में एक लक्ष्य नहीं माना कि राज्य का वह एक बनी माना में साधन मानता है जिसका साध्य है व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति। व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हो इस विषय पर गरन्तू अन्य विचारकों की अपेक्षा अधिक सतर्क है।

स्वतन्त्रता और शक्ति

गरन्तू ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Individual Liberty) एवं राजनैतिक शक्ति का भी समुचित रूप से अनुसन्धान केन्द्र का प्रमाण किया है। बान्तिव में राजनैतिक जीवन की प्रथम बड़ी समस्या ही यही है कि इनमें तालमेल किम प्रकार देखया जाय। प्रत्येक राज्य में शासक एवं शासित दो वर्ग होते हैं। इन दोनों वर्गों के पस्तिव के समान में राजनैतिक-जीवन की सम्पत्ता दुप्पर है। राजनैतिक शासन के विन्तर्ग में सामने यह समस्या गंदा ही रहती है। गरन्तू यह मानकर चलता है कि पूर्ण स्वतन्त्रता एवं पूर्ण समानता एक सम्भव सम्भाव्यवहारिक सम्पत्ति है, इसकी उपस्थिति भी किसी दृष्टिकोण में उपयुक्त नहीं जही या मजती। इसके साथ ही वैधानिक जीवन का निर्वाह करना एवं वैधानिक नियमों का पालन करना व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं समानता के निम्न पात्र

1 'It is the last and the perfect association. Originating in the bare needs of living it exists for the sake of complete life'

नहीं होगा। अरस्तू तो यहाँ तक कहता है किमी विधान के अन्तर्गत व्यतीत किया जाने वाला जीवन शान्ति का नहीं, अपितु सर्वोच्च कल्याणकारी जीवन समझा जाना चाहिये।¹ व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं राजकीय शक्ति में अनुत्तम कायम करके उसने एक विवादग्रस्त समस्या को वैज्ञानिक ढंग से सुलझाने का प्रयास किया है।

अरस्तू हमारे सम्मुख एक मयार्यवादी विचारक के रूप में आता है। मरतः उसने प्लेटो की नाति एक ऐमे आदर्श राज्य का चित्र अङ्कित नहीं किया जो केवल मृगशृङ्गा की नाति है। यह निश्चित करने में कि कौनसा संविधान श्रेष्ठ है, सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि कौनसा प्रकार व्यावहारिक है या दूसरे शब्दों में किमे सर्वश्रेष्ठ ढंग में प्राप्त किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार ही संविधान का स्वरूप निश्चित करना उचित होगा। अरस्तू यह मानकर चलता है कि मानव समाज में समीची और गरीबों की अति ही दुर्गुणों को जन्म देती है। प्रथम तो शाखापालन की समता का प्रभाव उत्पन्न करती है तथा द्वितीय आदेश देने की क्षमता में वंचित कर देती है। जिस राज्य की जनता समीची और गरीबों इन दो वर्गों में विभक्त हो जाती है वहाँ कोई वास्तविक राज्य नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ इन दो वर्गों में मन्ची मित्रता नहीं होगी जो मनी समुदायों का आधार है।² अतः वह राज्य सर्वश्रेष्ठ है जिसमें मध्यम वर्ग प्रत्येक में या दोनों छोरों में अधिक शक्तिशाली है। ऐमे राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाये रखने वाले कारण प्रमाणपूर्ण मात्रा में होंगे तथा स्थिरता राज्य का लक्षण होगी। वह संविधान, जिसमें मध्यम मार्ग का सिद्धान्त निहित रहता है, निश्चित ही 'पॉलिटी' (Polity) है किन्तु इससे भी यह अनिग्राय लेना गलत होगा कि पॉलिटी ही प्रत्येक प्रकार की दशाओं में आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तू की धारणादुसार परिस्थितियाँ संविधान के किसी भी प्रकार की सर्वश्रेष्ठ बना सकती हैं। यही सामान्य सिद्धान्त यह है कि वे शक्त जो कि वर्तमान संविधान को बनाये रखने में प्रमुख होने हैं उन तरकों की अनेका अधिक शक्तिशाली होने हैं जो कि किसी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में स्थिरता ही मापदण्ड है। वहाँ संविधान सर्वश्रेष्ठ है जो परिस्थितियों में सबसे अधिक समय तक टिका रहता है। अरस्तू ने उन दशाओं का भी वर्णन किया है जिन्हें अपनाकर ही कोई संविधान श्रेष्ठता की पंक्ति में सदा ही सकता है। यहाँ उसका दृष्टिकोण निश्चय ही उम डॉक्टर की नाति है जो रोग के कारणों के साथ ऐमे उपचार भी बताता है जिससे स्वास्थ्य बनाया रखा जा सके। अरस्तू स्वयं कहता है कि व्यक्ति की ही नाति राज्य के लिये सर्वश्रेष्ठ जीवन मद्दुणों

1. "For life in Subjection to the Constitution is not to be regarded as slavery, but as the highest welfare." —Aristotle, Politics.

2. "Where a population is divided into the two classes of very rich and very poor, there can be no real State; for there can be no real friendship between the classes and friendship is the essential principle of all association." —Aristotle's Politics.

की प्राप्ति में होता है, सम्पत्ति की शक्ति की प्राप्ति करने में नहीं।¹ जिस प्रकार एक व्यक्ति ने द्वारा दासों पर सामन करना कोई उच्च वस्तु नहीं है उसी प्रकार एक राज्य ने द्वारा निरंकुश साम्राज्य (Despotic Empire) की बनाये रखना कोई सम्मानजनक वस्तु नहीं है। एक साम्राज्य युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करना ही राज्य का उद्देश्य नहीं हो सकता। राजनैतिक और सामाजिक संगठन के सम्मत् तत्वा की क्रियाप्राप्ति में समरसता और पूर्णता प्राप्त करना ही सच्चा आदर्श है तथा उसमें ही व्यक्ति और राज्य का पूर्ण मूल निहित है। यह आदर्श कुछ भी न तो बाहरी दशावा पर निर्भर करता है किन्तु बड़ी मात्रा में लोग के चरित्र और समृद्धि पर निर्भर करता है।

सविधान

सविधानों का वर्णन एवं वर्गीकरण करने में सरसू ने जिस विद्वता का परिचय दिया है, इसमें भी सामग्री की गहनता स्पष्ट होती है। सविधानों का वर्गीकरण प्रथम तो यह उस समस्या के आधार पर करता है जिसमें सार्वभौमिक शक्ति निहित है तथा द्वितीय उस उद्देश्य के आधार पर जिसकी तरफ सरकार का आवरण निर्देशित है। बाद कापा सिद्धान्त विचुद्ध प्रकारों की छत्र प्रकाश में प्रेष करता है, क्योंकि राज्य का सच्चा उद्देश्य अपने सदस्या का पूर्णता प्राप्त करना है। जब हम उद्देश्य की मामने रखकर सरकार धार्मिक होती है तो वह प्रकार विचुद्ध है किन्तु इसके विपरीत जब प्रशासन सभी नागरिकों के हित की तरफ नहीं बल्कि केवल शासकीय सत्ता के हित की तरफ केन्द्रित होता है तो राज्य भ्रष्ट (Corrupt) होता है। सरसू ने राजतन्त्र (Monarchy), कुर्वीत तन्त्र (Aristocracy) एवं पोलिटि (Polity) की विचुद्ध प्रकार एवं आधाचार तन्त्र (Tyranny), धनतन्त्र (Oligarchy) तथा प्रजातन्त्र (Democracy) का इनके भ्रष्ट प्रकार माना है। इस वर्गीकरण में जो मुख्य ध्यान है वह यह कि विचुद्ध प्रकार एक आदर्श पर आधारित होने हैं जब कि इनके भ्रष्ट प्रकार (Corrupt forms) इन आदर्शों पर आधारित न होकर उसमें दूर दृष्ट होने हैं। इन दो प्रकारों में से प्रत्येक के अन्तर्गत सरसू ने एक के द्वारा, कुछ के द्वारा अथवा बहुतों के द्वारा बनाई जाती है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि सरसू ने सविधानों का वर्गीकरण करने में केवल समस्या की ही आधार बनाया है। धनी बहुमत (Rich majority) प्रजातन्त्र नहीं है, इसी प्रकार गरीब अल्पमत (Poor minority) को धनतन्त्र नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः धार्मिक में बहुत्वहीन हैं। धनतन्त्र आवश्यक रूप से धनीको द्वारा बनाई जाने वाली सरकार है। इसी प्रकार प्रजातन्त्र गरीबों के द्वारा बनाई जाने वाली सरकार है। इस दृष्टिकोण से पोलिटि आवश्यक रूप से मध्यम वर्ग की सरकार है। एक स्थान पर सरसू प्रजातन्त्र के अन्तर्गत की कुछ विशेषताओं को इस प्रकार से बताता है—उच्च जन्म, सम्पत्ति एवं शिक्षा। इसी प्रकार प्रजातन्त्र के अन्तर्गत की कुछ विशेषताएँ नीचा जन्म, गरीबी, अज्ञान आदि

1. "For the State, as for the individual the best life lies in the pursuit of virtue, rather than of power or wealth" - Aristotle's Politics.

है। संविधानों में भेद करने का एक और मार्ग है। हम यह पूछ सकते हैं कि वह कौनसा सिद्धान्त है जिसके आधार पर सरकारी कार्यालय वितरित किये जाते हैं। घनतन्त्र के सम्बन्ध में इसका उत्तर है सम्पत्ति। किन्तु गरीबी का प्रजातन्त्र में सरकारी कार्यालय सौंपने का आधार नहीं माना जा सकता। भाग्य ही वह आधार जिसके अनुसार राजतन्त्रों एवं कुलीनतन्त्रों में शक्ति निहित की जाती है। कवन राजा का अकेला होना अथवा कुछ शासक का होना ही नहीं है, अतः राजा का सर्वोच्च सद्गुण (Supreme virtue) अथवा शासकीय वर्ग का तुलनात्मक सद्गुण है।

संविधानों के वर्गीकरण में इन विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर फलस्वरूप यद्यपि इसे सम्भव माना कुछ कठिन प्रबन्ध हो गया है किन्तु हम संविधानों का विभाजन के निम्नी एक सिद्धान्त के आधार पर ही वर्गीकृत करने के विरुद्ध अस्मू की चेतावनी को ध्यान में रख सकते हैं। हम अब भी राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, घनतन्त्र एवं प्रजातन्त्र के बीच वही भेद स्थापित करने हैं जैसा अस्मू ने स्वयं ही किया। अस्मू के अनुसार वे सिद्धान्त जो हर समुदाय में सर्वाधिकारिता को शामिल करने के लिए भगड़े का कारण बन जाते हैं, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सद्गुण तथा जन्म आदि हैं। जन्म स्वतन्त्रता के आधार पर सरकार के आचरण में भाग प्रदान किया जाता है वहीं का संविधान प्रजातन्त्रात्मक है। जहाँ सम्पत्ति का मुख्य आधार बनाया जाता है वहीं की सरकार घनतन्त्रात्मक है। कुलीनतन्त्र में सद्गुण ही मुख्य आधार है जिसके आधार पर अधिकार वितरित किये जाते हैं। किन्तु पार्लियामेन्टरी वह संविधान है जहाँ स्वतन्त्रता और सम्पत्ति दोनों ही सिद्धान्तों का समावेश होता है। संविधानों का वर्गीकरण इतने वैज्ञानिक ढंग से अस्मू के पूर्व सम्भव नहीं हो सके थे।

सरकार का संगठन

अस्मू ने सरकार को तीन आवश्यक भागों में विभक्त किया है। प्रथम तो विचार-विमर्शपूर्ण भ्रम, द्वितीय मजिस्ट्रेटों का एक व्यवस्था तथा तृतीय एक श्यापिक भ्रम। इन तीन तत्वों के स्वरूप और कार्य की भिन्नता पर विविध संविधानों की प्रकृति निर्भर करती है। अतः को पहुँचे हुए प्रजातन्त्र में विचार-विमर्श करने वाला भ्रम समस्त व्यक्तियों की एक सभा होगी जो सभी प्रश्नों पर प्रत्यक्ष रूप में विचार करेगी। अतः को पहुँचे हुए घनतन्त्र में विचार विमर्श करने वाला भ्रम अत्यन्त घनी नागरिकों का एक समूह होगा जिनके पास असीमित शक्तियाँ रहेंगी। पार्लियामेन्ट में इन दोनों का मिश्रण होगा क्योंकि यहाँ विचार विमर्शपूर्ण भ्रम नागरिकों का वह समूह होगा जिनकी संपत्ति सम्बन्धी योग्यताओं मध्यम प्रकार की होगी जो विषयों के एक भाग पर ही अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

क्रांतियों और उनके उपचार

अन्तिम परिपक्व राजनीतिक बुद्धि के द्वारा अस्मू ने उन कारणों को जानने का भी प्रयास किया है जो एक संविधान को विह्वल कर देते हैं। अस्मू ने न केवल कारणों

पर ही प्रकाश डाला है बकि उपचार बनान में भी अपनी राजनीतिक बुद्धि एवं विवेक का परिचय दिया है। मरस्तू ने अनुसार क्रांति का एक मुख्य कारण व्यक्तिगत एवं पणीय तथा धन की दूषित धारणाओं हैं। प्रजातन्त्रवादी सोचने हैं कि व्यक्ति व्यक्ति सम्पत्ति में सममान हान हैं, अत उन्हें पूर्ण रूप से सममान होना चाहिए। वे कारण, जो क्रांतिकारी के मन की दशा को इस ओर ले जाने हैं वे हैं दूसरा के द्वारा लाभ या सम्मान हृदय सेना, क्रोध एवं प्रतिक्रोध की भावना, राज्य के किसी भाग में अनुपात रहित वृद्धि (Disproportionate increase in any part of the State), चुनाव थकान (Election fatigue) छोटे परिवर्तना पर आवश्यक ध्यान न देना आदि। ऐतिहासिक ज्ञान के आधार मरस्तू के कारण मरस्तू ने ज्ञान व इन कारणों के विभिन्न उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं एवं उनके उपचार भी बताये हैं किन्तु अपनाकर सचि यानों की स्थिरता निर्दिष्ट की जा सकती है।

मरस्तू के विचारों में हम उन सत्यों को उपस्थिति का आशय मिलता है जिनके आधार पर भागे माने जाने विस्तृत ने राज्य का सार्वभौमिकता (Sovereignty) सम्बन्धी दर्शन प्रस्तुत किया है। वह इस बात को मानकर चलता है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। किन्तु यह विस्तृत पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उदाहरण स्वल्प मरस्तू ने इस सर्वोच्च शक्ति को भी कानून में उपर नहीं मानकर उसके अधीन ही माना है। इस प्रकार सार्वभौमिकता सम्बन्धी अत्यन्त वैज्ञानिक विचारों का प्रतिपादन वह अपने ही नहीं कर पाया हो किन्तु जो कुछ भी उसने विचार प्रकट किये उन्ही पर भागे चलकर सार्वभौमिकता सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन किया गया।

अत स्पष्ट है कि मरस्तू के पूर्व के राजनीतिक विचारकान राज्य व सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये वे वैज्ञानिक नहीं थे। गुरुत्वात् न तो राज्य के सम्बन्ध में विचार ध्यान नहीं दिया। राज्य की स्थापना ही उसका परम ध्येय था। प्लेटो ने निराला मय के आधार पर जिन राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया है वे व्यावहारिक अधिक हैं। मरस्तू ही प्रथम राजनीतिज्ञ हैं जिसे अपने विचारों को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जा सकता है। उसका आदर्श राज्य प्लेटो के आदर्श राज्य की भांति काल्पनिक न होकर व्यावहारिक है। दोनों के बचन में वही कोई छुट्टि नहीं कि मरस्तू ही प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक या ओर राजनीतिक विचारक व इतिहास में उनका महत्व निश्चय ही निर प्रतीष्टित है।

BIBLIOGRAPHY

- (1) ROSS W. D. Aristotle
- (2) BARKER Plato and Aristotle
- (3) JOWETT The Politics of Aristotle
- (4) MAXEY Political Philosophies.
- (5) GOWPERZ Greek Political Thinkers

मध्ययुगीन विचारकों के मुख्य विचार

(POLITICAL IDEAS OF MEDIAEVAL THINKERS)

—निर्मल पूठिया

राजनैतिक दर्शन व इतिहास में मध्ययुग वह प्रारम्भ होता है इसके बारे में इतिहास एकामत नहीं है। लेकिन हमें ऐसे कुछ ऐतिहासिक पूर्वमध्यकाल और अनन्तरमध्य काल में मदद करते हैं और मुख्यतः, मुख्यतः आल्फ्रेड, पात्र प्रमुख तथा कुछ अन्य वर्ष अन्तर्गत का पढ़ने का माध्यम बन रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे ऐतिहासिकों के मतानुसार मध्यकाल समाप्त वर्ष की स्थापना के प्रारम्भ होता है। कुछ अन्य विचारकों के अनुसार मध्यकाल का प्रारम्भ 11वीं शताब्दी से होता है। स्विट्जरलैंड के हम इस मध्यकाल का प्रारम्भ मान सकते हैं। 11वीं के 13 वीं शताब्दी तक का एक वर्ष का स्वरूपयुग कहा जाता है। इसमें पात्र और वर्ष अपनी उत्तरी ओर पर सीमा पर पहुँच गये थे।

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु का विश्वास था कि सामाजिक जीवन का सबसे अच्छा रूप राज्य है। अगर राज्य में ही मनुष्य को जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में राज्य का उद्देश्य केवल अपने नागरिकों की नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना मात्र नहीं है बल्कि व्यक्ति के सामाजिक और वैदिक विचारों का अनन्तरमध्यकाल में भी बढ़कर है। इन दोनों दार्शनिकों ने व्यक्ति को राज्य में अपना जीवन-काल बिताने का अधिकार नहीं दिया था कि उनका स्वयं में कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा था। अरस्तु प्लेटो और अरस्तु के बाद आने वाले दार्शनिकों ने राज्य की महत्त्वपूर्णता का गुण जीवन व निरन्तर विचारों को नहीं माना। गुण जीवन की प्राप्ति के निरन्तर का राज्य में बहुत रहना चाहिए। यदि राज्य का पूर्ण बहिष्कार न कर सके तो राज्य में कम से कम संतुष्ट रहे। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के और उनके बाद आने वाले राजनैतिक विचारों के अनुसार वह हमें राज्य के विचार पर मानें हैं तो हमें एक निरन्तर सामाजिक वातावरण का अनुभव होता है। रोमन दार्शनिकों की मध्ययुगीन दन काटन तथा व्याख्या है। उनका अनुसार काटन धर्मनिर्देश है जिसका अर्थ जीवन की इच्छा के साथ निरन्तर है। यूनानी दार्शनिकों के विचारों के विपरीत रोमन विचारों के अनुसार व्यक्ति का धर्मनिर्देश मुक्ति है, उसका राज्य में विचार नहीं दिया जा सकता। रोमन विचारों में व्यक्ति ही काटन विचार का केन्द्र बन गया। व्यक्ति व इच्छाओं को पूरा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य ही माना था। रोमन के

अनुसार जनता शासक के आदेशों का पालन यह भोचकर करती है कि शासक उसकी दो हुई शक्ति का उपयोग करता है। इस प्रकार यह विचार उपभूत हुआ कि राज्य की शक्तिमत्त शक्ति पर जनता का अधिकार है किन्तु यह इसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों के मजबूत का भोष दती है। सामन्तवाद भी प्रारम्भिक मध्ययुग की ही देन है। इसका जन्म उस समय होता है जिस समय प्राचीन विचारधारा धीरे धीरे गमप्लन हो रही थी और एक नवोदय सामन्तवादी विचारधारा सामने आ रही थी। यह सामन्तवाद मध्ययुग पर पूरी तरह से छाया रहा।

सत अगस्तोनि और सहस्रस्तित्व सिद्धान्त

मध्ययुग के प्रारम्भिक चरणों में सन्त आगस्टाइन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसे रोमन चर्च फादर में महानतम सम्मान जाता है। आगे आने वाले विचारकों पर सन्त आगस्टाइन का काफी प्रभाव पड़ा।¹ उनका प्रादुर्भाव अगार के इतिहास में एक अचानक नाजुक समय में हुआ। ईसाई धर्म गिराफिया का 11 हतोड उत्तर देने के लिए उद्भूत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "दो गिनी आफ मोड" की रचना की। यह ग्रन्थ प्रायन्त महापुरुषों और विख्यात है। इसमें उन्होंने मनुष्य की दो राज्या का नागरिक माना है। बाहरी की दृष्टि से वह सौख्यिक राज्य का सदस्य है और आन्तरिक की दृष्टि से वह ईश्वरीय राज्य का सदस्य है। इन सौख्यिक नगर राज्य पर ईशान का शासन होता है जबकि ईश्वरीय नगर पर ईश्वर का शासन होता है। किन्तु जिनको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गी है उनकी दो दुग ईश्वरीय राज्य की सदस्यता मिलती है। ईश्वर और उनके नागरिकों में बड़े मजबूत सम्बन्ध होते हैं। अन्य सौख्यिक राज्या की भांति ईश्वरीय नगर राज्य में अराजकता नहीं होती। धर्म और शांति ईश्वरीय राज्य की विशेषताएँ हैं। आगस्टाइन अपनी पुस्तक में सौख्यिक राज्य को एक सर्वोच्च भव्य नहीं मानता। धूनानी दार्शनिकों की भांति सन्त आगस्टाइन ने दाम प्रया का भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार दामता मनुष्य के पापा का फल है जो मनुष्या को ईश्वर द्वारा दिया जाता है। आगस्टाइन राज्य की स्वतन्त्रता को भी स्वीकार नहीं करता। वह उसे ईश्वर की उच्चतर शक्ति के आधीन मानता है। राज्य के वाग्डान का पालन करना तथा उसकी शक्ति का सम्मान करना केवल नहीं। तब उचित है जहाँ तब वह ईश्वर के प्रति उसका कर्तव्य का उन्मथन न हो। दुग धारणा में स्पष्ट है कि हमने राज्य की चर्च के अधीन कर दिया था। पर वह आगे आने वाले विचारकों की तरह धर्मसम्बन्ध की रक्षा नहीं करता। वह राज्य की चर्च का एक पग नहीं बनाता। उसके अनुसार राज्य यदि आस्थाविधेय क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो उचित

1. 'His writings (St Augustine's) were a mine of ideas from which the later writers Catholics and Protestants have dug'

प्रति भक्ति का परित्याग कर देना चाहिये । मागस्टाइन इस बात पर भी जोर देता है कि लौकिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति व बिना मृत्यु प्राय है ।

पौपवाद और उसके समयक

परन्तु मध्य युग व उन्नतकाल में ध्यान वाले विचारका ने राज्य और धर्म के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी । टॉमस एक्वीनास, पाप ग्रेगरी गतुम तथा बनीफोन अष्टम जैसे विचारका ने राज्य का चर्च के अधीन करके चर्च की सर्वोच्चता का स्थापना किया । चर्च की प्रभुता व समर्थता में पाप ग्रेगरी मजबूत सबसे पहला दार्शनिक था । वह चर्च के उद्देश्य को राज्य व उद्देश्य में थोड़ा मानता था । इसी कारण राज्य का समस्त हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था । इसी प्रकार जान ग्राफ सैल्सबरी ने चर्च का सर्वोच्चता का स्थापना किया । उसने राजा का राज्य में बड़ी स्थान दिया जो शरीर में सिर का स्थान होता है । उसने चर्च की तुलना आत्मा से की है । जिस प्रकार आत्मा सिर और शरीर पर शासन करती है उसी प्रकार राजा भी ईश्वर और उसके प्रतिनिधियों के अधीन है ।

सन्त टॉमस एक्वीनास 13वां शताब्दी का महानतम व्यक्ति ही नहीं बल्कि उन्नीस मध्ययुग के महान्त विचारका में भी महानतम माना जाता है । एक्वीनास ने चर्च का राज्य में थोड़ा बताया पर भिन्न तरीके से । यद्यपि वह यह स्थापना करता है कि राज्य एक प्राकृतिक समस्या है । लेकिन दूसरी ओर वह यह भी स्थापना करता है कि राज्य का शक्ति ईश्वर से मिलता है । उसका मानना था कि मनुष्य का दो प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं—एक भौतिक आवश्यकता जिसका सम्बन्ध शरीर से होता है और दूसरी आध्यात्मिक आवश्यकता जिसका सम्बन्ध आत्मा से होता है । इन शारीरिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा की जाती है पर आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरी समस्या चर्च की उत्पन्न होती है । उसके अनुसार राज्य और चर्च में कोई विरोध नहीं है । वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ।¹ यद्यपि एक्वीनास राज्य और चर्च का एक दूसरे का पूरक मानता है पर साथ ही वह यह भी स्थापना करता है कि जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है उसी प्रकार राज्य भी चर्च के नियन्त्रण में है ।

राज्यवाद बनाम पौपवाद

दूसरी ओर कुछ ऐसे भी विचारक हुये जिन्होंने चर्च की प्रभुता को नहीं बल्कि

1 "His (St Thomas's) Philosophy sought to construct a rational scheme of God, nature and man with in which Society, and Civil authority find their due place In the sense Thomas's Philosophy expresses most maturely the convictions, moral and religious upon which mediæval civilization was founded."

राज्य की प्रभुता को स्वीकार किया। इसमें दांते, मार्सिलियो, विनियम आफ ग्रामम आदि के नाम लिये जा सकते हैं। दांते के विचार अपने पूर्व विचारों से भिन्न हैं। उसने पूर्व विचारों में चर्च का समर्थन किया पर उसने राज्य का समर्थन किया। परन्तु वह राष्ट्र राज्य की बात नहीं करता है, वह राज्य का चर्च व धन में विस्तृत मुक्त कर देता है। उसका मानना था कि मानव कल्याण के लिये राजन्य आवश्यक है। मनुष्य की यह विवेकता है कि वह विवेकी है। पर इस विवेकी जीवन को वह नहीं प्राप्त कर सकता है जब समाज में शांति हो। पर शांति सभी मनुष्यों को नहीं मिलती है जबकि हमारे समाज पर विश्व व्यापी सम्राट का शासन हो। दांते मार्सिलियो राज-तन्त्र का जोरदार समर्थक है। दांते ने सम्राट की प्रभुता को ईश्वर से प्राप्त बताया और व्यवस्था की स्थापना के लिये सम्राट के ऊपर ही चर्च के प्रभुत्व को इजाजत दिया। दूसरी ओर मार्सिलियो भी चर्च का कट्टर विरोधी था और राज्य का प्रत्यक्ष समर्थक था। वह इन्होंने की छूट तथा पराजय के लिये पाप का ही उत्तरदायी समझता था। मार्सिलियो चार्ल्स अठारहवीं की अधिन में अधिक सीमित करने के पक्ष में था। पों की प्रभुता को तो वह एकदम अस्वीकार करता है। उसने अनुसार पाप चर्च का सर्वप्रभुत्व प्रदान नहीं बल्कि केवल उसका मुख्य प्रशासकीय अधिकारी है। मार्सिलियो पादरियो को किसी भी प्रकार की विचारधारा की प्रति प्रदान नहीं करता। उसने अनुसार पादरी वहिष्कार करने का निर्णय तो द मक्ता है पर उसे मनवा नहीं सकता क्योंकि उसके पास किसी तरह की विचारधारा की शक्ति नहीं है। दांते की भांति हमने भी राजा के महाराज का समर्थन किया है क्योंकि राजा उस अन्याय और अराजकता का दूर करता है जो मनुष्यों के दुःख का कारण है। वह शांति और सुरक्षा के द्वारा मानव जीवन को सुखी बनाता है। मार्सिलियो राज्य को चर्च में प्रदान नहीं करता बल्कि वह राज्य को चर्च से अलग भी मानता है।

माइबिल-पॉलिटिक्स और रोमन कानून

मध्ययुगीन दर्शन के तीन मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे—'बाइबिल, ग्रन्थों की पालि-टिक्स और रोमन कानून।' इन तीनों की ही मध्ययुगीन चर्चों में प्रमुख प्रेरणा दृष्टि के ध्यानाधीन की है।¹ पर इनकी ध्यानाधीन करने समय मध्ययुग के अन्तर्गत स्वयं भी मूल-

1. "Few theorists in any age and now in the middle ages, cared to go as far as Marsiglio in whittling down the spiritual freedom which formed the permanently important claim fostered by Christianity"
—Sabini, P 263.

2. "The medieval writers seem like students writing essays on Political theory from text books and they are confused by multiplicity and diversity of three texts they use—the bible, the Roman law and the Politics."
—Barker.

मुनेषा में पड़ कर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका। मध्ययुग के चिन्तन में वास्तविकता और अवास्तविकता दोनों के ही दर्शन होते हैं। राजनैतिक सिद्धान्त की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण कार्य मध्ययुग में नहीं हुआ लेकिन राजनैतिक विचारों के दृष्टिकोण से मध्ययुग के विचारों का महत्व है।

राज्य

लगभग सभी मध्ययुगीन विचारकों ने राज्य के मन्त्रन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। कुछ विचारकों ने राज्य को एक प्राकृतिक सम्पदा माना तो कुछ दार्शनिकों ने इसे मनुष्य के पाप का परिणाम स्वीकार किया। मन्त ग्राम्प्टाइन इस परम्परागत ईसाई विचार का स्वीकार करने हैं कि राज्य मनुष्या के पाप का परिणाम है। ईश्वर ने राज्य को मनुष्या के पाप के उपचार के रूप में स्थापित किया है। इसीलिए उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिये। चर्च ग्राम्प्टाइन ने अत्यन्त रूप से राजा का चर्च के अधीन कर दिया पर उन्होंने दोनों के बीच किसी प्रकार की स्पष्ट रेखा नहीं खींची। पर मन्त एक्वीनास इस परम्परागत विचार का स्वीकार नहीं करता कि राज्य मनुष्य के पाप का परिणाम है। वह राज्य को मनुष्य के मानादिक स्वभाव का परिणाम समझता है। वह अरस्तु की इस बात में सहमत है कि राज्य सामाजिक सम्बन्धों का एक विधेयात्मक संगठन है और उसका उद्देश्य नागरिकों के लिए शुभ जीवन की व्यवस्था करना है। मानिये जा कि राष्ट्र राज्य का समर्थक या उसका मानना या कि राज्य का जन्म मनुष्य की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। राज्य एक जैविक ईकाई है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें विभिन्न समूहों तथा वर्गों में परस्पर सहायता होता है। राज्य का उद्देश्य शुभ जीवन की प्राप्ति है।

राज्य के विरोध का अधिकार

राज्य का विरोध होना चाहिये अथवा नहीं इससे बारे में मध्यकाल के विचारकों के अनुसार राज्य का विरोध होना चाहिये और कुछ विचारकों के अनुसार राजा का विरोध नहीं होना चाहिये। मन्त ग्राम्प्टाइन का विचार था कि राज्य शांति और व्यवस्था बनाये रखता है, नागरिकों की मन्त्रि की रक्षा करता है। अतः उसकी आज्ञाओं का पालन होना चाहिये, उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिये। वेम मन्त ग्राम्प्टाइन ने राज्य का ईश्वर की उच्च शक्ति के अधीन माना है और राज्य की आज्ञा का पालन करना केवल तब उचित बताया है जहाँ तक वह ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का उल्लंघन न करे। ग्राम्प्टाइन ने लौकिक तथा प्राकृतिक दोनों में एक विभाजन की रक्षा की है। वह प्राकृतिक विषयों पर मन्त्र को कोई अधिकार नहीं देता। यदि वह प्राकृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो नागरिकों का उनके प्रति श्रद्धा का त्याग होना चाहिये। वह इस बात पर भी जोर देता है कि प्राकृतिक और धार्मिक दोनों ही शक्तियों का परस्पर सहायता से कार्य करना चाहिये। इस प्रकार एक्वीनास का मानना है कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य जीवन के मन्त्रे लक्ष्य की प्राप्ति

करता है। यदि साम्राज्य अपने लक्ष्य का अन्वेषण करता है तो उसका विरोध किया जा सकता है। वह राज्य की नीति लक्ष्य और उच्च शक्ति की प्राप्ति के विषये जल्दी मानता है। एकीकृत मनुष्य की दैतमूलक प्रवृत्ति व कारण दोनों के महत्व को स्वीकार करता है और यह मानता है कि चर्च और राज्य दोनों में कोई विरोध नहीं है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं किन्तु फिर भी वह साम्यात्मिक आवश्यकताओं को भीतर आवश्यकताओं से श्रेष्ठ मानता है और यह स्वीकार कर लेता है कि राज्य चर्च के अधीन है।

दांते चर्च का समर्थक नहीं बल्कि राज्य का समर्थक था। पर वह स्पष्ट रूप से राष्ट्र राज्य की बात नहीं करता। दांते का मानना था कि राज्य का विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि वह मानव जीवन व कल्याण व लिए कार्य करता है।¹ दांते राज्य और चर्च दोनों व क्षेत्र को अलग अलग मानता है। उनका मानना है कि भौतिक साम्राज्य में दोलन का पाप का कोई अधिकार नहीं है। वह यह भी मानता है कि राजा की शक्ति पाप से नहीं बल्कि सीधी ईश्वर से मिली है। इसलिए पाप का राजा पर कोई अधिकार नहीं है। राज्य अपने नीति विषय में चर्च से विन्यस्त स्वतन्त्र है। दांते सम्राट की चर्च से पृथक् करके अपनी सर्वोच्चता कायम करने का प्रयत्न करता है। मानिन्दो जो राष्ट्र राज्य का समर्थक था उनके अनुसार व्यक्ति को राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए। वह चर्च का राज्य से कोई पृथक् अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यह चर्च को राज्य का एक विभाग मान मानता है। उसने चर्च का राज्य के प्राचीन दुर्मति लिए किया क्योंकि उसका विचार था कि दो समान शक्तियाँ का साथ साथ रहना असम्भव है। वह स्पष्ट रूप से चर्च को राज्य व प्राचीन बना कर राज्य की सर्वोच्चता का स्वीकार करता है।

सरकार

मध्ययुगीन विचारक सरकार के बारे में कोई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त नहीं करते। वे सरकार को एक ऐजेन्सी मानते हैं। प्रारम्भिक मध्ययुग के विचारकों ने सरकार के विषय में कोई विचार ही व्यक्त नहीं किये। किन्तु उत्तर मध्ययुग के विचारक ने राजतन्त्र का ही समर्थन किया क्योंकि वे राजा को ईश्वर का अवतार मानते थे। व प्रतिनिधित्व सरकार में कोई विश्वास नहीं करते थे। वह सरकार का सर्वनिशाली नहीं मानते बल्कि उसे अर्धसोमिल मानते थे। यह विचारक का तत्परा के

1 "Dante's monarch is not a Universal despot but a Governor of a higher order, set over the princes for keeping peace. He is to have the jurisdiction in modern language of an international tribunal."

सिद्धान्त में विश्वास करते थे¹ जिनके अनुसार राजा को पूर्व शक्ति प्राप्त नहीं थी यह शक्ति पाप और राजा में विभाजित थी। मन्त थामस और मार्मिनियो ने कानूनी ढंग से सरकार को देखने का प्रयास किया है पर एक्वीनास ने सिविल कानून को लागू करने वाली शक्ति को सरकार माना है। इन सब से अधिक स्पष्ट विचार दान्ते प्रकट करता है। यह सार्वभौमिक राजतन्त्र की कल्पना करता है। वास्तव में मध्ययुग में सरकार के विषय में कोई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किये गये। अगर कुछ विचारकों ने विचार किया भी तो उन्होंने राजतन्त्र का समर्थन किया और जनतन्त्र का विरोध किया।

सम्पत्ति

सम्पत्ति के विषय में भी मध्यकाल के विचारकों ने कोई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किये। मन्त थामस्टाइन ने व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार किया क्योंकि सम्पत्ति एक सुखी जीवन के लिये प्रति आवश्यक है। पर मन्त थामस्टाइन ने सम्पत्ति का एक सीमित अधिकार दिया है। मन्त एक्वीनास ने भी सुखी लौकिक जीवन का आधार धार्मिक माना है। एक्वीनास का मानना है कि लौकिक जीवन को सुखी बनाने के लिए राज्य धार्मिक धर्म में प्रवेश करता है। निर्धनो की उचित देखभाल करना राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार मन्त एक्वीनास व्यक्तिगत सम्पत्ति पर जोर न देकर सम्पत्ति को राज्य के अधीन करने का समर्थक है। मार्मिनियो ने सम्पत्ति के विषय में कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किये। पर उनके विचारों से प्रकट होता है कि वह सम्पत्ति को लोगो के चरित्र को विगड़ने का कारण समझता था। इस कारण वह व्यक्ति का सीमित सम्पत्ति का अधिकार भी नहीं देता।

कानून

प्रारम्भिक मध्ययुग के विचारका न कानून के विषय में भी अपने कोई विचार व्यक्त नहीं किये पर उत्तर मध्ययुग के विचारका ने विशेष रूप से मन्त एक्वीनास और थुडोर मोमा तक मार्मिनियो ने कानून के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मार्मिनियो कानून के विषय में एक्वीनास से भिन्न विचार प्रकट करता है। उसके अनुसार दैविक कानून ईश्वर के आदेश हैं। वहीं यह निश्चित करने हैं कि परलोक में सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या कार्य करने चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए। इसके विपरीत मानवीय कानून मनुष्य नागरिक समूह का आदेश है जिसे प्रत्यक्ष रूप में वे लोग बनाते हैं जिन्हें कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है। इस प्रकार दोनों कानूनों के स्रोत अलग अलग हैं। दाना में केवल इतनी ही साम्यता है कि दोनों का उल्लंघन करने पर दण्ड आगता पड़ता है। एक्वीनास जहां कानून का मूल रूप में तर्क और बुद्धि का आदेश समझता है वहां मार्मिनियो के लिए वह मानव

1. इस सिद्धान्त की मान्यता थी कि "Render unto Caesar that is Caesar's and render unto Peter that is Peters"

घोर दैविक इच्छा का अभिव्यञ्जना है। मामिलिया कानून की विवशकारी शक्ति पर जार दता है। कानून का उसका अनुसार दण्ड का भय से लागू किया जाता है घोर जिनको कानून का भय से लागू नहीं किया जाता वह कानून ही नहीं माने।

कन्सोलियर ग्रान्दोलन और मध्ययुग

15वीं शताब्दी का दार्शनिक न मध्यकालीन विचारधारा को एक नया माह दिया। इसी समय चर्च का सुधारन का नये कन्सोलियर ग्रान्दोलन हुआ। अब पोप प्रकृत ही धार्मिक शक्ति का स्वामी नहीं समझा जाता था। अब सम्पूर्ण शक्ति का निवास स्थान साधारण परिषद् में समझा जाना लगा था। इस माध्यम परिषद् में पोप स्वयं भी सम्मिलित था पर आगे चलकर पोप 23वें का धर्म विमुक्त हो जान पर परिषद् ने यह घोषणा की कि प्रभुता पोप सहित सम्पूर्ण परिषद् में नहीं बल्कि बसल उनका सदस्या में है। आवश्यकता पड़ने पर पोप की प्रतीक्षा नये बिना राजा उसे बुला सकता है। इस विचार का जॉन गार्सन ने विषय समर्पण किया। यद्यपि यह कन्सोलियर ग्रान्दोलन, जो धर्म में सुधार लाने का निष्कर्ष का विरुद्ध हुआ था, सफल नहीं हो सका किन्तु फिर भी इस चर्च के विरुद्ध प्रतिश्रिया का दो परिणाम निकल— पहला चर्च का जनतन्त्रीकरण किया गया मयाव पोप जनता द्वारा चुना जान लगा। दूसरा यह कि चर्च का जनतन्त्रीकरण होने से राजा की शक्ति बढ़ने लगी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि मध्यकाल की साधुभौमिक समाज की धारणा का नाश हुआ गया। 16 वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्या का उदय हुआ। राष्ट्र राज्या का उदय का साथ-साथ धर्म सुधार ग्रान्दोलन भी आये। धर्म सुधार ग्रान्दोलन न मध्ययुगीन विचार का पूरी तरह से समाप्त कर दिया घोर राष्ट्र राज्या तथा राष्ट्र चर्च का विचार का हट किया। 16 वीं शताब्दी ने मध्यकालीन विचारका के विचार का पूरी तरह से समाप्त कर देने का माधुनिक रूप प्रदान किया।

BIBLIOGRAPHY

- (1) SABINE • A History of Political Theory
- (2) MACLWAIN *Growth of Political Thought in the West*
- (3) GIERKIE AND MAITLAND *Political Ideas of the Middle Ages*
- (4) HEARNshaw *Social and Political Ideas of Great Medieval Thinkers.*

धर्मसुधार आन्दोलन और आधुनिक राजदर्शन (REFORMATION AND MODERN POLITICAL THOUGHT)

उर्मिला गुप्ता

उम महान् बौद्धिक उथल-पुथल ने, आ कि रैनसा क नाम से विख्यात है और जिसका फल सैकियावनी या, मध्यकाल का जीवन क प्रायः समस्त क्षेत्रों में समाप्त कर दिया। 16वीं शताब्दी के आरम्भ में धार्मिक, राजनैतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रों में नवीन क्षत्तियां कार्य करने लगीं या और नवीन पद्धतियां प्रयोग की जा रही थी परन्तु रोमन चर्च एक ऐसी सस्या थी जिस पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मध्यकालीन यूरोप का आधुनिकरण तब तक पूर्ण नहीं हो सकता था जब तक कि रोमन चर्च मध्यकालीन था। "शामन में, मिडान्ता में तथा जीवन में यह श्रव भी सबसे अधिक जोर उही परम्पराओं पर रखा था, जिन्हें कि प्रारम्भिक ईसा-इसत के आधार पर मध्यकाल का विगष स्थितियां न बनाया था और वह अपरिवर्तित के लिए ही बन्दिद था।" रोमन चर्च में परिवर्तन लाकर सम्पूर्ण यूरोप के ईसाई समाज मिडान्त का चुनौती देना और पोप की सर्वोपरि प्रधानता को नष्ट करना रिफार्मेशन का एक महान् कार्य था।

क्रान्ति अथवा प्रक्रिया

सुधार आन्दोलन किसी एक विषय तक सीमित नहीं था। इसने धाराप की सम्पूर्ण सभ्यता को प्रभावित किया पर यही भी खिासा की तरह प्रदन है कि क्या इसका प्रभाव ऐसा था कि इसे स्वयं में एक क्रांति माना जाए या निरन्तर प्रक्रिया का एक भाग। इसमें विषय में विचारका में मतभेद है। कुछ रिफार्मेशन को एक क्रांति मानते हैं और कुछ एक प्रक्रिया।¹

एन्ग और वाटन इन दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और शाना ही अपने अपने दृष्टिकोणों में लगी हैं। एन्ग का तर्क महा है जब तक वह यह कहता है कि रिफार्मेशन केवल चर्च की बुराईया के प्रति विद्रोह ही नहीं था बल्कि इसमें धर्म का नया दर्शन दिया। जहाँ तक बुराईया के विद्रोह का सम्बन्ध है उसका आरम्भ पल ही हो चुका था, पर ईसाई धर्म दर्शन पर पुनर्विचार नहीं हुआ था। वह रिफार्मेशन

1. G R Elton के अनुसार धर्म के क्षेत्र में यह एक क्रांति थी किन्तु धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रक्रिया की निरन्तरता। Kohler के अनुसार धर्म के क्षेत्र में भी यह एक प्रक्रिया ही थी।

आप सर्वप्रथम हुआ ईश्वर का सिद्धांत मानव को आवश्यकताओं के मापीन हो गया था पर लुथर ने इसे मित्र किया। उसने कहा कि ईश्वर विश्व धर्म का केन्द्र है। यहीं से मानव आवश्यकताएं ईश्वर की कल्पना के चारों ओर घूमने लगती हैं। इन्टन के अनुसार रिकार्मेशन के बाद एवं आन्तरिक पक्ष से पहले का सम्बन्ध चर्च की बुराईया से था जिसने विद्वद् विद्रोह किया गया और यह मध्ययुग में ही शुरू हो गई थी। आन्तरिक पक्ष में सर्वप्रथम रिकार्मेशन के बाद ईसाई दर्शन पर पुनर्विचार किया गया। ईश्वर की मनुष्य की जरूरत की पूर्ति का साधन माना गया जबकि पहले व्यक्ति की आवश्यकताओं को केन्द्र माना जाता था जिसके चारों ओर ईश्वर की कल्पना घूमती थी। इस प्रकार इन्टन ने हमें धार्मिक क्षेत्र में ज्ञानि का रूप प्रदान किया।

Kobler भी अपने दृष्टिकोण में सहो है। वह बेनल रिकार्मेशन के स्थापक पदों के बारे में बताता है। उसने इस सिद्धांत पर आक्रमण किया कि रोम का पोप चर्च का सर्वोच्च अध्यक्ष होना चाहिए और चर्च का संगठन परमोपान आधार पर होना चाहिए। इसके विरोध में पहले ही आवाजें उठने लगी थी। राष्ट्रीय स्वायत्त चर्च का विचार उत्तर मध्ययुग में शुरू हो चुका था जो परमोपान संगठन के विरुद्ध था। अतः रिकार्मेशन ने उन प्रक्रिया को ही सामे बढ़ाया जो उत्तर मध्य युग में शुरू हो गई थी। अतः रिकार्मेशन के आन्तरिक पक्ष में इन्टन की विचारधारा और संस्थागत रूप में कोह्लर की विचारधारा उचित प्रतीत होती है।

धर्म सुधार की प्रकृति

आन्दोलन के रूप में हमारी कई विशेषताएं हैं। यह बेनल धार्मिक आन्दोलन न होकर हमसे कहीं अधिक था। वास्तव में यह एक मासुतिन घटना थी। इन हमारे समान मन्दिर के मामाजिह, धार्मिक व राजनीतिक पदमू हैं। कुछ आलाचकों के अनुसार रिकार्मेशन एक धार्मिक आन्दोलन के रूप में उतना महत्वपूर्ण न था, जितना राजनीतिक आन्दोलन के रूप में। अतः यह बहुरक्षीय घटना थी। इमोनिल दुन लोगो ने इसे "Age of Reformation" कहा है।

धर्म सुधार अपनी उत्पत्ति में Inter-religious था। यह सब को आन्तरिक रूप में सुधारने का प्रयत्न था। चर्च केन आरा चर्च के भीतर से सुधारने का प्रयत्न था जिसने राजाओं ने राजनीतिक उद्देश्य से बाहरी ओर से इन सुधारों में मद्दत दी।

यह बिना एक देन तक सीमित न था। बाइबल में हमका सम्बन्ध दोरों के सारे महादोष से था जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड एवं स्कॉटलैंडिया आदि। जर्मनी व इंग्लैंड की देन इन दोन में अन्य देनों में अधिक थी।

विभिन्न विचारकों ने विभिन्न देनों में रिकार्मेशन के बारे में करने करने देन में करने २ देन की फूँठभूमि में सोचा। अतः रिकार्मेशन का अर्थ एक समान विचारों का

मनुह नहीं है। मुख्यतः रिफॉर्मेशन मूल के दो भाग हैं—(1) Luther School and (2) Non-Luther School.

मुधार आन्दोलन को विकसित करने में कई तन्त्रों ने अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ऐतिहासिक तत्व के कारण रिफॉर्मेशन एक प्रक्रिया की निरन्तरता थी। Anti papal Supremacy tradition इसका मूल थी जो उत्तर मध्ययुग में शुरू हो गई थी। पोप सब चर्चों पर सर्वोच्च नहीं होना चाहिए, यहाँ हेनरी द्वितीय और नूई प्रॉफ़ व्हेरिया का समय लिया जा सकता है। इन समय पोप के विरुद्ध आन्दोलन था। राजा अपने राज्य में सर्वोच्च होना चाहिए—राजनैतिक मामलों में ही नहीं बल्कि धार्मिक मामलों में भी।

धर्म मुधार आन्दोलन में चर्च के आन्तरिक स्वभाव को मुधारने का भी प्रयत्न पाया जाता है। यह भी मध्ययुग के उत्तर भाग में कासीनियर आन्दोलन के रूप में शुरू हो गया था। यह आन्दोलन चर्च को परिपक्व की सहायता में मुधारने का आन्दोलन था जिसकी भाग थी कि पोप को सर्वोच्च सत्ता के प्रयोग की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए।

ऐतिहासिक दृष्टि में राष्ट्रवाद का तब बड़ा नैतिक तत्व था जो स्वायत्त राष्ट्रीय चर्च की मांग कर रहा था। पोप ने स्वयं विभिन्न राज्यों के राजाओं की सहायता दी थी कि वे चर्चों को अपने राज्यों में भीतरी छोर में नियंत्रण में रखें। इसमें पॉरे-पॉरे राष्ट्रीय स्वायत्त चर्च का विकास हुआ। पहले तो राजा पोप की कर्पणता में चर्च पर नियंत्रण रखता था, पर बाद वह पोप व चर्च दोनों को क्षीय करने लगा। यह इंग्लैंड में हेनरी VIII के समय में शुरू हुआ।

इतिहास के साथ-साथ राजाजीन धार्मिक व नैतिक तत्त्व भी मुधार में सहायता कर रहे थे। नापारण्य जनता का जीवन पवित्र था। लोग ईसाई धर्म के उपदेशों का सामर्थ्यानुसार पालन कर रहे थे। दूसरे ओर पोप और चर्च के अधिकारी थे जो अष्टाधरण सेवा धन की साधना के कारण धैर्य दिमाई देने थे। दोनों के बीच खाई थी जिसकी पाटने के लिये मुधार आन्दोलन का होना आवश्यक था। हम आई के प्रति चेहना तो उत्तरमध्ययुग में ही का चुकी थी। धर्म मुधार ने केवल इसे एक मॉडल आन्दोलन का स्वरूप दिया।

मुधार के लिए पहले मुख्य तन्त्राधीन प्रभावक पहलू रिनामा था। इसने मुधार के लिए बौद्धिक दृष्टिकोण बनाई। रिनामा के द्वारा ही मुधार आन्दोलन शुरू हुआ। मुधार ने सामान्य व्यक्ति को चर्च की सत्ता को चुनौती देने का अधिकार दिया। मुधार का सिद्धांत था। रिनामा के बौद्धिक सोच हृदय जिम्मे बाइबिल को उदार ध्याना में बनवा दनाई। New Testament का अनुवाद किया गया। इस अनुवाद में मुधार ने प्रेरणा

ली। यह अनुवाद सुधार की ओर प्रथम प्रयास समझा जाना है। रिनासा ने ही मानव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म में प्रजासत्तव का विचार आया।

रिनासा ने आरम्भिक पूजोपास के प्राविर्भाव की सहायता दी, इससे प्रायिक क्षेत्र में गति प्रागर्द। धर्म लोग भौतिकवादी धर्मिक हो गये थे। उन्होंने धीरे-धीरे धर्म को ध्वनिगत वस्तु माना। धर्म अब सार्वजनिक वस्तु नहीं था। चर्च तभी रह सकती था जब वह धार्मिक परिवर्तन के अनुसार अपने में सुधार करे।

नूतन का नेतृत्व भी सुधार आन्दोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुधार आन्दोलन की मार्ग दर्शन के लिए एक प्रभावशाली नेता की आवश्यकता थी। नूतन ने इस कार्य को पूर्ण किया, इसे सार्थक बनाया। उसे सुधार आन्दोलन का दिना कहा जा सकता है।

धर्म सुधार का प्रभाव

सुधार आन्दोलन एक धार्मिक आन्दोलन न होकर कहीं अधिक वास्तव में एक सांस्कृतिक घटना थी। मन. इसके समान महत्व के समाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पहलू हैं। प्रत्यक्ष यह एक बहुआयामी घटना थी।

राजनीतिक क्षेत्र में सुधार आन्दोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कुछ प्राचीन-वर्षों के अनुसार रिफॉर्मेशन एवं धार्मिक आन्दोलन के रूप में उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना राजनीतिक आन्दोलन के रूप में। आरम्भ में अपने जटिल और दृष्टिकोण में रिफॉर्मेशन विमुक्त रूप से एक धार्मिक आन्दोलन था। उसका राजनीति में कोई सम्बन्ध नहीं था। परन्तु शीघ्र ही उसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिणाम निकला। उसका सत्तान प्रभाव हुआ राज्य की शक्ति का बढ़ना और निरन्तर राजनय का पुराण में एक सामान्य सामन रूप बनाना। यद्यपि सुधार ने पाप का धर्मों गद्दी में हटाया मतलब की स्थिति में हटाया पर इनके लौकिक शक्ति या राजा को पद से नहीं हटाया। लौकिक शक्ति के सम्मान पर जोर दिया क्योंकि वे ही माना धर्मों की व राजा से नहीं लड़ सकते थे। सुधार का युग ही राष्ट्रवाद के आरम्भ का युग था।

नूतन का आन्दोलन अपने प्रकार का सर्वप्रथम आन्दोलन नहीं था। चर्च की सुधारने के प्रयत्न पहिले भी हुए थे परन्तु वह सब विफल हो गये। नूतन ने अनुभव लिया कि अपने आन्दोलन में सफल होने के लिए रोम के विरुद्ध संघर्ष में राज्य का समर्थन करना आवश्यक है। राजाओं ने इन प्रस्तावनाओं में सहरी दिनचर्या दिखाई कि पोप का अधिकार केवल रोम के चर्च की निम्नो मर्यादा तक ही सीमित रहे और ईसाई जगत के अन्य चर्चों की समीप मर्यादा पर उनका कोई अधिकार न रहे। अपने अपने राज्यों में चर्च की मर्यादा के एक बड़े भाग पर अपना हाथ रखने की सम्भावना राजा के लिए असाधारण रूप में ही आकर्षक सिद्ध हुई क्योंकि इस तरह वह अपने राज्य की अधिक मर्यादा बना सकते थे। ईसाई तथा जर्मनी के समस्त प्रोटेस्टेंट

सुधारकों के पक्ष में हो गये। इन देशों में राष्ट्रीय प्रोटेस्टेंट चर्चों की स्थापना हुई और नवीन धर्म प्रणाली का प्रधान मस्यवा नरसक कहा जा सामक दना। इन गति-विधियों का स्वामाधिक परिणाम हुआ राज्य की शक्ति का दटना।¹

धर्म सुधार और राज्य विरोध

गिफोर्मेसन ने एक दहशत दहा प्रदन यह पंथा किया कि क्या नागरिकों का अपने शासकों की प्रवहेनना करने का अधिकार है? इसके दो विभिन्न उत्तर दिये गये। एक विचार तो यह था कि नागरिकों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें चुन-बाव राज्य की माला का पालन करना चाहिए। स्वयं मूयर इसी का उपदेश देता था। मारे जनकर यही बात राजाघरा के देवी अधिकार के सिद्धान्त में विकसित हो उठी। दूसरी धारणा यह थी कि नागरिक राजा की शक्ति का विरोध कर सकत थे क्योंकि राजा अपने शक्ति जनता में प्राप्त करता था। इसलिए उचित कारणों के लिए उसमें जबाब ठनव किया जा सकता था। यह 17 वीं शताब्दी में मविदा सिद्धान्त का पूर्व-मूकक बन गया। यद्यपि स्वयं कान्तिन का जो, कि एक महान् प्रोटेस्टेंट सुधारक था, यह विचार था कि किपिबन् निर्मित राजकीय शक्ति की प्रवण करना गमत है किन्तु फ्रान्स तथा स्काटलैंड में उसके अनुयायियों ने इसके विपरीत इस सिद्धान्त की प्रति-पादित किया कि धार्मिक सुधार के हित में राज्य की प्रवण की जा सकती है। स्काट-लैण्ड के जान नाक्स ने कैथोलिक शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिक प्रतिकारों के सिद्धान्तों की प्रतिपादित किया गया।

लौकिक राज्य के शायों को विनियमित तथा नियंत्रित करने वालों काई उत्तर मन्त्रोन्मोय शक्ति न रही। इस उत्तर शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक प्राकृतिक कानून, जिसे लोग भी नहीं बदल सकता था, की धारणा की पुनर्जी-वित किया गया जिसका मध्यकाल में बहुत प्रचार था। यह प्राकृतिक कानून एक विश्व-ध्यातक आदर्श मस्यवा मानदण्ड था जिसके द्वारा मानव सम्प्रदाय विनियमित होते थे। प्राकृतिक कानून के इस मध्यकालीन विचार की आधुनिक संसार में जाने वाला स्वरुह हुकर था।

मूयर के राजनीतिक विचार

मार्शन मूयर के राजनीतिक विचारों में बहुत अधिक विरोधानाम पाया जाता है। उनके बारे में संगतिबद्ध राजनीतिक दर्शन नहीं है। जो कुछ भी राजनीतिक विचार

1. मूयर के अनुसार चर्च की शुद्ध रखने तथा उनके वैभव को कायम रखने का कार्य ईश्वर ने राजाओं को सौंपा है। उनमें प्रभाव के उत्तर राजाओं के अधिकार की भार भी मरिह दृढ़ बनाया। यह इनका जंग था जिसने कि रिफॉर्मेशन ने राज्यतन्त्र को मन्दन पहुँचाया।

हम उसकी कृतियों में मिलने हैं, उन सबकी उद्भावना उस उस बाद-विवाद में हुई जिसमें कि वह जीवनपर्यन्त उत्तम रहा। यदि हम यह मान भी लें कि उसका कोई राजनीतिक दर्शन भी था, तो वह एक वितर्कण विरोधाभास ही था।

उसकी आशयिता चिन्ता यह थी कि यदि धार्मिक अधिकारी मर्याद पादरीमण्य दुराचार की चट्टान रोकेँ।।। उसका सुधार करना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। किन्तु जब जर्मनी में कृषकों ने सामाजिक न्याय के नाम पर धर्मका के विरुद्ध विद्रोह किया तो उस समय लूथर ने शासक का पक्ष ग्रहण किया और 'कृषक मुठ' की निन्दा करने लगा। उसने सामन्तता को यह भी सलाह दी कि विद्रोह को दुःसाधनापूर्वक दशने के लिए उन्हें निर्दयतापूर्वक विद्रोहियों को हराया करनी चाहिए।

एक ओर तो लूथर इन बातों के ऊपर बल देता है कि व्यक्ति का धर्म का मानना का पालन सुव्याप करना चाहिए और सक्रिय विरोध की निन्दा करता है क्योंकि उसके विचार से ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया है कि उसे धर्म की मानना का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर वह इन बातों का मानता है कि वे राजा-गण या सम्राट के प्राणी थे, सम्राट की अवहेलना कर सकते थे यदि सम्राट अपने धर्म का दुर्व्ययोग करे। इस मतसिद्धि परामर्श का कारण यह है कि लूथर सम्राट की धर्म की कम करने के लिए और राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए विवशित था।

लूथर राजाओं को साधारणतया धर्मों पर सबसे बड़े मूर्ख और निष्ठुरतम पूर्व समझता था। ऐसे मूर्खों और मूर्खों की मानना पालन के सर्वसाधारण के प्रवर्तन कर्तव्य पर बल देना कहाँ तक संगत है? दूसरी ओर वह कहता है कि यदि कोई राजा किसी व्यक्ति से अपना धर्म छोड़ने के लिए वह मा उसे राजा की मानना का पालन करने में दुष्कार कर देना चाहिए। लूथर की विचारधारा में राज्य के प्रति भक्ति ईश्वर के प्रति मिष्टा से मीमिष्ठ है।

एक ओर लूथर ने मानव समानता के सिद्धांत का प्रचार किया और उसे धर्म-संगठन तथा पादरियों के विरोध अधिकारी तथा विमुक्तताओं के ऊपर आक्रमण का आधार बनाया तो दूसरी ओर उसका जनसाधारण में कोई विश्वास न था। उन्हें वह रोमान कर कर पुकारता था। उसने अनुसार "अन्यता के नहीं काम करने की प्रतीक्षा मुझे राजा का मान काम करना भी अच्छा लगता है।"

लूथर ने राज्य के ऊपर धर्म के अनुशासन को भंग दिया और लौकिक धर्म का मानना उन्नत अन्तर्-धर्म नियन्त्रण से मुक्त कर दिया। धर्म लौकिक धर्म का को न धर्म-वर्द्धित कर सकता है, न पदच्युत पादरीमण्य जा कि सब उस पक्ष के प्रतीक थे, सब राज्य के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले थे इसलिए लूथर उन तथा साधारण नागरिकों के कोई अन्तर न देगा था। उसने यह भी कहा कि राज्य का हस्त धर्म पर नियन्त्रण करता चाहिए। उसका सर्व यह था कि धार्मिक पुरोहि-

साही के लुप्त हो जाने पर—दृश्य चर्च के बाह्य नया भौतिक स्वरूप की विनियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी। वह जनतन्त्रवादी नहीं था और जनसाधारण में उसे कोई विश्वास न था। इस प्रकार प्रत्येक राज्य का शासक अपने क्षेत्र में ममस्त लूबरवादिया का प्रधान विषय बन गया। “आध्यात्मिक तथा लौकिक का वह अन्तर जा कि मध्यमालवादिया के लिए इतना महत्वपूर्ण था, लूबर में धु धला पड़ गया।”¹

राज्यवाद का सवेशवाहक

इस सिद्धान्त में कि पादरीगण साधारण नागरिक हैं और इसलिए राज्य के कानून तथा न्यायालय के अधीन हैं, 16वीं शताब्दी के राजतन्त्र को काफी सम्बल पहुँचाया। आधुनिक यूरोपीय विचार में लूबर उदारवाद का प्रवर्तक नहीं, बल्कि राज्यवाद का मदेशवाहक सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि लूबरवाद पुनर्जागरण की उदारवादी शक्तियाँ को अपने मानववाद तथा लाज्जन की सम्भावना में दूर से जाने वाला एक बड़ा प्रतिगामी कदम था।

कान्विन के विचार

रिफॉर्मेशन के राजनैतिक विचारों के अधिक संगतिबद्ध, अधिक क्रमबद्ध तथा अधिक गतिशील विवेचन का श्रेय जान कान्विन को है जिसे कभी-कभी रिफॉर्मेशन का सिद्धान्त-वेत्ता (Law-giver) कहा जाता है। कान्विन के अनुसार राज्य और चर्च भिन्न-भिन्न हैं और एक दूसरे से पृथक् नहीं हैं। दोनों की स्थापना ईश्वरीय कानून की पूर्ति के लिए हुई है। कान्विन ने कहा है—“लौकिक शासन का उद्देश्य है कि जब तक हम समाज में रहते हैं वह हम में ईश्वर की ग्राह्य उपामना की भावना प्रेरित करे, विगुड़ मिडान्त नया चर्च की सत्ता की रक्षा कर, हमारे जीवन का मानव समाज के अनुरूप बनाये। राजकीय न्याय के अनुसार हमारे जीवन को दास और सामान्य शक्ति कायम रखे।”¹ इस प्रकार कान्विन के अनुसार राज्य का प्रथम कार्य भक्ति तथा धर्म का परिपालन है, नाशित और व्यवस्था की रक्षा नहीं। राज्य को मूर्तिपूजा, नास्निकता तथा मन्त्रे धर्म की निन्दा का समय करना चाहिए। इसका अर्थ है मेडान्तिक् रूप से राज्य की धर्मतन्त्र बनाना।

वास्तव में जहाँ-जहाँ भी कान्विनवाद का स्वतन्त्र हाथ रहा, वहाँ-वहाँ साम्प्रदायिक राज्य स्थापित हुये जिनमें पादरीगण तथा नामन्त्री वर्गों में गठ-बन्धन हुआ और जिनमें मर्त्यसाधारण को विगुड़ अन्त में रखा गया। उनका परिणाम हुआ एक ऐसे वर्गतन्त्र की स्थापना जो कि ‘अनुदार, दमनकारी तथा प्रतिजियावादी’ था।

कान्विन के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी श्रवणा करना ईश्वर

¹ Allen—A History of Political Thought in the Sixteenth Century.

को अवज्ञा करना है। कान्तिन ने यह भी कहा है कि राजा की क्षतिधा का समय रखना छोटे २ व्यापक राजा का कर्तव्य है। यदि वे राजा की क्षतिधायी प्रवृत्तियों को न रोक सकें और उनके विरुद्ध जनता की रणायन न कर सकें तो वे कर्तव्यहीनता के दोष व भागी हैं।

कान्तिन यह भी कहता है कि सामन्तगण कोई ऐसा कार्य करना चाहें जो कि ईश्वर के आदेश के विरुद्ध हो तो जनता का उसका ऊपर उठना भी ध्यानी नहीं देना चाहिए।

जहां तक राज्य धर्मसुधार की यात्रा का पालन करने की संसार का, कान्तिन उसके पक्ष में था, किन्तु जहां २ सरकार उसकी विरोधी थी, कान्तिन उसके ऊपर आक्रमण करने लगता है। राज्य के राजसुधार के नियंत्रण को उत्साह देने के साथ स्वतंत्रता में वैधानिक और कुलीनतन्त्रीय अल्पमतों की क्षति को भग करने में समझे मध्यवर्गी के प्रयास को सम्भव पहुँचाया।

रिफॉर्मेशन और राजनीति

धार्मिक क्षेत्र में रिफॉर्मेशन का बहुत अधिक प्रभाव है। सुधार आन्दोलन मुख्यतः धर्म के उपरान्त हुई बुद्धियों को दूर करने के लिए ही हुआ था। रिफॉर्मेशन का जन्मदाता मार्टिन लूथर थे जिन्होंने इन ईसाई धर्म-ग्रन्थों की पुनर्व्याख्या तथा सुधार के रूप में आरम्भ किया था। जहां-तक कि इसका उद्देश्य धर्म के समर्थन का सुधार करना धर्म में पोष की निर्पेक्षा करने के दावे की टुकराया तथा धर्म के अधिकार के लिए एक व्यापकतर आधार को मांग करना था, इसे कान्तिनियर आन्दोलन की ही प्रत्यावृत्ति कहा जा सकता है। यदि कान्तिनियर आन्दोलन सफल हो जाता तो रिफॉर्मेशन का जन्म ही न होता। लूथर ने पहिले भी धर्म के सुधार के लिए आन्दोलन लगे थे परन्तु उनका प्रभाव सीमित था और वे सफल नहीं हुए। रिफॉर्मेशन ने धार्मिक क्षेत्र पर जो प्रभाव डाला उसके दो पहलु थे।¹

नकारात्मक और सकारात्मक

नकारात्मक रूप में यह आधुनिक धर्मनिरपेक्षता के पदसोपान व्यवस्था पर एक आक्रमण था। यहाँ सुधार के नेताओं ने एक पोष के गारे योरोप की चर्चों पर सन्नोदित होने का विरोध किया और साथ ही धर्म के समर्थन में पदसोपान का भी विरोध किया। यहाँ राष्ट्रीय स्वायत्ता धर्म का विचार पैदा हुआ।

दूसरे पोष के प्रति जो कि अन्धकार और अज्ञानता में डूबा हुआ था, आघात किया। सुधार नेताओं के अनुसार जो रोम में मरने अन्ध व्यक्ति था, जो मरने को ईसा का प्रतिनिधि कहा जाता था। अन्ध पोष ईसायित के लिए धर्मनाश था।²

1 Ibid

2 Ibid

इसके प्रतिरिक्त पोप पर ईसाइयों से एकत्र किये धन को स्वयं पर खर्च करने का भी आरोप लगाया गया ।

पोप ही अष्ट नहीं था, अन्य चर्च के पादरी भी अपने २ क्षेत्रों में उन्हीं बुराईयों में युक्त थे ।

तीसरे पोप ने ईश्वर को मानव को आश्चर्यकृतियों के प्राप्तिन कर दिया था । ईश्वर को केन्द्रीय स्थान नहीं दिया गया परन्तु मुघार आन्दोलन ने ईश्वर को केन्द्रीय स्थान दिया । अब मनुष्य की आश्चर्यकृतताएँ व व्यक्तित्व की कल्पना ईश्वर की कल्पना के चारों ओर घूमने लगी ।

नकारात्मक तत्त्व से ही नकारात्मक तत्त्व निकलता प्रतीत होता है । मुघार नेताओं ने पुरानी मान्यताओं पर ही आक्रमण नहीं किया बल्कि एक नया वातावरण भी बनाया । इसी में मुघार का स्थायी प्रभाव निहित है । मुघार रिवाज से प्रभावित था । कई मुघार नेताओं ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया और कहा कि धर्म में विभिन्न दृष्टिकोण रखना पाप नहीं है, इस तरह धर्म में प्रजातन्त्र आया । यह सकारात्मक पहलू प्राधुनिकता और उदारवाद की ओर था । इसने धर्म निरपेक्ष प्रजातान्त्रिक विचार के लिए पथ-प्रदर्शन किया ।

मुघार नेताओं ने मानवीय सत्ता के विरुद्ध मानवीय चेतना के विकास पर जोर दिया । मनुष्य बाइबिल की व्याख्या स्वयं करने लिए कर मञ्जूर था, अपने अन्त-करण के अनुसार । क्रूर के अनुसार ईसाईयों को ईश्वर व विश्व के लिए बाइबिल के अनुसार विश्वास करना चाहिए पर उन्हें अपने अन्त करण के अनुसार व्यास करना चाहिए । यहाँ पर पोप की व्याख्या करने का एकाधिकार की सीमाएँ सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष था । हर व्यक्ति को अन्त करण की स्वतन्त्रता कान्टिकारी वस्तु थी ।

क्रूर के अनुसार हर ईसाई एक पादरी है, अतः उसे धार्मिक संस्कार करने, बाइबिल की प्रार्थना करने के अनुसार व्याख्या करने व अनुसरण करने का अधिकार था । पादरियों को कोई विशेष अधिकारपूर्ण स्थिति ईसाई समाज के अन्दर्गत नहीं दी जानी चाहिए । ईसाई चर्च का पदवीज्ञानीय संगठन समाप्त हो जाना चाहिए, और हर ईसाई अपने में एक उपदेशक बन जाना चाहिए । मुघार आन्दोलन ने सामान्य व्यक्ति व ईश्वर के बीच के माध्यमों, पोप व पादरी को समाप्त करके व्यक्ति व ईश्वर में सीधा सम्बन्ध स्थापित किया । सब ईसाई ईश्वर के पान पहुँचने में समान रूप के समर्थ हैं ।

मध्ययुगीन धार्मिक शक्ति के केन्द्रीकरण की परम्परा छूट गई व शक्ति को ईसाई समिति में बाँट दिया गया । अब चर्च के प्रदग्धक स्वेच्छा के कार्य नहीं कर सकते थे । संवेधानिक दृष्टि ने उन्हें आखण्ड करना था । इस तरह संवेधानिक ढाँचा चर्च में आने से राज्य में भी आया ।

धार्मिक क्षेत्र में भी मुघार आन्दोलन का प्रभाव पड़ा है । मुघार नेताओं ने परिधि पर दृष्टि अधिक जोर दिया । हर प्रकार का कार्य अपने में महत्वपूर्ण है । स्व-

स्वतन्त्र व्यापार नीति को विकसित किया जिसने अतः में आरम्भिक पूँजीवाद का पथ प्रशस्त किया। नर्वे का धन मध्यवर्ग व राज्य के पदाधिकारियों के बीच बाँटा गया और व्यापार पर जो मध्ययुगीन प्रतिबन्ध थे वे हटा दिये गये और भ्रम पर बहुत अधिक महत्व दिया गया।

इस प्रकार धर्म सुधार प्रान्दालन आर्थिक दृष्टि में भी क्रान्तिकारी या यथार्थ उभरा आर्थिक पहलू सदैव प्रमुख था।

BIBLIOGRAPHY

- 1 ALLEN A History of Political Thought in the 16th Century
2. FIGGS - *Studies in Political Thought from Gerson to Grotius*
- 3 HEARNshaw Social and Political Ideas of Great Thinkers of Renaissance and Reformation
- 4 CARLYLE A History of Mediaeval Political Theory in the West

टामस हाब्स के दर्शन में वैज्ञानिक भौतिकवाद

SCIENTIFIC MATERIALISM IN THE POLITICAL PHILOSOPHY OF THOMAS HOBBS

सुन्दर मायूर

राजनीतिक चिन्तन के इतिहास को मुख्यतः तीन युगों (प्राचीन, मध्य-कालीन और आधुनिक) में विभाजित किया जाता है। प्राचीन या यूनानी राजनीतिक विचारों पर नगर राज्य के स्वरूप तथा उस तर्क प्रदान भूमि का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण यूनान लिवामी तर्क (Reason) को संसार को समझने तथा उसमें मानव का स्थान निर्धारित करने की बुद्धि समझने थे। दूसरे शब्दों में उनका राजनीतिक चिन्तन तर्क और नैतिकता में घनिष्ठ रूप में मेल रहा था। मध्ययुगीन चिन्तन पर यह विश्वास छाया हुआ था कि विश्व में मानव का स्थान निर्धारित करने वाली शक्ति तब ही और मनुष्य के लौकिक हित प्राध्यात्मिक लक्ष्य के प्राचीन है। फलस्वरूप मध्य युग में सामाजिक या राजनीतिक शक्ति का धार्मिक शक्ति के प्राचीन समझा गया। शासक पर धर्म का यह अधिकार मध्यकालीन राजनीतिक चिन्तन की एक प्रमुख विशेषता थी। राजनीतिक चिन्तन के प्रति एक धर्म-निरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक युग में ही पैदा हुआ है। धर्म और राजनीति का स्पष्ट सम्बन्ध विच्छेद मैक्यावर्नी (1469-1527) ने किया। परन्तु 16वीं शताब्दी तक किसी भी विचारक ने अपने राजनीतिक परिणामों को वैज्ञानिक आधार प्रदान नहीं किया था। हाँ उस वक्त पहला राजनीतिक विचारक था जिसने राजदर्शन में निरंकुशतावाद तथा धर्म-निरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार बनाया तथा नीतिक विद्वानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिन्तन का आधार दे कर राजनीति की विज्ञान का स्वप्न दिया। यही कारण है कि उसे आधुनिक युग का प्रणेता कहा जाता है।

हाब्स के विचारों और पद्धति को उसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने काफी सीमा तक प्रभावित किया था। उसके समय में ब्रिटिश राज्यद्वीप पर जैसा प्रथम था जो कि राजाओं के दैविक अधिकार विद्वान्त का प्रतिपादक था और इसी कारण से ब्रिटिश

नमद उससे रुष्ट थी। उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम भी उसी की तरह मनुजल था। इसी बीच इंग्लैंड में क्रामवेल की प्रभुत्वता मध्यतन्त्र स्थापित हुआ पर वह भी अधिक नहीं टिक सका। ऐसी स्थिति में गृहयुद्ध भी चल रहा था। राजा और संसद के समर्थकों के बीच इस गृहयुद्ध में क्रामवेल की विजय हुई थी। इन्हो परिस्थितियाँ में अपना दर्शन निरूपित हुए हैं। न निरंकुश राजात्म्य और राज्याधिकार के प्रति समर्थन की भावना का हृदयमर्पण किया।

विज्ञान के धरण

हॉम के समय में विज्ञान जगत में एक भारी क्रांति आ रही थी। यांत्रिक विज्ञान (Mechanical Science) को बैपचर, मेनिमियो व डेकार्ट जैसे विद्वान सुप्रतिष्ठित कर चुके थे। प्रकृति का प्रयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए रॉयल सोसाइटी की स्थापना एक छोटी पहल ही है। डेकार्ट विश्वव्यापक व्यापकता की तथ्या सीवानेज और ग्यूनन कैलकुलस की सृष्टि कर चुके थे। ग्यूनन की गुरु के माथ वर्य बाद उनके ग्रन्थ प्रिन्सिपिया (Principia) ने ब्रह्मांड की एक नवीन यांत्रिक धारणा का प्रतिपादन किया था। ऐसे समय में हॉम जैसे दार्शनिक के लिये समस्त ज्ञान की यांत्रिक भौतिकवाद के सिद्धान्त पर आधारित करने का प्रयत्न करना स्वाभाविक ही नहीं बल्कि ग्राह्यपूर्ण भी था।

यूक्लिड (Euclid) की ज्यामिति और ज्योमिति का हॉम पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने उसकी पद्धति को न केवल प्राकृतिक धर्मशास्त्र की व्याख्या करने के लिए मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में भी प्रयोग करने का इरादा किया। हॉम का धर्म गणित शास्त्र की पद्धति के प्रयोग द्वारा यदि के आधार पर प्रकृति की व्याख्या करना था। दर्शन के प्रति जब तक उसकी रुचि जागृत हुई तो उसने राजनीति तथा मनोविज्ञान की सुनिश्चित भौतिक विज्ञानों में सदिष्ट करने का निश्चय किया। इस प्रकार वह माने हुए के उस महान विचार प्रवाह में पक्षर्पण करता है जिसके साथ डेकार्ट तथा गैलिलियो जैसे महान् व्यक्तियों का नाम संबद्ध है।

वैज्ञानिक जागृति और मानवतावाद

मध्ययुगीन धर्मशास्त्रों की समाप्ति के बाद 17 वां शताब्दी में वैज्ञानिक मानवतावाद विचार जगत का केन्द्र बिन्दु बना। वैज्ञानिक मानवतावाद का धर्म है एक अनुभवशास्त्र दृष्टिकोण (Empirical Outlook) जिसकी मूल मान्यताएँ दो—धर्म से प्रथम मनुष्य के सामान्य ज्ञान (Common sense) पर विश्वास, भौतिक प्रगति के लिए मानवीय बुद्धि की स्वोद्दिष्टि, सम्पत्ति की प्रगति के लिए धार्मिक प्रगति को न मानना, भौतिक प्रगति के लिए मनुष्य की प्रकृति का दास न बनना पर उसे विवेक के रूप में देवता और स्वर्ग की शक्ति में विश्वास रखना। वैज्ञानिक मानवतावाद के राजनीतिक विचारों पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े वे काफी मात्रा में हॉम में दम जा सकते हैं। सर्वप्रथम परिणाम था कि यदि मानव प्रकृति का विश्लेषण किया जाए तो

मौलिक नियमों की भाँति मानवीय व्यवहार के बारे में भी नियम बनाये जा सकते हैं। यह प्रमाण हॉब्स में स्पष्ट है। दूसरे, मनुष्य बुद्धिमान है और उसमें स्वयं के हित के लिए कार्य करने की क्षमता है। हाँअ, मनुष्य को यहाँ स्वार्थी मानता है फिर भी उसका कहना है कि मनुष्यों ने आपस में स्वयं मनमौता कर अपनी भलाई के लिए राज्य का निर्माण किया है। जोसरे, मनमौता करने की मनुष्यों में क्षमता है और वे राजा का पालन अपनी इच्छा से करते हैं। वैज्ञानिक मानववाद ने व्यक्ति को स्व-मनता देकर राजनीतिक विचार का केन्द्र बनाया था। हाँअ में यही व्यक्तिवाद काफी सीमा तक अभिव्यक्ति पाता है।

हॉब्स और डेकार्ट की वैज्ञानिक पद्धति

हॉब्स पर डेकार्ट का बहुत प्रभाव पड़ा था। वह भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग माना जाता है जिसमें हॉब्स ने लेकर भाष्य कि कुछ कोई भी विचारक प्रभावित नहीं रहा। उसकी पुस्तक "Discourse on Method" का प्रभाव राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र की विभिन्न शाखाओं पर पड़ा। अनुभववाद (Empiricism) उसके इस ग्रन्थ का केन्द्र-दिन्दु है। उसका मत था कि मौलिक विज्ञानों की भाँति सामाजिक विज्ञानों की भी एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए। उसकी वैज्ञानिक पद्धति के आधारभूत सिद्धान्त प्रकाश दे—निर्णय देने में सीधेता, पक्षपात को न माने देना, तथ्यों को देखते हुए जाने इन बड़ना दूसरी व्याख्या की आवश्यकता, किसी भी वस्तु को छोटे-छोटे भागों में बाँटकर व्याख्या में सम्पूर्ण रूप निकालना, सरलता में जटिलता की ओर बढ़ना, तथ्य एकत्रित कर फिर परीक्षण और उत्तरदाता निष्कर्ष निकालना आदि। इस पद्धतिके परिणामस्वरूप राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक नई स्पष्टता, शुद्धता, निष्पक्षता और एक ठो-सोचितावादी पहलू आया। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस पद्धति का प्रयोग में माने के प्रभाव स्वरूप हॉब्स के राजदर्शन में कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण (A priori Approach) का परित्याग हुआ। राज्य के प्रति वैदिक दृष्टिकोण और उसके मोचित्व के प्रति नैतिक दृष्टिकोण का परित्याग कर मानव को स्वार्थी बनाते हुए उसने राज्य की पूर्ण गतिमानता की प्रतिष्ठा की है।

इस प्रकार हॉब्स का मन्द्यद नवीन विचारधारा के इन पदचरणों में हुआ जिसका उद्देश्य मौलिक आधार पर विज्ञान की समदृष्टि रूप में मुनिद्विष्ट करना था। मौलिक वैज्ञानिकों की भाँति हॉब्स भी संसार को एक मौलिक पद्धति मानता है जिसमें समस्त घटनाएँ परमाणुओं की गतिमानता के ही विभिन्न रूप हैं। उसकी यह पद्धति वैज्ञानिक भाँतिवाद के रूप में विकसित हुई है।

प्राकृतिक विचार संरचना और मानव व्यवहार

हॉब्स के राजनीतिक विज्ञान में राजदण्डात्मक निरंकुशता का समर्थन कोई

विशेष महत्व की बात नहीं है। उसके विस्तार का मृत्यु न प्रेरणा प्रदत्त हो थी लेकिन उसके विस्तार के महत्व का कारण मृत्यु नहीं है।¹

हॉम की परन्तु उसके निश्चयों का परिणाम के विचार में भी नहीं की जानी चाहिये। वैज्ञानिक पद्धति के बारे में उसके विचार अपने समय के विचार होने हुए भी काफी पुराने पद चुनने पर उसके पास राजनीति विज्ञान जैसी एक निश्चित वस्तु थी और प्राकृतिक विचार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण चीजों का एक प्रश्न था जिस पर समाधारण स्पष्टता के साथ विचार किया गया है। इस कारण उसने उस विचारों की भी लाभ पहुँचाया जिन्होंने उसका प्रतिवाद करने की कोशिश की। इस स्पष्टता और ऐसी व कारण ही है कि यह चीजों भाषा जनता का सबसे बड़ा राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है।

राजनीति का गैलिलियो हॉम

वास्तव में हॉम अपने वैज्ञानिक विचारों का आधार पर एक समस्त दर्शन का निर्माण करना चाहता था। उसका राजनीतिक दर्शन उसका इस समय दर्शन का एक प्रश्न मात्र है। हॉम का यही समय दर्शन भौतिकवाद है। यद्यपि हॉम ने यहाँ और भौतिक विज्ञान का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया था पर उसने उस साध्य का प्रत्यक्ष समझ लिया था जिसकी ओर प्राकृतिक विज्ञान बढ़ रहा था। गैलिलियो का मीनि हॉम ने "पुराने विषय में मैं एक नये विज्ञान का जन्म दिया। यह नया विज्ञान गति का था जिसके अनुसार भौतिक गति का पूर्ण रूप से एक मात्रक व्यवस्था है। हॉम ने इसी विचारों को अपने दर्शन का केन्द्र-बिन्दु बनाया।" हॉम का विचार था कि मूल में प्रत्यक्ष घटनाएँ एक गति के रूप में होती हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत के घटने के घटित होती हैं। इन घटने के मूल में भी कुछ गतियाँ ही रहती हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं की समझने के लिए इन मूल गतियों का समझना आवश्यक है। हॉम के विचार में प्राकृतिक ध्यान के समझने का सन्तोषजनक उपाय यही है। प्रत्यक्ष घटना के मूल में पिछा की सरलतम गति रहती है जो बाद में जटिलतर होती जाती है। इस प्रकार उसने दर्शन के तीन भाग माने हैं—पहला भाग, पिछा में सम्बन्ध एका है और उसमें व्यापकता तथा यादृच्छिकता का सम्बन्ध होता है। दूसरा भाग, मानव प्राणियों के शरीर का मनोविज्ञान में सम्बन्ध रहता है। तीसरा भाग जो, सबसे अधिक जटिल होता है, समाज या राज्य के नाम से प्रख्यात इतिहास पिछा में सम्बन्ध रहता है।

1. मेकडन के अनुसार, "वास्तव में हॉम प्रथम आधुनिक दार्शनिक या जिसने राजनीतिक विचारों का आधुनिक विचारधारा के साथ पूरा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण करते समय प्रकृति के समस्त तथ्यों पर जिसमें मानव व्यवहार के व्यक्तियों के सामाजिक दाना का शामिल था, विचार किया था। इस प्रकार की परियोजना ने उसके विचारों का सामयिक और विशादत्त महत्त्व की ओरों से बढ़ा दिया।"

हॉन के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्योमिति और यांत्रिकी है ।

ज्योमिति प्रणाली और मनोविज्ञान

हॉन के दर्शन का उद्देश्य यह था कि मनोविज्ञान तथा राजनीति को विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानों के घटक पर प्रतिष्ठित किया जाये । उनमें मनोविज्ञान तथा राजनीति में इसी पद्धति का प्रयोग किया है । 17वीं शताब्दी के सम्पूर्ण विज्ञान पर ज्योमिति का छाड़ छाया हुआ था । हाय्ज भी इसका अपवाद नहीं था । उसके विचार में श्रेष्ठ पद्धति वह थी जिसमें वह अपने विम्वन को दूसरे विषयों में भी ले जा सके । ज्योमिति के क्षेत्र में यह बात विशेष रूप से सत्य थी । इस दृष्टि में हाय्ज के विचार प्रथम और डेकार्ट के बहुत निकट हैं । ज्यामिति, सर्वप्रथम सरलतम वस्तुओं की होती है और जब वह आगे चल कर अतिरिक्त समस्याओं में उन्नत होती है तब उन्हीं चीजों का प्रयोग करती है जिन्हें वह पहले प्रमाणित कर चुकी होती है । इस प्रकार ज्योमिति का आधार बड़ा मजबूत होता है । किसी वस्तु को इसमें स्वयं स्वीकृत नहीं माना जाता । एक वस्तु को प्रमाणित करने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है । इस प्रकार ज्यामिति में गलतियों की कोई सम्भावना नहीं रह जाती । हाय्ज ने भी अपने दर्शन का इसी प्रकार निर्माण किया है । उसका दर्शन परिमित के समान है । शासन बना मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करता है । सामाजिक व्यवहार मानव व्यवहार का वह पक्ष है जिसमें मनुष्य एक दूसरे से व्यवहार करने हैं । अतः राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान पर आधारित है और उसकी प्रक्रिया विधि निगमनात्मक (Inductive) है । हाय्ज का नदय यह प्रकट करना नहीं था कि शासन वास्तव में क्या होता है । उसका नदय तो यह था कि शासन को कैसा होना चाहिए जिससे कि वह उन प्रणालियों पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण कर सके जिनकी अनिप्रेरणा मानव मन की भाँति ही होती है ।

मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र के घटक पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है या नहीं, यह एक निम्न प्रश्न है, लेकिन हाय्ज ने गति के नियमों से संवेदन भावनाओं और मानवीय व्यवहारों को पहचानने की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को है । उसने सामान्य रूप में मानवीय व्यवहार के लिए एक निश्चित निकाय और यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि विभिन्न परिस्थितियों में यह निश्चित किन्तु प्रकार क्रियाविधित होता है । इन पद्धति के द्वारा वह मनोविज्ञान में राजनीति में प्रवेशता है ।

वैज्ञानिक नैतिकवाद

वैज्ञानिक नैतिकवाद का शाब्दिक अर्थ दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है । वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या । कार्य-कारण सम्बन्ध (Cause and Effect Relationship), व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति—हाय्ज ने इन सब मद पाये हैं । वह दूसरी प्राधान्य पर अपने राजदर्शन का निर्माण करता है जैसे वह सर्वप्रथम मानव स्वभाव और उसके चरित्र का अध्ययन करता है । उसका मान्य है, इच्छा, विचार का विवेक्षण

करता है और तभी वह इस परिणाम पर आता है कि हम प्रकार के प्राणी के माय व्यवहार करने तथा उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को बना होना चाहिए। वह समझीते द्वारा राज्य की उत्पत्ति बतलाता है पर इसके पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी करता है जिसके पश्चात् नागरिक समाज का निर्माण आवश्यक हुआ था। इस प्रकार हॉम, व्यवस्थित और क्रमागत साधारण पर सर्वप्रथम मानव स्वभाव का विश्लेषण, फिर प्राकृतिक कानून, अन्तर्धान प्राकृतिक अवस्था और अन्त में समझीते द्वारा राज्य का निर्माण करता है। कारण एक प्रभाव उनके सम्पूर्ण दर्शन में दबे जा सकते हैं। वह राज्य से आरम्भ करके उस निमायक सत्ता की पुष्टि कर उसके स्वल्प की व्याख्या कर सकता था लेकिन ऐसा न करके वह राज्य के लिए एक सारा व्यक्तित्व मानव प्राणियों से अपना दर्शन आरम्भ करके बनाना है कि किस प्रकार मानव स्वभाव मनुष्य के लिए राज्य की सृष्टि आवश्यक बना देता है और उसका स्वल्प भी क्या होना चाहिए।

भौतिकवाद शब्द का अर्थ है कि धार्मिक सम्प्रेषित्व, नैतिकता और ईश्वर विश्वास, इन सब में पुष्टि वास्तविकता वस्तु जगत है। वह वातावरण में विश्वास करता है और उनके दर्शन में व्यक्ति की वातावरण से अधिक महत्व देता है। भौतिक-वादिता के अनुसार दत्त हॉम इन अर्थों में पूर्णतया भौतिकवादी है। वह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसने मनोविज्ञान के कारण ही समझीते और क्षतिशाली राजतन्त्र की स्थापना होती है। हॉम का विश्वास था कि संगठन में पदार्थ के प्रतिरिक्त और कुछ भी माय नहीं है और जो कुछ 'प्रकृति अथवा पदार्थ' नहीं है वह विश्व का सग नहीं है। मैकडन के अनुसार, "हॉम पूर्णतः भौतिकवादी था और उनके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल एक काल्पनिक वस्तु मात्र थी। वह यह नहीं कहता कि अनुभूति नहीं होती या आध्यात्मिक माय नहीं होते। लेकिन उनका स्पष्ट मत है कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।"¹

अतः हॉम की सम्पूर्ण प्रणाली समाज के तीन भाग-प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य, तथा राज्य की व्याख्या, भौतिक सिद्धान्त व साधारण पर हुई है। वह भौतिक वातावरण की बहुत महत्व देता है। उनके अनुसार यही मानव मनोविज्ञान का साधारण व आरम्भ बिन्दु है। वैज्ञानिक भौतिकवाद से वह यह सिद्ध करता है कि वातावरण मानव समावृत्तियों का निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। यहाँ यह माइकेल्स का पद-प्रदर्शन है। वास्तव वातावरण व प्रभाव से ही मानव की सामाजिक पारस्परिक व्यवस्था प्रभावित होती है और फिर उसमें भावना, इच्छा, प्रेम तथा पृथक् पारि का जन्म होता है।

1. हॉम का विचार था कि, "समस्त वस्तुओं में विश्वास करना एक ऐसी गलती है जिसे हमने अस्तित्व से ग्रहण किया है और जिसका प्रकार पर्यावरण में दबे जाने मात्र के लिए करने पाये हैं।"

भौतिकवाद तथा प्राकृतिक कानून

मेदाइन ने हमके लिए "भौतिकवाद तथा प्राकृतिक विधि" शब्द का प्रयोग भी किया है। भौतिकवाद हॉम द्वारा दिये गए प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त का मूल है। वह प्राकृतिक कानून का यथवादी दृष्टिकोण देता है जो प्राकृतिक कानून को दैविक या अति भौतिक रूप में धुँव है और मनुष्य की व्याख्या और समझ में पर की वस्तु नहीं है। "यद्यपि यह प्रक्रिया विधि वैसी ही थी जिसे द्वारा आधुनिक ने न्यायशास्त्र का प्राधुनिक रूप दिया था, लेकिन हाथ के परिणाम प्रोग्राम में भिन्न थे। आधुनिक ने प्राकृतिक विधि को धर्मशास्त्र के दर्शन में प्रवेश किया था पर उसने प्रकृति को यात्रिक रूप देने की कभी कल्पना तक नहीं की थी। हॉम के दर्शन में न्याय के किसी आवश्यक नियम को मान्यता नहीं दी। उसके विचार प्रकृति और मानव प्रकृति के कार्य कारण का व्यापार मात्र थे। आगे जा कर स्पिनोसा ने यह प्रस्ताव किया कि वह नीतिशास्त्र तथा धर्म को गणितीय प्राकृतिक विज्ञान के अनुकूल बना दे।" हॉम के अनुसार प्राकृतिक कानून, विधि और परिणाम की मरुटित व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। इस समार की गति की प्रक्रिया जिन कारणों से परिणामों में भिन्न रहती है वही प्राकृतिक कानून है।

मानव स्वभाव तथा मानव मनोविज्ञान

मानव स्वभाव व मानव मनोविज्ञान के विषय में हॉम के विचार उनके समस्त राजनीतिक दर्शन की आधार रचना हैं। वह समार का एक घटक के रूप में और मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन और विश्लेषण करता है। मानव स्वभाव तथा मानव मनोविज्ञान का यह विश्लेषण भी हॉम वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर ही करता है। उसने अनुसार मनुष्य उत्कृष्ट शरीर है, एक ऐसा यन्त्र है जो कि पीछों और पशुओं के महान् गतिमान प्रणुषा का सम्मिश्रण है, जिसे मृत्यु, पर्यन्त क्रियाशील रहना है। मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे प्रकृति कहता है, जिसे वह प्राप्त करना चाहता है उसे वह कुछ करता है। हॉम ने मनुष्य की अनेक भावनाओं की एक अधिकारपूर्ण विवेचना करता है और अन्त में उन्हें दो भौतिक तथा प्रारम्भिक भावनाओं—इच्छा व अनिच्छा तक सीमित कर देता है। इच्छा वह भावना है जो किसी वस्तु वस्तु द्वारा चरित गति में शरीर में वह जो प्राण प्रक्रियाओं का उद्वेग बनाती है और तीव्र करती है। इसके विपरीत अनिच्छा उद्भावना है जो इन प्रक्रियाओं का शून्य करती है। इच्छा एका वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास है जबकि अनिच्छा उसने टूटकारा पाने का प्रयत्न। प्रिय वस्तु की प्राप्ति में हर्ष होता है और उसके का जाने पर दुःख होता है। इसी तरह हॉम वैभव, ईर्ष्या, दया, नफ़रत आदि भावनाओं का आधार भी इच्छा दो मूल प्रवृत्तियाँ—इच्छा और अनिच्छा को मानता है। उसका समस्त भावनाओं का केन्द्र मनुष्य का निरन्तर चलना है। ये मनुष्य के प्रहंकार और स्वायत्तता के विभिन्न रूप हैं। हॉमकी धारणा थी कि मनुष्य पूर्ण रूप में स्वार्थी है। समस्त मानव व्यवहार को प्रत्यक्ष पर आधारित करने के इस प्रयत्न ने ही

हॉर्मोन की प्रणाली को एक निश्चित वैज्ञानिक रूप दिया है जो उसे मैकगवली ने थोड़ा-बदल बनाया है।

प्राकृतिक श्रवस्या श्चौर अनबन्ध

मानव प्रकृति के विभिन्न के स्वाभाविक परिणामस्वरूप हॉयम प्राकृतिक व्यवस्था, सामाजिक समझौता और नागरिक समाज पर माना है। हॉयम के अनुसार प्रकृति की व्यवस्था पूर्व सामाजिक और पूर्ण राजनीति नहीं थी। इसमें हर व्यक्ति का सब व्यक्तियों के विरुद्ध संघर्ष था, मनुष्य किसी प्रकार की भी सम्यक्ता में डूब था और साथ ही सही और गलत के ज्ञान में भी परे था। ऐसी स्थिति में मनुष्य सम्य और गान्धिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा से (हॉयम के अनुसार मनुष्य में समझ बुद्धियों के साथ-साथ विवेक का तत्त्व भी है) आपस में समझौता करने हैं जिससे एक संग्रभु का जन्म होता है और वह पूर्ण अस्तित्ववादी है, मृत्यु देव (Mortal God) है। इसे सब व्यक्ति अपने को समित करने का अधिकार सौंप देने हैं, माना प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहा हो, कि 'मैं अपना स्वशासन का अधिकार इस व्यक्ति प्रयत्न व्यक्ति समूह को सौंपता हूँ बसते तुम भी इसी प्रकार अपने अधिकार सौंप दो'। इस प्रकार हॉयम के अनुसार समझौते द्वारा नागरिक समाज की स्थापना होती है। गान्धि व्यवस्था रखना और मनुष्य के अस्तित्व की अधिक अच्छी तरह रक्षा करना इस संग्रभु का उद्देश्य है। यद्यपि यह पूर्ण राजतन्त्र है और संग्रभु इसने किसी प्रकार में बाध्य नहीं है, परन्तु सरकारों की प्राकृतिक व्यवस्था का एकमात्र सही विचार है।

उपरोक्त वर्णन में स्पष्ट है कि जिस क्षा ने हॉम की महान् राजनीतिक विचार-रचनाया वह उनका निरंकुशवाद का समर्थन नहीं है, वह तो उनके प्रभावक राजनीति विचार का एक ऊपरी भाग है, न ही उनके राजनीति धोर धर्म का पूर्ण विस्मृत है। यह तो मैकापावनी और बोदा उनके पहले कर चुके थे। हॉम ने अनुभव किया कि साम्राज्य ने वैयक्त अधिकार के आधार पर निरंकुश राजतन्त्र को उचित ठहरेता ऐसा ही है जैसा कि दो पर मन्त्र बनाना। उनके उनका आधार मानव प्रकृति के सम्बन्ध में उन मानव स्वभाव सम्बन्धी सिद्धांत पर रखा जिसे वह निश्चिन्त समझता था। उनके धर्म की राज्य की प्राप्तिता में रहने का एक वैज्ञानिक तथा सर्वसम्मत आधार प्रस्तुत किया। मैकापावनी की भाँति उनके सजायी और प्रतिस्पर्धा सम्बन्ध मानव स्वभाव को पूर्णतः धर्म-निराज राजनीति दक्षिण का आधार बनाया और मानव स्वभाव की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम की।

वैजायिज भौजिजवाद की छट्टिने हॉन-न तबमाँटि-दिवातों ने शहीदा
में स्थान विवादास्पद है। जब विगमपन प्रकाशित हुई तब सभी ने उनके
नायिकावाद एवं वैजायिज भौजिजवाद की घोर निन्दा की थी। हेनरी मोर
तदा कदरव जेमे सामंतिजो, कंबरवेंड जेमे धर्मशास्त्रियो तथा रिमर जेमे राय-

नैतिक दार्शनिकों ने अपने नास्तिकवाद तथा भौतिकवाद के सिद्धांतों की तीव्र प्रशंसा की थी।

यद्यपि हॉप्स ने अपने दर्शन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया परन्तु इस दृष्टि में भी उसका लिखाया प्रभावहीन ग्रन्थ रहा। सत्रहवीं शताब्दी में वैज्ञानिक पद्धति को ज्योमिति की पद्धति या निगमन पद्धति (Deductive) के अनुसरण समझा जाता था। हॉप्स के बाद यह निश्चित हो गया कि ज्योमितिक के नमूने पर एक राजनैतिक विज्ञान या मानवविज्ञान के निर्माण का प्रयास केवल एक भ्रम है। राजनैतिक कल्प-विकल्प के क्षेत्र में इस पद्धति का अनुकरण निम्नोक्त के दृष्टिकोण और किसी विचारक ने नहीं किया था। परन्तु हॉप्स की पद्धति को हमें इस कमीटी पर नहीं कमना चाहिए कि उसके परिणाम कहा तक सही या गलत निकले या वह मानव तथा राजनैतिक विज्ञान के बीच सम्पर्क स्थापन में सफल रहा अथवा विफल। उसकी विशेषता यह है कि उसका विस्तृत समर्थन तथा समन्वित है और उसने संगतिबद्ध युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं और अपने निष्कर्ष पर वह दृढ़ता से कायम है। यदि हम उसके आरम्भ बिन्दु की स्वीकार करें तो उसके अन्तिम परिणाम को टुकड़ाना असंभव होगा।

अनुभववाद

मेदाइन का कहना है कि "यह पद्धति मूलतः निगमनारम्भ (Deductive) की।" इसमें अनुभव प्रमाणता का अभाव है, और वास्तविकता का छुट नहीं पा पाया है। "हॉप्स का राजनैतिक दर्शन अत्यधिक राजनैतिक निरीक्षण पर आधारित नहीं है। मनुष्य के नागरिक जीवन में प्रेरण ठीक-ठीक जीवन-जीवन रहते हैं इससे हॉप्स पूरी तरह परिचित नहीं था। उसका मनोविज्ञान भी निरीक्षण पर आधारित नहीं है। वह इस बात का विवरण नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य वास्तव में क्या है, प्रष्टुम वह इस बात का विवरण था कि सामान्य सिद्धांतों की ध्यान में रखते हुये मनुष्य को कैसा होना चाहिये।" आज अनुभववाद (Pragmatism) वैज्ञानिक पद्धति का महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसका तात्पर्य है जीवन के निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर विश्लेषणात्मक ढंग से निष्कर्ष निकालना। परन्तु हॉप्स अपने अन्तिम द्वारा पूर्व निर्धारित उपस्थानाओं (Hypothesis) में आरम्भ कर निष्कर्ष निकालता है, जीवन की व्यावहारिकताओं में नहीं। वे स्वयं एक मित्र मध्य में आरम्भ होती है और उन में परिणाम निकाले जाते हैं। परन्तु इस मान्यता के बावजूद भी यह स्वगोचर है कि सत्रहवीं शताब्दी की वैज्ञानिक पद्धति में जो उन समय विकसित हो रही थी, अनुभववाद पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना आज दिया जाता है। इसके विपरीत वैज्ञानिक पद्धति गणितीय और भौतिक विज्ञानों की भाँति अधिक थी। अतः यहाँ हॉप्स की यह युक्ति ठीक होगी कि वह वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत में अपने समय की सीमाओं में आगे नहीं बढ़ सका। इस सम्बन्ध में वह सत्रहवीं शताब्दी का शिरोधार्य है।

सेबाइन का मत

सेबाइन ने एक मध्य मालोचना करते हुए लिखा है कि हॉब्स स्वयं अपनी की व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं रहा। उसने अपनी पद्धति कुछ ऐसी मायमताओं से धारम्भ की जो तर्क की दृष्टि से ठीक सही थी, किन्तु व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से स्वयं में गलत थी। वह गणितीय पद्धति में इतना अधिक विश्वास करता है कि गणितीय ज्ञान और उपयोगिता पद्धति तथा अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान के सम्बन्ध में भ्रम में पड़ जाता है और कल्पस्वरूप यह मान बैठता है कि जिन निष्कर्षों पर वह अपने गणितीय ज्ञान और उपयोगिता पद्धति से पहुँचा है वे व्यावहारिक जीवन में भी सही होंगे। दूसरे हॉब्स मानव जगत और भौतिक जगत के अन्तर को भी भुला बैठता है और दोनों में एक ही पद्धति से व्यवहार करने का असफल प्रयत्न करता है। उसकी धारणा है कि जिस प्रकार ज्यामिति की सहायता से हम जटिल हैं जटिल वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं वैसे ही मानव के जटिल व्यवहार के सम्बन्ध में भी किया जा सकता है। हॉब्स उपयोगिता की सहायता से केवल मानव मनोविज्ञान का अध्ययन ही नहीं कर रहा था बल्कि उसका विचार था कि भौतिक विज्ञानों के नियमों (Laws of Physics) की भाँति 'मानवीय व्यवहार के नियम' (Laws of Human Behaviour) भी बनाये जा सकते हैं जबकि मानव व्यवहार के बारे में ऐसा करना निषेध ही बँधित है।

"सेबाइन ने हॉब्स के दर्शन पर केवल उपयोगितावादी होने का आरोप लगाया है।" हॉब्स के लिये विज्ञान का यही अभिप्राय था जिससे-सबसे वस्तुओं के मापन पर जटिल वस्तुओं का निर्माण किया जाय। इसका सर्वप्रथम उदाहरण उपयोगिता है। इस दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि हॉब्स ने शासन को पूरी तरह से लौकिक और उपयोगितावादी माना। उसके लिए शासन का महत्व केवल हम मान पर निर्भर करना है कि वह क्या कार्य करता है। चूंकि शासन का विषय असाध्य है अतः हममें कोई संदेह नहीं कि एक उपयोगितावादी को क्या चुनना चाहिए। इस चुनाव में याचना का कोई स्थान नहीं है। शासन के लाभ बिन्दुल ठोस हैं और ये व्यक्तिगत को ठोस तरीके से ही प्राप्त होने चाहिये—शांति, सुविधा, सुरक्षा और सम्पत्ति के रूप में। यही एकमात्र ऐसा आधार है जिस पर शासन या उसका मौलिक निर्भर है। सार्वजनिक इच्छा की भाँति ही सामान्य या सार्वजनिक हित केवल कल्पना की वस्तु है। केवल व्यक्ति ही अपने जीवन साधनों के लिये रहता और संरक्षण का उपयोग करना चाहता है।" इस प्रकार हॉब्स के अनु-सार राज्य के अस्तित्व अनुभव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तथा व्यक्ति की सुरक्षा की कल्पना के लिये है। उसका एकमात्र मौलिक अर्थ उपयोगिता है। उसके भौतिक भीतरों का स्रोत शांति की अनुभूति है। हॉब्स कोई अन्तर्द्वन्द्व नहीं था और उसके लिये जनता की सामान्य इच्छा (General Will) जैसी किसी चीज का अस्तित्व भी नहीं है। अस्तित्व केवल व्यक्तियों का है उनकी रक्षा करना उनका अपना कर्तव्य है। उनके निजी हितों का ध्यान ही सामाजिक हित है। हॉब्स के विचारों

के इन पहलू को बेधन तथा उनके अनुयायियों ने विकसित किया। राज्य को व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हितों का मध्यस्थ बना कर वह सम्बन्धितवादियों का पूर्व सूचक बन गया।¹

इस सब आलोचनाओं के बावजूद भी यह बड़ा सम्झना है कि होल्ज ने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में महत्व वाला दिया है। अब तक के इतिहास में राजनीतिक पद्धति की आदर्शरूपता के प्रति कोई चेतना नहीं थी। होल्ज ने यह अनुभव किया कि एक विकसित पद्धति के बिना राजनीति विज्ञान, विज्ञान नहीं बन सकता। दूसरे होल्ज इस दिशा में निर्देशन देने वाला वह सर्वप्रथम विचारक या विमर्शी मान्यता थी कि राजनीतिक पद्धति नैतिक विज्ञानों की पद्धतियों से दूर कुछ निर्यात सम्भूत है। अपने राजनीति के विभिन्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रारम्भ किया। दूसरे, यहाँ में होल्ज की महानता इस बात में है कि अपने अपने राजनीतिक परिणामों का आधार उस पद्धति पर रखा जिसे उस युग में पूर्ण वैज्ञानिक समझ जने लगा था। इस पद्धति का मार यह है कि समस्त दार्शनिक मोड़ ज्योनिजि की पद्धति पर लेनी चाहिये और नैतिक बात को एक विमुख सामाजिक प्रजातों के समान समझना चाहिये, विभिन्न-विभिन्न घटना की व्याख्या उसकी पूर्ववर्ती घटना अथवा घटनाओं के प्रकाश में की जा सके। वह राजनीति विज्ञान का मूल मनोविज्ञान की नीति पर काम चाहता है। इसकी पद्धति में अधिकार पूर्ण व्यक्तियों के उत्तर देने के विवे, या इतिहास की शिक्षाओं के विवे या धर्म ग्रन्थों के लिए कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि होल्ज की प्रागुक्तिक मान्यता है कि वह अपने मूल में अपने पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है।

पत्र 20वीं शताब्दी में बड़ी परलता में हम अपनी उस पद्धति में दृष्टि निगम सकते हैं जिसका प्रयोग करने मनुष्य तथा राज्य के सम्बन्ध के लिए किया और यह कह सकते हैं कि यह भी क्यों कि सामाजिक विज्ञानों के विकास ने यदि कोई बात निश्चि की है तो वह यह कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में नैतिक विज्ञानों की पद्धति का प्रयोग एक नैतिक पैमाने पर ही किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञानों के मूल पर एक मानव विज्ञान की रचना करने का प्रयास होल्ज का एक और प्रयत्न था। पर यदि होल्ज के प्रति हम ग्याम के ज्ञान में तो हम यह बात रखना चाहिये कि मनुष्यी शताब्दी में समस्त विज्ञान पर व्यक्तियों की एक समष्टि रूप थी। इस पद्धति को प्रयोग कर ही ज्योनिजि की मनुष्यता मान्य हुई थी और उसे सामाजिक सम्बन्ध के क्षेत्र में प्रयोग लेना उस समय के उदात्त, निरुद्ध, निरुद्ध जैसे महान विचारकों की आज्ञा थी। पर यह

1. इस प्रयोग में नेवाले ने किया है कि "यह कई प्राकृतिक घटना नहीं है कि वेधन बारी की होल्ज का उद्देश्य ही शायद है कि जिन कि उनके मूल विषय विचारों का। अपने बारी ज्योनिजि का नाम अपने सम्बन्ध रहा है परन्तु यह बड़ा प्राकृतिक न होती कि अपने एक ऐसी बात निश्चि है कि जिन मनुष्य नैतिक के विवे को समझ है क्योंकि अपने में मनुष्यता पावु, निश्चि है।"

कि लॉक भी जिसे सामान्यतः अनुभव प्रधान प्रणाली का जनक माना जाता है, राजनीति की ज्योमिति की भाँति एक प्रदर्शनात्मक विज्ञान बनाना चाहता था। फिर हॉम ने यदि ऐसा प्रयास किया तो इसमें आश्चर्य क्या ?

हॉम ने अपने परवर्ती अनेक राजनीतिक विम्वेषों और राजनीतिक विचार-धाराओं को प्रभावित किया है। उनके भौतिकवाद की छाप मान्टेस्कु और कार्ल मार्क्स पर देखी जा सकती है। उसमें उपयोगितावाद का भी आरम्भ मिलता है और बावजूद इस सब के कि समझौता नागरिक का स्वतन्त्रता पर न होकर दासता का बन्धन है, हॉम को उदारवाद का दार्शनिक और वैयक्तिक तथा मूल्य का पूर्ण समझा जाता है। वह एक ऐसी राजनीति तथा शासन शास्त्र का प्रतिपादन करता है जिसका आधार मनुष्य है और जहाँ से व्यक्तिवादो विचार पद्धति प्रजाजन का अपने शासकों को तोलने के लिए आधार प्रस्तुत करती है। "यदि अनुभवा की एक प्रायः राजनीतिक (Pre political) प्रपिचार प्राप्त है (जिसे गुर्राँन रचना राज्य का कार्य है) तो उसका परिणाम स्पष्ट है (वाहे उसे कोई वित्तों ही अनिच्छा से स्वीकार क्यों न करे) और वह यह है कि वह राज्य जो प्रायः उस अधिकार की पूर्ति करने में विफल रहता है उसकी व्यवस्था की जा सकती है।" हॉम के दर्शन को अपने युग का सबसे आन्तरिक मित्र बनाने वाला तत्त्व उसका व्यक्तिवाद है। उसने लेस्के फेयर (Laissez Faire) की उस भावना को पकड़ लिया था जिसने सामाजिक विम्वेष को दो धाराओं तक अनुशासित रखा। अतः यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद पर अपने दर्शन की आधारित कर हॉम ने राजनीतिक इतिहास के विकास में महान योग दिया है।

BIBLIOGRAPHY

- (1) SABINE A History of Political Theory
- (2) LEO STRAUSS The Political Philosophy of Hobbes
- (3) ZAGORIN Political Thought in the English Revolution
- (4) STEPHEN Hobbes.
- (5) WARENDER Thomas Hobbes

जॉन लॉक के राजदर्शन में व्यक्तिवाद

(INDIVIDUALISM IN THE POLITICAL PHILOSOPHY OF
J. LOCKE)

—शशि रिखी

जॉन लॉक सत्रहवीं शताब्दी इंग्लैंड का एक महान विचारक था। अनुसंधानवादी होते हुए भी इसके राजनीतिक विचार हॉब्स से बहुत दूर भिन्न हैं। यद्यपि लॉक के ग्रंथ में इनकी कमजोरी नहीं है शिवाजी कि हॉब्स के लेवियाथन (Leviathan) में पाई जाती है किन्तु फिर भी व्यावहारिक सिद्धांत के रूप में वह हॉब्स के लेवियाथन दर्शन से अधिक श्रेष्ठ है। लॉक का द्वांजद्वर (Treatise) उनके युग की मान्यता की अभिव्यक्ति करता है। उसने सन् 1668 की गौरवपूर्ण क्रांति के लिए एक सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया था। वोगन (Vaughan) ने अपनी पुस्तक स्टैंडींग इन दी हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल फिलॉसफी (Studies in the History of Political Philosophy) में लॉक के द्वांजद्वर के लिए लिखा है कि "वह अपने प्रमाणन के रूप में कम ॥ पीढ़ियों बाद तक इंग्लैंड और फ्रांस में नवतन्त्रता की साक्षित बनी रही।" इन्होंने अमेरिका के क्रांति-कारियों के लिए भी मौलिक प्रस्तुत किया। केवल राजनीतिक विचार क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में भी लॉक की रचनाओं ने कुछ ऐसी विचार रेखाएँ निर्धारित की हैं जिनका अनुसरण आधुनिक और विन्तक प्रायः तक करते आये हैं।

लॉक का राजनीतिक दर्शन

राजनीतिक दर्शन की जो परिभाषा लॉक ने दी, वह उनके राजनीतिक दर्शन का सर्वोपम आरम्भ बिन्दु है। उसका कहना था कि "सन्तति को नियमित तथा सुरक्षित रखने, कानूनों का विधान्वित करने, राज्य की दास्य प्राप्ति में सहाय करने तथा समाज की शक्ति के प्रयोगार्थ कानून बनाने और उन्हें लागू करने पर दंड देने के अधिकार को राजनीतिक शक्ति कहते हैं।" कानूनों को विधान्वित करने के लिए राज्य द्वारा दत्त प्रमाण केवल तभी व्यापक हो सकता है, जबकि उसे सन्तुष्ट समाज का समर्थन प्राप्त हो और उसका प्रमाण अस्ति के लिए किया जाय। लॉक एक ऐसा आधुनिक है जो अपने राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति और समुदाय दोनों को समान महत्व प्रदान करने की चेष्टा करता है।

हारस और लॉक

लॉक के अनुसार शासन विशेष रूप से राजा के प्रति तथा राजा के साथ-साथ संसद और अन्य राजनीतिक अभिकरण जैसे जनता भवना समुदाय के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी शक्ति कुछ तो नैतिक विधि द्वारा निदिबद्ध होती है और कुछ देश के इतिहास में लिखित संवैधानिक परम्पराओं और अभिमनया द्वारा जन्म लेती है। शासन के बिना कार्य नहीं चल सकता, इसीलिए शासन का अधिकार आवश्यक है। लेकिन, यह अधिकार इस धर्म में जनता से लिया गया है कि यह राष्ट्र के कल्याण के हित में है। यह सर्व समुदाय को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में ग्रहण करता है। लॉक के मुताबिक यह सिद्धांत पूर्णतः स्वभाविक भी था कि समाज लोकतंत्र द्वारा नियंत्रित होना था। हॉब्स के विरोधपूर्ण वाक्य यह प्रकट करना था कि वास्तविक समुदाय एक कल्पना है। उसका अस्तित्व केवल उसके सदस्यों के सहयोग पर निर्भर है। यह सहयोग केवल इस कारण है कि उसके सदस्यों को कुछ लाभ होता है। यह समुदाय का रूप उन्नीसवीं शताब्दी में धारण करता है जबकि कोई व्यक्ति प्रभुशक्ति का प्रयोग कर सकता हो। इस विरोधपूर्ण के माध्यम पर ही हॉब्स ने यह निष्कर्ष निकाला था कि शासन चाहिए वरना भी क्या न हो उसमें प्राचीनता आवश्यक है। उसने अनुसार अविद्या, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व जैसे विचार राज्य के अंतर्गत ही देखे हैं, राज्य के लिए नहीं।

इन दोनों दृष्टिकोणों में आधारभूत अंतर है। पहले दृष्टिकोण में लोगों पर बल दिया गया है। इनमें व्यक्तिवादी तथा संस्थावादी दलों के बारे में यह कल्पना की गई है कि ये दोनों सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य करते हैं। शासन सब की अलाई के विचार से उनका नियंत्रण करता है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार समान स्वार्थी व्यक्तियों का एक संगठन है। ये व्यक्ति अपने समान ही अन्य स्वार्थी व्यक्तियों में अपनी रक्षा के लिए विधि तथा शासन का माध्यम चाहते हैं। यदि लॉक इनमें से किसी एक दृष्टिकोण को पूरी तरह मानता तो और दूसरे को अस्वीकार कर देता तो उसने दर्शन में अधिक संगति रहती।

लॉक ने जिन परिस्थितियों में विचार था, उनमें दोनों ही दृष्टिकोणों को मानने की आवश्यकता थी। लॉक ने अपने सामाजिक दर्शन में हॉब्स द्वारा दी गई बहुत सी स्थापनाओं को भी स्थान दिया। वह प्राकृतिक विधि की व्याख्या इस रूप में करता है कि वह व्यक्ति में निहित कुछ अंतरों और अभेद अधिकारों का दावा है। इन अधिकारों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार एक आदर्श अधिकार है। शासन और समाज दोनों का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। इन अधिकारों की अभावता दोनों की मता में अंतर एक सीमा है। लॉक बार-बार यह स्पष्ट करता है कि शासन का उद्देश्य समाज का हित है। राज्य एक ऐसा यन्त्र है जिसे मनुष्य ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया है। हॉब्स और फिर से दोनों के लिए यह एक अन्तर्गत अंतर था। लॉक के एक भाग में व्यक्ति और उसके अधिकारों की प्रधानता दी है तो दूसरे भाग

में समाज की। इसीलिए कहा जाता है कि लोक व्यक्तिवादों था। उनकी दर्शन प्रणाली का केन्द्र है व्यक्ति तथा उसके अधिकार।

सम्पत्ति और प्राकृतिक अधिकार

लोक ने हॉब्स द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था की विमर्श रूप से आलोचना की है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ता रहता था। इसके विपरीत लोक का विचार है कि "प्राकृतिक अवस्था शांति मद्भावना पारस्परिक रक्षा और महायत्ना की अवस्था थी।" प्राकृतिक विधि मानवी अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी तरह से व्यवस्था करती है। प्राकृतिक अवस्था का एकमात्र दोष यह था कि उसमें मजिस्ट्रेटों, लिखित विधि और निर्दिष्ट दण्डों की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि अधिकार सम्बन्धी नियमों की मान्यता मिल सकती। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य अपने स्वतन्त्रता की जिम प्रकार भी हो सकता था, रक्षा करता था। इस अवस्था में उसे अधिकार था कि वह अपनी वस्तु की रक्षा करे, और उसका यह कर्तव्य भी था कि वह दूसरों की वस्तु का सम्मान करे। उसका यह अधिकार और कर्तव्य उतना ही पूर्ण होता था जितना कि किसी शान्त के अन्दर्गत सम्भव है।

लोक का विचार था कि प्राकृतिक अवस्था में सम्पत्ति इस अर्थ में एक थी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति में अपने जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त करता था। यही लोक आधुनिक विचारों की ना रहा है। मध्य युग में यह विचार असामान्य नहीं था कि, 'मान स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व की अनेक अधिक पूर्ण होता है और इसीलिए अधिक स्वभाविक भी। व्यक्तिगत सम्पत्ति मध्ययुग में मनुष्य के पत्र तथा उसके पापों का बिन्दु मानी गई थी। रोम की विधि में इनके दिवङ्गत मित्र मित्रान्त पाया जाता था। वह मित्रान्त था कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का जन्म उसी समय हुआ जबकि लोगों ने वस्तुओं पर अनाधिकार कब्जा आरम्भ कर दिया। इसने पूर्व सब लोग समीचीनों का मित्रान्त कर प्रयोग करने थे, यद्यपि उन समय भी सामुदायिक स्वामित्व नहीं था। लोक ने इन दोनो मित्रान्तों में मित्र अना मित्रान्त रखा है।

उसने कहा कि जिस चीज को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम से प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। उदाहरण के लिये, यदि वह किसी जमीन के बाग और दीवार बनाता है या उसे जोतता है तो वह उसका हो जाता है। उस समय समुदाय जैसे नए उपनिवेशों में यही हो रहा था। लोक पर कहा के उदाहरण का प्रभाव पड़ा। इनके साथ ही लोक यह भी मानता था कि व्यक्तिगत कृषि अर्थ-व्यवस्था में आदिम काल की नाभूतिक श्रेणियों की अनेक अधिक उपादन होता है। लोक का विचार था कि अधिक उत्पादन होने से सम्पूर्ण समुदाय का जीवन-स्तर ऊँचा बनता है। लोक के मित्रान्त का मूल बाह्य दुष्ट भी रहा हो, उसका दर्श यह था कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार इसीलिए उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति परिश्रम

करता है तब वह अपने परिचय से अज्ञित पदार्थ में अपने व्यक्तित्व का आराधण कर देता है। अपनी आन्तरिक शक्ति पर विश्वास करने वह उन्हें अपने व्यक्तित्व का धर्म बना लेता है। सामान्यतः उसकी उपयोगिता इन बातों पर निर्भर करती है कि उनके सम्बन्ध में किन्ता परिश्रम किया गया। इस प्रकार लॉक के सिद्धांत में समाजवादी सर्व व्यवस्था के धर्म सम्बन्धी मूल्य सिद्धान्तों (Labour Theories of Value) का पथ प्रशस्त किया।

लॉक ने व्यक्तिगत सम्पत्ति का जो सिद्धान्त दिया है उसमें यह स्पष्ट है कि मनुष्य का सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रादिम समाज में पहले का है। लॉक ने इन प्रादिम समाज को प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। उसने यह भी कहा है कि "सम्पत्ति समस्त आधारभूत ज्ञान के स्पष्ट समझने के बिना भी रहती है।" यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अधिक भाग के रूप में लेकर समाज में लाता है। इस प्रकार समाज अधिकार की मूर्ति नहीं करता, समाज और सामान्य दावा का उद्देश्य सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा करना है। यद्यपि लॉक ने सम्पत्ति विरुद्ध विरुद्ध प्रमाणों को दिया है तथापि इसका उद्देश्य मनुष्य सामाजिक दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। "सम्पत्ति" शब्द का अर्थ लॉक बहुत व्यापक अर्थों में करता है। उसने निम्न सम्पत्ति में जीवन, स्वतन्त्रता तथा मनुष्य का धर्म सम्मिलित है। लॉक जहां जहां किसी अधिकार के सम्बन्ध में कहना चाहता है, वह सम्पत्ति शब्द का प्रयोग करता है। यही सम्पत्ति ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसकी उसने विस्तार दी गयी है। अतः स्पष्ट है कि उसने इस अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण माना है। गाहे कुत्त भी स्थिति है, उसने समस्त प्राकृतिक अधिकारों को व्यक्ति का मनुष्यपूर्ण अधिकार माना है। अतः ये अधिकार समाज तथा सामान्य के प्रति व्यक्ति के मनुष्यपनीय दावे हैं। समाज का उद्देश्य इन दावों की रक्षा करना है अतः समाज उन पर उतना ही नियंत्रण रख सकता है जितना उनकी रक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पदा पर उसी सीमा तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, जितना सीमा तक कि उन कार्य में दूसरे व्यक्तियों के अंगों को क्षति की रक्षा करने में सहायता प्राप्त होती है। बर्तमान स्थिति में हमारा मत यह है कि यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक सीमा है। सरकार जन-दुश्मन के बिना सम्पत्ति का हनन नहीं कर सकती क्योंकि कानून सम्पत्ति की रक्षा के लिए ही बनाया जा रहा है। इस प्रकार लॉक की सरकार नागरिकों के कुछ स्वातंत्र्य अधिकारों के कारण मर्यादित है। ज्ञाते हैं। इन सब सिद्धांतों से स्पष्ट है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सरकार बदली दे या नहीं, इस बात को सर्वोच्च निर्णायक जनता है।

सामाजिक सविद्या

लॉक ने अपने दर्शन में सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। इस अवस्था को उसने व्यक्ति और पारस्परिक सम्बन्धों की अवस्था बताया है। उसने

प्राङ्गणिक अधिकारों को भी सम्पत्ति के आधार पर समाज से पहले विद्यमान माना है। इसके पदवात वह नागरिक समाज के उद्भव का वर्णन करता है। यह समाज अपने सदस्यों की सहमति पर आधारित है। उसके मिश्रित के इस पक्ष में अनेक दुर्बलताएँ थी।¹

नागरिक शक्ति का अधिकार प्रत्येक-व्यक्ति को अपनी और अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। शासन सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए जिस विधायी और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है, यह वही शक्ति है जिसे व्यक्ति ने समुदाय की प्रथा जनता को सौंप दिया है। इस शक्ति को हस्तान्तरित करने का कारण यह है कि यह प्राङ्गणिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिक अच्छा उपाय है। इसके द्वारा मनुष्य समुदाय का या राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं। यह समझौता सब का सबके साथ होता है। इसका स्वरूप सामाजिक है। इसने अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति सम्पूर्ण समाज को अपने वेबल के अधिकार देने को तैयार होता है जिनके प्रयोग में प्राङ्गणिक अवस्था में कुछ गड़बड़ पैदा होती थी और शांति खतरे में पड़ती थी। ये अधिकार थे : अपने लिए प्राङ्गणिक कानून की व्याख्या करना, उसे क्रियान्वित करना और उसे भंग करने वालों को दण्ड देना। शासन के दोष अधिकार, व्यक्तियों के पास सुरक्षित रहते हैं और राजनीतिक नियंत्रण को भयाहित करते हैं।

लॉक के अनुसार समझौता करने कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता पर कोई ऐसा बंधन स्वीकार नहीं करता जो दूसरों के आक्रमण में उसे सुरक्षित रखने के लिए तैयार न हो। इसके अतिरिक्त प्राङ्गणिक कानून की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने वाला राज्य स्वयं भी उसमें उतना ही बाधित है, जितना कि प्राङ्गणिक अवस्था में व्यक्ति।²

इस प्रकार सरकार के ऊपर दोहरा नियंत्रण लग जाता है। उसे जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के उन प्राङ्गणिक अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है जिनका उपयोग मनुष्य प्राङ्गणिक अवस्था में करते थे और उसे स्वयं भी प्राङ्गणिक कानून का पालन करना पड़ता है। माघस यह है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के विपरीत, जो कि शासन को अपरिमित तथा निरंकुश शक्ति का प्रदान करता है, लॉक का मोनिक

1. लॉक ने नागरिक सत्ता की परिभाषा इस प्रकार की थी, "यह सम्पत्ति की रक्षा और उसका नियमन करने के लिए दण्ड सहित कानूनों को बनाने का और इन कानूनों के निष्पादन में मार्गदर्शक हित के लिए समुदाय की शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार है।" इस प्रकार की शक्ति केवल महमति के द्वारा ही उत्पन्न होती है। यह शक्ति सीमित रूप में ही दी जा सकती है लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही दे सकता है।

2. लॉक स्वयं कहता है कि "प्राङ्गणिक कानून की सीमाएँ समाज में समाप्त नहीं हो जाती।"

समझोता शासक को केवल सीमित शक्तियाँ ही प्रदान करता है। लॉक का समझोता शासन की तरह है। शासक का पट्टा नहीं बदल सकता। स्वतन्त्रता का पत्र है। लॉक ने हाथ में पकड़ कर सविदा सिद्धांत उठाया। उद्देश्य की पूर्ति करना है, जिसके लिए मूल रूप से उसका प्रतिपादन किया गया। अर्थात् शासक की निरवृत्त शक्ति व दावे के विपरीत व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करना। लॉक इस सविदा का प्रयोग व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतन्त्रता को अधिकारों के सुरक्षित रखने के लिए करता है।

लॉक की सविदा की दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि यह सर्वसम्मति से की जाती है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतन्त्र और स्वाधीन है इसीलिए क्रिया की भी किसी की इच्छा के विरुद्ध राज्य का सार्वभौमिक होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जो लोग बाहर रहना चाहें वे प्राकृतिक अवस्था में रह सकते हैं। अभिप्राय यह है कि लॉक के अनुसार राजा जन इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। यह सविदा न केवल सर्वसम्मति से होती है बल्कि लॉक के अनुसार यह अटल भी है। क्योंकि एक बार समझौता कर लेने पर लोग इसके विपरीत नहीं जा सकते। हाँ, यदि किसी संकटवश उनके द्वारा बनाई गई सरकार ही विफल हो जाए तो दूसरी बात है। लॉक अपनी सविदा में यह मानता है कि यद्यपि राज्य का निर्माण करने वाले मूल समझौता न केवल सर्वसम्मति से हुआ है किन्तु राज्य के लिए यह निषेधित करने में निषेधित किया है, और उसका क्या दण्ड होना चाहिए, सर्वसम्मति आवश्यक नहीं है। राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानून में बहुमत शासन का नियमन कार्य करता है। सामाजिक समझौते में बहुमत शासन का सिद्धांत अनिवार्य रूप से निहित है। इस सिद्धांत को स्वीकार किए बिना कोई भी सामूहिक कार्य असम्भव हो जाता है और सविदा का साथ महत्व ही जाता रहता है।¹

लॉक की यह धारणा सही है कि एक जीवित समाज के निर्णयों का सर्वसम्मति से प्राप्ति नहीं किया जा सकता। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग किसी कारणवश कार्यवाही में भाग न लें और कुछ लोग मत की विभिन्नता के कारण उसे स्वीकार न करें। अल्पमत के लिए बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना यद्यपि आवश्यक है। परन्तु लॉक ने इस बात का स्पष्ट नहीं किया कि उस अल्पमत के विषय में, जिसे बहुमत न होने हुए भी बहुमत के निर्णय को मानना पड़ता है, यह कैसे कहा जा सकता है कि

1. लॉक के अपने शब्दों में—“अत्यधिक व्यक्तिगत दमन के साथ एक सरकार का प्राथमिकता में एक राज्य के निर्माण करने की अनुमति देना है। इस प्रकार वह अपने प्राथमिक दमन के निर्णय के सामने मुझे नया उभरे मानवित्व होने के लिए बाधित करता है। परन्तु यह मूल सविदा, जिसके द्वारा उनका दमन के साथ मिन कर नामांक की रचना की है, निरर्थक हो जाती और वह सविदा ही नहीं रहेगी।”

—(On Civil Government Book II)

यह स्वतन्त्र और समान है और उसकी सहमती से ही उस पर मान्य होता है। यदि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार अन्तर्णीय हैं तो दण्डन का भी हमें वर्जित करने का अधिकार हमें अधिक नहीं है बिना कि किसी एक व्यक्ति का है। इस बात का भी कोई उचित ज़ाह्य नहीं कि कोई व्यक्ति अपने निजी निर्गुण या केवल शरीरार्थ पर-रक्षा करे क्योंकि दण्डन से जहाँ हमें नज़र नहीं है। चाहे न उन समस्याओं का कोई सुविशुद्ध समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। बल्कि यह कह देना कि दण्डन मानव मूल सविदा में ही निहित है ना तो प्रश्न का जवाब हमें नहीं माना जा सकता।¹ दण्डन या शासन विनाश इतना मान्य नहीं है जितना कि चाहे हमें समझता था।

चाँकि वे इन सविदा सिद्धान्त में कुछ अस्पष्टताएँ और अनिश्चितताएँ भी पाए जाती हैं। यहाँ बात यह है कि चाहे बार-बार मूल सविदा (Original contract) की बात करता है, जिसके द्वारा मनुष्य एक राजनीतिक समाज में संगठित होने के लिए सम्मत् होता है। इस भाषा में प्रतीत होता है कि चाँकि केवल एक ही सविदा की कल्पना करता है। और हमें मूल सविदा द्वारा राजनीतिक समाज धर्मात् राज्य की स्थापना हो जाती है हमें ऐसा नहीं लगता कि वह सरकार तथा उसके संस्थानों की भी मूलि करता है। क्योंकि राज्य और सरकार दो भिन्न वस्तुयें हैं और चाँकि हम राज्य का मान्य होने प्रथम विचारकों में से एक था। परन्तु चाँकि ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि सरकार का निमाण कैसे हुआ और कब हुआ ?²

इस उद्दिष्ट का ज्ञान मेरा ज्ञान जैसे विज्ञान यह कह कर करना चाहते हैं कि "चाँकि की स्थिति अद्वितीय तथा निरन्तर के समान थी जिन्होंने कि वे सविदाओं की कल्पना की थी—एक व्यक्तिओं के बीच में, जिसके द्वारा समाज की रचना हुई और, दूसरा समाज और सरकार के बीच में।" परन्तु इस दूसरे समझौते का उल्लेख चाँकि ने नहीं किया। हालाँकि यह उसके शब्दों में सविदा अवश्य मान्य होता है।

कुछ दूसरे सिद्धांतों की धारणा यह है कि यदि चाँकि राज्य और सरकार में भेद नहीं रखा तब भी सरकार की रचना के लिए दूसरे समझौते का बहू ज़रूरत द्वारा भी संभव नहीं करता। चाँकि केवल एक ही समझौता माना जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक समाज की रचना होती है। कई भी राजनीतिक समाज सरकार के बिना न तो जीवित रह सकता है और न ही कार्य कर सकता है। शरीरार्थ दूसरा प्रथम कार्य होता है सरकार की स्थापना करना, जिसका कार्य है समाज में जीवन, और तथा मानव की रक्षा करना।

1. "It is plain the world never was and nor ever will be without numbers of men in that state".—Locke

2. "I affirm it at all men are naturally in that state and remain so till by their own consent they make themselves members of some Political Society".—Locke.

लोक स्वयं कृता है—'कई भी राजनीतिक समाज बना सकते हैं मनुष्य के व्यवहारों को दृष्टिगत करते ही शक्ति व विद्या न हो सकती है और न वायव्य रह सकता है। ईश्वरिण राजनीतिक समाज बना और बेचन नहीं हो सकता है जहाँ कि प्रत्येक मनुष्य ने अपनी प्राकृतिक क्षिति का परिचय करके उसे सम्पूर्ण समाज के हाथ में सौंप दिया हो। आ लोक एक समाज में स्थापित होता है और एक सामान्य वातावरण में स्थापना करने हैं, जिसे उनके भगवान् का निर्णय करने तथा व्यवस्थापिका को दण्ड देने का अधिकार होता है, एक राजनीतिक समाज में एक दूसरे के साथ एक-सा हो जाना है।' (ग्रेट्ट ट्रीटाइज गैगन 87)

लोक ने उपर्युक्त विचारों के परिणाम में निरूपित है कि राजनीतिक समाज का निर्माण सब एक पूर्ण नहीं समझा जा सकता जब तक कि वह सरकार की स्थापना न करे। जिस उद्देश्य के लिए समाज की स्थापना हुई, उसकी पूर्ति व विना सरकार का निर्माण करना उसका प्रथम कार्य होता है। यह सब कदाचित् होता है कि समाज तथा सरकार का जन्म साथ-साथ होता है।

एक प्रथम प्रश्न यह भी उठता है कि क्या वह सम्पूर्णता जिस द्वारा लोक राज्य की स्थापना होता मानता था एक ऐतिहासिक सत्य है प्रथम तीन एवं चार भागों में विचार ? लोक व विचारों से प्रतीत होता है कि वह दण्ड सम्पूर्णता का दार्शनिक एवं ऐतिहासिक होता ही मानना चाहता है। उसने अपनी ट्रीटाइज व 14वें भाग में यह निष्कर्ष दिया है कि भविष्य में ऐतिहासिक सत्य है। दूसरे विचारीत भाग 15 का प्रथम वाक्य यह जाहिर करता है कि वह विश्व का एक ऐसा भाग मानता है जिसने द्वारा हम राज्य का बेचन सम्पत्ति पर आधारित कर सकते हैं।

समाज और शासन

सब विचारों लोक ने सामन्य की स्थापना का नागरिक समाज का निर्माण करने वालों को सविशेष से कम महत्व की घटना माना है। जहाँ एक बार बहुमत सामन्य का निर्माण करने व विना दोषार हो जाता है, अनुशासन का सम्पूर्ण क्षिति स्व-भारत बहुमत के साथ हो जाती है। सामन्य का स्वरूप हमें यह पर निर्भर करता है कि बहुमत अपनी क्षिति का किस प्रकार प्रयोग करना चाहता है। बहुमत हमें बताता है कि हमें पात रस सकता है प्रथम यह उसे किसी विधायी सत्ता को भी शक्ति सत्ता है। दूसरे लोक की क्षिति के अनुभव के आधार पर लोक ने यह मान लिया था कि सामन्य में विधायी क्षिति सबसे ऊँची है। तब यह वह भी मानता था कि बाईबिलिओ विधि-सिद्धि में एक सत्य के सत्य है। क्षिति सामन्य की क्षिति को समित्त है। विधायी क्षिति स्व-भारत पारी नहीं हो सकती। स्व-भारतारी क्षिति सा उस सामन्य व साथ भी नहीं हो सकता न विधानमण्डल का निर्माण दिया था। वह अपनी सामन्य सामान्य के द्वारा सामन्य को कर सकते हैं। वह सम्पत्ति के बिना सम्पत्ति भी नहीं हो सकती। लोक ने अनुसार सम्पत्ति

का अर्थ बहुमत का निर्णय है। वह अपनी विधायी शक्ति किसी दूसरे को भी नहीं सौंप सकती। यह शक्ति तो वहीं रहनी है जहाँ समाज ने उसे प्रतिष्ठित किया है। सर्वोच्च शक्ति जनता के पास रहनी है। जब विधान मण्डल जनता की इच्छा के प्रतिबल बनता है तो जनता उस की शक्ति को वापस ले सकती है। कार्यपालिका की शक्ति तो और भी सीमित होती है—वह कुछ तो विधान मंडल के ऊपर निर्भर करता है और कुछ उसके ऊपर विधि का नियंत्रण रहता है। स्वतन्त्रता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि विधायी और कार्यकारी शक्ति एक ही हाथों में केन्द्रित न रहें। लॉक ने विधानमण्डल और कार्यपालिका के सम्बन्धों का जो विवरण दिया है, वह राजा और ममद के किसी न किसी बाद विवाद के पट्टन का प्रकट करता है।

लॉक के दर्शन की असंगतियाँ

लॉक ने शासन के ऊपर जनता की शक्ति दृढ़तापूर्वक रूप में स्थापित नहीं की है जैसा कि बाद के अधिक लोकतन्त्रवादी सिद्धांत में पाया जाता है। यद्यपि उसने विधानमंडल की शक्ति को एक अमानत (Trust) बताया है और यह कहा है कि समुदाय के नाम पर कार्य करने वाला बहुमत यह शक्ति विधानमंडल की सौंपता है, लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब तक शासन अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है उस समय तक जनता अपने अधिकारों में संचित रहती है। इस दृष्टि से लॉक द्वारा प्रतिपादित शासन जैसा कि बाद में रूसो ने भी कहा था, बहुत कुछ स्वैच्छाकारी था। यदि शासन जनता का दुश्मन है, तो यह समय में नहीं आता कि लॉक ने इस ट्रस्ट को पूरी तरह से क्रियाविरत करने का प्रयास क्यों नहीं किया? जनता की विधायी शक्ति में केवल एक ही कार्य आता है और वह है सर्वोच्च विधानमंडल की स्थापना। यदि समुदाय अपनी शक्ति को हमेशा के लिए वापस लेना चाहे तो वह उस समय तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि शासन का विघटन न हो जाए। रूसो जैसा लोकतन्त्रवादी भी इसे जनता की अपना शासन प्राप्त करने की शक्ति पर अनुचित प्रकट मानता था। लॉक के इस विचार के अनेक कारण थे। वह बड़ा भावधान और सम्मोहक व्यक्ति था। यद्यपि उसे एक क्रांति का समर्थन करना था, लेकिन वह उच्छृंखलता का किन्तुल प्रोत्साहन नहीं देना चाहता। इसके प्रतिरूप वह लोकतन्त्रवादी शासन का, कम से कम इंग्लैंड में एक बोद्धि प्रदान मानता था। इस प्रकार इंग्लैंड की क्रांति ने इंग्लैंड की शासन परम्परा का नहीं तादा था, उन्हीं प्रकार उसका दार्शनिक साक्षात् लॉक भी क्रांतिकारियों में सबसे अधिक अनुदार था।

लॉक का उद्देश्य 1688 की क्रांति की नैतिक वैधता का समर्थन करना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हुकर के सिद्धांत का स्वीकार किया, जो इस प्रकार था कि "इंग्लैंड का समाज और इंग्लैंड का शासन दो भिन्न वस्तुएँ हैं। शासन समाज की बनाई के लिए है और जो शासन समाज का नुकसान पहुँचाता है, उसे बदला जा सकता है।" इस युक्ति की पुष्टि में लॉक ने क्रांति के आधार का किन्तु

विवेचन किया है। लोके का कहना है कि यह अधिकार विजय के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। लोके ने यहाँ उचित और अनुचित युद्ध में भेद माना है। आक्रामक को कोई अधिकार नहीं मिलना। न्यायपूर्ण युद्ध में कोई विजेता धन ऐसे अधिकारों की स्थापना नहीं कर सकता जो विजित लोगों की सम्पत्ति व और स्वाधीनता के विरुद्ध हो। यह तर्क शासन के ऐसे प्रत्येक मिष्ठान के विरुद्ध है, जिसके अनुसार शासन, वन व मरुत प्रयोग के द्वारा धनो न्यायपूर्ण शक्ति प्राप्त करता है। लोके व तर्क का आधार शायद यही है जिसका बाद में स्मो ने विभाग किया था। यह आधार नैतिक मोक्ष और वन की दो भिन्न वस्तुएं मानता है। वन व आधार पर नैतिक मोक्ष नहीं किया जा सकता। इमोनिंग जो शासन वन में प्रारम्भ होता है, वह उसी समय तक न्यायपूर्ण माना जा सकता है जब तक कि वह व्यक्तियों और समुदायों के व अनिहित अधिकारों को मान्यता दे। दूसरे शब्दों में नैतिक व्यवस्था स्थायी और शास्त्र है और शासन नैतिक व्यवस्था में बदल सकता है। लोके के लिए प्राकृतिक विधि का शायद यही अभिप्राय था, जो उसका मिमरी, विवेक और न्यायपूर्ण मध्य युग के लिए था।

समाज के पृथक् शासन का उसी समय विघटन हो सकता है, जबकि या तो विधायी शक्ति के केन्द्र में परिवर्तन हो, या शासन उस विश्वास का उत्पन्न करे जो लोगों ने उगम किया हो। लोके के मामले में दो चरनाएँ थी और दोनों ही इंग्लैंड के पिछले पचास वर्षों के इतिहास पर आधारित थी। लोके यह सिद्ध करना चाहता है कि क्रांति हान या न होने का वास्तविक कारण राजा है। राजा ने अपने परमाधिकार को बचाने की और समूह के बिना शासन करने की कोशिश की थी। यह उग सर्वोच्च शक्ति का विस्थापन था जो समाज ने अपने प्रतिनिधियों में प्रतिष्ठित की थी। उसे उस समय की पार्लियामेंट व मजिस्ट्रेट व्यवस्था का भी स्मरण था, क्योंकि वह विधानमण्डल का भी प्रतिनिधित्व नहीं छोड़ना चाहता। प्रजापति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति पर प्रभाव डालना स्वतः प्रबंध है और जो विधान मण्डल ऐसा समझा करता है वह अपनी शक्ति में ह्रास पा बैठता है। इस प्रक्रिया में शक्ति जनता के पास वापस आ जाती है और जनता ने अधिकारों द्वारा नए विधानमण्डल की स्थापना करती है।

लोके के "विधिमग्न" शब्द ने कई बार धनाग्रहण भ्रम उत्पन्न किया है। वह कार्दालिना समवा व्यवस्थापिका के संबंध कायों की बार बार चर्चा करता है, जबकि वह यह सच्ची तरह जानता है कि यह कोई सुधारामय उपाय नहीं है। इसी प्रकार यह धारणाएँ शासन के विधिमग्न प्रतिरोध की चर्चा निरंतर करता है जब कि उसका वास्तविक अभिप्राय विधि बाह्य उपायों का अध्ययन है। लोके ने नैतिक दृष्टि से उचित, और वैधानिक दृष्टि से व्यावहारिक के बीच में कोई भेद नहीं माना है। यह विचार इस परमाणु व आधार पर विकसित हुआ था कि प्राकृतिक और नैतिक विधियों एक ही वस्तु हैं और इमोनिंग कुछ ऐसी मूल विधियों की हैं जिनकी रचना

उच्चतम विधानमण्डल तक नहीं कर सकते। इंग्लैंड में इस प्रकार के नियमों की वैधता उस क्रांति के साथ ही समाप्त हो गई थी, जिसका लोकोपकार करने का प्रयास कर रहा था। तथापि यह विद्वान् बराबर दना रहा कि संसद के ऊपर कुछ नैतिक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं।

तात्त्विक गुलियया

लोक के राजनीतिक दर्शन का सरल व्यवहार में व्यक्त करना कठिन है। इसका कारण यह है कि जब हमका विवरण किया जाता है तो हममें अनेक तात्त्विक कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं। ऊपर में देखने पर यह दर्शन काफी सामान्य मान्यता है और अपनी इस सरलता के कारण काफी लोकप्रिय भी रहा है, लेकिन वास्तव में इसमें अनेक छुई बंधी हैं। इन गुलियया का प्रधान कारण यह है कि मनुष्यों की शक्तों में लोक ने बहुत से प्रगति को देखा और इन सबका एक साथ समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन हमका मिथ्या इतना ठीक सम्मत नहीं था कि एक ऐसी कठिनाई और विषय वस्तु को सम्मान्य करता। यद्यपि परिस्थितियाँ ने उसे क्रांति का समर्थक बना दिया था लेकिन वह किसी प्रकार में सामान्य परिवर्तनवादी नहीं था। बौद्धिक मनोवृत्ति में वह मिथ्यावादी दार्शनिक भी नहीं था। हमने अपने मिथ्याता को अधिकतर उत्पत्ति-वार में प्राप्त किया था और उनको पूरी परीक्षा भी नहीं की थी। लेकिन वह वास्तविक शास्त्र के प्रति अवैज्ञानिक था और उसने उनका बुद्धिमानपूर्वक समाधान करने का प्रयास किया है। मनुष्यों की शक्तों के मध्यम में इंग्लैंड की राजनीति और इंग्लैंड की विचारधारा विस्तृत दर्शन गई थी। लोक ने अपने दर्शन में भूतकाल और वर्तमान का नई विचार की वाग्विश की है। हमने एक ऐसी आधारभूत दृष्टि की है कि जहाँ सभी देशों के बुद्धिमान व्यक्ति आकर मिल सकें। लेकिन हमने जो कुछ ज्ञात, वह हमका विवरण नहीं कर सका। जिस प्रकार हमने भूतकाल के विभिन्न तत्वों का अपने दर्शन में जोड़ा था, उसी प्रकार सामाजिक शक्तों में हमने राजनीतिक दर्शन के आधार पर अनेक मिथ्या भी निकाले हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता

लोक के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण धर्म यह है, जिसमें हमने राजनीतिक शक्ति के स्थान पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुधार दिया है। लोक के दर्शन में मनुष्य समुदाय के सदस्य है। हमने समाज का व्यक्ति की महत्ता पर आधारित माना है, जिनके व्यवहार में अभिजात्य दृष्टि है। तथापि हमने समुदाय को एक निश्चित दृष्टि और व्यक्तियों के अधिकारों का दृष्टि बना है। कुछ इसी तरह में समुदाय व्यक्ति का दृष्टि है। हमने, शासन के अन्तर्गत कार्यपालिका विधानमण्डल की शक्तों को महत्वपूर्ण और कम माना है। स्वतंत्रता तथा समाज की रक्षा में हमका विधानमण्डल कार्यपालिका पर निर्भर रहता है और समुदाय शासन पर स्वतंत्रता की रक्षा का अनुरोधित्व व्यक्ति के अपने ऊपर उसी समय माना है जबकि समाज का विधान होता है। लेकिन समाज

का विघटन होना जरा दूर की बात है। लॉक ने इस सम्भावना की गम्भीरता से कभी कल्पना नहीं की थी। लॉक के मन में मन्त्राज, राजा, विधान मण्डल इन सबके कुछ निहित अधिकार होते हैं, अथवा उनके पास स्वार्थी सत्ता होती है और इस सत्ता का प्रति-क्रमण केवल कुछ विशिष्ट सभ्यो के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन लॉक ने मत में स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार ऐसे हैं जिनका किसी भी दत्ता में प्रति-क्रमण नहीं किया जा सकता। लॉक ने यह कहीं नहीं बताया कि संस्थानों की व्यक्तियों के समान और अविच्छेद्य अधिकारों से किस प्रकार शक्ति प्राप्त है। इस कारण लॉक के सिद्धान्त में कल्पना का सार बह गया है।

प्रभाव

लॉक का चिन्तन ऊपर से देखने से तो बड़ा स्पष्ट लगता है परन्तु उसके प्रसार अनेक जटिलताएँ छिपी हैं। इस जटिलता के कारण यह समझना बड़ा कठिन है कि उनका बाद के सिद्धान्तों से क्या सम्बन्ध है। विचारकों ने उसके दर्शन के जिन तरकों की सुरक्षित ग्रहण किया, वे उसने सबसे स्पष्ट, लेकिन माप ही सबसे कम महत्वपूर्ण तरव थे। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भिक भाग में लॉक का दर्शन काफी लोकप्रिय हुआ। इसके दो कारण थे। पहला तो यह कि वह बहुत सरल लगता था, जबकि वह इतना सरल था नहीं। उनका दूसरा कारण यह था कि वह व्यावहारिक बुद्धि से सम्बन्ध रखता था। वांछित के बाद जो उदारवादी दर्शन जारी रहा था, वह लॉक के दर्शन की मूलरूपात्ता की लेकर आगे बढ़ता रहा। इस दर्शन में धार्मिक सहिष्णुता के तत्व की प्रधानता थी। अठारहवीं शताब्दी के इंग्लैण्ड में इसका बहुत महत्व था।

लॉक के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने अमरीका और फ्रांस की तरकासीन व्यवस्थाओं पर प्रभाव डाला। इसकी वरम परिणति अमरीका तथा फ्रांस में अठारहवीं शताब्दी के अन्त में होने वाली महान् क्रान्तियाँ थी। लॉक ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सहमति तथा संपत्ति के अर्जेन और उपयोग के अविच्छेद्य अधिकारों का प्रतिपादन किया था। लॉक का कहना था कि इन अधिकारों के नाम पर शासन शक्ति का विरोध भी किया जा सकता है। लॉक के इस मत का मुद्ररूपवादी प्रभाव पड़ा। ये विचार बीज रूप में लॉक से काफी पुराने थे। यह सोलहवीं शताब्दी के बाद ही ने योरोप के ममस्त राष्ट्यों का जन्ममिद्ध अधिकार रहा था। इसीलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि अमरीका और फ्रांस में विचार अनेक लॉक के माध्यम से ही पहुँचे लेकिन उनका महत्व राजनीतिक दर्शन की ओर ध्यान देने वाले प्रदेश व्यक्तियों की जान था। ईमानदारी, नैतिक विद्वानों में हड़ता, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार और मानव प्रकृति की गरिमा में विश्वास, मोक्षता, और सद्भावना उनके कुछ ऐसे दृष्टि थे जिन्होंने उसे मध्यमार्थ की जानि का आधार प्रकृत बना दिया। लॉक उदारवादी विचारों का प्रबल मध्यम था। इस दृष्टि में उसकी स्थिति बेजोड़ है। अस्मिन्प्रकरण

और बहुमत के निर्णयों में आस्था जैसे उसके अधिक संदेहास्पद विचार भी लोक-तन्त्रात्मक सिद्धान्त के अंग बन गये। लोक ने व्यक्तिगत अधिकारों को आदर्शरूप दिया, उपयोगितावाद को समस्त राजनीतिक बुराइयों का उपचार माना, सम्पत्ति के अधिकारों के प्रति आदर-भावना को कायम रखा और इस बात पर बार बार जोर दिया कि सार्वजनिक हितों पर व्यक्तिगत कल्याण के सम्दर्भ में विचार करना चाहिए।

BIBLIOGRAPHY

1. SABINE A History of Political Theory
2. VAUGHAN : Studies in Political Theories
3. MACGOVERN : *From Luther to Hitler.*
4. MAXEY : Political Philosophies

रूसो का राजदर्शन और सामान्य इच्छा सिद्धान्त

(POLITICAL PHILOSOPHY OF ROUSSEAU

AND HIS DOCTRINE OF GENERAL WILL)

—सोमप्रकाश भट्ट

रूसो का दर्शन तथा राजनीति सम्बन्धी समस्त साहित्य अपने जटिल और मान्य-विहीन व्यक्तित्व का परिणाम था। अपने सम्प्रेषण से अपने विभक्त व्यक्तित्व का स्पष्ट दर्शन होता है। अपने इन विभक्त व्यक्तित्व में जीवन तथा धर्म-विषयक प्रत्येक घर्तगतिनीची थी। उगने कहा भी है कि—“मेरी रचियाँ और विचार सदैव ही—उपव तथा अधम के बीच झूँटते हुए रहे।”¹

रूसो ने अपने सामाजिक समझौते को हॉग्स और लॉक से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। हॉग्स के अनुसार राज्यकी स्थापना का केवल एक ही उद्देश्य है और वह है समस्त व्यक्तियों की अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को प्रदान करना। समझौता केवल जनता में होता है। हॉग्स अपने सामाजिक समझौते द्वारा निर्बुद्ध राजनय को स्थापना करता है। उगने कहा है कि समझौता सरकार और जनता के बीच नहीं है। हॉग्स यह नहीं दिताना चाहता कि सरकार और जनता में समानता है। इसलिए वह सरकार का निर्बुद्ध और विविधता बना देता है। लॉक का तर्क इनके विपरीत है। वह कहता है जनता सरकार से अधिक शक्तिलाली है। सरकार के जनता के प्रति कर्तव्य है। सरकार जनता की ऐश्वर्य ही चाहती है, भागीदार नहीं। यदि हम सरकार की भागीदार बनें तो वह जनता के बराबर बन जाती है। इसलिए सरकार एक दुर्घटा के रूप में है। जनता के जीवन, शान्ति तथा स्वतन्त्रता के अविनाश के कारण लॉक की सरकार संवैधानिक मानी जाती है। सरकार अच्छी है या नहीं, इस बात की सर्वोत्तम निर्णयिता जनता है। लॉक, हॉग्स की तरह सारी शक्ति राजा का नहीं देता, बल्कि कुछ ही शक्तियाँ राजा को प्रदान की जाती हैं। जनता सरकार को हटा भी सकती है। इस प्रकार लॉक ने हॉग्स की निर्बुद्धता के स्थान पर अपने समझौते में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। परन्तु रूसो को सामाजिक संविदा के इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध ही नहीं है कि प्रथम राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। समझौते में वह भूत का इतिहास नहीं निगला बल्कि केवल राज्य के मूल स्वरूप की समीक्षा प्रस्तुत करता है और

इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा है कि एक आदर्श समाज की किस प्रकार संगठित किया जाये कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राज्याधिकार में संगति स्थापित की जा सके। इस प्रकार के समाज की स्थापना की पद्धति भी सामाजिक भेदवाद। उसका यह सामाजिक समन्वयता "एक ऐसी चीज नहीं है, जैसा कि सारासुत्रवादी माना जाता है। यह वह समन्वयता नहीं है जिस पर हम सब ने बहुत पहिले, प्रथम समाज की स्थापना करने के लिए अपने हस्ताक्षर किये थे। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें आदर्श समाज की स्थापना के लिए स्वीकार करना होगा। यह इतिहास नहीं है, पर किसी दिन इतिहास हो सकता है।"¹

1749 में रूसो ने होजार्न की आकाशवाणी द्वारा घोषित इस विषय पर कि "विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा इसके विनाशकारी कारण में" निबन्ध लिखा। उसके निबंध का सार यह था कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है किन्तु अस्वभाविक समन्वयता द्वारा उत्पन्न किये गये भ्रष्ट सम्पानों द्वारा वह बुरा बन जाता है। मनुष्य यदि अपना आदिमालिक मानन्द तथा निरलसता प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्राकृतिक जीवन की ओर लौट जाना चाहिये। इस निबन्ध ने न केवल पुरस्कार जीता बल्कि 'विवेक युग के दृष्टिम समाज में एक बड़ी हलचल मचा दी। रूसो के अनुसार जब तक राज्य कायम है, शान्ति असम्भव है। उसे प्राप्त करने का एकमात्र मानव प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट जाना है। रूसो का यह विचार शान के दृष्टिम जीवन पर एक बराबर प्रहार था। इस आक्रमण का एक निगाना शान का निर्बुद्ध राजतन्त्र भी था।

मानव प्रकृति का अर्थ

रूसो के अनुसार—"मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है किन्तु सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहुत से व्यक्ति अपने आरक्षी दूतों का स्वामी समझते हैं, तथापि वे दूतों की सेवा करें अधिक पर्याप्त हैं।"² मैकिवावेनो तथा होम्स जैसे विचारकों की यह धारणा रही थी कि मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट होता है कि मनुष्य की कला का उद्देश्य उसे उसकी दुष्ट प्रकृति में सुनिहिताना है। इसके विपरीत प्लेटो और रूसो की यह धारणा है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है, इसलिए मनुष्य कला का उद्देश्य उसकी स्वाभाविक अच्छाई का विकास

1. *His Social Pact*—"It is not as commonly supposed, a thing that we all signed long ago to start the first Society. It is what we must sign now, if we are to have the right one. It is not history, but may some day become history."—Wright, *Cleaning of Rousseau*, p. 71.

2. "Man is born free and everywhere he is in chains. Many men believe themselves the master of others, and yet he is a greater slave than they."—Rousseau.

करता है। स्वामी का विश्वास था कि समाज में पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि वह पूर्ण रूप से गलत एवं भ्रष्ट सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। एक मनुष्य कभी तथा मनुष्यता ने उसे पप भ्रष्ट कर दिया है। स्वामी मानते थे स्वभाव की दो चीजों का नियामक प्रवृत्तियाँ बताता है, जिन्हें स्वामी का उत्तर नष्ट नष्ट जा सकता है। प्रवृत्ति है—आत्म प्रतिरक्षण की भावना। अर्थात् "मनुष्य का प्रथम कानून स्वयं अपनी प्रतिरक्षा करना है, उसे सबसे पहिले स्वयं अपनी रक्षा रहनी है।"¹ दूसरी प्रवृत्ति है सहानुभूति अथवा परस्पर गहामता की भावना जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है, और मनुष्य को दूसरों की गति का सामाज्य प्रण है। क्योंकि ये भावनाएँ मूल हैं इसलिए स्वभावतया मनुष्य को अच्छा ही माना जाता चाहिये। परन्तु परिवारिक रिश्तों की दृष्टि से सभी-सभी ऐसे कार्यों की भाग करती है जो कि समाज के हितों से सातमेन नष्ट होता है। दोनों भावनाएँ पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं की जा सकती। इसलिए व्यक्ति इनमें समझौता करने के लिए विवक्षित होता है। इस प्रकार के निरन्तर समझौता ही एक नैतिक भावना उत्पन्न होती है जिसे अन्तःकरण (Conscience) कहा जाता है। अन्तःकरण बुद्धि तथा विज्ञान दोनों से प्रभावित है। यह प्रवृत्ति का उत्तर है। अन्तःकरण केवल एक नैतिक शक्ति है, नैतिक मार्गदर्शन नहीं। मार्ग-दर्शन के लिए मनुष्य का एक दूसरी शक्ति पर निर्भर करना पड़ता है जो कि उचित विकसित होती है और वह शक्ति है विवेक। विवेक व्यक्ति को यह सिखाता है कि उसे क्या करना चाहिए, किन्तु उसमें वह उस कार्य का क्या नहीं करता। मर्यादों की ओर प्रवृत्त करने वाला एकमात्र अन्तःकरण है। स्वामी ने विवेक की अन्तःकरण अन्तःकरण का अधिक महत्त्व दिया ता उसका कारण यही था कि उसने मनुष्य में अन्तःकरण की बहुत उम्मीदों की जा रही थी।

स्वामी का विवेक और विज्ञान के विरुद्ध विरोध

स्वामी ने विवेक पर आशय किया है। उन्हीं बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान का विरोध किया और इनके स्थान पर मनुष्यता की ओर ध्यान का प्रतिष्ठित किया है। स्वामी ने अन्तःकरण बुद्धि अन्तःकरण है, क्योंकि वह अच्छा का क्या करती है, विज्ञान विज्ञान है क्योंकि यह विश्वास की नष्ट करना है, विवेक युक्त है क्योंकि वह नैतिक मनुष्य ज्ञान के विरोध में सर्व-विवर्तकों को प्रमाणित करता है। विज्ञान को केवल अन्तःकरण का आधार नहीं मान्य रखना चाहिए जिसमें कि वह हृदय की प्रेरणाओं, धर्म तथा नैतिक शिक्षा को मुक्तान में पहुँचा सके।

1. "His first law is to attend to his own preservation, his first cares are those which he owes to himself."

रूसो के राजनैतिक दर्शन का आरम्भ विवेक के विरोध में नैतिक भावों की प्रतिष्ठा के साथ हुआ था। रूसो का विश्वास था कि नैतिक मनुष्य अपने गुणवत्तम रूप में सामान्य लोगों के बीच ही पाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने एनीस में कहा है कि—
 “सामान्य लोग ही मानव जाति का निर्माण करते हैं। जो चीज लोगों में सम्बन्ध नहीं रखती उस पर ध्यान नहीं देना चाहिये। मनुष्य सभी श्रेणियों में एक ना रहता है। अतः जिस श्रेणी के मनुष्य सबसे अधिक हों, हमें उसी श्रेणी का सबसे अधिक आदर करना चाहिए।”¹

प्रकृति और सरल जीवन

रूसो के अनुसार विज्ञानों की बर्चा करने वाला मनुष्यवादी मनुष्य प्रकृति में नहीं पाया जाता। वह केवल विज्ञान समाज में ही पाया जाता है। दार्शनिक इस बात को प्रचुरी तथ्य जानते हैं कि—“तन्दन प्रपञ्च पेरिस का नागरिक बना है लेकिन वे यह नहीं जानते कि मनुष्य क्या है?”² वास्तव में प्राकृतिक मनुष्य वन है, उस प्रसन्न का स्वर इतिहास के प्रान्त नहीं किया जा सकता। रूसो के विचार में प्राकृतिक मनुष्य केवल स्वतन्त्रता की वस्तु है क्योंकि स्वार्थ रक्षित, दूसरे के विचारों के प्रति आदर, कृता, गुण, दायित्व, अर्थ, दान्यद तथा पशु स्नेह ये सभी बातें केवल मनुष्यों में ही पाई जाती हैं, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है जो छोटे-बड़े मनुष्यों में निरन्तर रहते हैं। कोई भी समाज पूर्ण रूप से सहजकृति पर आधारित नहीं होता। रूसो ने यह एक तर्क ऐसा दिया है जो दुष्टि की दृष्टि में विस्तृत समन्वय था। उनकी रचनाओं में सामाजिक संविदा की अंशता निरन्तरवाद अधिक पाया जाता है। उनका यह विश्वास हो गया था कि एकजनीन जीवन समाज औरत का एक मानव मात्र है—एक वर्ग दक्षिण है या दूनप प्रसार। अधिक शोषण का परिणाम अनिवार्यतः राजनैतिक निर्दुष्टता होता है। रूसो ने इस विज्ञान समाज के विरोध में एक आदर्श रूप में सरल समाज की स्थापना का स्वप्न प्रस्तुत किया।

रूसो के चिन्तन में राज्य का महत्व

“राजनैतिक समाज अपनी दृष्टि में स्वयं एक नैतिक दृष्टि भी है और यह सामान्य-दृष्टि जो सर्व ही मनुष्यों तथा प्रत्येक भाग की रक्षा तथा सम्पत्ति के लिए प्रेरित होती है और विधियों का स्रोत होती है, राज्य के समस्त सदस्यों के लिए न्याय और सम्मान बना है, इस नियम का निर्माण करती है।”³ रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतन्त्रता होने केवल राज्य की मददगार है ही प्राप्त हो सकती है। राज्य ने स्वयं रहकर हमें ‘हम’ तथा परिमित पशु’ ही देने रहते हैं और हमारे

1. Quoted by Morley, “Rousseau” (1885) Vol. II, PP.

2. 226 f. L'état de guerre, Vaughan Vol. I P. 37.

3. Vaughan Vol. I, P. 241.

कार्यों को कोई नैतिक गुण प्राप्त नहीं होता । राज्य की सदस्यता के कारण ही शारीरिक प्रवृत्तियाँ के स्थान पर कर्तव्यशीलता प्रतिष्ठित होती है और मनुष्य अपनी प्रवृत्तियाँ के साथ-से-सुकरने से पूर्व अपनी बुद्धि की बाणी सुनने लगता है ।

रूसो डिक्लोज़मेंट में इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता था कि मनुष्य ने अपने प्रथम समाज का निर्माण किस प्रकार किया ? उसने लिए अपने यह कल्प-तत्त्व (Hypothesis) प्रस्तुत किया कि राज्य का जन्म सम्भवतः इसीलिए हुआ कि कुछ बानाक व्यक्तियों ने जो कि धनाढ्य बन गये थे और जो गरीबों के ऊपर अपने प्रभुत्व की माँग तथा घमट बनाना चाहते थे अपनी बुद्धि द्वारा गरीबों को राज्य की स्थापना में उनके साथ सहाय्य करने के लिए बहका लिया । प्रकट रूप से राज्य का उद्देश्य महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को सयत रखना तथा गरीबों की रक्षा करना बताया गया है । इस प्रकार के समाज की स्थापना के परिणाम अधिकतर बुरे निकलें । इसीलिए रूसो मनुष्य की प्रकृति के सरल जीवन की ओर लौट जाने का परामर्श देता है ।

सामाजिक समझौता (Social Contract)

रूसो के सामाजिक समझौते का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है कि प्रथम राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई । यह राज्य के मूल स्वतन्त्र की समीक्षा कर रहा है और उसमें इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि एक सार्वभौम समाज की किस प्रकार संगठित किया जाये, जिससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राज्याधिकार में सगति स्थापित की जा सके । इस प्रकार के समाज की रचना की पद्धति थी—'सामाजिक सन्धि' । रूसो की युक्ति यह है कि केवल वही समाज, जो अपनी कल्पना की सामाजिक सन्धि पर आधारित हो, अपने सदस्यों को वह नैतिक स्वतन्त्रता और सुरक्षा प्रदान कर सकता है जो कि बुद्धि के अनुसार आवश्यक करने से प्राप्त होती है । राजकीय विधि व्यवस्था का पत्न है । रूसो पर सन्धि का प्रभाव इसीलिए पड़ा क्योंकि उसने समय के बौद्धिक बानाकरण का सामाजिक सन्धि सिद्धान्त का आविष्कार महत्वपूर्ण भंग था ।

हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्ये तथा फेल्डरॉफ़ गरीबों के विचारों ने इस सन्धि सिद्धान्त को पहिले ही जनप्रिय बना दिया था । परन्तु रूसो जिस परिणामों पर पहुँचा उसमें इसकी संगति नहीं बैठती । वह इसे समाज के सिद्ध व्यक्तियों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता का आधार नहीं मानता । वह सर्वोच्च शासन की सन्धि पर आधारित नहीं करता जैसा कि लॉक ने किया था । रूसो के हाथ में सन्धि सिद्धान्त राज्य की व्यक्तिवाद की धारणा का पोषण नहीं करता । निम्न-लिखित यह बात धारण करने पर है कि रूसो सन्धि सिद्धान्त द्वारा इस परिणाम पर पहुँचा कि राज्य एक मानवनिर्मित दण्ड है तथा उसका अर्थ एक नैतिक एवं मापदण्ड व्यवस्था है । इस स्थिति में देशांतर का यह कथन कि रूसो का सन्धि सिद्धान्त का प्रयोग अकारण है, बहुत कुछ मार्थर का लगता है ।

मनो के अनुसार सामाजिक सविदा की गतें क्या होनी चाहियें, यह उन बातों पर निर्भर करता है जिसकी शक्ति के विषय व्यक्ति सम्यक् वा निर्माण करते हैं। इस उद्देश्य के दो अंग हैं, प्रथम, मनुष्य समूह इनलिङ्ग बनाने हैं कि करने धन-धन की रक्षा में उन्हें सम्पूर्ण समाज की सहायता प्राप्त हो सके। दूसरे, वे अधिकतम स्वतन्त्रता चाहते हैं। ये दोनों लक्ष्य विरोधाभासी हैं, इसलिए उनकी पूर्ति करने वाले समन्वये की गतें भी उतनी ही विरोधाभासी हानी चाहियें। समन्वय देश काय के विषये केवल एक ही सह-समन्वये हो सकता है। समन्वये की गतें विभिन्न बातों में और विभिन्न समाजों में अलग-अलग नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि हॉम, लॉक तथा अन्य विचारकों द्वारा वर्णित समन्वये की गतें मनो की भाव्य नहीं हो सकती और वह उन्हें आदर्श राज्य के संगठन का आधार नहीं बना सकता।

समन्वये की गतों का वर्णन मनो इन शब्दों में करता है—“हमने ये प्रत्येक करने धीरे-धीरे तथा धनकी सम्पूर्ण शक्ति की मद के साथ मानव्य रूप में ‘सामान्य प्रवृत्ति’ के सर्वोच्च निर्वहन में रक्त देना है और करने सामाजिक स्वभाव में हम प्रत्येक मनुष्य की सम्पूर्ण के एक अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। समन्वय व्यक्तियों के संगठन में बने हुए इस आर्थिक व्यक्ति की पहिले स्तर कहते हैं। अब उसे गुरुत्व्य करते हैं। अब यह निश्चित रहता है दो इसे राज्य कहते हैं और अब यह सक्रिय हो जाता है तो संगठन। ऐसे ही अन्य निष्कर्षों में इसकी तुलना करने पर इसे शक्ति कहा जाता है।”

उपरोक्त सामाजिक सविदा के क्रियाशील एवं केन्द्रीय भाग का अर्थ यह है कि समाज का प्रत्येक मनुष्य करने समन्वय अधिकार सम्पूर्ण समाज की समन्वित कर देता है। इसके इस समन्वय में प्रत्येक की मान होता है और हानि किसी को नहीं होती। हानि इसलिए नहीं होती कि करने करने के प्रति समन्वित करने में व्यक्ति किसी एक के प्रति समन्वय नहीं करता और जो कुछ भी वह मद को देना है, उसे वह सम्पूर्ण का एक अविभाज्य अङ्ग होने के लिये वापिस पा लेता है। किसी भी मनुष्य को विन्मो-पिहार प्राप्त नहीं होते और मद का स्थान समान होता है। इस प्रकार मनो के राज्य में न्यायिक की स्वतन्त्रता तथा समानता प्राप्त होती है।

मनो के अनुसार सविदा व्यक्ति के दो स्वभावों के मध्य होती है। मनुष्य एक ही साथ निष्क्रिय प्रकाशन भी है और क्रियाशील संगठन भी। एक संगठनार्थ मध्य का मनुष्य होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति उन्मा स्वतन्त्र नहीं रहता है जिसका कि वह पहिले था, बल्कि उसकी स्वतन्त्रता और भी अधिक बढ़ जाती है तथा सुरक्षित बन जाती है। मनो के समन्वये में उद्भव होने वाले समाज का स्वभाव सावयविक (Organic) है, हॉम या लॉक की धारणा के समाज के मनुष्य व्यक्तिवादी नहीं। समन्वये एक ऐतिहासिक तथा सामाजिक शक्ति का निर्माण करता है जिसका करने लिये जीवन है,

अपनी निजी इच्छा तथा अपना निजी अस्तित्व है। रूसो इसे सार्वजनिक ध्वनि (Public Person) कह कर पुकारता है।

संविदा के महत्व को बतानाते हुए रूसो कहता है कि जो चीज मनुष्य को पशुधारा के स्तर से ऊपर उठाती है और उसे सवसुत्र मानव बनाती है, वह है उसकी राज्य की सदस्यता। इसके द्वारा ही मनुष्य में भावनाओं में स्थान पर जनधर्म की प्रतिष्ठा होती है और यही इसके बायीं हाथ नैतिक गुण प्रदान करती है, जो कि उसमें पहिले नहीं थे। सामाजिक संविदा से पूर्व 'उसके पास उन वस्तुओं पर जिन्हें कि वे अपनी कहने का साहस करते थे, एक अस्थिर अधिपत्य था। संविदा के उपरान्त उन्हें अपनी सम्पत्ति पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

प्राकृतिक अवस्था (State of Nature)

रूसो के विचार में मानव में दो तरह की असमानता होती है, पहली नारीतिक या प्राकृतिक और दूसरी नैतिक तथा राजनीतिक। प्राकृतिक असमानता प्राकृतिक राज्य में पाई जाती है। यहाँ नैतिक और राजनीतिक असमानता नहीं थी। प्राकृतिक राज्य में मनुष्य अवैराग्य रहता था। उसका जीवन स्वतन्त्रतापूर्ण था। उस समय न संघर्ष था न प्रतियोगिता। प्राकृतिक स्थिति न तो नीतिवादी ही था और न दुष्ट ही। वह दुःखी नहीं था, लेकिन वह गुपी भी नहीं था। स्पष्ट है कि उसमें पाम सम्पत्ति भी नहीं थी। उसमें इतना साहस भी नहीं था कि वह दूसरों से लड़ता। प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने मानव में दो मूल प्रवृत्तियों को पाया। प्रथम यह कि मानव स्वयं को प्यार करना है और इसलिए वह शांति बनाये रखता है। दूसरे उसमें सहयोग की भावना होती है इसलिए वह अपने साविदा में नहीं लड़ता। रूसो का मानव हान्य की संघर्षमय प्राकृतिक अवस्था में नहीं रहता। उस का प्राकृतिक राज्य एक शांतिपूर्ण राज्य था। परन्तु यह मानव विकास की स्थिति नहीं थी, क्योंकि उन अवस्था में मानव एक दूसरे से अलग रहने थे और जब तक वह दूसरों से मिलकर नहीं रहने तक तक उनका विकास नहीं हो सकता।

समाज (Civil Society)

रूसो यह मानता है कि प्राकृतिक राज्य और नागरिक समाज के बीच एक अन्तरिम समय था। इस अवस्था में मानव साथ मिलकर कार्य करने लगे थे। परन्तु इस अवस्था में संगठित समाज नहीं था। यह सम्पर्क की स्थिति थी। परन्तु इस समय में तीन प्रक्रियायें आरम्भ हो चुकी थी। पहली सुनना की प्रक्रिया, दूसरी प्रतिभागिता की और तीसरी मनोवैज्ञानिक स्तर पर असमानता की। इस अन्तरिम अवस्था में मानव ने एक दूसरे पर निर्भर होना सीखा। यह समाज स्वार्थी, लाचरी और दुर्गुण पर आधारित था। यही है नागरिक समाज (Civil Society) का आरम्भ होता है। नागरिक समाज में सम्पत्ति की समस्या सामने आई। इस समय मानव सम्पत्ति को प्यार करने लगा। इसका विकास हुआ और इस कारण मनुष्यों ने सम्पत्ति की ओर ध्वि

मान दिया। कुछ व्यक्तियों ने भूमि पर अधिकार कर लिया और कुछ व्यक्तियों ने उनके भूमि-स्वामित्व को स्वीकार किया। यही के सामुद्र में नागरिक समाज का आरम्भ होता है। इस समाज में दो वर्ग उत्पन्न हुए; धनी और गरीब। परन्तु धनी व्यक्तियों को यह दिव्यता मालूम लगी कि बिना भूमि पर उन्होंने अधिकार किया है वह उनकी नहीं है। बाद के इतिहासी हैं परन्तु कुछ समय बाद निर्धन एकत्रित होकर नागरिकता बन गये हैं। धनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने राज्य और सरकार की स्थापना करनी चाही। इसलिए, सभी के समुदाय राज्य का जन्म कुछ व्यक्तियों ने (जो कि समाज बन गये थे और जो गरीबों के ऊपर अपने समुदाय की मांग तथा धनर दाना चाहते थे), धनी व्यक्तियों द्वारा गरीबों की राज्य की स्थापना में उनके साथ सहयोग करने के लिए सहकार कर दिया।

सभी की सामान्य इच्छा (General Will)

सभी के विचार में सबसे महत्वपूर्ण दो बातें थी—सामान्य इच्छा का विधान और प्राकृतिक अधिकारों की स्थापना। सभी का विश्वास था कि अगर-सत्य ऐसा एक छोटा सा समुदाय सामान्य इच्छा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सभी के सामान्य-इच्छा विधान का उनकी मौखिक संरचना की धारणा के परिणामस्वरूप है।

व्यक्तिगत इच्छा और वास्तविक इच्छा (Actual Will and Real Will)

वैयर्थ्य व्यक्ति होने के नाते हम निम्न समयों पर विभिन्न पक्षों की कामना करते हैं। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं का परस्पर सामंजस्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनकी निश्चित करने वाला उनके जीवन का एक वैयर्थ्य समय न हो और बिनाकी शक्ति द्वारा मनुष्य की पूर्ण संतोष प्राप्त हो सके। हमें हम अपनी वास्तविक इच्छा कह सकते हैं। प्राकृतिक इच्छाओं को, जिन्हें कि मनुष्य समय समय पर करते सामने रहता है, व्यक्तिगत इच्छा कहा जा सकता है। ये इच्छाएँ स्याई रूप में मानव व्यक्तित्व में उत्पन्न-उत्पन्न में उत्पन्न हैं। इस व्यक्तिगत इच्छा की एक विशेषता यह होती है कि वह वास्तविक इच्छा की पूर्ण भाव की दृष्टि नहीं कर सकती और केवल उनकी दृष्टि मात्र के व्यक्ति की पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होता। व्यक्तिगत इच्छा विद्युत ही वास्तविक इच्छा के समान होती है उन्नी ही अधिक मात्र में उनके दृष्टि प्राप्त होती है।

सभी इस बात की जानता था कि एक मनुष्य होने के नाते एक व्यक्ति की इच्छा विभिन्न उनकी व्यक्ति की एक नागरिक होने के नाते सामान्य इच्छा के विपरीत हो सकती है। सभी के शब्दों में—“सामान्य इच्छा में वह बात निहित है कि जो कोई भी सामान्य इच्छा की भाव धारण करने में इंकार करता है उसे सम्पूर्ण समाज द्वारा ऐसा करने के लिए विवश किया जा सकता है।

सामान्य इच्छा तथा ‘मनुष्यिक इच्छा’ में विवेक करने के लिए सभी काही परिश्रम करता है। उम्मा कहना है कि समाज के सम्पूर्ण सदस्यों की इच्छाओं का वृत्त योग सामान्य इच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सम्पूर्ण सदस्यों की इच्छाओं में

मदम्या के व्यक्तिगत हिता का मिश्रण होता है जबकि सामान्य इच्छा का सम्बन्ध केवल सही सामान्य हिता से ही होता है।

सामान्य इच्छा की विशेषतायें

सामान्य इच्छा निराम होना है। रूसो की धारणा है कि यह निराम तब सामान्य इच्छा से दो प्रकार से होता है—प्रथम इसका व्यय सदैव सामान्य हिता होता है और दूसरे यह सदैव जन सेवा भाव से ही प्रेरित होती है। सामान्य इच्छा एकमत होती है क्योंकि इसे अभिव्यक्त करने वाला सप्रभुतापारी निराम एक नैतिक तथा सामूहिक निराम होता है। सामान्य इच्छा को उत्पन्न करने के लिए किसी समाज के समस्त सदस्यों का सर्वसम्मति होना आवश्यक नहीं है। सामान्य इच्छा सदा एक प्रभुत्व होती है क्योंकि वह जन हित के लिए ही होती है और केवल जनमत प्रपञ्च बहुमत उसे जन्म नहीं देता।

सामान्य इच्छा और सप्रभुता

रूसो का सामान्य इच्छा मिथ्यात्व का उमका लोकप्रिय सप्रभुता की धारणा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। लोकप्रिय सप्रभुता मिथ्यात्व का प्रतिपादन वह केवल सामान्य इच्छा मिथ्यात्व से ही करता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सप्रभुतापारी है और इसका सप्रभुता की सभी विशेषतायें भी होती चाहिए। सप्रभुता निराम होती है और इसलिए वह इसे भी निराम मानता है। सप्रभुता अधिभाग्य तथा मर्यादा है और सामान्य इच्छा भी मर्यादा और अधिभाग्य है। सप्रभुता की अधिभाग्य कहने से रूसो का अभिप्राय यह है कि वह सम्पूर्ण समाज में ही रह सकती है। उसे छोड़-छोड़ कर किसी में विभक्त नहीं किया जा सकता जैसा कि सामूहिक बहुतायदी (Pluralists) उसे करना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में भी उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सप्रभुता सम्पन्न नहीं हो सकती। वे तो सामान्य इच्छा के प्रत्यक्षता का पालन करने वाले प्रतिनिधि मात्र हैं। सामान्य इच्छा का कार्य कानून बनाना है उन्हें लागू करना नहीं। इस प्रकार रूसो सप्रभुता सम्पन्न जनता तथा उसके अधिभाग्य और उमर प्रति उत्तरदायी सरकार में विभेद करता है। उसके अनुसार जब तक सामान्य इच्छा सप्रभुता सम्पन्न रहती है तब तक इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि सरकार लोकप्रणी है या कुलीनवादी प्रपञ्च राजप्रणी।

क्या सामान्य इच्छा सम्भव है ?

सामान्य इच्छा किसी भी वास्तविक कथा में हो वह संभव नहीं हो सकती। उमका यह निराकार स्वरूप उसे विशेषण का अत्यन्त कठिन बना देता है। रूसो का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना था, तथापि उमका मिथ्यात्व बहुमतवादी का पोषण बन गया। बहुमत से बहुमत बन जाने वाला व्यक्ति का वह बहुमत के सामने खड़े होने के लिए तैयार रहता है। रूसो के मिथ्यात्व में व्यक्ति मरने

समस्त प्रतिभाओं तथा शक्तियों को सामान्य इच्छा के नाम से सम्मिलित कर देता है, जो कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में शासन करती है। निम्नलिखित व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी-
 तरफ की व्यवस्था नहीं करना। सामान्य इच्छा के निवास-स्थान के विषय में उनकी
 प्रतिनिधित्वता निम्नलिखित एक सम्बन्धिता है। कर्मों के विधान न मुख्य कठिनाई यह है
 कि सामान्य इच्छा का दर्शन सम्भव है और स्वयं कर्मों की इस विषय में पूर्ण रूप से
 निरविवश नहीं है।

महर्षि मुनि 'महाभारत' में कर्मों विभिन्न रूप परस्पर विरोधी करते कहता
 है। कर्मों की इसका अर्थ यह दिखाने वाला है कि सामान्य इच्छा वस्तुतः की इच्छा
 है, निम्न वस्तु में भी वह सामान्य इच्छा के सम्मिलित नहीं मानता। कुछ स्थानों
 पर वह यह नमिष्ट करता है कि परिणाम में एकत्रित वस्तुओं में नष्ट की विभिन्नताएँ
 जब एक दूसरे के विरोधी नहीं हो जाते हैं और उनके फलस्वरूप भी पैदा रहता है वह
 सामान्य इच्छा है। और वे सामान्य इच्छा की कार्यविधि करते हुए बिना है कि हमें
 बताया जाता है कि सामान्य इच्छा में विनियमितता की महत्त्व होती है वह सम्पूर्ण
 राज्य की व्यवस्था होती है। एक व्यवस्था राज्य ही सम्पादित हो सकता है।
 इसके विरोध एक निरंकुश शासक करने प्रत्येक व्यवस्था प्रदान कर
 सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि राज्य स्वयं करने की व्यवस्था बनाने में
 करने वालों की शक्त नहीं बना करेगा।¹ कर्मों की सामान्य इच्छा निम्नलिखित
 एक सम्माननक धारणा है। उनकी सम्पूर्ण शक्ति "एक हार्दिक वचन है, वह
 एक ऐसा दर्शन है जो लोगों की पृथक्-पृथक् तथा परिणामों की विपदा के ऊपर राज्य
 में बनाने जाती है। कर्मों के सामान्य इच्छा के निवास का सामाजिक रूप यह है कि
 वस्तु आवेगविक रूप वस्तु संनिष्ठ है। उनकी धारणा धर्म-धर्म के लिए लोगों में ही
 पूरी हो सकती है। मात्र के सम्पूर्ण लोगों में रहा कि प्रभुत्वमान मनोभावों का स्पष्ट
 प्रतिनिधि पाठ्यक्रमों के विचार है, इस दर्शन का निवास नहीं हो सकता। कर्मों के
 प्रभुत्व यदि प्रतिनिधि सरकार सामान्य इच्छा की शक्ति करके तो वह प्रतिनिधि
 कर्मों की सामान्य इच्छा होगी, सम्पूर्ण मनोभावों की नहीं।

प्रतिनिधि के निवास का कर्मों द्वारा विचार और वीर्य की शक्तों में
 कार्य विचार बनाना है। कर्मों का यह है तो इच्छा सर्व स्वयं संचालन का
 विचार करना है। सामान्य इच्छा का निवास सरकार के महत्व की बात
 करता है। कर्मों का कहना है कि सर्व, देव-मनुष्य, सामाजिक रूप करने के अनुसार
 मनोभावों की सामान्य इच्छा के विचारों में एक सम्मानन का धारणा है। सामाजिक रूप
 में यदि मनोभाव के जीवन में स्वच्छता के अनुसार एक महत्त्वपूर्ण रूप देने की है,
 इन निवास के मुख्य और भी बन हो जाता है।

रूसो की परस्पर विरोधी व्याख्याएं

रूसो प्रेच क्रांति का सबसे प्रमुख तथा महानतम बौद्धिक संदेशवाहक था। अपनी सबल एवं मौलिक प्रतिभा की ध्याप उसने राजनीति, शिक्षा, धर्म, साहित्य सभी पर छोड़ी है। लेखन के अनुसार प्राधुनिक युग की साने वाले सभी मार्गों के द्वार पर हम उसे खड़ा हुआ पाते हैं। परन्तु किन्ती विलक्षण बात है कि समाजवादी में जितनी मत-विनिमयता रूसो के विषय में है उतनी बद्राविन् ही अन्य किसी दार्शनिक के विषय में रही हो। मालें का तो यहां तक कहना है कि सोचना तो उसने सभी सीधा ही नहीं था। यदि बर्क को रूसो का कल्प विकल्प मूल्यहीन दिखाई पड़ा तो वाग्ट को उसमें 'बुद्धि के अनुपम गाम्भीर्य' के दर्शन हुए। रूसो एक अत्यधिक विरोधाभासी चिन्तक है। प्रकृति की ओर लौट चलने के उसने आवाहन का अर्थ यह लगाया जाता है कि उन समस्त सुखों को त्याग दिया जाय जिन्हें सम्पत्ता ने सपरिश्रम प्राप्त किया है। इसके विपरीत कुछ विचारकों की धारणा यह है कि रूसो एक उच्चतर सभ्रुति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। सातवीं मानता है कि रूसो का प्रगति में उत्कट विश्वास था। कुछ व्यक्तियों के मतानुसार रूसो एक पूर्ण व्यक्तिवादी था क्योंकि वह व्यक्ति के लिए अधिकतम स्वतन्त्रता चाहता था। दूसरी ओर कुछ के अनुसार वह व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन बना देना चाहता था। एक समय सेल्फ कांस्टेपट का उसके विषय में कहना है कि वह प्रत्येक प्रकार के निरंकुशवाद का सबसे भयंकर मित्र था। वोगां (Vaughan) के अनुसार रूसो एक ओर तो राज्य का घोर समर्थक था किन्तु दूसरी ओर व्यक्ति का तीव्र पोषक, घोर इनमें है किसी भी आदर्श का परिचाय करने को वह तैयार नहीं था। 'डिस्कॉर्सेज' में रूसो सम्पत्ति की माटे संकट का मूल कारण मानता है, किन्तु महाजोप में दिये हुए अपने एक निबन्ध में उसे वह एक पवित्र संस्थान बतलाता है। समस्त मनुष्या के लिए वह सहिष्णुता का उपदेश देता है, किन्तु नास्तिकता का राज्य में बहिष्कार करना है। उसने विवास्तोत्र व्यक्ति की पतिव प्राणी तक वह कर पुकारा है। एक ओर तो वह प्रजासत्त का समर्थक है पर दूसरी जगह सौन-सत्त का अस्मिताधिक वह कर वह उसका समर्थन भी करता है। रूसो का यह मत है कि जब तक सामान्य इच्छा सम्प्रभुता-सम्पन्न रहती है तब तक हम बात में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि सरकार सौनसत्ती है, कुलीनसत्ती अथवा राजसत्ती। वह एक ओर जबकि पार्सवाद का पड़ता विचारक कहा जा सकता है तो दूसरी ओर उसे 'सुपर टू हिटनर' नामक पुस्तक में पामिस्म ओर नासिस्म का जन्मदाता कहा गया है। एक ओर उसने विवेक की मान्यता की है किन्तु दूसरी ओर विवेक को एक पवित्र स्थान भी उन्हीं के दर्शन में मिला है।

रूसो एक व्यक्तियुक्त राजनीतिक विचारक नहीं है। उसने अपने विचारों का विरमेषण करने में काफी स्थान रिक्त छोड़ा है। यह मान्यता

की जाती है कि जिस विश्व में वह रहता था उसके बड़े राष्ट्रीय राज्यों के लिए उसने विचार नहीं किया। उसके आदर्श छोटे-छोटे नगर राज्यों पर ही लागू हो सकते थे।

हॉब्स और हांस्

हॉब्स और हॉम्स दोनों ही सामाजिक सविदा विद्वान् के मुख्य विचारक हैं पर दोनों में आधारभूत अन्तर पाये जाते हैं। हांस् ने प्राकृतिक अवस्थाओं का और समझने का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, जिसका अन्त के लेखों में पर्याप्त प्रभाव है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त के मन्त्रिण में सविदा विद्वान् का स्थान केवल घोण है। हांस् के मतानुसार व्यक्ति अपनी शक्तियाँ का समर्पण एक व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह को करता है, जिसने सविदा में कार्य भाग नहीं लिया बल्कि वह उससे बाहर है। किन्तु अन्त के अनुसार व्यक्ति अपने प्राण की सम्पूर्ण समाज को समर्पित करता है। ऐसा करने से व्यक्ति जो कुछ देता है वह उस संप्रभुता सम्पन्न समाज का घटक होने के नाते पुनः प्राप्त कर लेता है। इसीलिए राज्य में भी वह उतना ही स्वतन्त्र रहता है, जितना कि वह प्राकृतिक अवस्था में था। हांस् में यह समर्पण एक बाहर के व्यक्ति को होता है जो प्रजापति का स्वामी बन जाता है और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता। हांस् यह दावा नहीं कर सकता कि सविदा के उपरान्त भी व्यक्ति उतना ही स्वतन्त्र रह जाता है जितना कि वह पहले था। फिर हांस् की प्राकृतिक अवस्था संश्लेषण है। उसने व्यक्ति को स्वार्थी, मानवी और अनाद्य बतलाया है। परन्तु अन्त की प्राकृतिक अवस्था शान्तिमय है। उसने नैतिक तथा राजनीतिक मान्यताएँ नहीं पाईं जहाँ। उसके अनुसार मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ प्राकृतिक अवस्था में थी—स्वार्थ की अतिरिक्त रहने की इच्छा और दूसरों के साथ सहयोग और सहानुभूति की भावना। अन्त प्रजापति का समर्पण दिखाई देता है परन्तु वास्तव में वह भी हांस् की तरह निर्दुःखता का प्रजापति बन जाता है। अन्त का महार-देव (Leviathan) सम्पूर्ण समाज है, जब कि हांस् का केवल एक व्यक्ति। अन्त में संप्रभुता सम्पन्न राज्य तथा सरकार में भेद है जब कि हांस् में वे शान्ति एवं हो गये हैं।

हॉब्स और लॉक

अन्त और लॉक के विचार में भी इसी तरह के महत्वपूर्ण अन्तर पाये जाते हैं। लॉक की हांस् की तरह सामाजिक समझौता का विचार पूर्वक वर्णन करता है। उसने समझौता अवस्थाओं में माना है। सरकार समझौते में भाग नहीं लेती इसीलिए वह जनता को निर्णायक न मानकर उसके लिए एक दृष्टि के रूप में है। अन्त के अनुसार समझौता एक वास्तविक वस्तु है। वह समझौते के अनुसार राज्य की स्थापना के विषय में चिन्तित नहीं दिखाई देता। लॉक का विचार सम्पन्न है। वेला के अनुसार—“व्यक्तिगत अपने दर्शन का आधार है। परन्तु अन्त के दर्शन में व्यक्तिगत दिखावा मान्य है। लॉक का दर्शन

व्यावहारिक और उपयोगी है परन्तु रूसो का दर्शन अन्तर्मनोवैयक्तिक और विरोधाभासी है। लॉक ने सरकार को ट्रस्ट कहा है, जिसकी शक्तियाँ धरोहर के रूप में हैं। रूसो मनुष्यता-सम्पन्न जनता की अपनी व्यवस्थान्वित सम्बन्धी शक्तियों को किसी प्रतिनिधि निधाय के पक्ष में हस्तांतरित करने का निवेद्य करता है। लॉक के अनुसार व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रयोग साधारणतया जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिए जबकि रूसो संसदात्मक संस्थाओं का विरोध करता है और उन प्रत्यक्ष जनतन्त्र का समर्थन करता है, जिसमें न प्रतिनिधि हैं और न दल। उसका यह सिद्धान्त प्राचीन नगर राज्यों पर ही लागू हो सकता है। आधुनिक प्रजातन्त्र के लिए लॉक को शिष्टार ही अधिक उपयोगी लगते हैं। लॉक नैतिक राजतन्त्र का पक्षपाती था। वह निरंकुश राजतन्त्र में विश्वास नहीं करता। दूसरी ओर रूसो सामाज्य इच्छा सिद्धान्त के द्वारा लोकतन्त्र प्रभुत्व का समर्थन करता है परन्तु अन्ततः उसका सामाज्य इच्छा सिद्धान्त निरंकुश राजतन्त्र का पक्षपात बन जाता है।

BIBLIOGRAPHY

1. VAUGHAN : *Studies in the History of Political Theory*
2. ROUSSEAU : *Social Contract*.
3. COLE : *Rousseau*

‘ग्रीन-एक उदार आदर्शवादी’

(GREEN—A SOBER IDEALIST)

—रामलाल बस्वा

ग्रीन के आदर्शवाद को उन्नीसवीं शताब्दी के हीगनवादी दार्शनिक दलवाद के विद्वद् एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहा जाता है। ग्रीन से पूर्व भी अनिपन्निष्ठ दलवाद (Laissez faire Policy) के विद्वद् दलवादी विचारणा का दबदबा हो चुका था किन्तु यह केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित था। अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में यह विचारणा उदार नहीं थी, अन्तः इतनी नोकरीय नहीं हो पाई। ग्रीन का महत्व इस बात में है कि हमने उस उदारवादी प्रवृत्ति को जो प्रचार में परिवर्तित कर अधिक शक्ति बनाया—एक ओर हमने राजनीतिक क्षेत्र में हीगन के अनावादी दल (Authoritarian element) का विरोध किया, दूसरी ओर हमने उसे इंग्लैंड की सर्वपान्थिक परम्पराओं में डाला। हमने हीगन की उस अन्तरेवना का कि हमने एक वर्ग के हितों की ही प्रशान्ता है और हीगन की स्वतन्त्रता विषयक धारणा ऐसी है जो मानाधिक शक्ति एवं सुरक्षा की ओर झिझक घमान नहीं देती। हमने दलवादी होने का भी पूर्ण निपन्त्रण एवं अनिपन्निष्ठ स्थिति की सम्भवनी विचारणा प्रदर्शित। ग्रीन द्वारा दिये गये दलवाद के इस संश्लेष को ही उदार आदर्शवाद (Sober Idealism) कहा जाता है। इसे नव हीगनवाद (Neo Hegalism) भी कहा जाता है।

राज्य का आदर्शवादी सिद्धान्त राज्य का एक आदर्श विषय प्रस्तुत करता है। बड़े Ideal का आर्थिक अर्थ विचार सम्बन्धी होता है—दरन्तु प्लेटो ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पूर्णतया विचार में ही सम्भव है और हम जगत की सभी वस्तुओं प्रभु हैं। इसीसे Idealism का सम्बन्ध राज्य के आदर्शिक स्वप्न से न होकर सर्वोत्कृष्ट अथवा आदर्श राज्य से है। बरी कारण है कि इस दर्शन में राज्य का स्थान देविक मन्त्रा तक पहुँच गया है। विचार-प्रपात अथवा दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रशान्ता होने के कारण ही बोलार्थ ने उसे ‘राज्य का दार्शनिक सिद्धान्त’, होब्स-हाउस ने ‘आध्यात्मिक सिद्धान्त’, वॉट ने ‘निष्पक्षतावादी सिद्धान्त’ तथा मैकफार्लर ने ‘रूपवादी सिद्धान्त’ कह कर पुकारा है। हीगन तथा उनके कुछ अन्तः प्रवृत्तियों के लेखों में इस सिद्धान्त ने जो रूप प्रदत्त किया है उसे देखने का आदर्शवाद के दलवाद

नाम उचित ठहराये जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने राज्य को पूर्ण विवेक (Perfect reason) का प्रयोगकर्ता एवं एक नैतिक मन्त्रा मान कर व्यक्ति को पूर्णतया उनका आधीन बना दिया है। परन्तु उक्तोक्त मन्त्राये घोस ने उदारवादी आदर्शवाद के लिये उचित नहीं ठहराया। यद्यपि आदर्शवाद का उदारवादी एवं व्यावहारिक मध्यमार्गी स्वरूप एक अन्तरविरोध (Contradiction) का प्रतीत होता है किन्तु घोस ने धन दर्शन में इन दो प्रवृत्तियों का सुन्दर सामंजस्य कर आदर्शवाद को व्यावहारिक एवं प्राक्क बनाया। यही घोस अपनी राजनीति परिस्थितियाँ एवं राजनीय विनियमावली में प्रभावित लगता है।

जर्मन आदर्शवादियों ने विचार एवं ऊँचे धरातल पर चल कर दुर्बोध एवं शोभित हमलिये बन जाते हैं कि उन समय जर्मनी के विभाजित होने के कारण मुख्य समस्या एकीकरण थी। बाँट तथा हीनता आदि ने राज्य का एक चरमवादी मित्रान्त (Absolute theory) प्रस्तुत किया। जर्मन साम्राज्य को सङ्गठित एवं सुदृढ़ बनाने के लिये जर्मन आदर्शवादियों ने राज्य की सर्वगन्तिमत्ता एवं सर्व गुण सम्पन्नता का पक्ष लिया और उसे सभी क्षेत्रों में निरन्तर बना कर व्यक्ति को बहुत ही महत्वहीन बना दिया। परन्तु इंग्लैंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों किन्तुल मित्र थी। उस समय तक इंग्लैंड एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित कर रहा था तथा दीर्घपूर्व क्रान्ति द्वारा वहाँ उदारवादी चलन बन चुके थे। धन ऐसी परिस्थितियों में घोस जैसे प्रमुख आदर्शवादी के लिये बहु सम्भव नहीं था कि वह जर्मन निरन्तरतावादी प्रवृत्तियों को गया का ल्यों स्वीकार कर लेता। था। उसने अपनी राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुकूल आदर्शवाद को एक उदारवादी स्वरूप दिया। इन परिस्थितियों में घोस ने समय प्रवर्तित उपयोगितावादी विकासवादी एवं व्यक्तिवादी विचारधाराएँ जहाँ चरम भौतिकवादी दर्शन (Materialistic Rationalism) बन चुकी थी वही दूसरी ओर हीनता का दर्शन चरम आदर्शवादी दर्शन (Extreme Idealism) था। स्वभावतः घोस ने व्यावहारिक एवं मध्यमार्गी दर्शन की अवश्यकता प्रमाणित की।

घोस एक औद्योगिक आर्थिकवादी दर्शनिक था। उसने इन परिस्थितियों में हीनता के इस मित्रान्त को पूर्णतया दोषपूर्ण पाया कि व्यक्ति की परिपूर्णता राज्य में ही सम्भव है। घोस ने अपनी दूर-निरीक्षण शक्ति के आधार पर यह पाया कि राज्य कारणात्तों व पैरामितियों में अन्तर्भूत व शोषण को दूर करने में असमर्थ है। वह उन्हें सामंजस्य की परिस्थितियों में प्रगट नहीं करता था। धन उसने समाज में व्यक्ति के सामंजस्य विकास में कोई योगदान नहीं था। एक स्थान पर घोस ने कहा है—
 ६८८ के किसी अनेक नागरिकों का इंग्लैंड की सम्पत्ति में उन्नीस प्रतिशत कोई भाग नहीं है किन्तु कि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति में एक पाय का पा। इसी राज्य की प्रतिनिधिता

स्वयं हीन ने राज्य के स्वयंसाध्य (An end in itself) स्वरूप को प्रतीकार कर दिया और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा-हेतु राज्य की सर्वशक्तिमत्ता पर बुद्ध भीमापे मगार्दे हैं।

इस प्रकार हीन जेसन आदर्शवादियों की भांति आन्ध्रकारिक एवं अनुनय पुण्य दार्शनिक मात्र (Armchair Philosopher) नहीं था जो केवल कल्पना ही उठाने भरवा, इसके विपरीत उसने अपने दर्शन की ठोस मर्याद में सम्बद्ध किया है। इस प्रसंग में स्कोल्ड मेर ने कहा है "हीन ने आदर्शवाद की दार्शनिक पतवार को एक दिव्य नवीन दिशा की ओर घुमाया और यह दिशा थी उसकी यथार्थानुष्ठी आदर्शवादी दिशा (Sober Idealism)।" यदि हीन की पुस्तक—"Lecture on the Principles of Political Obligation" में वर्णित राज्य, स्वतन्त्रता, अधिकार, पुत्र, दण्ड आदि में सम्बन्धित उसके विचारों पर दृष्टिगत किया जाये तो उसका यह यथार्थानुष्ठी उदार आदर्शवादी स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है—

राज्य एवं उसके कार्य

हीन राज्य की मानव चेतना (Human conscience) की उपर मानता है। बार्कर के शब्दों में वह अपनी इस मान्यता के पक्ष में इस प्रकार तर्क देता है — "मानव चेतना स्वतन्त्रता की इच्छा रखती है, स्वतन्त्रता के विषे अधिकार आवश्यक हैं और अधिकार राज्य की सेवा करते हैं।" 1 कर्मान् हीन मानव चेतना के विकास के विषे स्वतन्त्रता की आवश्यक स्थिति समझता है, परन्तु हीन का स्वतन्त्रता में तात्पर्य केवल बुद्ध इच्छित एवं करने योग्य कार्यों को करने की शक्ति में है न कि प्रत्येक कार्य को करने की शक्ति में। यद्यपि क्रांति का भी इसी मत था कि मनुष्य के साम्य रूप में बने रहने के लिए अन्या स्वतन्त्र रहना आवश्यक है, परन्तु क्रांति की धारणा यह थी कि मनुष्य स्वतन्त्र तब होगा है तब उसकी रक्षा वर्णमय के निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) द्वारा निर्धारित हो। हीन का मत है कि मनुष्य केवल तब स्वतन्त्र कहा जा सकता है जबकि उसकी इच्छा मानने योग्य बन्तु में सम्बन्धित हो और यह निर्धारित करने में राज्य उसकी सहायता करता है। यह ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार हीन क्रांति की स्वतन्त्रता की धारणा राज्य के स्वतन्त्र एक नाचनकाल (Abstract) धारणा है वहीं हीन के हाथों में यह विवेकान्त एवं सम्बन्धित स्वयं में होती है। यह उसकी

1. "Human consciousness postulates liberty, liberty involves rights, and rights demand the state".

यद्यार्थोन्मुखी प्रकृति का ही परिणाम है। हीगन भी यद्यपि स्वतन्त्रता की पूर्ण अभिव्यक्ति राज्य में ही सम्भव मानता है, हीगन के अनुसार व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता है जब वह यह अनुभव करे कि राज्य के द्वारा निर्धारित इच्छा ऐसी ही है जैसी कि स्वयं उसके द्वारा निर्धारित होनी। परन्तु हीगन अपने इस मन की वरम सीमा तक लेजाता है और व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के आधीन बना देता है। ग्रीन राज्य को यन्त्र की तरह पशु इच्छाओं की पूर्ति में सहायक मानता है। वह राज्य को स्वयं मानव इच्छा का प्रतिबिम्ब नहीं कहना। इसीलिए उसे उदार भावधर्मावादी कहा जा सकता है।

ग्रीन यह भी स्वीकार करता है कि व्यक्ति में अपनी इच्छात्मक भावना की चेतना के साथ ही साथ इस बात की भी चेतना होती है कि अन्य व्यक्तियों का भी समान स्वभाव होने के कारण उन्हें भी उसी की भाँति सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसका प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए सुविधाओं की माँग करता है और दूसरों की उसी प्रकार की माँग के प्रतिफल को भी स्वीकार करना है। इस प्रकार व्यक्तिगत माँगों के पीछे समाज की स्वीकृति का संकेत छिपा हुआ जाता है। इन्हें ही दूसरे राज्यों में अधिकार कहा जाता है। ग्रीन के शब्दों में "अधिकार अपने प्राकृतिक विभाग के लिए व्यक्ति द्वारा बाह्य परिस्थितियों की माँग है जिन्हें समाज द्वारा संरक्षण मिलता है।"¹

ये अधिकार जिन्हें ग्रीन व्यक्ति के स्वाभाविक विभाग में सहायक होने के कारण प्राकृतिक अधिकार कहा है, यदि राज्य द्वारा क्रियाश्रित न किये जायें तो नैतिक दावे मान रह जायेंगे। भक्त अधिकारों की क्रियाश्रित करने के लिये मार्ग-भोदिततायुक्त राज्य का जन्म होता है। यद्यपि व्यक्ति सामान्यतया सभी अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं किन्तु भ्रष्टाचार, लोभ, स्वार्थ आदि के प्रभाव में वे अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों के उपयोग में बाधा डाल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में राज्य उनके शिष्ट धर्म का प्रयोग कर सकता है। परन्तु स्पष्ट है कि इसके मूल में हमारे इच्छा नियन्त्रण है और इस प्रकार "राज्य का वास्तविक आधार वर न होकर हमारी मरनी इच्छा है।"² ग्रीन ने स्पष्टतया कहा है—“समस्त अधिकार एक जन-व्य, समाज के समस्त संस्थान, यहाँ तक कि राज्य का जन्म एक सामान्य हित की चेतना में होता है।”

1 "Rights are the outer conditions for the inner development of man, protected by the state"

—Green : *Lectures on the Principles of Political Obligation*

2 "Will, not force is the basis of state."

—Green : *Lectures on the Principles of Political Obligation*

इसी सामान्य हित को चेतना को ग्रीन 'सामान्य इच्छा' कहता है। यद्यपि ग्रीन राज्य के उद्भव के सम्बन्ध में न्याय का समन्वित मिश्रित स्वीकार नहीं करता परन्तु वह उनका 'सामान्य इच्छा' मिश्रित इस रूप में स्वीकार करता है कि राज्य मनुष्यों के सामान्य हित की सिद्धि की इच्छा का फल है। यहाँ भी ग्रीन का यह मिश्रित राज्य की उस सामान्य इच्छा का मिश्रित नहीं है जिसके नाम पर फासिस्टों ने इतने घोर अत्याचार किये, और उनकी एक विवृत व्याख्या कर अल्पमत वालों को कुचला। यहाँ भी ग्रीन का उदार आदर्शवादी स्वरूप दृष्टिगत होता है। वह सामान्य इच्छा का सम्पूर्ण राज्य के हित के लिये राज्य की निर्दिष्ट करने वाली इच्छा के रूप में प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रीन राज्य को न तो होमल की नाति दैविक इच्छा की अभिव्यक्ति एवं आत्मचेतनायुक्त नैतिक तत्त्व मानकर अत्याचार करने की स्वीकृति देता है और न ही उसे सामान्य इच्छा की धोखा में अत्याचार करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में ग्रीन का मत है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा करने व्यक्ति का विकास करवाना है। वह वाँट की नाति यह मानता है कि नैतिकता का व्यक्ति के अन्तःकरण से सम्बन्ध होने के कारण राज्य नैतिकता को लागू नहीं कर सकता। परन्तु ग्रीन के आदर्शवादी राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे (To hinder the hinderances) तथा ऐसी परिस्थितियों का सृजन करे जिनमें नैतिकता का विकास हो सके। इस प्रकार वह राज्य को निष्पातक एवं विधेयात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य प्रदान करता है। निष्पातक कार्यों में अज्ञानता, घराबखोरी आदि को दूर करना जैसे कार्य सम्मिलित हैं और विधेयात्मक कार्यों में शिक्षा की व्यवस्था आदि आने हैं। अतः ग्रीन राज्य को साम्य न मानकर बल्कि व्यक्ति की नैतिकता के विकास का साधन समझता है। उसकी राज्य की कल्पना चरमतावादी न होकर बाध्य एवं आन्तरिक दोनों दृष्टियों से सीमित है।

राज्य के विरोध का अधिकार (Right to Resistance)

ग्रीन राज्य को केवल सीमित अधिकार क्षेत्र देने के प्रतिष्ठित उसके विरुद्ध विद्रोह के अधिकार का कुछ परिस्थितियों में उचित दताकर भी उसे सीमित बनाता है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति राज्य के प्रति नाति इसलिये रखता है कि वह यह समझता है कि यह सामान्य हित में सहायक है। परन्तु यदि कोई कानून विशेष सामान्य हित की धारणा के विरुद्ध हो तो व्यक्ति को कुछ दशास में राज्य का विरोध करने का भी अधिकार है। किन्तु ग्रीन इसे प्राकृतिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं करता। उसके अनुसार समाज की विरुद्ध व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विरोधानुस है; कि अधिकार समाज द्वारा प्रदान नृसिपासों का ही

नाम है। वह इस अधिकार को प्रतिबन्धित करते हुए कहता है कि सामान्यतया तो सामान्य हित के विरुद्ध कानून का भी पालन नहीं करना चाहिये क्योंकि वह अधिकारों की उस प्रणाली का एक अङ्ग है जो समाज के 'सुख' के लिये निमित्त है। एक अङ्ग के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया जाना उचित नहीं इसलिये ग्रीन ने कहा है "एक व्यक्ति द्वारा एक बुरे कानून को मानने की अपेक्षा उसे तोड़ने से सामान्य हित को अधिक बाधात पहुँचना है।" मत. ग्रीन का मन है कि व्यक्ति को एक पणित कानून का विरोध तभी करना चाहिये जब उससे अधिकारों की समस्त प्रणाली के भ्रष्ट होने की सम्भावना हो एवं उसे रद्द करने के समस्त संवैधानिक साधन विफल हो चुके हों। हीगल एवं बांट के सर्वव्यक्तिमान राज्य में तो विरोध का यह प्रतिबन्धित अधिकार भी सम्भव है, जैसा कि संसद् ने कहा है — 'हीगल का अतिरिक्त जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न में इनका विहित था कि उसने व्यक्ति को राज्य में विनिर्णय करते समय कोई हिंसावादी नहीं दिया। वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान चढ़ा देता है।" मत. राज्य की प्रवृत्ति के अधिकार को स्वीकार करने समय ग्रीन हिंसेलियन न होकर बहुत कुछ व्यक्तिवादी है एवं इंग्लिश उदारवाद की छाप उस पर स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है।

युद्ध का मनोचित्र

ग्रीन एक उदारवादी की भाँति युद्धविरोधी है एवं अन्तर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक है। अपने इस विचारों को वह 'जीवन के अधिकार' की सहायता से सिद्ध करता है। उनकी दृष्टि में युद्ध इस मौलिक अधिकार में बाधा होने के कारण अनुचित है।

ग्रीन युद्ध को राज्य की सम्पूर्णता एवं आन्तरिक आर्थिक व्यवस्था का दोषक मानता है। वह विश्वासपूर्वक प्रतिनिधित्व में भी (उदाहरणार्थ, आत्मरक्षा के लिये लिये गये) युद्ध को भी पूर्ण उचित न मान कर एक निर्दयतापूर्ण आक्रमण के अन्तर्गत नहीं मानता। उसके मत में देश रक्षा के लिये किया गया युद्ध भी एक अनुचित कार्य की दोहरे के लिये दूसरा अनुचित कार्य है। उसका मन है कि ज्यादा-ज्यादा राज्य पूर्णता की ओर अग्रसर होने जायेंगे युद्ध का भी अन्त हो जायेगा। ग्रीन युद्ध को बड़ी मात्रा पर की जाने वाली हत्या (Multitudinous murder) कहता है। हीगल का मत है कि युद्ध को हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हत्या में एक निश्चित हत्या होता है एवं उसका उद्देश्य मृत्यु एवं विधेयक होता है जबकि युद्ध में ऐसा नहीं होता। परन्तु ग्रीन का मत है कि युद्धभूमि में की जाने वाली हत्याओं का उद्देश्य विधेयक क्रिमि न किमी व्यक्ति पर अन्वेष्य होता है।

ग्रीन के अनुसार दृढ़ सुधारात्मक दृष्टि में होता है कि व्यक्ति अपने ही उस दंड का पात्र समझकर पदचालन करता है। वह सुधारात्मक इस कार्य में नहीं हो सकता कि उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अपराधी का नैतिक सुधार करना हो सके। उसके भरोसे राज्य का कार्य दुष्टता को दलित करना नहीं करना उसने द्वारा सामाजिक व्यवस्था के लिए गये उत्सर्जन के आधार पर अपराधियों को दलित करना है, जिनमें कि अन्य व्यक्ति अपराध करने को बाध्य नहीं। ग्रीन ने तो सर्वसाधारण प्रतियोपा-
त्मक दृढ़ प्रणाली अपनाया है और न ही मनुष्य के गुणों पर अत्यधिक विश्वास कर कोई सुधारात्मक दृढ़ व्यवस्था स्वीकार करता है। मध्यमार्गी निरोपात्मक प्रणाली को अपनाकर वह एक उदार एक व्यावहारिक आदर्शवादी के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है।

सम्पत्ति का अधिकार

सम्पत्ति के विषय में भी ग्रीन का आदर्श न तो समाजवादी है और न ही व्यक्तिवादी वह इन दोनों के संतुलित रूप में अपनाता है। वह कंठ एक हीमत की भांति प्रत्येक व्यक्ति के स्वतन्त्र जीवन अधिकार के प्रयोग के लिए सम्पत्ति को प्राव-
श्यक मानता है। उसे वह नैतिक विकास के लिये आवश्यक बतलाना है। परन्तु वह इन दोनों की भांति व्यक्ति को सम्पत्ति का अधीनस्थ अधिकार नहीं देता, क्योंकि इसमें असमानता, प्रतियोगिता तथा दोषण जैसे दोष उत्पन्न होत हैं। इसी स्थिति में ग्रीन सुरक्षित व्यक्तिवाद से समाजवाद पर आ जाता है और कहता है कि राज्य को सम्पत्ति का उपयोग समान वितरण करना चाहिए। पूर्ण समान वितरण को वह मभव नहीं मानता क्योंकि सम्पत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अनुसार निश्चित रूप में भिन्न होगा। परन्तु अनिवार्यता जनसंख्या को भी ग्रीन अवांछनीय बतलाना है और इस तरह एक मध्यमार्गी व्यावहारिक आदर्श प्रदान करता है।

उत्तरोक्त विचारों में यह स्पष्ट है कि ग्रीन अपने सामान्य दर्शन में व्यक्ति-
हीमतवादी था, किन्तु व्यावहारिक राजनीति में उसे एक उदारवादी विचारक कहना अधिक उपयुक्त होगा। बार्कर का कहना है कि—'ग्रीन एक ऊँची उड़ान में उड़ने वाला आदर्शवादी तथा ठोस पदार्थवादी था।'¹ यद्यपि कुछ आलोचकों का मत है कि ग्रीन ने पूँजीवाद का पक्ष पोषण किया है और उनकी प्रवृत्ति एक पूर्ण समाज की व्यापक स्थिति के आदर्शों को करने की ओर है, परन्तु वास्तव में यह उग्रा २ व नही मनुष्य एक दुष्ट है कि उसने दो प्रवृत्तियों को समन्वित किया। बेपरवाह मत है कि "ग्रीन की देन यह है कि हमने आँखों को हम मूल्य पर जो है देने की सोच रखी, बेधमकाय

1. 'Green was a soaring idealist and a sober realist.'

—Barker - "Political Thought in England"

से अधिक संतोष प्रदान करने वाला आदर्श दिया । उसने उदारवाद को एक अभिप्राय के स्थान पर एक विश्वास बनाया और व्यक्तिवाद को नैतिक एवं सामाजिक तथा आदर्शवाद को सुरक्षित एवं ग्राह्य बना कर प्रस्तुत किया ।”¹

BIBLIOGRAPHY

- (1) GREEN *Lectures on the Principles of Political Obligation*
- (2) BARKER *Political Thought in England*
- (3) SABINE : *A History of Political Theory*
- (4) Maxey *Political Philosophies*

1. Here then, is Green's achievement, that he gave to Englishmen, something more satisfying than Benthamism at a price they were prepared to give, that he left liberalism a faith instead of an interest, that he made individualism moral and social and Idealism civilised and safe".—Waper : "*Political Thought*", Page 193.

मार्क्सवाद के कुछ पहलू (SOME ASPECTS OF MARXISM)

—कृष्णा भागव

आधुनिक विश्व-राजनैति के दो विरोधी गुटा में विभक्त होने तथा उनके इस पारस्परिक विरोध से उत्पन्न होने वाली सभी सैद्धान्तिक अटिक्तियों के मूल में मार्क्सवाद है। मार्क्स की उत्तरकासीय सभी समाजवादी विचारधाराओं या ही मार्क्सवादी (Marxist) हैं या मार्क्स-विरोधी (Anti Marxist) अथवा अर्धमार्क्सवादी (Inas-Marxist)। यहाँ तक कि समस्त समाजवादी (Non Socialist) विचारधाराओं भी या तो मार्क्स की अस्मय मिट्ट करने के अपने प्रयासों में व्यस्त हैं अथवा उसे प्राक्षिप्त रूप में स्वीकार कर उसमें प्रेरणा ग्रहण करती हैं।

मार्क्स ने छात्रावृत्ति सतावृत्ति में चरम व्यतिवाद एवं ग्रहस्तरोप नीति (Laissez Faire) की उच्चाल एवं अममानतापूर्ण प्रवृत्तियों से प्रतिक्रिया पाकर उत्पन्न होने वाले समाजवाद की एक महान् जन आन्दोलन का स्वरूप दिया। परन्तु हमका तात्पर्य यह नहीं कि मार्क्स ने कोई सर्वथा नवीन और पूर्णतः मौलिक राजनैतिक दर्शन प्रस्तुत किया है। मूलतः उसके मुख्य सिद्धान्त नये नहीं थे किन्तु अपने पुराने विचारों की विषय एवं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने हुए उन्हें एक नवीन और प्रभावकारी सीमा में बाँटने का प्रयास किया है।¹

मार्क्स ने पद्यमरवेक से प्रभावित होकर आदर्शवाद का परित्याग किया एवं विश्व के प्रति एक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसने हीमन के विचारों में अपने तद्विन्त दर्शन का वैज्ञानिक आधार ग्रहण किया। इसी प्रकार उसने पूंजीवाद के समर्थन में अपने युग के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मुख्य सिद्धान्त (Value Theory) की उन्ही की आलोचना के लिए प्रयुक्त किया। मार्क्स की विशेषता यह है कि उसने समस्त प्राप्य सामग्री की बुद्धिमत्तापूर्वक सज्जीत कर उसमें सर्वव्यवस्था और समबद्धता उत्पन्न की और उसे विशिष्ट रूप से एक दार्शनिक ढाँचे में बाँटकर अमनीवी कर्ण का दर्शन बना दिया। यही कारण है कि विश्व की पीढ़ित एवं शक्ति जनता का एक बड़ा बड़ा भाग अपने जाना और उद्धार मार्क्स में धर्म की तरह अन्धी धृष्टा रखती है।

एवं उसके कन्वुनिस्ट 'मनीफेस्टो' तथा 'दास कैपीटल' को आर्थिक द्वाइविल मानकर थड़ा और आत्मा से देखता है।

शोषित एवं शोषणकारी वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण मार्क्सवाद का स्वस्व केवल राजनीतिक ही नहीं बरख आर्थिक अथवा नीतिक भी है। यही कारण है कि मार्क्सवाद में आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों का एक अविच्छेद मिश्रण है जिसके कारण कुछ विद्वान जबकि मार्क्स को विमुक्त मन से एक आर्थिक विचारक¹ मानते हैं तो अन्य उसे एक राजनीतिक सिद्धान्तवेत्ता² बतलाते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि मार्क्स का 'सर्वोत्तम समाजवाद' एक अविभाज्य इकाई है और उसके विभिन्न विचार जटिल रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए, तथा इस तरह अन्वयोन्यासित हैं कि उनमें से किसी भी एक विचार को दूसरे की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। यही पर हम मार्क्सवाद के चार प्रमुख सिद्धान्तों अथवा पहलुओं की विवेचना करेंगे :—

(१) इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Materialistic Interpretation of History)

(२) द्वन्द्ववादी भौतिकवाद (Dialectical Materialism).

(३) वर्ग संघर्ष (Class War).

(४) पूंजीवाद का विनाश एवं समाजवाद की स्थापना का कार्यक्रम।

इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या

समाजवाद को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय मार्क्सवाद को दिया जाता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वह आधार है जिसके द्वारा मार्क्स ने समाजवाद को कल्पनावादी पृष्ठभूमि से स्वतन्त्र कर एक वैज्ञानिक भावभूमि पर खड़ा किया है। मार्क्स का मत है कि सामाजिक पुनर्निर्माण की योजनाओं में सबर्ट मोशन, साइमन आदि कल्पनावादियों की विनियमन सफलता केवल इसीनिधे नहीं मिली कि उनका समाजवाद प्राचीन व्यवस्थाओं के किसी स्पष्ट एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित नहीं था। मार्क्स ने उनकी इस विफलता के जिज्ञा ग्रहण की और अपने विस्तृत में इतिहास का एक दर्शन (Philosophy of History) प्रस्तुत करने की चेष्टा की।

मार्क्स ने पूर्व इतिहास की व्याख्या की अनेक प्रणालियाँ प्रवर्तित कीं जैसे—
दैविक व्याख्या, राजनीतिक व्याख्या तथा हीगल की विचारों के आधार पर दार्शनिक

1. "Marx was primarily an economic theorist and was very little concerned with political ideology as such."

—Maxey : Political Philosophy, Page 579

2. "There are some sociologists who think there will be no harm to Marxian principles if we take away his economic ideas"

—Laidler : Social & Economic Movements.

व्याख्या। मार्क्स इन सबको अस्वीकार करता है क्योंकि उसके अनुसार ये सब इतिहास की व्याख्या के प्राथमिक तथा दोषपूर्ण आधार प्रदान करती है। इन सब में मित्र अपने 'इतिहास की मोनिक्वादी व्याख्या' प्रथम बोल के शब्दों में 'इतिहास की प्राथमिक व्याख्या' प्रस्तुत की है। वे वस्तुएं जिन्हें वह इतिहास के विकास और निर्धारण में क्रियाशील निर्णायक समझता है, वेवन उत्पादन की शक्तियाँ (Mode of Production) है जैसा कि हैलोवेल (Hallowell) ने लिखा है —

“मार्क्स के अनुसार इतिहास न तो ईश्वर एवं व्यक्ति का सघर्ष की कहानी है, न ही प्राध्यात्मवाद व भौतिकवाद के विचारों के सघर्ष का वर्णन है, बल्कि अपने उसे मनुष्य द्वारा अपने प्राथमिक सदस्यों की प्राप्ति का उत्तम मान माना है।”¹ मार्क्स का मत था कि विचार प्रथम सांस्कृतिक शक्तियाँ प्राथमिक परिणामों का कारण नहीं बल्कि उत्पादन के साधनों की उत्पत्ति हैं। अपने अपने ही शब्दों में “जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन की प्रकृति ही जीवन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की स्थिति को निर्धारित करती है। मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी चेतना को निर्धारित करती है।”² मार्क्स की धारणा है कि मानव इतिहास का तीना काल दस बात के उदाहरण हैं कि उत्पादन तथा वितरण की प्रणाली में परिवर्तन होने ही तदनुसार धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए ग्रीक सभ्यता के कृषि प्रधान होने के कारण राजनीतिक शक्ति भूमिपतिव्यक्तियों के पास थी। मध्ययुग का अन्त निश्चित रूप से पर जब सामन्तवाद पतन की ओर जाने लगा तो इसके साथ ही समस्त सामन्तवादी राजनीतिक संस्थाओं में गड़बड़ एवं नवीन राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। सामन्तवाद पूँजीवाद एवं समाजवाद इन प्रणालियों के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले क्रमिक सोपान हैं।

मार्क्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा करने हुए यह कहा जाना है कि सामाजिक सम्बन्ध इतने जटिल होते हैं कि कोई भी एक कारण उनका आधार नहीं हो सकता। यदि मार्क्स के इस कथन को सही मान लिया जाय कि एक समाज की कानूनी, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति उसकी प्राथमिक प्रणाली से ही निर्धारण प्राप्त करती है तो अपने पास इन बातों का कोई उत्तर नहीं है कि समान प्राथमिक प्रणाली धरने वाले राज्य सर्वथा भिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक विचारधाराओं को क्यों स्वीकार करते हैं।

1 Hallowell “Main Currents in Modern Political Thought”

2 Marx ‘Communist Manifesto’—“It is not the consciousness of man that which determines their existence, but on the contrary, it is their social existence which determines their consciousness”.

एन्जिन् ने इन घातों का ठहर देते हुए लिखा है कि "यद्यपि हमारे शिष्यों ने आर्थिक कारणों पर उचित और अधिक जोर दिया है पर यह इमरिये कि हमारे विरोधी इसे अस्वीकार करते हैं। इनके विरोध के लिए हम इसके आधारभूत तत्वों पर इतना अधिक दब देने के लिए विवश हुए हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया के अन्य तत्वों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया की समुचित व्याख्या के लिए न तो हमारे पास समय या और न स्थान है।"

इस प्रकार मार्क्स ने आर्थिक कारणों को इतिहास का एकमात्र आधार न मानकर सर्वप्रमुख आधार माना है। यह मार्क्स की राजनीति दर्शन को एक उपयोगी देन है। आर्थिक कारणों के इस केन्द्रीय महत्व को स्वीकार किये बिना इतिहास का कोई भी सही अध्ययन आज सम्भव या नाता है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आर्थिक रूप से नहीं होते बल्कि एक द्वन्द्वात्मक प्रणाली के अनुसार होते हैं। अतः इतिहास की आर्थिक व्याख्या को यदि सामाजिक परिवर्तन का एक सिद्धान्त कहें तो उसके अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद उसका एक अन्य रूपका साबित है जिसे द्वारा ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया एक प्रवस्था से दूसरी प्रवस्था में प्रवेश करती है।

मार्क्स ने यह द्वन्द्वात्मक पद्धति यद्यपि हीगन से ग्रहण की तथापि दोनों में गम्भीर अन्तर है जैसा कि मार्क्स ने स्वयं कहा है—“मैंने जब हीगल का अध्ययन आरम्भ किया तो उसकी द्वन्द्वात्मकता सीपावन कर रही थी, मैंने उसे केवल अपने पैरों के दब खड़ा करने की कोशिश की है।” हीगल के अनुसार प्रकृति-ब्रह्म दैविक आत्मा (Divine Spirit) या निरपेक्ष (Absolute Idea) की ओर बढ़ने वाली एक प्रक्रिया मात्र है। प्रत्येक राष्ट्रीय संस्कृति इस विश्व आत्मा की अस्थायी अभिव्यक्ति है और विकास की एक आन्तरिक आवश्यकता के कारण करने विरोधी विचार की जन्म देती है। परन्तु विरोध की यह प्रवस्था सदा नहीं होती अतः एक सामंजस्य की ओर बढ़ती है। यह जब तक चलता रहता है जब तक कि निरपेक्ष विचार के रूप में पूर्ण सत्य प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार हीगन इस परिणाम पर पहुँचा कि इतिहास प्रजातों की लड़ाई मात्र नहीं है बल्कि विकास की एक निरन्तर गतिशील प्रक्रिया है और विरोध उसका मुख्य प्रेरक शक्ति है। मार्क्स हीगन की इस धारणा से काफी प्रभावित हुआ था किन्तु उसके आदर्शवाद में उसे विश्वास नहीं था। वह विचारों (Ideas) के स्थान पर पदार्थ (Matter) को अन्तिम वास्तविकता मानता था। उसने अपने इस भौतिकवाद का सम्बन्ध हीगन की द्वन्द्वात्मक पद्धति से स्थापित किया। एक ऐसा समाज जिसमें एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण न हो। उसने विकास की इस

प्रक्रिया का अन्तिम लक्ष्य माना। उसके अनुसार मानव सम्प्रदाय के विकास के Thesis, Antithesis और Synthesis आर्थिक वर्ग हैं, प्रयुक्त विचार नहीं।

मार्क्स अपने दृष्टात्मक भौतिकवाद का आर्थिक निर्णयवाद (Economic Determinism) के रूप में भी प्रस्तुत करता है। उसका मत है कि आर्थिक शक्तियाँ मनुष्य की इच्छा से स्वाधीन रहते हुए भी इतिहास में प्रवाह को निर्धारित करती हैं। साम्यवाद, पूँजीवाद एवं समाजवाद इस विकास के क्रमिक सोपान हैं जिनसे विकास एक असम्बद्ध प्रक्रिया नहीं है बल्कि उसके समस्त सोपान एक दूसरे पर आधारित हैं—पूँजीवाद को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम उसे ऐतिहासिक विकास की एक प्रक्रिया में साम्यवाद से समाजवाद के बीच की एक सक्रमण अवस्था के रूप में न देखें। मार्क्स अपने ऐतिहासिक निर्णयवाद के आधार पर ही इस एक तथ्य को घटल साथ मानता था कि पूँजीवाद का अवसान निश्चित रूप से समाजवाद में होगा। उसकी यह धारणा थी कि पूँजीवाद अपने अन्दर अपने विनाश के बीज उसी प्रकार रखता है जिस प्रकार हीमन की बीमियाँ अपने अन्दर एंटीबीमियाँ के तत्व लेकर बनी होती हैं। उसका मत था कि पूँजीवाद बीमियाँ और उसके एंटीबीमियाँ सर्वहारावर्ग के बीच संघर्ष का परिणाम एक साम्यवादी समाज का जन्म होगा जिसमें न कोई वर्ग होगा और न कोई दमनकारी शक्ति। मार्क्स द्वारा मानव इतिहास के क्रमिक विकास के सम्बन्ध में एंजल्स का मत है कि "मार्क्स को इस निष्कर्ष ने इतिहास के लिए वही कार्य दिया जो डार्विन ने सिद्धान्त के जीव विज्ञान के लिए दिया था।"¹

परन्तु मार्क्सवादी का मत है कि आदर्शवाद में सम्बद्ध रह कर तो दृष्टात्मक पद्धति की फिर भी कुछ साम्यता सम्भव हो सकती है किन्तु भौतिकवाद के साथ सम्बद्ध होने पर उसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिप नहीं रह जाता। भौतिक दस्तुप्रा में सम्बन्ध या तो समानता के होते हैं अथवा अन्तर के और वे एक दूसरे की विरोधी नहीं हो सकती। पानी का गैस का विरोधी बूझा निरर्थक है। मार्क्सवादी का यह भी मत है कि मार्क्स का ऐतिहासिक निर्णयवाद आर्थिक अन्तर्भाव के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। वास्तव में मार्क्स इतिहास की सामान्य दिशा का पूर्व निर्धारित मानता है और छोटी-मोटी घटनाएँ उसकी दृष्टि में अन्तर्भाव स्वरूप हैं।

वर्ग-संघर्ष

मार्क्स के अनुसार न केवल विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ न ही विरोध पाया जाता है बल्कि एक ही प्रकार की आर्थिक प्रणाली में भी विभिन्न विरोधी वर्गों का

1. Engels. "This proposition in my opinion is destined to do for history what Darwin's theory has done for biology."—Quoted by Laidler in "Social & Economic Movements".

अस्तित्व होता है जो परस्पर संघर्षरत रहने है। इतिहास के युद्धों के युद्धों एवं युद्धांगों के कारणों का सन्धानोन्धान न मानकर मार्क्स को विरोधी वर्गों के संघर्षों की गृहस्था दत्ता है। इतिहास का निर्माण करने वाले सामाजिक आन्दोलन उनकी दृष्टि में वर्ग-आन्दोलन हैं। प्रत्येक काल में समाज दो विरोधी वर्गों में विभक्त रहता है—एक विरोधाधिकार प्राप्त उत्पादन के स्वामियों का छोटा या वर्ग (Haves) तथा दूसरा अशक्तों का Haves देना कि मार्क्स ने अपने ग्रन्थ कम्युनिस्ट मनिफेस्टो (Communist Manifesto) में कहा है—

“प्राचीन रोम में कुलीन नरेश एवं साधारण मनुष्य एवं श्रम दे। मध्ययुग में सामन्त, नरेश तथा ठेकेदार और आधुनिक समाज पूँजीवाद तथा श्रमिक वर्ग में विभक्त है। इनमें कभी युद्ध व कभी बुल्लनबुल्ला निरन्तर वर्ग युद्ध चलता रहता है।”

मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों में संघर्ष का कारण परस्पर विरोधी हित है। एक वर्ग का लाभ दूसरे वर्ग की हानि करने ही सम्भव है। पूँजीरति श्रमिकों में अधिक ज्ञान लेकर उन्हें कम वेतन देकर स्वयं लाभ कमाने हैं (Surplus Value)। इसके विरोध श्रमिक वर्ग का हित इसमें निहित है कि उसे उसके श्रम का अधिकतम प्रतिफल मिले। श्रमिकों के अधिक संख्या में होने पर भी पूँजीरति यह शीघ्र करने में इसलिये सफल होते हैं कि मजदूरों का श्रम नाशवान होता है, पर पूँजीरतियों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। वे प्रतीक्षा करते श्रमिकों को झुकने के लिए विवश कर सकते हैं।

पूँजीरति एवं श्रमिक वर्ग के बीच विरोध का एक अन्य कारण मार्क्स यह भी दत्ता है कि पूँजीरति न केवल आर्थिक जीवन पर ही नियन्त्रण रखते हैं बल्कि सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं को भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करने की कोशिश करते हैं। सम्पत्तिहीन वर्ग को इन संस्थाओं और प्रक्रिया में भाग देना चाहता है। अतः प्रत्येक समाज में इनके नियन्त्रण के लिए वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मार्क्स के अनुसार बुनियादी एवं दृष्ट वर्ग के बीच संघर्ष इसी प्रकार का था और इनने सामन्तवादी व्यवस्था को उल्टे दिया। आधुनिक समय में पूँजीरतियों एवं वर्ग चेतना में नये मजदूरों के बीच चलने वाला संघर्ष भी पूँजीवाद की उल्टे खोजती कर रहा है और इसका अन्तिम परिणाम श्रमिक वर्ग की विजय में होगा। यह स्वयं एक संगठित की प्रवृत्ति होगी और अन्त में सम्पत्ति वर्ग नष्ट हो जायेंगे और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी।

यद्यपि मार्क्स की यह धारणा सत्य है कि समाज में निरन्तर वर्गों का अस्तित्व रहा है परन्तु यह वर्ग नरेश आर्थिक वर्ग ही रहे हैं यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता। सम्पत्तिहीन इतिहास के एक मनुष्यपूर्ण विषय पति एवं सम्राट के बीच चलने

वाला संघर्ष शासक वर्ग के घातकारिक विरोधों का उदाहरण कहा जा सकता है, परन्तु उभे शोषक एवं शोषित वर्ग के बीच का संघर्ष कहना संदेहास्पद होगा। अतः यह कहना भी उचित नहीं माना जा सकता कि अधिक वर्ग की विजय के पदवात् समस्त वर्ग संघर्षों का सर्वे के लिए अन्त हो जावेगा।

पूँजीवाद का अन्त तथा साम्यवाद की स्थापना का कार्यक्रम

मार्क्स के समस्त सिद्धान्तों विशेषतः दुग्दात्मक भौतिकवाद और वर्गसंघर्ष का उद्देश्य यही सिद्ध करना था कि वर्गचेतना एवं क्रान्तिकारी श्रमजीवी वर्ग अपने पूँजीवादी विरोधियों पर अन्तिम विजय प्राप्त कर उस साम्यवादी समाज की स्थापना करेगा, जिसमें 'प्रत्येक को आवश्यकानुसार दिया जावेगा एवं योग्यतानुसार काम लिया जावेगा।' अपने मुक्तिवात् श्रम 'कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो' में जिसे मार्क्स ने समस्त काल का एक महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी अभिलेख' कहा है और जिसकी तुलना काम की अधिकार घोषणा, अमेरिका की स्वतन्त्रता घोषणा (*American Declaration of Independence*) एवं (French Declaration of Rights) से की जाती है। मार्क्स ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिसे अपनाकर श्रमजीवी वर्ग अपना श्रेष्ठ शोषण से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मार्क्स के मत में इस विधि को न अपनाये जाने पर भी पूँजीवाद का पतन अवश्यम्भावी है, क्योंकि वह स्वयं में अपने विनाश के बीज रक्षता है। यह इस बात से स्पष्ट है कि पूँजीवाद के उत्पादन तथा विनिमय के महाकाम साधनों को जन्म दिया है। पर वह उनको नियन्त्रित करने में सर्वथा असमर्थ है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण बार बार उत्पन्न होने वाले आविर्भाव संकट तथा गिरती हुई लाभ दरों के कारण अविकसित देशों में पूँजी लगाना प्रयत्न उभे नष्ट कर देना आदि घटनायें पूँजीवाद की आत्मघातक घातकारिक अस्थिरता की सूचक हैं। विकास के साथ पूँजीवाद की उपयोगिता का ह्रास उसने पाये जाने वाले इन्हीं विरोधाभासों के कारण हुआ है।

पूँजीवादी उत्पादन की प्रवृत्ति केन्द्रीकरण की ओर होती है और प्रतियोगिता के माध्यम द्वारा बड़े व्यापारों छोटे व्यापारियों को समाप्त कर देने है। अतः उत्पादन के माध्यम छोटे-से बड़े पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं। ये ही बड़े बड़े कारखाने खोलते हैं और उन्हें मजदूर वर्ग की संख्या दिनदिन बढ़ते सपत्ती है। बड़े बड़े औद्योगिक नगर केन्द्रों का जन्म होता है और वहाँ भी हजारों मजदूर छोटे-बड़े क्षेत्रों में रहने लगते हैं। इस स्थिति में इनमें स्वभावतः पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित होने हैं और अपनी कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं के प्रति एक मजबूत आती है। परिणामस्वरूप सभी मजदूर मिलकर पूँजीपतियों के विरुद्ध अपने संगठन बनाने लगते हैं और संघर्ष एक निरन्तर तथा ऊँचे स्तर पर चलने लगता है। यह संघर्ष इस स्थिति में

व्यक्तिगत पूंजीपतियों के विरुद्ध न रह कर प्रवृत्त- पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध बन जाता है और शनैः शनैः उसमें उग्रता आने लगती है।

पूंजीवाद का दूसरा विरोधानाम यह है कि पूंजीपति अपनी आवश्यकताओं के लिये मशीनों, यातायात एवं संवादवाहन के माध्यमों का विकास करते हैं, परन्तु यह सब प्रगतिम रूप में श्रमिकों की वर्ग चेतना और संगठन में महात्मक निम्न होने हैं। मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाने के कारण श्रमिक अपने व्यक्तिगत नैतिक गुणों को खोने लगते हैं। उनकी दृष्टि दूर समानता तथा गिरता हुआ चरित्र श्रमिकों में वर्ग चेतना का उन्मेष करता है। द्रुतगति से विकसित होने लगे परिवहन तथा यातायात के माध्यम सभार भर के श्रमिकों में विचार विनिमय सम्भव बनाने लगते हैं और इस प्रकार वर्गसंघर्ष जो पहले स्थानीय था, धीरे-धीरे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर विरुद्धवापी क्रांति का जन्म देता है।

पूंजीवाद की जड़ों को खोखला करने वाला दूसरा विरोधानाम है उसकी श्रमिक का श्रम और उनके कष्टों को बढ़ाने की प्रवृत्ति। लैंडलर (Landler) ने इसे (Theory of accumulation of Wealth and Misery) पूंजी और पीडा का संग्रह मिश्रण कहा है। पूंजीवाद की इस प्रवृत्ति को स्पष्ट करने हुए उसने लिखा है कि "पूंजीवाद में एक मिर पर पूंजी का जमाव, दूसरे मिर पर कष्ट, दासता एवं प्रतानता की शृंखला का जन्म देता है।"¹ यह श्रमिकों में इन प्रणाली के विरुद्ध तीव्र असन्तोष उत्पन्न करता है और वे क्रांतिकारी बनने लगते हैं। कोकर ने पूंजीवाद के इन विरोधानामों का इन शब्दों में स्पष्ट किया है।

"पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें संगठित समूहों में एक साथ लाती है, उनके परस्पर में मिलने जुटने के माध्यम प्रदान करती है और उन्हें अधिकधिक शोषण द्वारा संगठित विरोध के लिये उत्प्रेरित करती है।"²

परन्तु मार्क्स ने केवल पूंजीवाद के इन विरोधानामों की ओर ही ध्यान आकर्षित नहीं किया बल्कि वह कार्यक्रम भी दिया है जिसे अपनाकर मजदूर लोग अपने आन्दोलन को एक स्वाभाविक आर्थिक संघर्ष में बदल सकें हैं। मार्क्स का यह कार्यक्रम विकासवादी एवं क्रांतिकारी (Evolutionary and Revolutionary) दोनों प्रकार का है। मार्क्स घोषणा करता है कि—

"श्रमिक वर्ग द्वारा क्रांति में पहला कदम श्रमजीवी वर्ग को शायक वर्ग के पद

1. "Accumulation of wealth at one pole is, therefore, at the same time accumulation of misery, slavery, and brutality at the opposite pole."—Landler : Social and Economic, Movements
2. Coker : Recent Political Thought, Chapter 2, Vol. Part 1.

पर प्रतिष्ठित करना तथा लोकतन्त्र के युद्ध की जीतना होगा।" एक सातहत्थी राज्य में लोकतन्त्रात्मक उपायों द्वारा विजय पाने के प्रत्येक उपाय है—जैसे एक राजनीतिक दल बनाना, निर्वाचक मंडल से प्रदीप्त करना, राष्ट्रीय सगद में बहुमत प्राप्त करना इत्यादि। मार्क्स चाहता है कि इन साधनों से प्राप्त सम्पत्ति शक्ति का प्रयोग मजदूरों द्वारा धीरे-धीरे पूँजीवादी वर्ग के समस्त पूँजी को छीनने एवं उत्पादन के समस्त साधनों की धमजीवी वर्ग के हाथों में केन्द्रित करने के लिये किया जाना चाहिये। इसमें स्पष्ट है कि पूँजीवाद के अन्त तथा पूँजी के समाजीकरण की प्रक्रिया क्रमिक होगी और पूँजीवाद एक ही चोट में समाप्त नहीं होगा।

परन्तु मार्क्स ने इस सम्भावना पर भी विचार किया है कि जो पूँजीपति इतनी दृढ़ता से जमे हुये हैं, अमिक वर्ग को शायद ही सबैधानिक साधनों द्वारा विजय प्राप्त कर सके। मार्क्स की धारणा थी कि ऐसी परिस्थिति में अमिकों को संगठित शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और क्रान्ति आवश्यक अवस्था अवसरमात्र की जायेगी। ऐसा कहना जाना है कि मार्क्स की क्रान्तिवादी विचारों की प्रेरणा इंग्लैंड के वाट्सट आन्दोलन में मिली। माने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहायक होने वाले मजदूरों के प्रत्येक कदम को समझे अनित बतलाया और इसी संदर्भ में मार्क्स के हिसाब और क्रान्ति के सिद्धान्त उत्पन्न हुए।

परन्तु मार्क्स के मत में क्रान्ति द्वारा पूँजीवाद के विनाश के परवानु भी साम्यवाद की तुरन्त स्थापना सम्भव नहीं हो सकती। अतः इस बीच धमजीवी वर्ग की तानाशाही का एक संक्रमण काल होगा। मार्क्स की इस अवस्था में पुरानी व्यवस्था की कुछ विशेषतायें बनी रहेंगी। उदाहरण के लिए मार्क्स वर्ग राज्य का विरोधी है, परन्तु उसकी इस संक्रमण अवस्था में वर्ग राज्य विद्यमान रहेगा फिर भी मजदूरों की तानाशाही वाले मार्क्सवादी राज्य में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण अन्तर पाजायेंगे।

प्रथम पुराने पूँजीवादी राज्य में अल्पगन्धर्व राजनीति शक्ति का प्रयोग बहुगन्धर्वों की सम्पत्ति के हरण के लिए करने के पर वहाँ अल्पगन्धर्व व्यापकपूर्ण वितरण के निम्न राज्य की शक्ति का प्रयोग करेंगे। दूसरा अन्तर यह होगा कि जहाँ पुराने पूँजीवादी राज्य का उद्देश्य वर्गभेद को बनाये रखना और सम्पत्तिशाही वर्ग की सुरक्षा करना था वहाँ धमजीवी वर्ग की तानाशाही वर्गभेदों को मिटाने का प्रयत्न करेगी और ऐसा करने की प्रक्रिया में वह स्वयं अपना भी अन्त कर देगी। मजदूर वर्गों के सर्वहारा वर्ग जब राजनीतिक शक्ति द्वारा समस्त पूँजीपतियों एवं पूँजीवादी प्रवृत्तियों का विनाश करने में समर्थ हो जायेगा तो केवल धमजीवी वर्ग का ही अस्तित्व शेष रहेगा और जिस अन्तर्गत ही नहीं रहेंगे, तो एक विविष्ट दमनकारी शक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और वर्ग संगठन के रूप में राज्य धीरे धीरे अस्तित्वमान हो जायेगा। अतः मार्क्स की परि-
रचना का भावो समाज कृति वर्गहीन है अतः वह राज्यहीन भी रहेगा।

इस सदर्म में इतिहासकार सैबाइन का मत है कि मार्क्स के दर्शन में श्रमिक वर्ग की अन्तिम विजय के अटल विश्वास को सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके मत में वर्गहीन समाज की कल्पना क्रान्तिकारी दल को दृढ़ता एवं प्रेरणा प्रदान करने के लिये एक प्रकार की गल्प (Myth) है और उसका यह आदर्श यूरोपियन समाजवादियों से कोई कम कल्पनावेदी (Utopia) नहीं है।

मार्क्स की राज्य सम्बन्धी धारणा के विषय में यह कहा जाता है कि वह जिस राज्य का विवरण करता है उसके सर्वोत्तम स्वरूप का विवरण नहीं देता। निस्सन्देह यह तो सत्य है कि इतिहास में शासकों ने कभी-कभी एक सीमित समूह के सन्तुष्टि हितों की सिद्धि का प्रयत्न किया है किन्तु ऐसे उदाहरणों के आधार पर राज्य के सिद्धांत का निर्माण करना उतना ही अनुचित होगा जितना कि चोरो और डाकुओं के कुकुर्यों के आधार पर एक मानव के सिद्धांत की रचना करना। यद्यपि मार्क्स का यह सिद्धांत उन्नीसवीं शताब्दी के शक्तिवादी राज्य के लिये ठीक कहा जा सकता है परन्तु बीसवीं शताब्दी के कम्युण्डारी राज्य पर इसे आरोपित करने में स्वयं मार्क्स की भी काफी कठिनाई आयेगी।

यह भी कहा जा सकता है कि मार्क्स की यह भविष्यवाणी भ्रान्त सिद्ध हुई है कि पूंजीवाद पतन की ओर अग्रसर हो रहा है बल्कि ऐतिहासिक सब तो यह है कि वह दिनोदिन सुदृढ़ बनता जा रहा है। अपने को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में पूंजीवाद ने एक अद्भुत मनीषिता और सोव का परिचय दिया है जबकि मार्क्स ने एक वैज्ञानिक की भाँति केवल तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण कर उससे भविष्य में बड़े बड़े निष्कर्ष निकाले हैं। उन्नीसवीं शताब्दी की पूंजीवादी परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता में द्रुतगति से विकास हो रहा था परन्तु मजदूरों की सुख-सुविधायें नहीं बढ़ रही थीं। इसके कारण अनेक आन्दोलन हुये। ऐसी परिस्थितियों में मार्क्स का इस निष्कर्ष पर पहुँचना स्वाभाविक ही था कि पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ मजदूरों का संकट बढ़ता जायेगा और असन्तुष्ट मजदूर एक राजनीतिक आन्दोलन करेंगे, जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी प्रणाली तहस नहस हो जायेगी।

मार्क्स की धारें कुछ भी दुर्बलतायें रही हो पर इतना स्पष्ट अवश्य है कि उसके दर्शन ने समस्त विश्व के विचारकों को राजनीति की कुछ मूल समस्याओं के प्रति प्राकटित किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने पूंजीवाद की कुछ ठोस आलोचनायें सामने रखी हैं। समाज के एक विद्यालय जनसमूह अथवा पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है तथा अपने भावी समाज की जो कल्पना दी है उसे प्राप्त करने के सम्भव साधनों के लिए भी विवादास्पद सुझाव रखे हैं। ये सब विशेषतायें मार्क्सवाद की एक अत्यन्त ठोस एवं सत्यपूर्ण सिद्धान्त बना देती हैं और इसी कारण

सभी भावी समाजवादी विचारक उसके सिद्धान्तों द्वारा प्रभावित हुये हैं जैसा कि अमेरिकन समाजवादी Morris Hillquit ने कहा है—

“मार्क्सवाद आज भी समस्त समाजवादी दलों का मार्ग सिद्धान्त है और प्रत्येक दल प्राधुनिक समाजवादी आन्दोलन के सत्वापन के सैद्धान्तिक तत्वों को सच्चाई से ग्रहण करने का दावा करता है और अपने विरोधी समाजवादी दलों पर आरोप करता है कि उन्होंने उसके मूल सिद्धान्त का त्याग कर दिया है।”

अतः यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद न केवल एक विचारधारा अपितु आन्दोलन है वरन् एक जीवनदर्शन भी है जो कुछ नये मूल्यों एवं आदर्शों को स्वीकार करता है। मार्क्स के ये मूल्य जूनि परम्परागत उदारवादी मूल्यों से भिन्न नहीं लाने अतः स्वाभाविक है कि वर्तमान सत्तारूढ़ कुछ लोग उसे एक उदार के रूप में देखें तथा कुछ अन्य एक मंहारक के रूप में।

BIBLIOGRAPHY

COCKER : Recent Political Thought

EBENSTEIN : Today's Isms

MAXEY : Political Philosophies

LAIDLER : Social and Economic Movements

SABINE : History of Political Theory

मार्क्सवाद के रूसी एवं चीनी संस्करण (RUSSIAN AND CHINESE VERSIONS OF MARXISM)

—शकुन्तला राव

मार्क्स के सर्वाधिक जनद्वष्ट एवं विप्लववादी विचार होने के बावजूद भी मार्क्सवाद ने जितने परिवर्तित एवं संशोधित रूप ग्रहण किये हैं तथा उसका जितना विस्तारवादी रूप है, राजनीति दर्शन के इतिहास में शायद ही किसी अन्य विचारवादी का ऐसा हो। परन्तु इससे यह सातत्य नहीं कि मार्क्सवाद का यह भावी परिवर्तन मार्क्स के विचारों में किसी सैद्धान्तिक तथ्यों की पूर्ति के लिये हुआ है। इसका वास्तविक कारण तो यह था कि मार्क्स ने केवल तकनीकी परिस्थितियों के आधार पर ही अपना दर्शन निर्मित किया था और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की भावी प्रवृत्तियों उनकी विवेचना में समुचित स्थान नहीं था। अतः क्रांति के बाद उनके विचारों की अनेकानेक समस्याओं में संशोधन एवं प्रयोग किया जाना स्वाभाविक ही था। बर्न्स (Burns) ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मार्क्स के बाद राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन आये वे इतने त्वरित थे कि उनके द्वारा बनाये गये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं हो सके।¹

मार्क्स के जीवनकाल में ही उनके विचारों की व्याख्या के सम्बन्ध में मतभेद प्रकट होने लगे थे और स्वयं मार्क्स को यह संशय करने पड़ी थी कि वह पूर्ण मार्क्सवादी नहीं है। मार्क्स के बीसवीं शताब्दी में होने वाले विस्तारवादी के अन्तर्गत कुछ विचारवादी तो ऐसा हैं जिन्हें निश्चित रूप से मार्क्सवादी तो नहीं कहा जा सकता किन्तु अपने मूल विचारों के लिये वे मार्क्स की निश्चित रूप से श्रेणी प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिये मिश्र समाजवादी एवं संघवादी मार्क्स के वर्गवाद के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास करते थे। संघवादियों ने उनके अन्तिमकालीन चिन्तन को भी अपनाया उसी प्रकार रूस के पेट्रोववादी मार्क्स द्वारा की गई पूँजीवाद की अवस्था के सभी तत्त्वों को स्वीकार करते हैं।

इसके अलावा वर्गहीन आदि विचारों की गणना भी जा सकती है, जिनकी

1. 'Political and economic conditions had changed so radically since Marx that the remedies he proposed no longer conformed to disease.'
—Burns : Ideas in Conflict page 146.

मान्यता दी कि बदलती हुई परिस्थितियाँ में मार्क्स ने कुछ मित्रागत अग्रगण्य सिद्ध हो गये हैं। मत: यदि मार्क्स को जोड़ित रखना है तो उसके दर्शन में संशोधन करना आवश्यक है। इस प्रकार के मार्क्स के अनुयायियों को संशोधनवादी (Revisionists) कहा जाता है।

परन्तु इस दृष्टिकोण ने विपरीत सोवियत मंच एवं चीन में मार्क्स के जो अनुयायी हैं वे सम्पूर्ण मार्क्सवाद को पूर्णतया गलत समझते हैं और उसे अपने अपने देशों में व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनके अग्रगण्य लेनिन, स्टालिन एवं माओत्से तुंग मानते हैं। रूढ़िवादी मार्क्सवाद (Orthodox Marxism) को व्यावहारिक स्वरूप देने की प्रक्रिया में इन्होंने उसमें समुचित परिवर्तन किये हैं, किन्तु इनका दावा है कि मार्क्सवाद की मूल धारणाओं ज्यों की त्यों सुरक्षित रह सकी है। इन अग्रगण्य मार्क्सवादियों (Neo-Marxists) का कहना है कि मार्क्सवाद की अग्रगण्य व्यावहारिक रूप तो दिया भी नहीं जा सकता। माओत्से तुंग ने एक स्थान पर कहा है कि "समस्त मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं है। वह केवल साधारण वस्तु रूप में है जिसे राष्ट्रीय स्वरूप में ग्रहण किया गया है अर्थात् मार्क्सवाद की रूस व चीन में देशवासी परिस्थितियों की अनुरूपता के संदर्भ में अपनाया गया है न कि समुचित रूप में।"¹

सोवियत संस्करण—रूसी समाजवादी व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ लेखकों का मत है कि यह मुख्य रूप से रूस के प्राचीन इतिहास की उत्पत्ति है। मार्क्स के सिद्धांतों को सोवियत मंच में केवल प्रसंगत: लागू किया गया है किन्तु फिर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने रूस में नवम्बर १९१७ में शासन सम्भाला था वे मार्क्स के माने हुए अनुयायी थे। १९१७ के मध्य में लेनिन ने जो "राज्य तथा क्रान्ति" (State And Revolution) नामक पुस्तक लिखी उसका अर्थ मार्क्स एवं एंजिल्स की कृतियों के उद्धरण देकर यह दिखलाना था कि उनके द्वारा आयोजित क्रान्ति और उसके फलस्वरूप स्थापित होने वाली साम्यवादी शासन-व्यवस्था मार्क्स की कल्पना के बिनाबल अनुरूप ही होगी। परन्तु वास्तविक तथ्य यह है कि लेनिन एवं उनके उत्तराधिकारियों ने हमने रूस की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किये हैं, क्योंकि वे मार्क्स की भाँति केवल विचारक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक राजनीति भी थे।

लेनिनवाद—मार्क्सवाद की सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय लेनिन को है। लेनिनवाद को मार्क्सवाद का रूसी संस्करण कहा जाता है। स्टालिन ने कहा है कि "लेनिनवाद साम्राज्यवाद एवं श्रमजीवी क्रान्ति के युग का मार्क्सवाद है।" १९४८ में 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' के प्रकाशित होने की तिथि तथा १९१७ में

1. "There is no such thing as abstract Marxism but only concrete Marxism that has taken a national form, that is, Marxism applied to concrete conditions prevailing in China or Russia and not Marxism abstractly used.—MAOTSE-TUNG."

वाल्सेविक क्रान्ति द्वारा लेनिन के हाथों में सत्ता आ जाने के बीच के वर्षों में संसार में ऐसी दहड़त और घटनाएँ घटीं जिन्होंने मार्क्सवाद में संशोधन करना आवश्यक बना दिया। इस अवधि में पूँजीवाद का तीव्र गति से विकास हुआ और उसमें अन्तर्निहित विरोध अपनी चरम सीमा तक पहुँच कर यूरोपीय राष्ट्रों के बीच साम्राज्यवाद के लिये विरोध उत्पन्न करने लगे। सन् १९१४ में लड़ा गया प्रथम विश्वयुद्ध पूँजीवादी साम्राज्यवाद के विकास का ही भयानक परिणाम था। ऐसे समय में श्रमिक वर्ग की क्रान्ति जिसका मार्क्स ने उल्लेख किया है एक ज्वलन्त प्रदर्शन बनी। मार्क्स की शिक्षाओं का प्रतिपादन एकाधिकारों प्रवृत्ति के पूँजीवादी साम्राज्यवाद तथा श्रमिक वर्ग की क्रान्ति के युग में पूर्व हुआ था। अतएव उसे समय के अनुसार ढालना था। इसके प्रतिरिक्त मार्क्स ने श्रमिक वर्ग की क्रान्ति का उल्लेख मात्र किया था, उसे क्रियागिरि करने के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी युद्ध करना के विषय में वह मौन था। लेनिन ने इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति की। उसने मार्क्सवाद में पाये जाने वाले उन क्रान्तिकारी तत्त्वों का पुनरुद्धार किया जिन्हें द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के अवसरवादियों एवं संशोधनवादियों ने धूमिल कर दिया था। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उसे श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही को मार्क्स के राग्य सिद्धान्त में एक केन्द्रीय स्थान देना पड़ा।

लेनिन और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

लेनिन ने मार्क्स में अपने प्रकट विश्वास का प्रकट करने के लिए केवल उसके साम्यवाद एवं पूँजीवाद सम्बन्धी विचारों की पुष्टि करना ही पर्याप्त नहीं समझ कर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास प्रकट करना भी उसे आवश्यक प्रतीत हुआ। सन् १९०९ में प्रकाशित ग्रन्थ "Materialism and Empirio Criticism" लेनिन की साम्यवाद की प्रमुख देन तथा साम्यवादी दार्शनिक ऋद्धिवाद का मापदण्ड माना जाता है। इस ग्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्तों का तनिक भी विरोध क्रान्ति के प्रति विद्रोह समझा जाने लगा था। इस पुस्तक में लेनिन ने बताया है कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक विज्ञानों की स्रोता प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक समीप है। उसके अनुसार वैज्ञानिक निरामक्ति एवं दर्शन तथा धर्मशास्त्र और राजनीति में निरालसता संभव नहीं है। इन्हें वास्तव में निहित स्वार्थों की पूर्ति के दहाना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लेनिन के अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के साथ ही दो वैज्ञानिक प्रणालियाँ हैं—एक मध्यवर्ग के हित में (पूँजीवाद) और दूसरे सर्वहारावर्ग के हित में (साम्यवाद)। श्रमजीवी सामाजिक विज्ञान को वह पूँजीवादी सामाजिक विज्ञान से अत्यन्त समझता है, क्योंकि मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पद्धति उसे एक उदात्तमान वर्ग घोषित करती है। अतः लेनिन ने यह स्पष्ट किया है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिये अपने प्रारम्भिक विश्वासों के रंग में रंगे हुए होने हैं।

लेनिन ने मार्क्स की द्वन्द्वात्मक पद्धति को सार्वभौम पद्धति का रूप दिया। इसका आरोपण सभी प्रश्नों पर किया जा सकता है।¹

लेनिन और साम्राज्यवाद

लेनिन ने मार्क्सवाद के सैद्धांतिक पिष्टपोषण के साथ-साथ आलोचकों द्वारा उभे पर किये जाने वाले प्रहारों से भी उसकी रक्षा करने का प्रयत्न किया है। मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक प्रणाली के आधार पर यह भविष्यवाणी की थी कि विनाश की इस प्रक्रिया में पूंजीवाद विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है और समाजवाद की स्थापना एक अवश्यम्भावी सत्य है। मार्क्स की आलोचना मुख्य रूप से इसी आधार पर की जाती है कि उनके बाद की ऐतिहासिक घटनाओं उसकी भविष्यवाणी के अनुरूप नहीं होती। मार्क्स की भविष्यवाणी में तो पूंजीपति एवं श्रमिकों के दो शिरोषी वर्ग बने और न ही श्रमिक वर्ग की दशा उत्तरोत्तर गिरी, बल्कि इसके विपरीत श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ा है और समाजवाद की स्थापना के स्थान पर साम्राज्यवाद की स्थापना हुई है। अतः लेनिन ने मार्क्स का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन सब घटनाओं की तदनुकूल व्याख्या की है जो उनकी भविष्यवाणी के विपरीत प्रतीत होती हैं। यह कार्य लेनिन ने अपने जिस सिद्धान्त द्वारा किया उसे पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था अर्थात् साम्राज्यवाद का सिद्धान्त कहते हैं।

साम्राज्यवाद और पूंजीवाद

अपने ग्रन्थ "साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अन्तिम अवस्था है" (Imperialism is the last stage of Capitalism) में लेनिन ने बताया है कि वर्ग संघर्ष कुछ देशों में और इसलिए नहीं पकड़ सका कि वहाँ की प्रापिक स्थिति आधीनस्थ उपनिवेशों के कारण काफी गम्भीर बन चुकी थी। इस तथ्य के कारण पराधीन राष्ट्रों एवं औद्योगिक राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध अत्यन्त ही एव पूंजीपति का बन गया और जो पहले साम्राज्य के अभाव में अत्यन्त ही थे, वे साम्राज्यवाद में पूंजीपति बन गये। लेनिन का दावा है कि यद्यपि मार्क्स की साम्राज्यवाद की इस अवस्था का पूर्वाभास नहीं मिला था किन्तु इसका मार्क्स के मूल मन्त्र से कोई शिरोष नहीं है। यह मानना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद के विरोधानाम एवं आखिरी मंजरी का ही परिणाम है। साम के उद्देश्य के लिए ही पूंजीपति अविश्वसित देशों को हस्तगत करते हैं। लेनिन के अनुसार इन साम्राज्यवाद में भी पूंजीवाद की भांति अन्तर्विरोध है। सर्वप्रथम तो इनमें पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण स्वयं पूंजीवादी देशों में युद्ध होता है और अन्त में उन्हें

1. परन्तु मेकाइन इसे पूर्ण रूप से मारहीन कहता है। इसी प्रकार वेबर के अनुसार, "लेनिन की भोतिषवाद के विषय में धारणा एक दृष्टिधारणा है जो पशुपरमैव के भोतिषवाद की उस धारणा से कुछ भिन्न नहीं है जिसकी मार्क्स ने निन्दा की थी।"

निर्वन बनना पड़ता है। दूसरा विरोध शोषक राष्ट्र एवं औद्योगिक राष्ट्र के हितों के बीच होता है। शोषित देश जाति के आने पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की माँग करते हैं और यह श्रमजीवी क्रान्ति के त्रये उपयुक्त अवसर सिद्ध होता है। संक्षेप में लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूँजीवाद की भ्रष्टावृत्त अवस्था है और यह मार्क्स की कल्पना में किसी भी प्रकार निहित नहीं है।¹

लेनिन की इन धारणा का महत्व इसलिए अधिक है कि इसने प्रचलित ही प्रशंसनीय एवं चानुर्यपूर्ण दंग में विश्व युद्ध प्रारम्भ होने पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या मार्क्सवाद की मूल धारणा में हटे बिना करके, उसे मुहड़ बनाया।

क्रान्ति की टैक्निक और दल

द्वन्द्वात्मक मौलिकवाद के मार्क्सनीमिकरण तथा साम्राज्यवाद के मार्क्सवादी विरुद्धता में वहीं अधिक महत्वपूर्ण लेनिन की यह धारणा है कि मार्क्सवाद मूलतः एक क्रान्तिकारी विचारधारा है। उसने क्रान्ति की टैक्निक देकर इसे व्यावहारिक स्वरूप दिया। उसका कथन था कि—“पूँजीवादी राज्य के स्थान पर सर्वहारा राज्य की स्थापना हिमालय क्रान्ति के बिना सम्भव नहीं है।” इसी बात की पुष्टि करते हुए वह मार्क्स का यह कथन उद्धृत करता है कि—“यदि एक मजदूर फ्रांसेन क्रान्तिकारी नहीं है तो वह कुद भी नहीं है।” परन्तु लेनिन ने इसके साथ ही क्रान्ति के लिए प्रत्यक्ष मार्ग भी संभव बताया है एवं उस समय की नम की क्रान्ति के लिए उसे परिपक्व भी माना है। उसका कहना था कि मध्यवर्गीय क्रान्ति के लिए प्रतीक्षा करना मार्क्सवाद की मूल दृष्टि के लिए अनिष्टान करना है। मार्क्स इस मत में इनकार करता है कि मजदूर मार्क्सवादी की वास्तविक तथ्यों की ध्यान में रखना चाहिए। लेनिन की प्रत्यक्ष मार्ग मन्दग्री। यह धारणा मार्क्स के इस मत में विपरीत थी कि राजनीति उत्पादन के सम्बन्धों पर निर्भर करती है और कोई भी राष्ट्र विकास की स्वाभाविक अवस्थाओं में गुजरे बिना नहीं रह सकता। लेनिन का विचार था कि क्रान्तिकारी भावनाओं का उदय श्रमिक वर्ग में स्वतः नहीं होता बल्कि उनका प्रवेश श्रमिकों में बाहर से कराया जाता है। मजदूरों में केवल युनिटन बनाने की चेष्टना होती है किन्तु क्रान्तिकारी भावना का संचार केवल साम्यवादी दल कर सकता है। यही क्रान्ति को सम्भव बनाता है और युद्ध के पश्चात् भी पूँजीवादी अवस्थाओं को समाप्त करने तथा श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित करने के लिए आवश्यक है। लेनिन के अनुसार साम्यवादी दल इन

1. इस मन्दर्न में केवल का मत है कि लेनिन ने अपने इस मत द्वारा मार्क्सवाद को किसी भी प्रकार में मुरखित नहीं बनाया क्योंकि—“लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धान्त जहाँ तक मार्क्सवाद का समर्थक है, समर्थ एवं वेदमानीपूर्ण है और जहाँ मन्वा है वहाँ वह मार्क्सवाद का समर्थन नहीं करता।”

भावश्यकताओं की पूर्ति तभी कर सकता है जब वह दौड़िक तथा नैतिक दृष्टि से ये ठ व्यक्तियों द्वारा सगठित हो। दल की यह निर्णयना उसे वास्तव में नदीकृत सगठन बनाती है जो अन्ततः आलोचकतन्त्री स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसमें सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग सम्मिलित नहीं होता। "दल का बोटी का सगठन दल का स्थान ले लेता है। समिति संगठन समझी जाती है और अन्त में अधिनायक केन्द्रीय समिति का स्थान ले लेता है।" इस लेनिनवादी परम्परा को स्टालिन ने पूर्णरूप से बनाये रखा और वह बहुत कुछ सीमा तक आज भी वायव्य है।

श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही

लेनिन ने श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही के सम्बन्ध में भी विचार प्रकट किये हैं। स्टालिन ने 'लेनिनवाद के आधार' नामक पुस्तक में इस लेनिनवाद की प्रमुख समस्या माना है। यह श्रमजीवी तानाशाही की समस्या की श्रमिक वर्ग द्वारा आगति के परिणामों को बनाये रखने के लिए तथा पुंजीपतियों के प्रतिरोध की रीतने के लिए आवश्यक मानता है। श्रमजीवी तानाशाही का अन्तिम लक्ष्य वह कि सोवियत की प्राप्ति करना है अतः लेनिन का मत था कि सोवियतों द्वारा श्रमिक लोकतन्त्र का उपयोग कर सके। परन्तु वोकर का मत है कि व्यावहारिक रूप में यह श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही न होकर उन पर स्वयं तानाशाही बन जानी है। यह मार्क्स की कल्पना के अनुसार श्रमजीवी वर्ग के बहुमत द्वारा चलाई जाने वाली सरकार नहीं है अपितु श्रमिक वर्ग के भीतर मुद्दों पर समाजवादियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है।

इस प्रकार लेनिन ने यद्यपि प्रारम्भ में अन्त तक अपने की मार्क्स का अनुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न किया तथापि उसकी आवश्यकताओं का जो परिणाम निकलता है वह वास्तव में मार्क्सवाद की विवृत करता है।¹

लेनिन ने आर्थिक दलियों के स्थान पर विचारों की तथा श्रमजीवियों के स्थान पर सम्पत्तियों बुद्धिजीवियों की मध्य देखर एवं आगति का अन्तमार्ग बतलाकर मार्क्सवाद की जित प्रकाश मिर के बन सड़ा किया है, उसे फिर भी वेरो के बन सड़ा करने वाला कोई अन्य अनुयायी आज तक नहीं हुआ। लेनिन मार्क्सवादी मूलों की तभी तक अपनाता है जब तक वे उसके आगतिकारी उद्देश्य में सहायक होते हैं। जहाँ वे उसके मार्ग में बाधक बनने लगते हैं वहाँ वह उनको छोड़ना दिखाई देता है। मार्क्स ने मूल बहुत कुछ सीमा तक लेनिन के भी मूल रहे पर लेनिनवाद का अर्थ मार्क्सवाद से बहुत भिन्न हो गया है।

1. संवाद ने भी यही कहा है—“मार्क्स का यह दावा था कि अपने हीमल की पद्धति की पैरों के दल सड़ा कर दिया है, लेनिन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद की अपने मिर के रूप सड़ा कर दिया है।”

स्टालिनवाद और राष्ट्रीय साम्यवाद

लेनिन के बाद स्टालिन के कभी राजनीति में प्रागमन ने भी मार्क्सवाद की अवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। स्टालिन ने वहाँ से ही चलना शुरू किया जहाँ तक लेनिन पहुँच चुका था। उसने अपने समस्त कार्य लेनिन के नाम पर किये थे। यद्यपि यह सब है कि स्टालिन ने जिस राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन दिया एवं जिस नवीन रूपि नीति को अपनाया वह लेनिन की शिक्षाओं के एकदम विपरीत थी।

स्टालिन की 'एक देश में समाजवाद' की मान्यता लेनिन की स्पाई एवं विश्व-व्यापी क्रान्ति के विरुद्ध थी। मार्क्स भी अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति का ही समर्थक था। उसने विश्व के मजदूरों को एक हो जाने के लिए कहा। परन्तु स्टालिन की इस नीति ने उस समय कम्युनिस्टों में भ्रम फैलाने में सहायता दी कि राष्ट्रीय समाजवाद को कम किया चूँकि दूसरे देश यह सोचने लगे थे कि स्टालिन समस्त संसार में क्रान्ति लाने को उत्सुक नहीं है।

दल बनाम नेता

परन्तु इसका परिणाम यह भी हुआ कि कम में एक दल के स्थान पर एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो गई, क्योंकि स्टालिन ने देश में समाजवाद की शक्ति को हटाने के लिए औद्योगिकरण की नीति अपनाई। उसकी इस नीति में राज्य की शक्तियों का विस्तार हुआ, जिसका प्रयोग दल का अधिनायक ही करता था। इस प्रकार लेनिन के काट में बाद-विवाद की जो स्वतन्त्रता थी, स्टालिन ने उसे भी दबाने दिया। उसने राज्य की व्यक्तियों के कल्याण के कार्य लेकर मार्क्सवादी श्रमशीली तानाशाही की अवस्था का अनुकरण नहीं किया किन्तु मार्क्स के अनुसार राज्य का एकमात्र समय पूँजीपतियों का दमन करना था।

मार्क्स के राज्य विद्वान्त का भी लेनिन ने परिहार किया था। उसके अनुसार राज्य शक्ति का विस्तार तब तक होगा रहेगा जब तक कि उसके चारों ओर पूँजीवाद घेरा बना रहेगा तथा "एक देश में समाजवाद" के विद्वान्त द्वारा पूँजीवादी घेरे को निकट भविष्य में नष्ट होने की सम्भावना नहीं होगी। परन्तु स्टालिन राज्य शक्ति का विस्तार करता चला गया। यद्यपि वह साम्यवाद की अन्तिम विषय विश्वव्यापी साम्यवादी क्रान्ति में ही समझता था, परन्तु वास्तव में उसका विश्वक्रान्ति ने तानाशाही के नेतृत्व में विश्वव्यापी क्रान्ति करना था। इन प्रकार स्टालिन का अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद मार्क्स से दूर निकल रहा था।

सुशेव और उदारतावादी साम्यवाद

सुशेव के रूप में राजनीति में पुनः एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ होता है। उसने एक नवीन अवस्था पर विचार किया कि वह अपने इन दो पूर्व दार्शनिकों ने

निवार नहीं किया था। लुइचेव ने पूँजीवादी शक्तियों के युद्ध की अनिवार्यता (Inevitability of War) की भावना, सैनिक तथा स्टालिन को धारणाओं में आसून-बूल परिवर्तन किया। मार्क्स ने पूँजीवादी पद्धति के आन्तरिक विरोध के कारण दोनों वर्गों में युद्ध आवश्यक बताया था। सैनिक एवं स्टालिन ने इन वर्गों के स्थानीय युद्धों के अतिरिक्त पूँजीवादी देशों एवं साम्यवादी देशों में संघर्ष को अनिवार्य माना था।

शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व

परन्तु लुइचेव ने इसका विरोध किया। इसके अनुसार मार्क्स व सैनिकवाद की यह धारणा 'उन समय बनाई गई थी जब कि साम्राज्यवाद एक विश्व व्यापी व्यवस्था थी तथा अन्य शक्तियाँ निर्बल थीं। मगर साम्राज्यवाद की युद्ध का परिणाम करने के लिए बाध्य करना दुष्कर कार्य था परन्तु आज इनको रोकने योग्य शक्ति सम्भव है। मगर साम्राज्यवादी युद्धों की आशानों से रोका जा सकता है। इस प्रकार लुइचेव ने रूस की वर्तमान प्रणुणति के चल पर युद्ध की अनिवार्यता के स्थान पर शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व पर जोर दिया। उसके अनुसार युद्ध की अनिवार्यता का अभाव किसी भी प्रकार की क्रांति की प्रक्रिया की धीमा नहीं करता। लुइचेव के वर्तमान उत्तराधिकारी भी इसी नीति में विद्यमान करते हैं।

इस प्रकार जहाँ सैनिक और स्टालिन क्रांति को अनिवार्य बतलाकर अपने दर्शनो की प्रमुख रूप से क्रांतिकारी विचारधारा बना देते हैं-वहाँ लुइचेव शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व की नीति की अपनाने पर मार्क्सवाद के विकासवादी पहलू को पुनः प्रतिष्ठित करता है। परन्तु इतना मानना होगा कि मार्क्स के उत्तराधिकारियों के हाथों में मार्क्सवाद अपने विद्युत् रूप में नहीं रह सका है और इसी प्रकार बदल गया है जिस प्रकार कोई नई वस्तु अनेक हाथों में जाकर अपना प्रारम्भिक स्वरूप खो बैठती है।

चीनी मार्क्सवाद

चीन में साम्यवादी दल के वर्णधार माओत्से तुंग हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में अक्टूबर १९५६ में चीन में साम्यवादी दल द्वारा नक्सलवादी एवं धर्मिकों की लानागाही की स्थापना की गई थी। तब से अब तक माओ ही चीन की साम्यवादी विचारधारा के मुख्य सूत्रधार रहे हैं। मगर चीनी विचारधारा ने रूसी विचारधारा की नीति विभिन्न रूप धारण नहीं किये।

माओत्से तुंग मार्क्स एवं सैनिक में बड़ा प्रभावित हुए हैं, किन्तु उन्होंने उनके निष्ठाओं को चीनी परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर लाया है। जिस प्रकार सैनिकवाद मार्क्सवाद का रूसी संस्करण था, उसी प्रकार माओवाद भी मार्क्सवाद का प्रारणान्तर है। माओ भी इस परिवर्तन की मार्क्स के निष्ठाओं के अनुसार ही समझता क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि—“यदि हम चीन की परिस्थिति के

अनुसूत एक सिद्धान्त का निर्माण नहीं करेंगे, एक ऐसे सिद्धान्त का जो हमारी आवश्यकताओं और निश्चित प्रकृति के अनुरूप नहीं होगा तो हमें अपने प्रापको मार्क्सवादी विचारक कहना एक अनरक्षामित्वहीनता होगी।”¹

माओ ने रुम में सेनिन की अकूतदर क्रान्ति में प्रभावित होकर कहा है कि चीन में रुस की ही भांति क्रान्ति की स्थिति या दिवमान है, यद्यपि उनका स्वरूप भिन्न है। चीनी क्रान्ति रुसी क्रान्ति में भिन्न एक पूँजीवादी जनतांत्रिक क्रान्ति थी, पर उसे भी पूँजीवाद के विनाश तथा साम्यवाद की स्थापना की मध्यकालीन क्रान्ति कहा जा सकता है। माओ ने भी सेनिन की भांति क्रान्ति के लिए साम्यवादी दल और विगैथ रूप से उनके बुद्धिजीवी वर्ग को महत्व दिया है।

कृषि साम्यवाद

माओ ने मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए कृषक वर्ग पर महत्व दिया है, रुस की भांति श्रमिक वर्ग की नहीं। इसका कारण यह है कि चीन प्रमुख रूप से एक गैरीहो देश है, जहाँ प्रम्नी प्रतिशत जनता खेती करती है। इसी कारण माओ मानता है कि वहाँ साम्यवाद उभी सफल होगा जब कि कृषकों के कामों को महत्ता दी जायेगी।

मार्क्सवादी विचारपात्र की तरह माओ भी यह मानता है कि राज्य श्रमिक वर्ग के हाथ में एक दमन यन्त्र है। उनके अनुसार भी साम्यवादी दल शक्ति प्राप्त करने के बाद राज्य की शक्ति का प्रयोग पूँजीपतियों का नाश करने के लिए करेगा। यह केवल साम्यवादियों की ही अधिकार देगा, गैर साम्यवादियों को नहीं। अतः माओवाद साम्यवादियों के लिए प्रजातन्त्र तथा गैर साम्यवादियों के लिए अधिनायक तन्त्र (Democratic Dictatorship) कहा जा सकता है।²

माओ और खुदशेव

माओ खुदशेव के आर्थीन रुम की अन्तर्राष्ट्रीय नीति में दिये गये परिदर्शनों को स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार शक्ति सम्पुलन का साम्यवादियों के पक्ष में हो जाना पूँजीवाद की शक्ति को बढ़ा नहीं देता। नाग्रान्यवाद के रहने मार्क्समोम एवं स्पासी शान्ति स्थापित होना असम्भव है। अतः युद्ध ही वह एकमात्र साधन है जिसके

1. "If we have not created a theory in accordance with China's real necessities, a theory that is our and of a specific nature than it would be irresponsible to call ourselves, marxist theoretician." Quoted by Stuart. R. Schram in the Political Ideas of Maotse Tung.

2. स्वयं माओ ने यह कहा है कि "हमें अधिनायकवादी कहा जाता है यह ठीक है चीनी जनता के विरुद्ध कुछ दमक बलों के अनुभव ने बताया है कि जनता की प्रजातान्त्रिक सत्ताशाही की स्थापना की जानी चाहिए।

माधार पर विश्व व्यापी साम्यवाद की स्थापना की जा सकती है यह मार्सो के दर्शन पर लेनिन के प्रभाव का परिणाम है। मार्सो लुक्सेम पर संशोधनवादी होने का आरोप लगाता है।

वर्तमान काल में साधनों के अतिरिक्त विश्वव्यापी स्ट्रुटेजी एवं नेतृत्व के प्रश्न पर भी रूस व चीन में व्यापक मतभेद है। वह साम्यवादी शिविर की शक्ति के अनेक केन्द्रों के स्थान पर एकल केन्द्र (Monocliticism) का समर्थक है। इस रूप में भी वह लेनिन और स्टालिन का अनुयायी है।

अतः मार्सो की विचारधारा अथवा चीनी साम्यवादी विचारधारा के सम्बन्ध में यह फार्मूला बनाया जा सकता है—

मार्क्सवाद + लेनिनवाद + चीन की परिस्थिति = चीन का मार्क्सवाद या मार्सोवाद।

वर्तमान काल में रूस एवं चीन की साम्यवादी विचारधारा मार्क्स के सिद्धान्तों के दो विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से किसी एक को मार्क्सवाद के अधिक निकट नहीं कहा जा सकता क्योंकि मार्क्स की विचारधारा में दोनों की ही महत्व प्राप्त है। तार्किक दृष्टि से यह सच है कि संशोधनवादियों ने मार्क्स का सही रूप में अनुसरण नहीं किया। कारण स्पष्ट है और वह यह कि यदि स्वयं मार्क्स भी इन नवीन परिस्थितियों में निम्नता से साम्य इन भिन्न और संशोधित दिशाओं को स्वीकार करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती।

BIBLIOGRAPHY

- (1) COKER Recent Political Thought.
- (2) SABINE A History of Political Theory
- (3) LAIDLER : Social and Economic Movements.
- (4) BURNS Idea's in Conflict.
- (5) STUAR-R . Schram : Mao-Tse Tung & Pol. Thought.

राजनीतिक बहुलवाद (POLITICAL PLURALISM)

—गोविन्दराम

१. बहुलवाद राजनीति-ज्ञान में पर्याप्त नवीन सिद्धान्त है। इसका प्रादुर्भाव राज्य की संप्रभुता (Sovereignty) के बारे में एकत्ववाद (Monism) तथा आदर्शवाद (Idealism) के अनुसार प्रदत्त सर्वोच्च स्थान की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। हीगल आदि विचारकों ने राज्य की 'धृष्टी पर ईश्वर का अवतरण'^१ मानकर इसे न केवल वैधानिक (Legal) ही अपितु नैतिक संमति (Moral sanction) भी प्रदान की थी। इससे राज्य सम्पूर्ण शक्तिशाली हो नहीं, बल्कि अनुरक्षणी (irresponsible) भी होने में सक्षम हो सका। इस अवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप ही इस शताब्दी के द्वितीय और तृतीय दशक में डा० जे० एन० फिगिस (J. N. Figgis), ए० डी० लिंडसे (A. D. Lindsay) तथा हेराल्ड लॉन्की (Herold J. Laski) आदि ने इंग्लैंड में, लियोन ड्युगुइट (Leon Duguit) ने फ्रांस में तथा क्रैबे (Krabbe) ने हालैंड में इसका प्रतिपादन किया। एर्नेस्ट बार्कर (Ernest Barker) ने इंग्लैंड में तथा मिस फॉलेट (Mies Follett) ने अमेरिका में इसके आलोचनात्मक रूप को और भी निश्चाय।

यह व्यक्ति, उसकी स्वतन्त्रता एवं मानव सम्पत्तियों की मानव व्यवस्था में उसके स्थान प्रदान करता है। राज्य की सत्ता की ये विचारक सर्वोच्च एवं सम्पूर्ण न मानने हुए सीमित शक्तिशाली मानते हैं। बहुत से मनुष्यों के अस्तित्व के कारण ही राज्य की शक्ति को सीमित मानने का विचार रखा गया है। परन्तु बहुलवाद राज्यविरोधी दर्शन नहीं, संप्रभुता विरोधी है। इसका आदर्श निरंकुश राज्य नहीं, मर्याद स्वरूप राज्य है। उनके अनुसार राज्य की सभी आदर्श सम्पत्ता माना जा सकता है जब वह मानव आदर्शों के लक्ष्य की पूर्ति करे। इस उद्देश्य तथा व्यक्ति के बहुमुखी विकास के उद्देश्य से बहुलवादी विचारकों ने व्यक्ति को सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार गठित धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा राजनैतिक मनुष्यों के प्रति निष्ठा को मान्यता प्रदान की

1. "The state is the march of God on earth."

—Hegel's Philosophy of Rights. P.247.

है। इन्हें राज्य के समकक्ष स्थान प्रदान करते हुए, राज्य को इनके समन्वय (Co-ordination) का कार्य सौंपते हैं। लास्की ने माना है कि सामाजिक स्वरूप सघीय होना चाहिये।¹ अतः यह कहा जा सकता है कि मूलतः और तत्त्वतः बहुनवाद राज्य की संप्रभुता और सद्गति राज्य सम्बन्धी एकलवादी (Monistic) सिद्धान्त का निषेध और उसके स्थान पर एक बहुनवादी राज्य की प्रतिष्ठित करने का प्रयास है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बहुनवाद एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में बीसवीं शताब्दी में ही प्रकट हुआ, परन्तु इसकी विकास की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही बनती चली आ रही थी।

यूनानी नगर राज्य (Greek City-State) में राज्य सर्वोच्च सामाजिक संगठन था। उन्होंने अन्य समुदायों को भी मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य समझा परन्तु राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की। प्लेटो (Plato) ने यहाँ दार्शनिक शासक (Philosopher King) की सर्वोच्च माना वहाँ अरस्तू (Aristotle) ने राज्य को सर्वोच्च संगठन की मान्यता प्रदान की।²

रोमन जनम् में साम्राज्य का स्वरूप प्रकट हुआ तथा रोमन सम्राट् ने साम्राज्य का स्वरूप लिया।

मध्यकाल (Middle Age) में संप्रभुता बहुत सी संस्थाओं में बँटी थी, राज्य ही एकमात्र सत्तापारो संस्था न थी। रोमन चर्च, पवित्र रोमन सम्राट (Holy Roman Emperor), राजा, सामन्त (Feudal Lord), नगर परिषद (Chartered Town) तथा संघ (Guild) प्रभुत्व के सहयोगी थे। बारबार ने इसीलिए मध्यकाल की अराजक-नैतिक तथा राज्य की चर्च का पुनः विभाग माना माना है। 'दो तलवारों के सिद्धान्त' (Theory of the Double Sword) के अनुसार दो संप्रभुओं का विचार पनपा तथा 'राज्य-चर्च-संघर्ष' ने स्थान लिया। पीप तथा राजा का यह सहप्रतिष्ठ बहुनवाद का प्रथम स्तर माना जा सकता है। मैटलैण्ड (Maitland) तथा गीर्के (Otto Gierke) आदि विचारकों ने मध्यकाल में गिल्ड, सीनेट, चर्च आदि के प्रत्यक्ष इन स्वायत्त संस्थाओं (Autonomous Institutions) द्वारा शासन कार्य चलाते की बात करते हुए 'निगम सिद्धान्त' (Theory of Corporations) की उद्भावना की।

1. "The structure of social organisation, if it wants to be adequate, must be federal in character."

—Prof. Laski—"Grammar of Politics"

2. "The state is the highest of all associations which embraces all the rest."

—Aristotle, "The Politics."

१६वीं एवं १७वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई तथा फिर योरोप में कुछ ऐसे देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि) में राष्ट्रीय राज्यों (Nation States) का जन्म हुआ, जिनमें राजनैतिक सत्ता एक स्थान पर केन्द्रित थी। ऐसे राज्यों में प्रभुत्व का रूप एकत्ववादी था तथा उनमें संघों भयवा समुदायों के प्रभुत्व का कोई स्थान न था। एकत्ववादी दर्शन ने नये राष्ट्रीय राज्यों की पृष्ठि की और स्थानवादी अर्थसराज्यवाद को न्यायरहित बताया। बोदी (Bodin) ने अपनी 'डि रिपब्लिका' (De Republica) में राज्य की सर्वोच्च संस्था के रूप में कल्पना की। इससे उसे वैधानिक संप्रभुता (Legal Sovereignty) का संस्थापक कहना अनुचित न होगा। हॉब्स (Hobbes) ने इसी विचारधारा को विकसित करने हुए सराज्यता की अवस्था से तानाशाही को प्रकटा मममा। रूसो (Rousseau) के अनुसार संघों की अनुपस्थिति में ही "सामान्य इच्छा" संभव हो सकती है। ऑस्टिन (John Austin) के मतानुसार केवल "निर्दिष्ट जनघेष्ठ" की आज्ञा ही नियम है। आदर्शवाद ने इस विचारधारा की ओर प्रवृत्ता दी। उद्य आदर्शवादियों ने संप्रभुराज्य को मानव प्रगति का चरम उत्कर्ष बताया। होगल का राज्य "विश्वारामा" या "मूर्त्युपायक विचारतत्व" का प्रतिनिधि या वह ईश्वर तुल्य था। इन विचारकों ने राज्य को साम्य एवं व्यक्ति को भाषन माना। राज्य की यह प्रभुसत्ता धीरे-धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि राज्य समाज की सर्वोच्च शक्ति बनकर मानव जीवन के समस्त पहलुओं पर छा गया। राज्य के कर्णधारों ने इस काठावरण से पर्याप्त लाभ उठाया। संप्रभु राज्य की आदर्श तथा ईश्वर-तुल्य बताकर जनता से कहा गया कि राजनिष्ठा से ही स्वतन्त्रता, नैतिकता एवं प्रगति सम्भव है।

कुछ मानववादी दार्शनिकों ने इस निरंकुशता में व्यक्ति व्यक्तित्व, उसकी नैतिकता एवं स्वतन्त्रता का हनन देखा। उन्होंने इस निरंकुशवाद की अनेक हटिकोणों से आलोचना की। व्यक्ति के अधिक एवं स्वतन्त्रता पर जोर देते हुए उन्होंने संघों को राष्ट्रीय जीवन में उच्च स्थान प्रदान किया। प्रभुत्व के इस केन्द्रीकरण के विरुद्ध इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप राज्यप्रभुत्व की, एकत्व विरोधी बहुत्ववादी विचारधारा का उदय हुआ। शायद लाम्बी ही प्रथम विद्वान् था, जिसे बहुत्ववाद (Pluralism) शब्द का प्रयोग किया।

१६वीं एवं १७वीं शताब्दी में बहुत्ववाद के उदय के लिए बहुत मो दानें दितकर मिल गईं, जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं—

व्यक्तिवादी तत्व — बहुत्ववाद व्यक्ति एवं व्यक्तिस्वातन्त्र्य को ध्यान में रखने हुए हीमनवादी राज्य-सर्वोच्चता के विद्वान्त की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुआ था। जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन नॉक तथा मॉरिस्वू आदि व्यक्तिवादी विचारकों ने व्यक्ति की

स्वतन्त्रता के नाम पर राजकीय सत्ता के केन्द्रीकरण का जो विरोध किया उसमें उस पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, जिसमें बहुनवादी विचारधारा का उदय सम्भव हो सका।

समाजवादी तत्व—समाजवादी विचारधारा में है उन विचारधाराओं के प्रतिपादकों द्वारा बहुनवाद को समर्थन मिला जो राजसत्ता का विरोध करते हैं। इनमें प्रराजकतावाद (Anarchism), मधवाद (Syndicalism) तथा ग्रेटिस्म समाजवाद (Guild Socialism) आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 'मिडीवेट' तथा मधों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा न केवल मान्यता अथवा प्रतिनिधित्व भी प्रदान करने की माँग की। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (Territorial Representation) के स्थान पर व्यावसायिक (Professional) अथवा वocational (Vocational) प्रतिनिधित्व के समर्थक विचारका ने भी बहुनवाद के उदय में योग दिया।

मध्यराष्ट्रीय संघवादी तत्व—गीर् एव गेटवैण्ड आदि विचारकों ने भी बहुनवाद के पक्ष में मदद की। उन्होंने हम सोच ध्यान आकृष्ट किया कि मध्यकाल में बहुत से संघ (Guilds) समाज व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य करते थे तथा राज्य के समान ही महत्वपूर्ण थे। उसी दूर पर इन समय भी मनुष्य के विभिन्न समूहों अथवा समुदायों की प्रभुता का भागी बनाया जाय तो समाज बर्याण अधिक सम्भव होगा। जिस ने भी समूहों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, राज्य की अहंतावादी न बताते हुए 'संघों का मय' बताया। यह विचार सात्की, कोल, डिगे, बार्बर आदि के लिए पक्ष प्रदर्शक हुआ।

राज्य की कार्य वृद्धि—१९वीं शताब्दी में राज्य के कार्य अत्यन्त बढ़ गए। इन बहुमुत्तीय कार्यों की पूर्ति के राज्य समर्थक था। राज्य के कार्यों के विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें यह एक लोकतांत्रिक-कारी राज्य (Welfare State) का स्थान ले सके।

विधि शास्त्रवादी तत्व—बानून राज्य में ऊपर की वस्तु है, विधिसाक्षियों के इस प्रतिपादन से निश्चय ही राज्य की प्रभुता की अनन्यता सम्बन्धी मान्यता को पक्का लगा और बहुनवादी विचारधारा के प्रादुर्भाव का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय तत्व—अन्तर्राष्ट्रीयवादियों ने भी राज्य की संप्रभुता पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की आवश्यकता मान कर बहुनवाद को समर्थन प्रदान की। बहुनवादी दर्शन के सिद्धान्त

बहुनवाद एतत्ववाद (Monism) एवं प्रराजकतावाद (Anarchism) के मध्य की स्थिति सम्पन्न है। यह प्रराजकतावादियों की तरह राज्य का अस्त नहीं चाहता; राज्य की अनिवार्यता स्वीकार करता है। परन्तु यह अनिवार्यता एतत्ववादी अनिवार्यता का थोड़ा "दीर्घकाय" या "निश्चित जनश्रेष्ठ की उपस्थिति की देता है, यही बहुनवाद उसी अनिवार्यता अन्तिम स्वीकार करता है कि वह 'संघों का मय' है तथा मय-

न्यय का कार्य करता है। यह आदर्शवाद में भी निहित है। जहाँ आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक मय्या है क्योंकि वह "विद्वत्वात्मा" एवं सामान्य इच्छा का प्रतिधित्व करता है, वहाँ दृढ़तावाद के अनुसार राज्य को तभी आदर्श मय्या माना जा सकता है जब वह आदर्श ध्येय (व्यक्ति की प्रगति) में महायक हो। प्रो. कोकर (F. W. Coker) के मतानुसार दृढ़तावाद संप्रभुता विहीन राज्य का पक्षपाती है, उसकी आदर्श व्यवस्था में राज्य का स्थान है परन्तु अद्वैतवादी संप्रभुता का नहीं।¹

मूलतः दृढ़तावादी विचारधारा राज्य की संप्रभुता और तद्वर्जित राज्य मन्धन्गी एकतावादी (Monistic) सिद्धान्त का निषेध और उसके स्थान पर दृढ़तावादी राज्य का प्रतिष्ठित करने का प्रयास है। इसलिए संप्रभुता के अर्थ और एकत्ववादी राज्य के स्वरूप के विषय में कुछ गन्द नितान्त आवश्यक हैं।

संप्रभुता का सिद्धान्त—संप्रभुता के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र में एक ही संप्रभुता होती है और अन्य सभी व्यक्ति तथा समुदाय उसके अधीन होते हैं। यह सर्वोच्च समा राज्य की मना होती है। संप्रभु राज्य अपने अन्तर्गत सभी व्यक्तियों एवं समुदायों का नियन्त्रण करता है और उनके व्यवहार के लिए कानून बनाता है। कानून बनाने का उसका यह अधिकार मौलिक (Original), स्थायी (Eternal) सर्व-प्रापी (All pervasive), अविभाजनीय (Indivisible) तथा निराल होना है और यही राज्य की संप्रभुता होती है। चूँकि राज्य संप्रभु होता है, अतः सम्पूर्ण समाज का नियन्त्रण एवं नियमन उसके निराल अधिकार की वस्तु होती है। राज्य के अधिकार की इस एक्युनता को ही राजनैतिक एकत्ववाद (Political Monism) कहते हैं जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज की सम्पूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केन्द्र एक राज्य होता है। बोदा (Bodin) की प्राथमिक युग में संप्रभुता के विकास में हॉब्स (Hobbes), रूसो (Rousseau) तथा बेन्थम (Bentham) का कार्य उल्लेखनीय है। इस सिद्धान्त को पूर्णता देने का श्रेय १९वीं सताब्दी के सुविख्यात अंग्रेज न्यायविद् जॉन ऑस्टिन (John Austin) को है।

राजनैतिक एकत्ववाद के इस विचार के विरुद्ध बहुसमुदायवादियों ने विचार प्रकट करने हेतु राज्य की संप्रभुता पर कड़ा प्रहार किया। राज्य की संप्रभुता पर यह प्रहार तीन प्रकार का किया गया। प्रथम, राज्य सरकार के अन्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समुदायों के उच्चतर नहीं हैं, अतः सर्वोच्चता विभाजनीय है एवं शीत अन्य समुदायों द्वारा भी बाँटी जाने योग्य है, द्वितीय, राज्य दूसरे राज्यों से सम्बन्ध में स्वतन्त्र नहीं होता चाहिए, तृतीय, राज्य कानून में ऊपर नहीं, बल्कि कानून राज्य में ऊपर तथा स्वतन्त्र है। इन तीन आधारों पर दृढ़तावादियों के विचारों का उल्लेख निम्नानुसार जाना जा सकता है।

राज्य सर्वोच्चता एवं समूह स्वायत्तता

(State Sovereignty and Group Autonomy)

बहुलवाद हीगलतादियो द्वारा राज्य को सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न (Omnipotent) तथा वैधानिक एवं नैतिक (Legally and morally) रूप से सर्वोच्च मान जाने का विचारधारा पर प्रहार करता है। उनका मत है कि व्यक्ति व हित के लिए बहुत से आवश्यक समुदाया में राज्य भी एक है। मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न समुदायों की आवश्यकता है। कोकर (F W Coker) के शब्दों में, मनुष्य का सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार वह धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक बहुत से समूहों का पनपाना है जिनमें से कोई भी नैतिक अथवा व्यावहारिक दृष्टि से हमारे उच्चतर नहीं है।¹

बहुलवाद की जड़ें सम्प्रकार की 'गिल्ड प्रथा' (Guild System) में थी। उस समय की व्यावसायिक गिल्ड स्वायत्तता (Autonomy) का उपयोग करके हुए निगम (Corporation) का स्वरूप लिए थे। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के साथ इनका पतन हो गया। ग्रीकों (Greeks) ने जर्मनी में तथा मॉन्टेनैग (Mantland) ने इंग्लैंड में आधुनिक समय के बहुलवाद का जन्म दिया। उनके अनुसार प्रत्येक सगठित समुदाय अपना स्वतन्त्र अस्तित्व एवं एक 'वास्तविक व्यक्तित्व' (Real Personality) तथा अलग सामूहिक चेतना (Collective Consciousness) रखता है। कानून निर्माण में हिस्से का अधिकार रखता है। वे राज्य का विभिन्न समुदायों में संयोजक के रूप में स्वीकार करते हैं परन्तु इनमें ऊपर नहीं मानते।

फिगिस (Dr J N Figgis) वर्ष आदि सामाजिक समूहों में राज्य के अनाधिकार प्रवेश का खेड़ा की आलोचना करते हुए उन्हें स्वनिर्भर होकर विद्यमान करने का मत रखता है। राज्य इनमें सामंजस्य पैदा कर सकता है, निदरता नहीं।

पॉन्-बॉन्कर (M Paul Boncour) तथा डर्वहाइम (Durkheim) ने समाज के व्यावसायिक एवं आर्थिक समूहों (Professional and Economic Groups) के आधार पर खोजने तथा राजनैतिक प्रतिनिधि व प्रभुत्व करने की मांग की।

लास्की (Laski) ने समुदायों का बहुत से समूहों (Groups) द्वारा बँटने का विचार रखा। उसके अनुसार राज्य एक मध्यस्थकर्ता का कार्य करे, परन्तु संपूर्ण शक्ति का अधिकारी नहीं। उसने अनुसार सत्ता का गर्भीय स्वरूप होना चाहिए।²

1. "Man's social nature they maintain finds expression in numerous groupings, pursuing various ends religious, social, economic, professional, political, no one of the groups is superior morally or practically to the others."

—F W Coker Recent Political Thought, Page 497.

2. "Authority should be federal."

—Laski "Grammar of Politics."

ग्रेगो-समाजवादी (Guild Socialist) कोन (G. D. H. Cole) के अनुसार समाज का स्वरूप संघीय (Federal) है अतः संघभूता के एकत्व पर आधारीत राज्य ऐसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। साथ ही राज्य सम्पूर्ण समाज की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अतः केवल उसे ही शक्ति प्रयोग का अधिकार प्रदान करना प्राप्त नहीं होना चाहिए। उनकी कल्पना के समाज का संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें उपनोक्तताओं और टपाइयों के स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर के स्वतन्त्र और दृढ़ संघ हों। उपनोक्तताओं के संघों का प्रतिनिधित्व प्रादेशिक (Territorial) एवं टपाइयों के संघों का प्रतिनिधित्व व्यावसायिक (Functional) हो। इस प्रकार कोन ने भी अपनी ग्रेगो-समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभुता की सहूलता का समर्थन किया।

मेकाइवर (Maciver) ने विभिन्न समुदायों में से राज्य की भी एक माना है, हालांकि राज्य एक विशेष कार्य की सिद्धि करता है।¹ यह एक निगम के समान रहता है। राज्य के निश्चित एवं सीमित शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व हैं। राज्य का कार्य समाज की व्यवस्था में एक-वैध करना है। मेकाइवर वैधानिक संघभूता के सिद्धान्त की भी गलत सिद्धि करता है। वह शक्ति की बात करता है जब कि राज्य की सेवा आध्य है तथा शक्ति साधन।

लिनसे (Dr. Lindsay) ने तो राज्य के सघनत्व के विरोध में यही तर्क कह दिया है कि "यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रभुत्व सघन राज्य के सिद्धान्त का लक्षण हो चुका है।"² उसने संघों की आवश्यकता पर इन दोष दिए हैं कि वे वह कार्य पूरा करते हैं जो राज्य नहीं कर सकता। राज्य आवश्यक तो है पर वह संघों का संघ है। उसके अनुसार मानव जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान केवल एक ही संस्था द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है। राज्य का कार्य अधिक से अधिक विविध संघों में समन्वय स्थापित करना हो सकता है।

बार्कर (Barker) हालांकि सभूतों के 'वास्तविक व्यक्तित्व' (Real Personality) के विचार को स्वीकार नहीं करता पर वह भी यह मानता है कि समाज में पाये जाने वाले विविध समुदाय राज्य से पूर्वजातीय हैं और उनमें से प्रदेश के राज्य से एक-एक अनेक-अनेक कार्य हैं। इन समुदायों का सामाजिक जीवन में राज्य है कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की सब आवश्यकताएँ राज्य के अतिरिक्त अनेक समुदायों

1. "The business of the state is merely to give a form of unity to the whole system of social relationship." — Maciver.
2. "If we look at the facts, it is clear enough that the theory of sovereign state has broken down." — Lindsay.

के बिना पूरी नहीं हो सकती। उसने व्यक्ति के स्थान पर समुदाय का समान की इकाई मानते हुए कहा है कि सब प्रश्न "व्यक्ति बनाम राज्य" का नहीं, बल्कि "समुदाय बनाम राज्य" का हो गया है। फिर भी व्यक्ति व अधिकांश की सुरक्षा एवं उसे समुदाय व अत्याचार से बचाने का कार्य बार्कर व अनुसार बहुलवादी समाज में भी राज्य का ही रहता है। इन सम्बन्ध में बार्कर का कहना है कि "सम्पूर्ण जीवन का योजना का प्रतीक होने के कारण राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने, अन्य समुदाय के तथा उनके सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाये रखे। अपने सम्बन्धों का सामंजस्य बनाये रखना इसलिए आवश्यक है कि उसकी योजना सुरक्षित बनी रहे तथा अन्धों के साथ सम्बन्धों का सामंजस्य इसलिए आवश्यक है कि बालू के समान सब समुदाय की समानता बनी रहे और समुदाय के सम्मानित अत्याचार से व्यक्ति की रक्षा हो सके।"¹

वास्तव में वैज्ञानिक मानववाद तथा लोककल्याणकारी राज्य के विचार के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के इनके विकास हो जाने पर राष्ट्रीय सर्वोच्चता प्रत्येक राज्य की सप्रभुता उपहासपद की लगती है इसलिए विश्व संघ (World Federation) का विचार पनपा।

राज्य की सप्रभुता एवं अन्तर्राष्ट्रवाद (State Sovereignty and Internationalism)

कुछ समय से अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र तथा विश्वशांति एवं व्यवस्था के समर्थकों द्वारा बाह्यसप्रभुता के सिद्धान्त (The Doctrine of External Sovereignty) का विरोध किया जा रहा है। उनके अनुसार आन्तरिक रूप से (Internally) चाहे राज्य सप्रभु हो, परन्तु बाह्य मामलों में इसे सुना नहीं दिया जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सहभावना व समर्पकता (Laski) ने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राज्य की सप्रभुता का विरोध किया। उनके अनुसार यह युग अन्तर्राष्ट्रीय एकाता, सहयोग और आन्तरिक सहभावना का है। ऐसी परिस्थिति में एकात्मवाद और शान्ति व प्रभुत्व सम्बन्धी सिद्धान्त से काम नहीं चल सकता। कोई भी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से समीप प्रभुत्व वाला नहीं रह गया है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बालू उनको प्रभुता की नीमिष कर रहे हैं। कोई भी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बालू, अन्तर्राष्ट्रीय अधियों तथा नैतिकता की उल्लंघना नहीं कर सकता। पर यह कहना कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य

1. "The state, as a general and embracing scheme of life, must necessarily adjust the relations of associations to itself, to other associations and to their own members, to itself, to maintain the integrity of its own scheme, to other associations in order to preserve the equality of associations before law, and to their own members in order to preserve the individual from possible tyranny of the group"

सर्वोच्च तथा सम्पन्न है, निरर्थक है। राष्ट्रों का कहना है कि "अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतन्त्र एवं सर्वोच्च तथा सम्पन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है।"¹ इसी कारण उनमें यह प्रतिपादित किया है कि "यदि संप्रभुत्व सम्बन्धी सम्पूर्ण विचार का त्याग कर दिया जाय तो यह समाज के लिए एक स्पष्ट लाभ होगा।"²

राज्य की संप्रभुता एवं कानून (State Sovereignty and Law)

डुगु (Duguit) ने ध्यान में तथा क्रेब (Krabbe) ने हागे-ड में दूनवाद के समर्थन में कानून के दृष्टिकोण से मार्ग। वे इस बात का स्वीकार नहीं करते कि कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य का प्राप्ति है। विरो के अनुसार कानून की शक्ति राज्य की शक्ति से स्वतन्त्र है।³ इसके अनुसार कानून राजनैतिक संगठन से स्वतन्त्र, जब तथा प्राचीन है और कानून उद्देश्य सम्बन्धी (Objective) है, न कि अधिकार सम्बन्धी (Subjective)।⁴ कानून सामाजिक न्यायिक व्यवस्था मनुष्यों की सम्पन्निकर्षता का दशा है। वे सामाजिक हित में हैं, इसलिए उनका पालन होता है। कानून राज्य को बाध्य करते हैं, कानून राज्य से बाध्य नहीं। प्रत्येक राज्य के कर्तव्यों पर बल दिया जाय न कि अधिकारों पर। राज्य का गुरु जनसेवा (Public service) है न कि संप्रभुता का उभरण। गेटेल (Gettell) ने उक्तु ही कहा है—"जिसे की प्राथमिक रूप से सामाजिक मनुष्यों का राज्य न राजनैतिक मनुष्य दिवसाने में ही खि नहीं है इसकी मुख्य खि प्रगामकोय कायों पर न्यायिक प्रतिबन्ध नगाकर एक उतरदायी राज्य के सिद्धान्त के विकास में है।"⁵ वास्तु में सामाजिक स्वायत्त (Social Solidarity) उसका उतरदायी का आधार।⁶ इस प्रकार विरो न न्यायानियों की शक्ति दशा दो, कानून का उतरदायी हुमा तथा राज्य दशा केवाला क निर न्यायानियों के प्रति उतरदायी हुमा।

क्रेब (Krabbe) न भी विरो के अनुसार मत रखते हुए कानून का राज्य से

1 "The nation of an independent sovereign state is on international side, fatal to the well-being of the humanity" —Laski

2 "It would be of lasting benefit to the society if the whole concept of sovereignty is surrendered" —Laski

3 "The authority of law is independent of state power"

—Duguit

4 "Law is independent of, superior and anterior to, political organisation, and that law is objective, not subjective" —Duguit.

5 "Duguit is not primarily interested in the political importance of social groups within the state; his chief interest lies in placing judicial limitations on administrative action and in developing the theory of state responsibility."

—Gettell.

उच्चतर माना है। यह राज्य के निवासियों के विवेक से सफल होता है। गति राज्य का आवश्यक गुण नहीं, राज्य एक वैधानिक समुदाय है। इस प्रकार इन विचारकों ने राज्य पर भी कानून की सीमा मान कर राज्य की संप्रभुता सम्मर्या। इस विचार का विरोध किया कि 'कानून संप्रभु का उद्देश्य है।'¹

राज्य की संप्रभुता के बारे में ए० डी० लिंडसे (A D Lindsay) का मत है कि 'यदि हम तथ्यों पर देखते हैं तो यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता सम्प्रदाय का सिद्धान्त भंग हो चुका है।'² बार्कर (Barker) के अनुसार "कोई भी राजनैतिक धारणा इतनी निष्पन्न नहीं हो गई है, जितना कि संप्रभुता सम्प्रदाय का सिद्धान्त।'³ लास्की (Laski) की राय में "संप्रभुता के कानूनी सिद्धान्त को राजनैतिक दार्शनिकों के लिए मायब बना देना प्रसम्भव है।'⁴ क्रेब (Krabbe) ने तो यहाँ तक कह डाला है कि "संप्रभुता की धारणा को राजनीतिशास्त्र में से निष्काश देना चाहिए।'⁵

इन विचारों से स्पष्ट है कि एक के स्थान पर अनेकों की प्रतिष्ठा बहुलवाद है। समाज में राजनैतिक संप्रभु एकमात्र राज्य ही नहीं, अनेक हैं। इसके अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र एवं राज्य के समक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। ये समुदाय राज्य के अधीन न होकर उनके समक्ष होने चाहिए और इस प्रकार समाज का मजबूत संप्रभुता की दृष्टि से एकात्मक न होकर सघातमय होना चाहिए।

सैद्धान्तिक दुर्बलतायें

एकत्ववाद (Monism) की प्रतिपादना के विरोध में जब बहुलवादी भी प्रतिपादना से काम लेते हैं, तो इनका दृष्टिकोण निम्नवत् ही ऐसा हो जाता है जिसे एकत्ववादी अनर्थवाद के जोड़ में बहुलवादी अनर्थ की सजा दी जा सकती है। उदाहरणार्थ लिंडसे के इस दृष्टान्त की मान्यता कि "संप्रभु राज्य का सिद्धान्त वस्तुतः खण्डित हो चुका

1 'Law is the command of the sovereign'

2 "If we look at the facts it is clear enough that the theory of the sovereign state has broken down" —A D Lindsay

3 'No political phenomenon has become more arid and unfruitful than the doctrine of the sovereign state' —Barker

4 "It is possible to make the legal theory of sovereignty valid for political philosophy" —Laski

5 'The notion of sovereignty must be expunged from political theory' —Krabbe.

है।¹ 2 दार्कर की इन टिप्पणी को ठीक मान कर कि "राजनैतिशास्त्र में संप्रभु राज्य के सिद्धान्त से दूरकर शुष्क और व्यर्थ का विषय कोई नहीं है,"³ क्रैब के इन मुन्नात्र की मान कर कि "संप्रभुता के सिद्धान्त को राजनीति से हटा देना चाहिये,"³ कोल के इस मत को मानकर कि "सर्वशक्तिमान, सर्वनियन्त्रा, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापी तथा सार्वभौम राज्य की कल्पना अब अतीत की बात हो गई है" अथवा सास्की के इस मुन्नात्र की मान कर कि "यदि संप्रभुता के विचार को त्याग दिया जाय तो राजनैतिशास्त्र को स्पाई लाभ होगा,"⁴ यदि बिना राजकीय संप्रभुता के राजनैतिक समाज की कल्पना की जाय तो मनर्थ के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दशा में सब समुदाय अपनी-अपनी बतायेंगे, वह एक अपराजकता (Anarchy) की दशा होगी।

मनी दूनवादी विचारक इन तथ्य के प्रति सजग हैं कि एक संस्था को संप्रभु बनाये बिना राजनैतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ कारण है कि सभी ने विविध समुदायों के अस्तित्व, उनकी स्वतन्त्रता के विवेकीकरण आदि की बात करने हुए भी, एक ऐसी संस्था के अस्तित्व को अवश्य स्वीकार किया है जो विविध समुदायों के सम्बन्धों में सामञ्जस्य बनाये रख सके तथा समन्वय (Coordination) का कार्य कर सके। लास्की जैसा स्वतन्त्रता (Liberty) का तीव्र समर्थक भी राज्य को सामंजस्य स्थापना के प्रतिरिक्त राष्ट्रीय उद्योग के प्रवन्ध तथा मवाजन का अधिचार देते हुए कहता है कि 'वैधानिक दृष्टि में यह प्रमाण नहीं आ सकता कि प्रत्येक राज्य में किसी न किसी ढंग की मता प्रतीयित होती है।'⁵ राज्य के ये कार्य ऐसे हैं जिनके सम्पादन में सम्बन्धित शक्ति राज्य के पास होने के कारण उनकी स्थिति अन्य समुदायों से उच्चतर हो जायेगी। यहाँ कारण है कि दूनवादियों की यह कह कर आलापना की जाती है कि वे "संप्रभुता को सामने के द्वार में बाहर निकाल कर पीछे के द्वार में पुनः पापस लाते हैं।" कान्टविक्रता यह है कि दूनवादी विचारकों में यह अन्तविरोध है कि वे सिद्धान्त रूप में राजकीय संप्रभुत्व का बड़े उत्साह में विरोध करें, जब उनके संस्थापक पक्ष की बात करने हैं, तो बिबस हाकर उन्हें राज्य के संप्रभुत्व का मनर्थन किसी न

1. 'The theory of sovereign state has broken down.'—Lindsay.

2. "No political common place has become more arid and unfruitful than the doctrine of the sovereign state" —Barker.

3. 'The theory of sovereignty must be expunged from politics' —Krabbe.

4. "It would be of lasting benefit to the society, if the whole concept of sovereignty is surrendered" —Laski.

5. "Legally no one can deny that there exists in every state some organ whose authority is unlimited" —Laski.

किसी रूप में व्यक्त करना पड़ता है। समाजशास्त्री विधि विधानों द्वारा राज्य के सम्प्रभुत्व का विरोध एकपातीय है। कानून का आधार न तो केवल सामाजिक माय्यता ही है और न केवल राजकीय स्वीकृति। सामाजिक माय्यता यदि उसके विषय का निरूपण करती है तो राजकीय स्वीकृति उसका रूप निधारण करती है। यह कानून के सम्बन्ध में रूप निर्धारण सम्बन्धी प्रसुता हमें राज्य को ध्वंस्य नहीं होगी।

बहुसमुदायवादियों ने समुदायों के स्वतन्त्र प्रभुत्वपूर्ण अस्तित्व के आधार पर व्यक्ति की बहुमुखी उत्पत्ति की वामना की है परन्तु हमें समुदाय पूर्णतः निरवुग हो जायेगे। समुदायों को पूर्णतः निरवुग मानने से उनकी स्थिति भी बड़ी हो सकती है जिसका बोझ हम प्रभुत्व सम्पन्न राज्य को मानने हैं और राज्य की तरह समुदाय माय्य तथा व्यक्ति माय्य बन सकता है। व्यक्ति को इस प्रकार की स्थिति में बसाने के लिए राज्य की सर्वोच्चता व्यक्ति एवं समुदायों दोनों पर आवश्यक है चाहे हमें बहुलवाद का विचार भी स्पष्ट न हो। स्वयं बार्बर ने भी 'सामुदायिक अत्याचार (Group tyranny) से व्यक्ति को रक्षा करने का कार्य राज्य का बताया है।

इस प्रकार बहुलवादी विचारधारा विरोधियों से भरी हुई है। इनके विचारों निश्चित सत्य के प्रति एकमत नहीं हैं। ये बहुलवादी समाज की संगठन, सत्यता, अधिकार, निष्ठा, नियंत्रण, समन्वय, सामंजस्य आदि की समस्याओं के बारे में निश्चित निष्कर्ष नहीं निजाल सके। ये जिस राज्य की सम्प्रभुता एवं एकलवादी (Montinistic) मिश्रण की मान्यता करने वाले थे पूरे रूप से तथा विचारों को ही सत्ता प्रयोग रूप में स्वीकार कर लेते हैं।

बहुलवाद की दो और भट्ट

बहुलवाद में अराजकतावाद एवं एकरववाद (Monism) का सत्य की स्थिति मिले हुए, एकरववाद की प्रतिगमता के जोड़ में यद्यपि अनेक ऐसी बातों का प्रतिपादन भी किया है जो प्रतिगमतापूर्ण हैं तथा विरोधियों से एक असंगति में युक्त है फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि बहुलवाद ने एकरववाद के उस एकाधिकारवादी गढ़ की ध्वंस करने का जनवाद की पुष्टि की है जिसकी छाड़ में समय-समय पर व्यक्ति को राज्य का दास बनाया जाना रहा है और जगत के समस्त इस सत्य की ओर स्पष्ट प्रकट कर दिया है कि व्यक्ति के सर्वोच्चतम विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने जीवन के विविध चरित्रों से सम्बन्धित विविध समुदायों का अन्तर्गत सम्पठित होने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उसके इन समुदायों को मानव जीवन के विकास के लिए कार्य करने की आवश्यक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार हमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य सोचान्वय यह नहीं है, जिसमें व्यक्ति निर्वाक्य के समस्त मत धारण कर कर दे और वे सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का भवामन एवं केन्द्र में होता रहे

वरन् मन्वा लोकतन्त्र वह है जिसमें मन्वा का विकेन्द्रीकरण हो, व्यक्ति सामाजिक जीवन की समस्याओं के प्रति सदा मुक्त रहे और भाषाईक सामाजिक विकास में वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग दे सके । इसके फलस्वरूप मन्वा प्रगतिशील नेताओं ने विकेन्द्रीकरण, संघों के अस्तित्व और वैयक्तिक स्वतन्त्रता की आदर्श व्यवस्था स्वीकार किया ।

राजनैतिक विन्तन के इतिहास में दण्डवाद की यह सेवा एवं योगदान महत्वपूर्ण है कि राज्य समूह जीवन (Group life) को समझ सका । यह स्वीकार किया गया कि व्यक्ति के दण्डनीय विकास में उसके दण्ड में धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक एवं राजनैतिक समुदायों का योगदान है तथा इन्हें राज्य के समक्ष मान्यता प्रदान हो, राज्य का इन पर सीमित अधिकार हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी दण्डवाद ने मानववाद (Humanism) तथा अन्तर्राष्ट्रवाद (Internationalism) के आधार पर, अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International law) के अन्तर्गत विश्वशांति-सहयोग-सहअस्तित्व एवं सहभावना के लिए राज्यों की बाह्य संप्रभुता (External Sovereignty) पर नियन्त्रण की बात कर महत्वपूर्ण कार्य किया । परिणामस्वरूप हम राष्ट्रसंघ (League of Nations) तथा हार्ग न्यायालय (Hague Tribunal) ने इन और कदम बढ़ाया तथा मात्र संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization) की संरचनाओं को देखते हुए हम 'विश्व संघ' (World Federation) के संरक्षण में मानवता की सुरक्षा की परिच्छिन्ना कर रहे हैं ।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि हालांकि दण्डवाद की विचारधारा पूर्ण स्पष्ट एवं निश्चित उद्देश्यों वाली न होकर मदान् विरोधानामों तथा अस्पष्टताओं में युक्त है, फिर भी इसने राज्यों की बाह्य एवं आन्तरिक संप्रभुता पर नियंत्रण लगाने हुए उसे शक्ति प्रयोज्य के स्थान पर समाजके दाने में मदद की है ।

BIBLIOGRAPHY

1. COPER. F. W. : "Recent Political Thought," Ch. XVIII.
2. LASKI H. J. : "The Problems of Sovereignty" (1917)
: "Authority in the Modern State." (1919)
: "A Grammar of Politics." (1925)
3. MACIVER : "The Modern State."
4. BARKER E. : "Political Thought in England from Spencer to Today."
5. AUSTIN, J. : "Lectures in Jurisprudence-Vol 1, Lecture VI.

नेहरू की विरासत

(LEGACY OF NEHRU)

—विद्यासागर शर्मा

“नेहरूजी के सक्रिय और सार्वदेशिक नेतृत्व के बिना भारत के स्वरूप का चिन्तन लगभग असम्भव या सपना है। हमारे देश के इतिहास का एक युग समाप्त हो गया है।”¹

वास्तव में 27 मई, 1964 को श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के साथ भारत में एक युग की समाप्ति होती है, जिसे ‘नेहरू युग’ (Era of Nehru) कहा जा सकता है। वैसे 1916 में कांग्रेस के ‘सत्यनन्द-सम्मेलन’ में महात्मा गांधी से प्रथम भेंट के साथ नेहरूजी का राजनीतिक जीवन प्रारम्भ हुआ था। बाद में ‘होम रूल लीग’ एवं ‘समूहयोग आन्दोलन’ में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। परन्तु ‘नेहरू युग’ का प्रारम्भ 1929 से माना जा सकता है, जब कांग्रेस ने उसी सम्मेलन में ‘साहौर-सम्मेलन’ में ‘पूर्ण स्वाधीनता’ (Complete Independence) के लक्ष्य की घोषणा की थी। 1929 से 1946 तक ‘नेहरू युग’ का ‘पूर्वकाल’ एवं 1947 से 1964 तक ‘उत्तर काल’ माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में नेहरूजी ने समाजसेवी, जागरूक प्रहरी, बीर योद्धा, राष्ट्र प्रेमी एवं एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आन्दोलन का सफल संचालन किया था। 2 सितम्बर, 1946 को गठित ‘अन्तरिम सरकार’ (Interim Government) में कार्य-कारिणी समिति के उपप्रधान मन्त्री के रूप में स्वतन्त्र भारत के प्रथम मन्त्री, विदेश मन्त्री तथा योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य पर्यन्त भारत के नवनिर्माण, प्रगति, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास द्वारा मनीनीकरण, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, धर्म-निरपेक्षवाद तथा एक मौलिक एवं स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के स्थाप की प्रति हेतु जीवन भर लूफने रहे। एक अन्तर्राष्ट्रवादी व मानवमात्र के

1 ‘It will be difficult to reconcile ourselves to the image of India without Nehru's active and all pervasive leadership. An epoch in our country's history has come to a close’

—Dr. R. L. Krishnan ‘The Hindustan Times’ (May 29, 1954)

कल्याण के इच्छुक होने व मात्र विरव-व-शुल, मृदुमेय एवं मृदुभावना, शान्तिपूर्ण सहस्रान्तिव, सहिष्णुता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और सश्रुता, पंचशील, अन्तर्गतता, निष्पक्षीकरण तथा सश्रुति के शान्तिपूर्ण खनातनक प्रयोग पर वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दल देकर नेहरूजी ने न बवल 'प्रोग्रेसिव आन्दोलन' अथवा मनुक्त राष्ट्रसंघ का समर्थन किया, अपितु समस्त मानवता के कल्याण का मूत्रनर रह 'रा' के महामानव' का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

भारत व विश्व का नेहरूजी की विद्यमान का वर्णन करने से पूर्व, नेहरूजी की 1947 में नेहरू नमानने के समय विद्यमान में मिली सम्मिल एव विद्वत् समन्वयों का परिचय अनिवार्य है, जिन्हे यह जाना जा सके कि उन्होंने किस स्थिति में शान्त नगर सम्नासा था। दो महाजिदों के दान्विरोधीय शेषरु तथा विश्व युद्ध के विनाश के परिणामस्वरूप देश का आर्थिक दम्भ दिव्य हुआ था। निर्धनता के साथ ही शान्त व अन्धविश्वास का बोधवना था। विनाशन शाय प्रभुत ईश्वरों कटु मनोदधि व्याप्त थी। 600 'देशी-रिपब्लिक्स' (Native States) देश को एकता में बाधक थी। सामान्य जनता प्रजातान्त्रिक स्वशासन (Democratic self-government) के अनिष्ठा व मन्त्री शक्ति के प्रति प्रजातृत होते हुए भी स्वोन शान्तकर्ताओं से पुनर्वास व विद्वान समन्वयी जलिन समन्वयों के दीप्त समवाधान की आकांक्षा कर रही थी। महाना गांधी भी हमारे नेहरूजीन होने के कुछ ही समय बाद, बुद्धि शत्रुत्व व बलता शाय देश का राजनीतिक एकिकरण करने वाले सरकार बलननवाई पाले जैसे योग्य नदी की कृष्ण से नेहरूजी पर कान का बोध और अधिक का मया। कश्मीर पर आक्रमण गांधीजी व कांग्रेस शाय निर्धारित शान्तिवादी नीति को एक चुनौती था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शीतयुद्ध (Cold War) की स्थिति व्याप्त थी। इन सब समन्वयों एवं परिस्थितियों की ध्यान में रखते हुए ही नेहरूजी ने भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक परम्पराओं, गांधी व टैगोर के मानववाद, बुद्ध व महात्मा की कल्याणपूर्ण महिमा तथा वैज्ञानिक मानववाद (Scientific humanism) पर आधारित विश्वामूर्त मानव मानवताओं की वदभावना की। उनकी मानवता के प्रति सेवा एवं विद्यमान का मृदुभावना भारतीय मन्त्र में दानुक्त हो गया था —

"राष्ट्रनिता (महाना गांधी) के देहान्त के बाद यह राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा क्षति है — श्री जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मुख्य मन्त्री हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन न केवल राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य, एकता एवं स्थानिक के प्रार्थों के लिए, अपितु विश्वशान्ति तथा प्रगति के लिए भी समर्पण अर्पित था।"¹

1 "The country has suffered its greatest loss since the death of the Father of the Nation. Jawaharlal Nehru was the chief architect of modern India. His entire life was dedicated not only

राष्ट्रीय विरासत (National Legacy)

मार्शल ,टोटो के ये शब्द ब्याप्य हैं कि 'नेहरूजी आधुनिक भारत के पिता' थे ।¹ १७ वर्ष तक देश के एकमात्र नेता, शासक व नियामक रह कर नेहरूजी ने देश का एक करने, जनतन्त्र की जड़ें मजबूत करने एवं प्रजासत्ता की स्थापित्व प्रदान करने हुए नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए भागीरथ प्रयत्न किया ।

प्रजातन्त्र (Democracy)

भारत ने नेहरूजी के नेतृत्व में प्रजातान्त्रिक विरासत दिया । भारत के प्रजातान्त्रिक संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत नागरिक अधिकारों का पूर्ण ध्यान रखा गया है । नेहरूजी ने पारम्परिक साहित्य एवं दर्शन का गहन अध्ययन तथा राजनैतिक व्यवस्था और संस्थाओं का अवलोकन किया था, अतः वे भारत में भी संसदीय जनतन्त्र (Parliamentary Democracy) द्वारा प्रजातन्त्र की नींव डालने एवं स्वयं परम्पराओं को जन्म देने में सफल हो सके । उन्होंने विश्व के सबसे बड़े प्रजातान्त्रिक देश के लगभग १७ वर्ष तक प्रधानमंत्री रह कर संसद् व संसदीय जनतन्त्र के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये । अपने भाषणा व यात्राओं द्वारा जनमन्यर्क हासिल कर वे भारत की जनता के हृदय सम्राट् बन गए थे । उन्होंने विरोधी दल के महत्त्व को समझते हुए उनके विकास व पनपने की हार्दिक इच्छा रखी । परन्तु उनके अनुसार प्रजातन्त्र का सत्य आधेगुल उभ था—

"प्रजातन्त्र सामान्यस्वरूप, मतदान, चुनाव आदि से बड़ कर कुछ और है । अन्तःसंगतता, यह एक विशेष प्रकार के चिन्तन, कार्य एवं व्यवहार वाली जीवनधारा है । आन्तरिक भावना की पूर्ति न करने हुए इसे बाहरी ढांचा मात्र देने से यह सफल नहीं हो सकता ।"²

to the ideals of national freedom, unity and solidarity but equally to those of world peace and progress."

—'The Gazette of India' (July, page 50).

1. 'Nehru was the architect of modern India'

—Joseph Broj Tito : *Nehru—As I Understood Him*
(*The Illustrated Weekly of India*—Nov. 22, 65, p. 12)

2. "Democracy is something deeper than a form of government—voting, elections, etc. In the ultimate analysis, it is a manner of thinking, a manner of action, a manner of behaviour. If the inner content is absent and if you are just given the outer shell, well, it may not be successful."

—'Link' : August 15, 1964, p. 18.

प्रजातंत्र के महत्व को सर्व मन्दीय जनतंत्र की भावना का मनन करने के कारण ही अक्सर पाते हैं। जो व भविष्य की ७४ वीं धारा¹ के अन्वये इसे पर भी एक दाना ग्राह्य या निरंकुश शासक का रूप न बनना कर उन्होंने अनन्ति और जनतंत्र की मज्जी सेवा की।

धर्मनिरपेक्षवाद (Secularism)

नेहरूजी भारत की राष्ट्रीय एवं नागरिक एकता तथा सामाजिक दृष्टि से सर्व समरूप के समर्थक थे। अन्धश्रद्धाओं के त्याग के प्रति उनके मन में महत्त्वपूर्वक थी। परन्तु वे किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता (Communalism) के विचारों को समर्थ नहीं करते थे, जैसा कि उन्होंने २ अक्टूबर १९४८ का देशी में रेडियो भाषण में कहा था—“हम इस देश में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता को जन्म नहीं देंगे।”² के राष्ट्रीय स्वातंत्र्य का दायरे के समय में जिना के ‘ट्रिपल आलियंस’ (Tri-nation Theory) तथा ‘हिन्दू-महासभा’ के दुष्प्रचारों से बचने के लिए। वे सर्वप्रथम देगोर की ‘विश्ववाद’ की समझदानीय विचारधारा से प्रभावित थे, परन्तु उन्हें स्वामी रामानन्द, विवेकानन्द, पात व अरविन्द घोष आदि की भी, राष्ट्रवाद की धार्मिक व्याख्या समर्थक न थी।³ नेहरूजी के अनुयायियों ने भारतीय भविष्य के तृतीय मार्ग के मौलिक अधिकार सम्बन्धी अनुश्रवणों में धर्मनिरपेक्षता का निश्चित अर्थ बताया है (अनु. २/ के २८)। ओं की थी, वर्मा के अनुसार—“नेहरूजी अपने दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्ष रहते हैं— धर्मनिरपेक्षवाद के प्रति नेहरूजी की मूल्य निष्ठा ने भारत के अन्धश्रद्धाओं का महान् चहुट दी है। विवेकानन्द पर इन इन वर्मा के वैज्ञानिक पद्धति के प्रति उनकी निष्ठा ने उनकी राष्ट्रवादी राजनैतिक विचारधारा के विकास में योगदान दिया है, जो धर्मनिरपेक्षवादी प्रजातन्त्र पर इन दती है तथा मध्यस्थानीय प्रवृत्तियों, अन्धश्रद्धाओं एवं धार्मिक दृष्टि की चुनौती है।”⁴

1. “There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions”

“The Constitution of India”—Part V—Art 74 (1)

2. N. H. Sen “Wit and Wisdom of Nehru”, Page 539

3. Jawaharlal Nehru “Glimpses of World History”, page 437.

4. “Nehru has been secularist in his approach Nehru's heroic loyalty to secularism has been a great relief to the minority groups in India. His devotion to scientific methodology with its stress on rationalism has helped the evolution of his nationalist political ideology which in its emphasis on secularist democracy is a

समाजवाद (Socialism)

नेहरूजी के मार्क्सवाद, केवियनवाद आदि समाजवाद की विभिन्न शाखा का अध्ययन किया था। नवम्बर, १९२७ की रूम यात्रा में नेहरूजी का वहीं की देहागिर, नारी-स्वातंत्र्य तथा कृषक समस्या के क्षेत्र में प्रगतिशील सुधार देने का प्रयत्न प्राप्त हुआ।^१ १९२७ में योरोप से लौटने के उपरान्त उन्होंने समाजवाद के विचारों की प्रमिति की। उनके अनुसार आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता महत्वहीन है। इसीलिए १३ दिसम्बर, १९८६ को मंत्रिपरिषद् ने विचारपूर्ण शब्दों में कहा—“मैं समाजवाद तथा इस बात का हिमायती हूँ कि भारत एक समाजवादी राज्य के विधान की ओर बढ़ेगा और मुझे हृदय विस्वास है कि मारे गसर का इस मार्ग पर प्रसरण होना होगा।”^२

इस ध्येय के लिए उन्होंने समाजवादी समाज व राज्य की कल्पना की। १९३० के ‘करोवी-प्रभियोग’ में प्रजातान्त्रिक व सामाजिक विचारधारा के अनुकूल मौलिक अधिकारों की माँग द्वारा इसकी नींव रखी गई। ‘पंचवर्षीय योजनाएं’ (Five year plan) उनकी दृष्टि दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने राजनैतिक व आर्थिक प्रजातंत्र की एकलपना करने का प्रयास किया, जिसका प्रमाण है योजना आयोग (Planning Commission) के अध्यक्ष के रूप में समाजवादी व प्रजातन्त्रीय आधारों पर नियोजित विकास के अन्तर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) की प्रथम दना। नेहरूजी ने १९३९ में ‘नेशनल प्लानिंग कमेटी’ (National Planning Committee) के चेयरमैन के रूप में औद्योगीकरण (Industrialization) द्वारा मुक्त स्वतंत्र भारत की कल्पना की। स्वतंत्र भारत के तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास के साथ ही कृषि एवं भूमिसुधार द्वारा जमींदारों के शोषण में दबी आर्मीण अर्थव्यवस्था का परिवर्तन चाहता। १९४८ में ‘कांग्रेस कमेटी’ ने नेहरूजी द्वारा निमित्त यह प्रस्ताव पारित किया—

“हमारा उद्देश्य एक ऐसे आर्थिक ढांचे का निर्माण होना चाहिए जो बिना अतिशय एकाधिकार तथा पूंजी के वैश्वीकरण के अधिकतम उत्पादन प्रदान करते counterpoise to medievalism, obscurantism and religious dogmatism.”

--Dr. V. P. Verma “Modern Indian Political Thought”,

page 475 and 476.

1. “Jawaharlal Nehru : “Soviet Russia” (Allahabad, Law Journal Press, December, 1928), pages 63-74.

2. “I stand for socialism and that India will go towards the constitution of a Socialist State and I do believe that the whole world will have to go that way.”

—(Speech in a Constituent Assembly, Dec. 13, 1946)

हूँ, गृहरी व शान्तिपूर्ण अर्थ-व्यवस्था में दृढ़ता से अनुनयन पैदा करेगा। ऐसा सामाजिक बाका व्यक्तिगत मान मानना मे संवाचित निती पुँजीवाद की अर्थ-व्यवस्था तथा एकाधिकार-वादी राज्य की नैतिकदृष्टि का विरुद्ध हो सकता है।¹

इस उद्देश्य पूर्ति के लिए नेहरूजी ने जीवन, मनाज व सरकार के सम्बन्ध में समाजवाद एवं प्रजातांत्रिक मापनों को निताना चाहा, जैसी थी मुनाफ़खन्द दोम को ३ अप्रैल, १९३६ को लिखे पत्र के अनुसार उनकी दृष्टि थी—“मेरा स्थान है कि मैं स्वभाव व शिक्षा-दीक्षा के एक व्यक्तिवादी तथा विचारों के एक समाजवादी हूँ, मने ही इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। मेरा मत है कि समाजवाद व्यक्तिवाद का प्रवर्द्धन प्रदाय समन नहीं करता; वास्तव में, मैं इसके प्रति आकर्षित हूँ, क्योंकि यह अनेक व्यक्तियों को आर्थिक व सामाजिक संघर्षों से मुक्त करेगा।”²

इस समाजवाद की अवधारणा में नेहरूजी ने ‘मध्यम मार्ग’ (Middle way) का अनुसरण करते हुए प्रजातांत्रिक मापनों द्वारा समाजवादी मनाज व राज्य की स्थापना चाही न कि क्रांतिकारी व हिंसातुक्त मापनों द्वारा। १९४४ में लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare state) का स्वरूप रखने के उपरान्त १९४९ के ‘सामाजिक-व्यवस्थापन’ में ‘समाजवादी मनाज के ढांचे’ (Socialistic Pattern of Society) की परिचयना की। १९४८ के ‘गाँवों की व्यवस्थापन’ में ‘सहकारी खेती’ (Co-operative Farming) का प्रतिपद दिया। १९६४ के ‘सुवर्णयुग व्यवस्थापन’ में ‘प्रजातांत्रिक समाजवाद’ (Democratic Socialism) द्वारा समाजवादी राज्य (Socialist State) की स्थापना की गई। भारतीय अर्थ-व्यवस्था एवं आर्थिक में विदेशी ऋण (Loan) की भरपूर, उन्माद पर करपार (Tax), ‘मिश्रित अर्थ-व्यवस्था’ (Mixed Economy) के अन्तर्गत ‘निजी क्षेत्र’ (Private Sector) की प्रदान महत्वपूर्ण स्थान व दृष्टिक

1. “Our aim should be to evolvean economic structure which will yield maximum production without the operation of private monopolies and the concentration of wealth, and which will create a proper balance between urban and rural economies. Such a social structure can provide an alternative to the acquisitive economy of private capitalism [and the regimentation of a totalitarian state].
—‘Link’: August 15, 1954, page 22.

2. “I suppose I am temperamentally and by training an individualist and intellectually a socialist, whatever all this might mean. I hope that socialism does not give or suppress individuality; indeed I am attracted to it because it will release innumerable individuals from economic and cultural bondage.”

—N. B. Sen: “Will and Wisdom of Nehru”, page 553.

तथा राष्ट्रीयकरण (Nationalization) के प्रति मिमिक के कारण आलोचना होने पर भी कांग्रेस व देश में समाजवाद के सामाजिक व आर्थिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में नेहरूजी का महत्वपूर्ण स्थान है।¹ वे भृत्यवर्ग के देश में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता के लिए प्रयत्नशील रहे तथा अपनी पेंड' पर अमरीका कवि 'राबर्ट फ्रास्ट (Robert Frost) की कविता की इन पंक्तियों को लिखकर बर्मिंघम की तरह यह बताया कि 'सब कागजों व फाइलों को भुगता' कर भी वे 'मायम हारम' समझते थे—

"The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep"

तबीनीकरण

वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास — नेहरूजी ने इसाहावाद, हीरो व कैम्ब्रिज के अध्ययन काल में विज्ञान और सांस्कृतिक दर्शन का गहन अध्ययन किया था, जिसका उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।² बर्नार्ड शॉ (Bernard Shaw) और बर्ट्रैंड रसेल (Bertrand Russell) के विचारों का उन पर महान् प्रभाव पड़ा था। उन्होंने वैज्ञानिक मानववादी (Scientific Humanism) पद्धति से भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक यहाँ तक कि धार्मिक समस्याओं का समाधान किया। नारी के सामाजिक व वैधानिक उत्थान, अस्पृश्यता निवारण, शिक्षाप्रसार तथा-पुरातन परम्पराओं, सामाजिक दोषों व धार्मिक आडम्बरों जैसी विचार उन द्वारा भारत के तबीनीकरण के प्रमाण हैं। देश के औद्योगीकरण, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए उन्होंने तर्क, विवेक व मर्यादवाद में युक्त व्यवहारवादी पद्धति का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रयोग किया। राजनैतिक व आर्थिक विचारों की धार्मिक रहस्यवाद पर आधारित आलगाव भाषा का जमा यहना उनमें समझ न था।³ परन्तु वे इस तबीनीकरण में भी भारतीय संस्कृति और सम्पत्ति के दूताचारों तथा मानवीय सहनशीलतायुक्त कदमों के पक्षपाती थे।

1 Dr. V P Verma "Modern Indian Political Thought", page 430

2 Robert Frost

3 Jawaharlal Nehru : "An Autobiography".

4 ".....my preferences are all for science and the methods of science"

—Nehru : "Glimpses of World History", ch. 56, p. 173

प्राधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनैतिक चिन्तन' को नथदिशा

“मेरी कहानी”, “विश्व इतिहास की झलक”, “भारत की खोज” तथा “पिता के पत्र पुत्री के नाम”¹ आदि ग्रन्थों द्वारा नेहरूजी ने ‘प्राधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनैतिक चिन्तन’ (Modern Indian Social and Political Thought) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ग्रन्थों के अलावा उनके ‘भाषण-संग्रह’ भी पठनीय हैं। राष्ट्रवाद की धर्मनिरपेक्ष व्याख्या, पुरातनवाद (Revivalism) एवं सन्तदावाद (Communalism) की निन्दा, गांधीवाद की व्यावहारिक क्रिया-विधि, संसदीय जनतंत्र एवं प्रजातांत्रिक समाजवाद की सिद्धि में प्रयत्न तथा उदारवाद (Liberalism) के आवरण में उग्रवादी (Extremist) कार्यक्रम द्वारा ‘प्राधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनैतिक चिन्तन’ को नई दिशा प्रदान की है। इसकी नवीनतम विचारधाराओं, समाजवाद (Socialism) एवं अन्तराष्ट्रवाद (Internationalism) के आवरण में प्रजातन्त्र और समाजवाद तथा पूर्व और पश्चिम के प्रगतिशील ममत्ववाद (Synthesis) की उद्भावना की है। श्री के. पी. कल्याणकर के अनुसार नेहरूजी समाजवाद एवं अन्तराष्ट्रवाद के प्रमुख विचारकों में से एक थे।² डॉ. बी. पी. वर्मा के शब्दों में नेहरूजी के योगदान का सही मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है— “नेहरूजी उन ग्रन्थों में एक राजनैतिक दार्शनिक नहीं हैं, जिन ग्रन्थों में यह विचार उभरता है, हॉम या रूसा के बारे में लागू होता है। लेकिन निश्चय ही वे एक विचारक व्यक्ति हैं। एक क्रियाशील मनुष्य-यक्ति होते हुए भी, नेहरूजी में दार्शनिक विरक्ति की क्षमता है तथा एक अद्वैतीय विचारक की तरह वे दुनियाँ सन्देश और अन्वेषण-वृत्ति से सन्तानित रहते हैं। — वैज्ञानिकता और प्राधुनिकता की यात्रा को भारतीय राजनैतिक व सामाजिक चिन्तन के प्रति उनका योगदान माना जा सकता है।”³

1 “Autobiography” (1936) “Glances of World History” (1938) “The Discovery of India” (1946), “Letters From a Father to His Daughter” (1938)

2 “Pandit Jawaharlal Nehru was one of the outstanding exponents of socialism and internationalism”

—K P Karunakaran “Modern Indian Political Tradition”
page 27-28

3 “Nehru is not a political philosopher in the sense in which this appellation is applied to Cicero or Hobbes or Rousseau. But certainly he is a man of ideas. Although a great man of action, Nehru has the capacity for philosophic detachment and like a thinking introvert he has often been tormented by doubts and quests . .

ध्यावहारिक गांधीवाद

1916 में 'लखनऊ-अधिवेशन' में स्थापित गांधीजी के नेहरूजी का सम्बन्ध विरहाल तक बना व बढ़ता रहा। नेहरूजी की सदैव उनके प्रति हादिक व भावनात्मक भक्ति एवं श्रद्धा बनी रही।¹ महात्माजी से भी प्रसाद व आत्मीयता के रूप में नेहरूजी को बहुत कुछ मिला।² परन्तु नेहरूजी गांधीजी का अनुकरण करने की तैयारी न थे। संसद सदस्य श्री कमलनयन बसाल ने 4 जनवरी, 1964 को ग्रहमदाबाद में युवक कांग्रेस के उत्थापन में आयोजित एक सभा में सम्पूर्ण मुनाने हुए सभा में श्री मोर प्रोजेजियन के बारे में गांधीजी और नेहरूजी का ऐसी प्रकार का मतान्तर बताया। उन्होंने बताया कि गांधीजी ने इन सम्बन्ध में पूछे जाने पर एक बार कहा था—“जवाहरलालजी चाहते हैं कि प्रोजेज यहाँ से चले जाएँ और प्रोजेजियत बनी रहे, और मैं चाहता हूँ कि प्रोजेज चाहे हमारे देश में रहें, लेकिन हमारे देश से प्रोजेजियत चली जानी चाहिए।”³ यह माना जा सकता है कि राजनीतिक विचारों में तो दोनों की लगभग समान धारणा थी, परन्तु सामाजिक और धार्मिक समस्याओं पर सैद्धांतिक मतभेद था। गांधीजी के देहावत के बाद नेहरूजी ने गांधीवाद को तबीन, ध्यावहारिक, धर्षार्यवादी एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। तर्क, विज्ञान एवं पादचाय प्रभाव वाले नेहरूजी का विस्वास, ध्याव्यात्म एवं भारतीयता के पुजारी महात्मा गांधी के उसी प्रकार का सम्बन्ध एक विभिन्न दृष्टिकोण रहा जैसा अभिराम, सुलीन, कविता एवं मल्ल कविता में श्यात शमिक प्लेटो (Plato) तथा भदी शक्त व बाल वाले शुक्त दार्शनिक सुकुरात (Socrates) का शयवा वैज्ञानिक विषयो में अनुगत रखने वाले, ध्यावहारिक एवं धर्षार्यवादी उद्यनात्मक (Inductive) सिध्य धरन्तू (Aristotle) तथा दार्शनिक बिन्सन में शवि रखने वाले, धार्श एवं शरुतावादी निगमनात्मक (Deductive) शुक्त प्लेटो का रहा था। इसी प्रकार 'गांधीवाद' और 'नेहरूवाद' में भेद करना भी उसी प्रकार शक्ति है, जैसे सुकुरात और प्लेटो के विचारों का औरशरीर विवेक असम्भव है। नेहरूजी की गांधीजी के 'राजनीति में नैतिक दृष्टिकोण' (Moral approach to politics) एवं 'साधना तथा साधनों की परिचिता' (The

the quest for scientificity and modernism may be regarded as a contribution of Nehru to Indian political and social thinking."

Dr. V. P. Varma : "Modern Indian Political Thought", page 468 and 484

1. Nehru . "Autobiography", page 373

2. Michael Brecher —Nehru : A Political Biography (Ab. Ed.) page 120

3. 'हिन्दुस्तान' 5 जनवरी, 1965.

purity of ends and means) न विचारों ने प्रभावित किया। गांधीजी के प्रभाव, स्वातंत्र्य, निर्माकता, मानव कल्याण, अहिंसा और शान्ति के विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय नीतियों में गांधीजी द्वारा प्रदर्शित तथा समर्पित मार्ग एवं पद्धति पर चलने हुए उन द्वारा सौंपी गई विरासत की मुक्त-पूर्ण अनिवृद्धि में सतत प्रयत्नशील रहे तथा गांधीजी के इस स्वप्न को पूरा किया—“श्री जवाहरलाल मेरा उत्तराधिकारी होंगा” और मैं यह जानता हूँ कि जब मैं जाता जाऊंगा, जवाहरलाल मेरा ही नाया में दाखल होगा। राष्ट्र उसमें हाथों में सुपन्नित है।”

कांग्रेस पार्टी

पट्टाभि के अनुसार “गांधीजी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली कांग्रेसी बड़ी थे, जो कांग्रेस को अन्दर से बागे बहने की शक्ति देते और बाहर से रोक भी लगा सकने” “इसे समाजवाद, कहो या गांधीवाद, कांग्रेस जिस चीज के पक्ष में है वह यही है। यही नहीं, जवाहरलालजी जिस चीज को चाहते हैं उसमें और कांग्रेस के आदर्श में और भी ज्यादा अनुसृत है।”¹

राष्ट्र द्वारा विश्वास और दृढ़ता प्राप्त कांग्रेस पार्टी भारत के संसदीय जनतंत्र (Parliamentary Democracy) को नेहरू जी की महत्वपूर्ण विरासत है। राष्ट्रीय आन्दोलन काल में इसी के माध्यम से उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया था। कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता (Complete Independence) के लक्ष्य से आपने आन्दोलित किया था। विभिन्न अविवेचनाओं की अभ्यसना करने हुए उन्होंने ऐतिहासिक प्रस्ताव रखे थे। स्वतन्त्रता शान्ति के उपरान्त प्रदानमंत्री के रूप में उन्होंने नेहरू जी व कांग्रेस पार्टी के प्रयासन, समझन, प्रयत्न और अन्तर्भाव का प्रमाणित दिया था। ‘कामराज योजना’ (Kamraj Plan) द्वारा उन्होंने कांग्रेसियों के लिए सत्ता की मोट्टो-पट्टा स्थापन कर संसदन की मूर्धनता एवं समावर्तन का प्रस्ताव रखा। परन्तु वह संसदीय जनतंत्र की मान्यताओं और आवश्यक परिस्थितियों में भी परिचित थे, अतः विरोध दनों अपना राजनैतिक दनों के विकास तथा वाक्स्वातंत्र्य के मद्द्द सन्मर्क थे। वे कांग्रेस के निर्विरोध, सर्व सम्मत एवं एकमत नेता थे। उनके नेतृत्व के बाद पार्टी

1. “Next to Gandhi, he was the most dynamic Congressman providing the drive for the Congress from within and the brake to it from without — call it socialism or call it Gandhism that it exactly what congress seeks And too, there is much more in common between what Congress seeks and what Jawaharlal seeks”.

—Dr. Pattabhi Sitaramayya - “The History of the Indian National Congress”, page 8 and 27.

का कोई मुद्दा नेता नहीं मिल रहा है तथा सामूहिक (Collective) नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की गई। कांग्रेस परिषद उनसे बिना मुने, नीरस एवं नियंत्रणहीन दिखाई देने लगे तथा कोई भी राष्ट्रीय प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय नीति एकमत व सरलता से निर्धारित नहीं हो पाती। दुर्गापुर (कांग्रेस नगर) में कांग्रेस के ६६ वें अधिवेशन के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए श्री कामराज ने नेहरूजी की उदारता, प्रेम एवं पथ-प्रदर्शन का स्मरण करते हुए ६ जनवरी, ६५ को समयावधि अंतरावनी दी है—“भाज जवाहरलालजी का महान् व्यक्तित्व जो जनता के सम्मुख हमारी गतिविधि की ढरे हुए था हमारे बीच नहीं है। भाज जनता हमारे हरेक कदम की सावधानी से परीक्षा कर रही है। वह हमारी गतिविधियों को माफ नहीं करेगी।”¹

अन्तर्राष्ट्रीय स्थािति

स्वतन्त्र एवं मौलिक विदेश नीति—विषय ३५ वर्षों में कांग्रेस के विदेश नीति सम्बन्धी प्रायः सभी प्रस्ताव नेहरूजी द्वारा तैयार किए गए थे। विदेश नीति पर उनके प्रभावपूर्ण प्रभाव का कारण न केवल उनका प्रधानमन्त्री या विदेश मन्त्री होना था, बल्कि वैदेशिक विषयों का अत्यधिक अनुसंधान, पाण्डित्य एवं अन्तर्राष्ट्रवादी और अन्तर्जनतावादी विचार होना रहा है। वे विदेशनीति के नियामक तथा मूकधार रहे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की, महाशक्तियों के परस्पर विरोधी युद्ध से पुष्कल रहने की तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं संगठन की समर्थक, अंतर्जनता, संप्रभु राष्ट्रों की स्वतन्त्रता व समानता तथा बहुस्तरीय के उदात्त विचार पर आधारित शांतिपूर्ण महाशक्तिवाद की नीति का मूलाधार रखा—ध्वनील की। २० सितम्बर, १९६२ को नीनी सम्मेलन पर भी अन्तर्जनता की नीति की न छोड़ कर नेहरूजी ने यह मित्र कर दिया कि अन्य देशों की विदेशनीति के समान भारत की विदेश नीति भी कारे उदात्त मादनों पर नहीं है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कुछ मौलिक धर्मों से निर्धारित हुई है—भारत जैसे एक नवविवाहित युवक अर्थात् नवस्वतन्त्र राष्ट्रराज्य (New nation state) के लिए अन्तर्जनता की नीति हिज्जर की, त्रिभुजा भाविक, सामाजिक, राजनैतिक और औद्योगिक पुनर्निर्माण होना था। भौगोलिक दृष्टि से ३५०० मील लम्बी समुद्री सीमा एवं ८२०० मील लम्बी स्थलीय सीमा होने का महाशक्तियों के युद्ध दिग्गज पर जिनो युद्ध में होने पर दूसरे पक्ष को हट कर उस ओर की सीमा की अक्षित करना हिज्जर न था। विदेशनीति भारत की परम्परागत शांति, सहिष्णुता, सहानुभूति और उदारता की नीति, बेदायतवाद, बुद्ध तथा महात्मा गांधी की प्रहिता एवं अन्तर्जनता की कल्याण की उन्नति नहीं कर गजों थी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शीतयुद्ध (Cold-war) एवं शक्ति के द्विधर्मिकरण (Bipolarisation)

की स्थिति व्याप्त होने पर समंजनता और शान्तिपूर्ण सहमन्त्रित्व की नीति विरुद्ध-शान्ति, संयुक्त एवं सहयोग के विरुद्ध आवश्यक हो नहीं, द्विचक्र की घी। यह नीति पनादनवादों, पूर्णरूप में शान्तिवादों (Pacifist), पार्ष्वकवादों (Isolationist) अथवा अनावात्मक उदम्बता (Negative Neutrality) की नीति जैसी अतिपाशोक्त नीति नहीं बल्कि विरुद्ध-राजनैति एवं शान्तिपूर्ण कामों में पूर्ण रवि रहने वाली नावात्मक (Positive) गतिशील (Dynamic) तथा क्रियाशील (Active) विदेशनीति रही है, जैसी नेहरूजी ने व्याख्या की थी—“जब हम कहते हैं कि हमारी नीति अशं-नात्मता की है, तो स्पष्ट रूप में हमारा अर्थ सैन्य दृष्टि से समंजनता होता है। यह एक अनावात्मक नीति नहीं है। मुझे आशा है कि यह नावात्मक, निरिक्त एवं गतिशील नीति है।”¹

ऐसी समंजनता एवं शान्तिपूर्ण सहमन्त्रित्व की गतिशील विदेशनीति भारत के राष्ट्रीय हित (National Interest) को बढ़ाने वाली सिद्ध हुई है। हातांकित सितम्बर, १९४६ में सं० रा० प्रधनका का कांग्रेस के समक्ष श्री नेहरूजी ने एक भाषण में कहा था—“जहाँ स्वाधीनता संकट में हो, व्यापक छत्र में हो; आक्रमण की घटना हुई हो; हम वहाँ न उदम्ब रह सकते हैं और न उदम्ब रहेंगे।”² फिर भी चीनी आक्रमण के समय ऐसी स्थिति माने पर भी इस कड़ी अग्नि परीक्षा में नेहरूजी ने समंजनता की नीति न छोड़ी। इस संदर्भ में भारत की दोनों दृष्टि ॥ महापता भिरी एवं समर्पण प्राप्त हुआ तथा भारत ने अपनी सैन्य दुर्बलताओं पर पुनर्विचार करने हेतु सैनिक सहाय और आर्थिक विकास में द्रुत गति लाने का व्यावहारिक दायरवादो दृष्टिकोण अपनाया।

यह भारत का सौभाग्य था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समन्ते वाले ४-५ विरुद्ध-राजनैतिकों में शौर्यपूर्ण स्थान माने वाले नेहरूजी ने देश के प्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री के रूप में भारत की स्वतन्त्र एवं सैनिक परराष्ट्रनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्रदान की। यह उन्होंने के नेतृत्व एवं निर्देशन का परिणाम है कि पॉलर (Palmer) और पर्किंस (Perkins) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-विचारकों ने भारत की संयुक्त राष्ट्रसंघ में अकेलिवाई दृष्ट का नेतृत्वकर्ता मानते हुए आदरपूर्ण स्थान प्रदान दिया है।³

1. “When we say that our policy is one of non-alignment, obviously we mean non-alignment with military blocs. It is not a negative policy. It is positive one, definite one and, I hope a dynamic one.”

2. Nehru's address at the U. S. Congress in Washington, 1949.

3. “India disclaims any desire to act as a leader in Asia, but she is a leading champion of Asia's claims to a greater place in world affairs, and her actions suggest that she is not always averse to taking the initiative”. India was the main organizer and is now the accepted leader of the powerful Asian African bloc in the United Nations.”

—Palmer and Perkins : “International Relations” p. 763.

अन्तर्राष्ट्रीय विरासत (International legacy)

सताब्दी के महात्मा नेहा, विश्वशांति के धर्मदूत तथा 'मानवता के मसीहा'¹ श्री जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के लिए अपितु समस्त मानवता के लिए प्रवास-पुंज² थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रवादो तथा मानवतावादी विचारों से आलोकित विश्वशांति एवं सहयोग का प्रसमनीय विचार मानवता को प्रदान किया।

'अफ्रीका-एशियाई मुक्ति आन्दोलन'

एशिया और अफ्रीका में स्वतन्त्रता और राष्ट्रवाद की सहर पैदा करने में नेहरूजी की उपनिवेश एवं साम्राज्यवाद विरोधी नीति तथा मानवमान की स्वतन्त्रता के लिए किए गए प्रयास स्तुत्य हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के परतन्त्र राष्ट्रों ने नेताओं से साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए बहुत पहले से ही उन्होंने सम्बन्ध बढ़ाया; उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की; समर्थन तथा सहयोग प्रदान किया। १९२७ में ब्रुसेल्स (Brussels) में हुए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोधी विश्व-सम्मेलन में अरब नेताओं से मिले। १९२९ के 'साहोर अधिवेशन' का पूर्णस्वतन्त्रता का प्रस्ताव अफ्रीका-वादी राष्ट्रों के प्रति प्रेरणात्मक चुनौती था। मार्च, १९४७ में दिल्ली में हुए 'एशियाई देशों के सम्बन्ध सम्मेलन' (Asian Relations Conference) के संयोजन और कार्यक्रम में प्रमुख भाग लिया। १९४४ में चीन के प्रधानमंत्री श्री चाऊ-एन-साई के साथ पंचशील की घोषणा के बाद १९४५ के ऐतिहासिक 'बांडुंग सम्मेलन' (Bandung Conference) में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके इन मानवस्वातन्त्र्य के बाल में योगदान के कारण उनकी गणना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों के महात्मा राष्ट्रवादी नेताओं में की गई है।³ डॉ॰ बी॰ पी॰ वर्मा ने अफ्रीका-शियाई राष्ट्रवादियों में उनका प्रमुख स्थान मानते हुए कहा है—'नेहरूजी मात्र अफ्रीका-शियाई राजनैतिक एवं आर्थिक पूर्ण स्वतन्त्रता की आकांक्षाओं के प्रमुख अभिरक्षक हैं। उनके अफ्रीका-शियाई एकता एवं प्रगति के विचार ने नासिर, एंकूमा⁴ आदि की प्रेरित किया है।'⁵

1. अमरीकी विदेशमंत्री होवरस्क द्वारा ध्वांजित।

2. संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नसर द्वारा ध्वांजित।

3. Palmer and Perkins—"International Relations," P. 498.

4. "Nehru today is the leading spokesman of Asian and African aspirations for absolute political and economic freedom. His concept of Afro Asian unity and progress had inspired Nasser, Kwame Nkrumah of Ghana, Sékou Touré of Guinea, Kamal Jumblatt of Lebanon, and Kassim."

—Dr. V. P. Varma : "Modern Indian Political Thought", P. 477

असंलग्नतावाद (Policy of Non-alignment)

इन नवम्बरतकता प्राप्त एवं नवविशालोन्मुख अफेसियाई राष्ट्रों के विदेशसम्बन्ध-म्यान्तार्थ राष्ट्रीयहिता के अनुसृत अमन्यता की नीति नेह्न्जी ने अन्तराष्ट्रीय राजनीति को दी। प्रारम्भ में इसकी भावना ठीक तरह से समझी न जाने के दम उदाहरित होना पड़ा, परन्तु धीरे-धीरे इस और समझी दोनों ने इसका महत्व समझा, समर्थन किया तथा प्रशंसा की। अधिकतर नवम्बरतक तथा विशालोन्मुख राष्ट्रगण (Nation-States) ने इस नीति में अपनी स्वतन्त्रता, मजबूती तथा राष्ट्रीय हिता के सुरक्षित सम-क्षेत्र हुए इसे समझाया। साथ अमन्यराष्ट्र पूर्वों तथा पश्चिमी गुटों के बीच में एक सन्तुल्य और संतुलक (Balancer) का कार्य कर रहे हैं तथा इन्होंने मजबूतसंघ (U. N. O.) में तीसरे गुट का भा कार्य करते हुए शीतयुद्ध में शिथिलता (Thaw in the cold-war) ला दी है। 1961 में बेल्ग्रेड में हुए तटस्थराष्ट्रों के सम्मेलन (Belgrade Conference) में उन्होंने तटस्थ राष्ट्रों का मजबूत नेतृत्व किया। उनके देहान्त के बाद 5 अक्टूबर, 1964 से काहिरा में प्रारम्भ हुए तटस्थराष्ट्रों के दूसरे सम्मेलन में उनकी मजबूत तथा अविस्मरणीय स्मृति करने हुए उपनिवेशवाद के अन्तर्धन तथा सभी अन्तराष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे पर बत दिया गया।

राष्ट्रमण्डल (Common Wealth)

नेह्न्जी का राष्ट्रमण्डल के संस्थापकों में गौरवरूप म्यान् है। उन्होंने स्वतन्त्रता-शान्ति के बाद की ब्रिटेन में भारत का पविष्ट सम्बन्ध बनाए रखना तथा गणराज्य एवं अमन्यराष्ट्र होने हुए भी ब्रिटिशराष्ट्र-मण्डल का सदस्य बनना भारत के राष्ट्रीय, राज-नीतिक एवं धार्मिक हित की दृष्टि में उचित समझा। वे स्वतन्त्रता के उपरांत 1947 में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमंत्री सम्मेलन में जाने गये तथा 1964 में 8 से 15 जुलाई तक होने वाले सम्मेलन में भी जाने की तैयारी कर चुके थे पर 27 मई का उनका देहान्त हो गया। संयुक्तसंघ में ब्रिटेन द्वारा काश्मीर नीति पर पाकिस्तान के पक्ष एवं 1964 के सम्मेलन में 'बादशहर विवाद की बर्षा' को लेकर भारत में राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्यागने की माँग की गई। परन्तु 3 दिसम्बर, 1964 को सन्धन पर्वत पर प्रज्ञानमंत्री श्री लालबहादुरशास्त्री ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री हैराल्ड विन्सन से मोहार्दपूर्ण बातचीत द्वारा राष्ट्रमण्डल की नींव को और मजबूत कर दिया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की राय में नेह्न्जी के देहान्त ने राष्ट्रमण्डल में अपना कुशल नेता को दिया है। नाआर्यो प्रतिश-वेय का यह मोक्षमंदरा राष्ट्रमण्डल के प्रति की गई नेह्न्जी की सेवाओं को स्वीकार करता है—“उनका निपट निदर की समस्त शान्तिप्रिय जनता तथा राष्ट्रमण्डलीय जनता के लिए बड़ा शांतिदायक है।”

विश्व समुदाय-भावना-संयुक्तराष्ट्रसंघ

नेह्न्जी ने विश्वसमुदाय एवं विश्वव्युत्थ की भावना पर बत देते हुए राष्ट्रीय

की समानता, स्वतन्त्रता, सप्रभुता एवं विकासयुक्त प्रगति की स्थायी संयुक्तराष्ट्रसंघ तथा उसके चार्टर का समर्थन किया। कोरिया, जापान, स्वेज, विभक्ततामय प्रश्न का काँगो का जब भी अन्तर्राष्ट्रीय संकट आया, उन्होंने संयुक्तराष्ट्रसंघ का सहयोगयुक्त समर्थन प्रदान किया। रंग, दश, धर्म प्रभवा प्रजाति किसी भी प्रकार का भेद उन्हें पसन्द न था। इसकी सफलता के लिए वे प्रत्येक राष्ट्र की अतिविशेषीय उन्नति चाहते थे। आपसी झगड़ों में वे संयुक्तराष्ट्रसंघ के सत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law) के अन्तर्गत शांतिपूर्ण निपटारे के समर्थक थे, कश्मीर समस्या इसका सुन्दर उदाहरण है। चीन से सप्तर्षि चलने पर भी संयुक्तराष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए उनका समर्थन करने इसे वास्तविक एवं क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रीयसंगठन एवं विश्वसंघ बनाना चाहता। विश्व के दो छुट्टों में बंटने एवं संयुक्तराष्ट्रसंघ को 'द्वितीय अराका', बनाने से रोकने के लिए ही उन्होंने प्रसंलग्नता पर बल दिया। क्षेत्रीय संगठनों (Regional Alliances) के वे तीव्र प्रालोचक थे। उन्होंने 1948 में हुए संयुक्तराष्ट्रसंघ की महासभा (General Assembly) के तृतीय अधिवेशन में भाषण दिया। 1960 में अंतिम बार उन्होंने संयुक्तराष्ट्रसंघ की कार्यवाही में भाग लिया तथा विश्वशांति एवं महाशक्तियों के नेताओं के सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापनार्थ प्रयास किया। काँगो-संकट के समय संयुक्तराष्ट्रसंघ की नैतिक सहायता देकर नेहरूजी ने इसे शांति स्थापनार्थ बचम उठाने में मदद की।

मानववाद-पंचशील

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नेहरूजी 'नैतिक एवं मानवीय अन्तर्राष्ट्रवाद' (Moral and humanist internationalism) के पक्षपाती थे। विज्ञान के ज्ञाता तथा व्यापक दृष्टिकोण वाले होने से वे परमाणु बमों की निर्मित करने, हस्तक्षेपों की होड़ रोकने, निस्स्त्रीकरण (Disarmament), युद्ध के अन्त तथा भ्रूत एवं भय के स्वतन्त्रता आदि मानव कल्याण और शांति के मूलतत्वों के पक्षपाती थे। मानवता के प्रति विश्व के किसी भी कोने में संकट उपस्थित होने पर उन्हें बड़ा दुःख पहुँचता था। अगस्त 1963 में तीन अणुशक्तियों द्वारा हस्तक्षेप की गई आंशिक अणुपरीक्षणप्रतिबंधसंधि (Nuclear test ban treaty) पर हस्ताक्षर करने वाले वे सर्वप्रथम शासनाध्यक्ष (Head of Government) थे। सब तरह के सैन्य तथा राजनैतिक छुट्टों का विरोध, समंतानता तथा शांतिपूर्ण-महामुक्ति के समर्थन के साथ एकविध की कल्पना करने हुए 20 जून, 1954 को उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री श्री चाउ एन साई के साथ 'पंचशील' के मूल्यों का प्रचार किया जो थे—(1) एक दूसरे की आदेशित अराजकता और भ्रांत्युत्पत्ति (Sovereignty) के लिए आरक्षित सम्मान की भावना (2) अनाक्रमण, (3) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप, (4) समानता तथा एक दूसरे को साम प्रवृत्तता, (5) शांतिपूर्ण सहसंस्थान (Peaceful co-existence)।

नेहरू का विरासत

प्रमाण है दोना गुणे (bloccs) से सहायता और समर्पन व साथ ही निरक्ष जनमत प्राप्त होना, जिससे चीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में घबरा पाठ गया। दाना गुं घास असमर्थता की नीति को समझते हैं समर्पन प्रदान करने हैं तथा प्रगता करत हैं। इस नीति ने चीतयुद्ध में निमित्तता (Tham in the cold war) सा दी है।

प्रधान मन्त्री के रूप में नेहरूजी ने 'प्रणामन में एकाधिकार' (Monopoly) रख कर सत्ता का प्रणामाजन' (Delegation of authority) उपयुक्त माना म नहा दिया, जिससे नायक-पूजा (hero-worship) को प्रथम मित्त तथा नरुद की प्रणि-क्षण का अवसर न मिल सका। यही कारण था कि 'नेहरू व बाद कौन' (After Nehru who ?) की साक्षात्ता समय-समय पर ही उठती रही। प्रणामन में व्याप्त प्रष्टाचार, विद्वानों से बड़ी कार्यवाही व स्थान पर भेजे गए विरोधी पत्र, सामा पाणि-स्तानिया के भारत में अवैध प्रवेग, बेकारी, मूल्य वृद्धि एवं महंगाई आदि प्रणामनिक कमजोरिया तथा सिविता को देख कर राष्ट्र व एकीकृत भवन निर्माण करने का लोह पुरुष सरदार पण जैसे दण प्रणामक एवं कर्मयोगी की सभी महसूस की गई। चीन द्वारा हुक्रे गए सुखण्ड तथा पाकिस्तान द्वारा कल्ले में लिये गए कर्मवीर व भाग को वापिस लेने के लिए नेहरूजी द्वारा कोई सुरद या प्रणामनाली बदल न उठाये जाने की विशेषत विरोधी दलों द्वारा साबितना हुई।

नेहरूजी ने अपने अन्तिम दिनों में बेल्वाही, 'कामराज योजना', नल अन्तुत्सा की रिहाई, मागालैण्ड के प्रति उदारता तथा पश्चिमी भाषा के प्रथम आदि घटनाओं में राजनैतिक अस्थिरता का परिचय दिया जिससे जनमानस में कुछ अमन्तोष, निराशा तथा चिन्ता में जन्म लिया। कांग्रेस पार्टी से भी वे अपने अन्तिम दिना में उमी तरह खिन्न थे जैसे गांधीजी की अपने अन्तिम दिना में होना पडा था। उनका इस पर एकछत्र नेतृत्व, प्रभाव एवं नियन्त्रण धीरे धीरे कम होता गया। 'कामराज योजना' के रूप में हुक्रे पवित्रीकरण या पुनर्मुधार का आन्दोलन भी अमकल रहा।

नेहरूजी ने योजना आयोग (Planning Commission) के अध्यक्ष के रूप में देश में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता की स्थापना के लक्ष्य के साथ ही औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास द्वारा देश के नवीनीकरण व लिये किए गए सक्षम में आर्थिक निधि ही प्राप्त की। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोगन में विदेशी ऋण (loan) की भरमार, जनता पर करभार (tax), राष्ट्रीयकरण (Nationalization) के प्रति भिन्न तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) व अणुर्जन 'निजी क्षेत्र' (Private Sector) को प्रदान महत्वपूर्ण स्थान एवं उन्मुखि के लिए उनकी साबितना होजी रही। पंचवर्षीय योजनाया (Five Year Plans) में सामान्य जनता बहुत कम परिचित या प्रभावित हुई। प्रणामकीय महयोग उचित माना

में न मिल सका, ऐसा कि नेहरूजी ने भी दोषारोपण किया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अयोध नेहरू के अनुसार—“इन योजनाओं का क्रियान्वय ही वृद्धिपूर्ण नया वस्त्र योजनाएं स्वयं में भी वृद्धिपूर्ण थीं।”¹ योजना आयोग (Planning Commission) के संगठन की भी आलोचना होती रही। प्रधान मंत्री श्री लालबहादूर शास्त्री के नेतृत्व में २ जनवरी, १९६५ को कांग्रेस के दूरभाष अधिवेशन में सर्वसम्मति से स्वीकार किये गए आर्थिक नीति मन्त्रालय प्रस्ताव द्वारा इन कुटिल में गुप्त रूप से नेहरूजी की नीतियों को तबोत दिया प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिसके अनुसार चौपी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि तथा आर्निंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।² परन्तु डा० मन्मोहनबन्ध के अनुसार ‘समा-तामिक समाजवाद’ (Democratic Socialism) का स्पष्ट स्वप्न न हो नेहरूजी की उपस्थिति में व्याख्यित किया आम्का तथा न उनके देशान्त के बाद कि “कांग्रेस सन्तत समाजवाद किन बातों में सर्वोपरि है, किन बातों में डा० मोहिया के मत में और सर्वोपरि किन बातों में कम्युनिज्म में मिलन है ?”³

नेहरूजी के कार्य जगत एवं मानवता के निरूपण करने अधिक है कि उनके देश-काल की ‘नेहरू युग’ (Era of Nehru) तथा उनके विचारों की ‘नेहरूवाद’ (Nehruism) का ज्ञान देने हुए उनके देशान्त के बाद भी (Nehru is dead, long live Nehru) की बात कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया। श्री बी. एन. मन्ध के अनुसार उन्होंने अपनी दायिमा तथा नेहरूजी जीवन में करने ‘अद्वय’ की भी रचना दिया—“काल से लोग मात्र श्री मोहियान नेहरू की श्री अवाहरमान नेहरू के पिता के रूप में मान करते हैं जैसे कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में कुछ लोगों की दृष्टि में श्री अवाहरमान के महत्व प्रदानार्थ मुख्य ‘अद्वय’ था कि वह अपने जीवन पिता का पुत्र था।”⁴

१. योजना आयोग के सम्पादन अधिकारियों की १ दिवसीय गोष्ठी का ५ अगस्त, ६४ को दिल्ली में उद्घाटन करते हुए जगज्ज में मत

(‘हिन्दुस्तान’, अगस्त १, १९६४)

२. ‘हिन्दुस्तान दायिमा’ (१० जनवरी, १९६५)

३. डा० मन्मोहनबन्ध : ‘अवाहरमानजी के बाद क्या’

(‘हिन्दुस्तान’—वाचनिक दिवस परिशिष्ट ११ अगस्त, १९६४)

4. “Many people today remember Motilal Nehru as that father of Jawaharlal Nehru, just as in the nineteen twenties there were not a few in whose eyes Jawaharlal's chief title to distinction was that he was the son of distinguished father.”

—B. R. Nanda : “The Nehrus : Motilal and Jawaharlal”, p. 9

उन्होंने 1947 में धार्मिक विनाश, घरीबी, अज्ञान, अक्षयिस्वाम, 600 देशी रियासत, प्रजातान्त्रिक स्वशासन एवं संस्थाओं से अपरिचित जनता वैसे तथा पुनर्वास एवं विकास की समस्याओं से पूर्ण देश का नेतृत्व संभाला था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रगति को विवेकपूर्ण जाँच करने पर ही उनके प्रतिदानों (Legacy) एवं प्राप्तियाँ (Achievements) का सही मूल्यांकन करते हुए इतिहास में स्थान निर्धारण करना न्यायसंगत होगा। प्रजातन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षवाद द्वारा भारत को बहुमुखी विकास तथा अस्तुयुग में अग्रगस्त संसार की शान्तिस्थिति पवशील प्रदान कर नेहरूजी ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन को नया मोड़ दिया, जिसके लिए भारतीय तथा विश्व इतिहास में उन युगनिर्माणा का नाम स्मरणीय एवं स्थान गौरवपूर्ण रहेगा। डॉ० राधाकृष्णन् के शब्दों में—

“यद्यपि जब हम उनके विषय में सोचते हैं तो हमारे सम्मुख एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो मानवजाति का महान् मुक्तिदाता था, जिन्होंने मानव-मस्तिष्क की राजनैतिक धधन, धार्मिक दामना, सामाजिकदमन तथा सांस्कृतिक जड़ता से उबारने के लिए सम्पूर्ण जीवन तथा शक्ति समर्पित की।”¹

1. 'Our thoughts go out to him as a great emancipator of human race, one who has given all his life and energy to the freeing of men's minds from political bondage, economic slavery, social oppression and cultural stagnation. We can do no better than work for the ideals he cherished. That is the best tribute we can pay to our departed leader'

शक्ति सन्तुलन

(BALANCE OF POWER)

—महेन्द्र वरदा

मानव अनादिकाल से ही युद्ध में बचने के उपाय साधता रहा है, क्योंकि प्रकृति में ही वह एक शक्तिप्रिय जीव है। युद्ध में बचने और शक्ति में जीवन व्यतीत करने की साधनों के अनेक उपायों में से शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त भी एक है। शक्ति-सन्तुलन का कार्यक्रम (Process) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वाभाविक एक सावदयक है, क्योंकि इसमें अनेक राष्ट्र विद्यमान हैं। इस सिद्धान्त का आदर्श है—अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन (International Equilibrium) या अन्तराष्ट्रीय राजनीति की गतिमान प्रकृति (Dynamic nature) पर आधारित है। आज की राजनीति में यह विदव को तथा मानव जाति को युद्धों की आलाओं तथा भयंकरताओं से बचाने तथा विदव शक्ति स्थापित करने का एक उपाय समझा जाता है।

शक्ति सन्तुलन की प्रकृति (Nature of Balance of Power)

शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त कोई नई विचारधारा नहीं है। इसे प्राचीन समय में भी प्रयोग में लाया जाता था और मानव समाज को इसका पर्याप्त ज्ञान था। पामर और परकिनस (Palmer and Perkins) की राय में शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त उन सभी युगा में, जहाँ की बहुत राष्ट्रप्रकृति थी, विद्यमान था।¹ प्रो० हार्टमन (Prof. Harimann) भी इस मत से सहमत हैं और कहते हैं कि अनेक या बहुतराष्ट्रप्रकृति (Multi-state system) में शक्ति सन्तुलन की प्रक्रिया (Process) स्वाभाविक और सावदयक है। इस प्रकार से बहुत राष्ट्रप्रकृति शक्ति सन्तुलन के स्वभाव में निहित है। प्रो० क्वीसी राइट (Prof. Quincy Wright) ने इस सिद्धान्त की ऐतिहासिकता की धार खोले करने का सिद्धांत है कि 1500 A. D. तक शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं-कहीं पर परिपूर्ण सिद्धान्त के रूप में विद्यमान था।

1. "The concept of the balance of power has been present wherever and wherever the multiple state system has existed"

—Palmer and Perkins.

परन्तु १६४८ की वेस्टफालिया की सन्धि (Treaty of Westphalia of 1648) के पश्चात्, यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का एक प्रमुख नियम घोर विद्या बन गई।¹ साथ ही साथ यह यह भी कहते हैं कि जब कि सन्धि सन्धि ने भी, ३० वर्षीय युद्ध (Thirty years' war) के पश्चात् की विचारणा का सामान्य स्फोटक के रूप में, यूरोप में हुए युद्धों और शान्ति के लिए, प्रस्तुत किया जा सकता है।² अठारहवीं शताब्दी की कई सन्धियाँ में इसका वर्णन किया गया है और उन्नीसवीं शताब्दी में इसका सफल प्रयोग हुआ है।

शक्ति सन्तुलन के विभिन्न अर्थ तथा परिभाषा

(Various meanings of Balance of Power and its Definition)

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की परिभाषा की परिधि में बांधना मार्कोरवी कार्य (Herculean task) है। लेखक व विद्वानों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। 'शक्ति सन्तुलन' एक अस्पष्ट व बहुवर्ण्य शब्द है। हमने निम्न अर्थ दी सकते हैं —

(१) किसी भी प्रकार का शक्ति विभाजन (Any distribution of power)-संततार के राष्ट्रों में किसी भी प्रकार का शक्ति विभाजन शक्ति के नाम से पुकारा जा सकता है।

(२) असन्तुलन (Imbalance)—शक्ति सन्तुलन का प्रयोग असन्तुलन के अर्थ में भी किया जा सकता है। इस अर्थ में इसका मतलब होगा एक राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के ऊपर उच्चता (Superiority) और प्रभुता (Domination) है।

(३) समता (Equilibrium) शक्ति सन्तुलन का अर्थ यह भी हो सकता है कि विश्व के अनेक राष्ट्रों में उचित शक्ति सन्तुलन है न कोई अधिक शक्तिशाली है न पर्याधिक कमजोर है।

(४) स्थायित्व और शान्ति (Stability and peace) शक्ति सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायित्व तथा विश्व में शान्ति की स्थिति को भी प्रकट करता है।

(५) इतिहास का सर्वमान्य नियम (Universal law of history)—एक ऐसा तात्पर्य यह है कि शक्ति सन्तुलन विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर सदा प्रकट (Appear) होता रहा है और होता रहेगा।

1 " . . . it scarcely existed anywhere as a conscious principle of international politics before 1500. Especially after the treaty of Westphalia of 1648, it became a cardinal feature of international relations."

2 " . . . while other factors have had an influence, the concept of balance of power provides the most general explanation for the oscillations of peace and war in Europe, since the Thirty years' war"

(८) जटिल शक्ति संतुलन (The complex balance of power) में तात्पर्य इस प्रकार के शक्ति संतुलन में है जिसमें अनेक शक्ति का विभाजन अनेक राष्ट्रों में है।

(९) साधारण शक्ति संतुलन (The Simple balance of power) — इसका अर्थ होता कि शक्ति सामान्यतः दो महाशक्ति राष्ट्रों में विभाजित है।

(८) इसका अर्थ निर्देश राष्ट्रों का शक्तिशाली बनने के प्रयत्नों में भी हो सकता है।

प्रो० मॉरान्थान (Prof. Morenathan) ने अपनी पुस्तक "Politics Among Nations" में इस शब्द (Term) का प्रयोग बार-बार इसी में किया है—

(१) एक प्रकार की नीति (As a policy aimed at certain state of affairs),

(२) वास्तविक परिस्थिति (As an actual state of affairs), (३) शक्ति विभाजन

संज्ञान्ति (As an approximately distribution of power) और (४) शक्ति

विभाजन (As a distribution of power)

जी० लॉरेन्स डिकिन्सन (G. Lawes Dickinson) इस शब्द (शक्ति संतुलन) के दो अर्थों का स्पष्ट बख्तर निकालते हैं कि एक तरफ इसका अर्थ है समानता में, जिस प्रकार कि दो तरफ का हिसाब बराबर हो, तथा दूसरी ओर इसका अर्थ है समानता में, जिस प्रकार कि एक राष्ट्र का बँट में 'Balance' या बनावट हो।

प्रो० फ (Prof. Fay) ने Encyclopaedia of the Social Sciences में शक्ति संतुलन की परिभाषा करते हुए लिखा है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति शक्ति विभाजन है, इस प्रकार का शक्ति विभाजन कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपनी शक्ति न बल सके और न ही वह राष्ट्र इस बल से बच सके।^१ एम० मार्शल्ले बाल और एम० सी० कैला (M. Margaret Ball and Hugh B. Killough) अपनी पुस्तक 'International Relations' में लिखते हैं कि शक्ति संतुलन, या विपरीत राष्ट्रों द्वारा मध्य राष्ट्रों के मध्य शक्ति बल शक्ति बनाए रखने का प्रयत्न है।^२

प्रो० हार्टमन (Prof. Hartmann) ने अपनी पुस्तक 'The Relations of Nations' में इस प्रकार के मध्य शक्ति संतुलन के स्पष्ट किया है। शक्ति संतुलन का अर्थ या अर्थ के रूप में (Balance of Power as a pattern) और शक्ति संतुलन

1. "It means such a just equilibrium in power among the members of the family of nations as will prevent any one of them from becoming sufficiently strong enough to enforce its will upon the others."

2. "A power equilibrium established among rival states through allowing themselves with other states a technically referred to as a balance of power."

क्रम या रीति के रूप में (Balance of Power as a Process) एक राष्ट्र जो कि 'शक्ति सन्तुलन आकार' (Balance of Power as a Pattern) का प्रयोग कर रहा है, कुछ अन्य राष्ट्रों के साथ अपने विरोधी राष्ट्र के विपक्ष में बनाता है तथा इस प्रकार विरोधी राष्ट्र की शक्ति का प्रतिरोध करने में 'शक्ति सन्तुलन' का प्रयोग करता है। शक्ति-सन्तुलन क्रम या रीति शक्ति सम्बन्धी सभी समस्याओं का सामान्यकरण (Generalization) है। यह वास्तविक शक्ति सम्बन्धों को बनवाता है और राष्ट्र के 'शक्ति सन्तुलन आकार' की ओर दृष्टिपान नहीं करता।

प्रो० मारगनथॉ (Prof Morgenthau) के मतानुसार शक्ति सन्तुलन आकार (Patterns of Balance of Power) दो प्रकार के हैं—प्रथम The pattern of Direct Opposition—इस प्रकार के ढाँचे में शक्ति सन्तुलन दो या अधिक तथा समुदा के कारण उत्पन्न होता है। एक राष्ट्र अपनी नीतियाँ दूसरे राष्ट्र पर थोपने की कोशिश करता है। राष्ट्र अपनी नीतियों की दूसरे राष्ट्रों पर प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाते हैं। द्वितीय Pattern of Competition—इस 'आकार' के कारण छोटे राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता कायम रख सके। साथ ही इसी के कारण उन्हें अन्य राष्ट्रों के अधीन होना पड़ा।

इस प्रकार शक्ति सन्तुलन को परिभाषित करना अव्ययिक कठिन है परन्तु उपरोक्त परिभाषाओं और विभिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शक्ति सन्तुलन का केन्द्र बिन्दु या मुख्य विचार यह है कि यदि प्रगति-राष्ट्रीय जगत् में शक्ति सन्तुलन है और कोई भी राष्ट्र यह जानता है कि यदि उसने इस शक्ति सन्तुलन को तोड़ने या बदलने की कोशिश की तो उसे अव्ययिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रो० लर्क (Prof Lerche) कहते हैं—“A statesman will not normally resort to war when the odds are heavily against him” अर्थात् एक राजनीतिज्ञ युद्ध प्रसन्न नहीं करेगा यदि उसे ज्ञात है कि विरोध बहुत अधिक है।

शक्ति सन्तुलन की विशेषताएँ (Characteristics of Balance of Power)

प्रो० पामर और परकिनस् (Prof Palmer and Perkins) “International Relations” में शक्ति सन्तुलन की निम्नलिखित बातें विशेषताएँ बताते हैं—

प्रथम 'शक्ति सन्तुलन' शब्द समता (Equilibrium) की ओर संकेत या इंगित करता है लेकिन इतिहास साक्षित करता है कि सन्तुलन कभी-कभी असमानता (Disequilibrium) को प्रकट करता है। दूसरा, यह एक राजनैतिक स्पष्ट-योजना है (A diplomatic co-ordination), इतिहास का पता नहीं। तिसरा, यह सन्तुलन के अन्तर्गत है, शक्ति सन्तुलन अन्तर्गत का उपहार नहीं है बल्कि सन्तुलन के प्रयत्नों का फल है। शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के लिए सन्तुलन के युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तीसरा, सन्तुलन शक्ति-

सन्तुलन सिद्धान्त एकसौ स्थिति (Status-quo) के पक्ष में है परन्तु प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि यह परिवर्तनशील और चक्रवर्तु हो। चौथा, सच्चे प्रयोगों में शक्ति सन्तुलन बहुत कम प्रयत्नों पर हो सकता है। पाँचवा, शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त निष्पक्ष (Objective) और व्यक्तिगत (Subjective) दोनों ही प्रकार की विचारधाराओं को स्थान देता है। मार्टिन राइट (Martin Wright) कहते हैं,

"The historian will say that there is a balance when the opposing groups seem to him to be equal in power. The statesman will say that there is a balance when he thinks that his side is stronger than the other. And he will say that his country holds the balance, when it has freedom to join one side or the other according to its own interest." इतिहासकार दृष्टिकोण (Objective view) लेता है तथा एक राजनीतिज्ञ मातृपरक दृष्टि (Subjective view) से स्थिति को देखता है। स्पाइकमेन (Spykman) और क्वीन्सी राइट (Quincy Wright) का मत है कि राजनीतिज्ञ का मत अधिक वास्तविक है। छठा, शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त रीति के रूप में न तो प्रजातन्त्र और न ही तानाशाही के अनुरूप है। सातवा, शक्ति-सन्तुलन बड़े राष्ट्रों के लिए तथा उनके हित में होता है। छोटे राष्ट्र तो इस सिद्धान्त के शिकार तथा दर्शक मात्र होते हैं। यह किस प्रकार कार्य करना है? (How it appears)?

राजनीतिक विचारक इन बातों पर एकमत नहीं है कि शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त किस प्रकार से कार्य करता है। इन बारे में तीन मत रखे जाते हैं। वे मत हैं— प्रथम, शक्ति-सन्तुलन स्वयं चालित (Automatic) है। दूसरा, यह अर्ध-स्वचालित (Semi automatic) है तथा तीसरा, यह अनेक राष्ट्रों के सहयोग से कार्य करता है।

प्रथम मत के अनुसार शक्ति-सन्तुलन एक प्राकृतिक क्रिया है। किसी भी राष्ट्र को इसके कार्य के विषय में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। यह स्वयं संवाधित होता रहता है। जेम्स (Rousseau) ने इसे प्रकृति का कार्य अधिक बतलाया है, राजनीतिज्ञ की भ्रमशा। यह प्रकृति का मापारण नियम है कि जब एक राष्ट्र या अन्य कोई वस्तु अधिक शक्तिशाली बन जाती है तो अन्य राष्ट्र या वस्तुएँ भी अपनी शक्ति बढ़ाती हैं और अधिक शक्ति ग्रहण करती हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० टोयनबी (Prof. Toynbee) ने इसे "Political Dynamics" के नाम से पुकारा है तथा इसके कार्य करने के लिए "Automatically" शब्द का प्रयोग किया है।

द्वितीय मत के अनुसार यह पर्यन्तवाचित और पर्यवाह्य शक्ति के प्रयोग से कार्य करता है। इस मत के समर्थकों के सम्मुख इंग्लैंड का उदाहरण है। उसके मतानुसार शक्ति सन्तुलन मिटाने के कार्य करने के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्र की आवश्यकता

संयुक्तता है जो कि सम्बन्धनकर्ता (Balance) का भाग या कार्य कर सके । सम्बन्धनकर्ता के विषय में तीन विचार या मन हैं—

(क) छोटे छोटे राष्ट्रों का समूह (Combination of small states)

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisation)

(ग) परम्परागत अर्थ में सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र शक्ति को सम्बन्धित करने में सहायक का कार्य करे तथा शक्ति-संघर्ष (Power conflict) में भाग लेने की उद्यत न हो । इंग्लैंड ने यह भाग पूर्ण काल में बड़े सफल तरीके से प्रदा किया । भारगन काँ ने अपनी पुस्तक (Politics Among Nations) में दो उदाहरण, हेनरी अष्टम तथा मास्मातो ऐमिआडेय प्रथम के समय के दिये हैं, यह प्रदर्शित करने की कि इंग्लैंड बहुत पहले से ही सम्बन्धनकर्ता का तैल तैल रहा है । १८वीं और १९वीं शताब्दी में इंग्लैंड का कार्य तथा भाग सम्बन्धनकर्ता के रूप में विशेष महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट-नीय है परन्तु १९वीं शताब्दी के अन्त और २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अमेरीका तथा यूरोप में नये राष्ट्रों के उद्घाटन के पक्षस्वरूप इंग्लैंड अपना ऐतिहासिक भाग इन सदियों में प्रदा करने में सफल रहा और आज परम्परागत अर्थों में सम्बन्धनकर्ता का मिलना अव्यभिचार कठिन है ।

(क) द्वितीय अन्तर्जातीय छोटे-छोटे राष्ट्र मिल कर सम्बन्धनकर्ता का भाग प्रदा कर सकते हैं । वर्तमान युग में असंलग्न राष्ट्र (Non aligned Countries) शीतल युग और समुदाय राज्य अमेरिका के मध्य सम्बन्धनकर्ता का कार्य कर रहे नहे जाने हैं ।

(ख) तृतीय अन्तर्जातीय शक्ति सम्बन्धन सिद्धान्त के कार्य के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है । ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार की शक्ति अंग्रेजों के वक्त अपनी शक्ति कमजोर राष्ट्रों की ओर लगा देनी है तथा इस प्रकार शक्ति सम्बन्धन बना रहता है । आज के युग में अनेक राष्ट्र संघ (U.N.O.) का नाम उदाहरणार्थ दिया जा सकता है ।

तृतीय अन्तर्जातीय के अनुसार शक्ति सम्बन्धन न तो स्वयं आविर्भूत है और न ही एक राष्ट्र के प्रयत्न का फल ही सफलता है । इसके कार्य करने के लिए आवश्यक है कि सब के सब राष्ट्र इसके लिए प्रयत्न करें । अर्थात् प्रत्येक राष्ट्र यह देखे कि शक्ति सम्बन्धन काममें है या नहीं । इस सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रों का और राजनीतिज्ञों का यह कर्तव्य है कि वे यह देखें कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान शक्ति सम्बन्धन का किसी प्रकार उपलब्ध न करदे तथा वह ऐसे प्रयत्न करता रहे जिसमें मानव जाति पुनः की अमानवताओं से दूर शक्ति की मोड़ में मुक्त हो रहे ।

इन बातों के बारे में यही कहा जा सकता है कि शक्ति सम्बन्धन के कार्य के निम्ने कोई एक मन पूर्णतः अन्तर्जातीय उत्तर नहीं देता । अनुभवों से ऐसा लगता है कि राष्ट्रों

की ओर से प्रयत्न तथा अन्तर्राष्ट्रीय भस्या का योगदान इस कार्य के लिए आवश्यक है।

शक्ति मन्तुलन सिद्धांत की आवश्यकताएं

(The Pre-requisites of the Balance of Power)

शक्ति मन्तुलन के मुख्य कार्य के लिए कुछ प्रतिद्वन्द्व हैं। उन प्रतिद्वन्द्वों की पूर्णता पर ही शक्ति मन्तुलन का कार्य सम्भव है। यह आवश्यकताएं निम्न हैं—

(१) अधिक फैलाव तथा द्रव्यता (Dispersal and Fluidity)—शक्ति मन्तुलन के मुख्य कार्य करने के लिए आवश्यक है कि शक्ति का विभाजन अत्यधिक फैला हुआ हो क्योंकि शान्ति, शक्ति मन्तुलन से उभरी स्थायित्व होना सम्भव है जब कि शक्ति अनेक राष्ट्रों के मध्य विभाजित हो। इस सम्बन्ध में प्रो० लर्क लिखते हैं कि, "शक्ति का केन्द्रीकरण और सम्बन्धों की कठोरता, यह दो ऐसी चीजें हैं जिनको शक्ति तथा मन्तुलन के समर्पक तथा लेखक, शान्ति के मार्ग में सबसे बड़े बाधक मानते हैं। अतः अत्यधिक फैलाव तथा द्रव्यता शक्ति मन्तुलन के कार्य के लिए पूर्व आवश्यकताएं (Pre-requisites) समझी जाती हैं।"

(२) अनेक या बहुराष्ट्र पद्धति (Multi-state system)—शक्ति मन्तुलन के सिद्धान्त के कार्यान्वित होने के लिए आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक सिन्डिकेट पर अनेक राष्ट्रपद्धति विद्यमान हो।

(३) रहस्यमयी तथा गुप्त सन्धिपत्रों (Secret Negotiation and Pacts)—शक्ति मन्तुलन का सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि प्रत्येक राष्ट्र में कुछ चतुर व शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हों, जो अन्य राष्ट्रों के साथ रहस्यमय सम्बन्ध व सन्धिपत्र रख सकें।

(४) यदि शक्ति मन्तुलन सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करना है तो आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के राजनैतिक नेता तथा राजनीतिज्ञ अन्य देशों की शक्ति के अनुमान तथा इन देश की शक्ति के विषय पर घनता अत्यधिक समय व्यतीत करें।

(५) शक्ति मन्तुलन स्थायित्व करने का एक साधन शक्ति मन्तुलन सिद्धान्त के विचारकों के अनुसार कुछ है। उनका कथन है कि शक्ति को मन्तुलित करने के लिए कुछ नौ लड़ा जा सकता है परन्तु यह कुछ अत्यधिक दुर्लभायी व भयावह न हो।

(६) प्रत्येक राष्ट्र में यह भावना हो कि वर्तमान स्थिति शक्ति मन्तुलन ठीक है और इसमें किसी प्रकार के बड़े सुधार की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कुछ छोटे २ सुधार अवश्य होने की जरूरत हो।

(७) सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रतिद्वन्द्व या पूर्व आवश्यकता शक्ति मन्तुलन के सिद्धान्त के लिए है—मन्तुलनकर्ता की स्थिति एक ठेकेदार की या

स्थापित सन्तुलन ॥ सन्तुष्ट हो और उसे कायम रख मने । वह यह प्रयत्न करे कि स्थापित शक्ति सन्तुलन समन्वित न हो । १६वीं और १६वीं सदियां में इंग्लैण्ड ने यह प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भाग प्रदा किया । प्रो० मारगनथा के अनुसार सन्तुलनकर्ता, शक्ति सन्तुलन मिळाने में मुख्य व महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि उसकी स्थिति पर शक्तिद्वन्द्व का परिणाम आश्रित है ।

प्रो० सर्व का विचार है कि भारत व हमने सहयोगी राष्ट्र भावी सन्तुलनकर्ता बनने की क्षमता रखते हैं । उनका विश्वास है कि चीनी, एशिया तथा मध्य एशिया के नेतृत्व के साथित्व हम तथा मध्य एशिया के मध्य शक्ति-सन्तुलन स्थापित कर सकेगा ।¹

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है शक्ति सन्तुलन के सफल कार्य के लिए कुछ बातों की पूर्ति आवश्यक है । बिना इन पूर्ण आवश्यकताओं की परिपूर्णता के शक्ति सन्तुलन का मिळाने कार्य रूप में परिणीत नहीं किया जा सकता है । शक्ति सन्तुलन का मिळाने वाली स्थान (Vacuum) में कार्यशील नहीं हो सकता ।

शक्ति सन्तुलन करने के साधन

(Devices for Maintaining the Balance of Power)

सन्धिया और विरोधी या प्रति सन्धिया

(Alliances & Counter alliances)

सन्धिया और प्रति सन्धिया शक्ति सन्तुलन स्थापित करने का प्राचीनतम और प्रत्यक्ष प्रयोग किया हुआ साधन है । प्रो० मारगन था कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि ॥ शक्ति सन्तुलन दो मित्र राष्ट्रों की समता में प्रतिष्ठित नहीं होकर, एक राष्ट्र या समूह और दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र समूह के सम्बन्धों के रूप में दृष्टिगोचर होता है ।² जब किसी राष्ट्र का एक समूह शक्ति सन्तुलन को विस्थापन करने में प्रयत्न करता है तो एक अन्य राष्ट्र समूह का जन्म हो जाता है । उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व

1 ' India and its allies constitute a strong candidate for the future balances. If the Afro-Asia-Arab bloc led by India continues to gain power it might be able to hold balance between U. S. A. and U. S. S. R. ' —Prof. Lerche

2 ' The historically most important manifestation of the balance of power, however is to be found not in the equilibrium of two isolated nations but in the relations between one nation or alliance of nations and another alliance ' —Prof. Margenthau

Triple-Alliance (जर्मनी, इटली और फ्रांसिया के मध्य) तथा Triple Entente (ब्रिटिश—फ्रांस, रूस और इंग्लैंड के मध्य) तथा माथारण और विस्तृत प्रयोगों में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद परिवर्तित हुए तथा साम्यवादों हुए और बाद में अत्यन्त राष्ट्र हुए को जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति (Compensation)

प्रो० हार्टमन का मत है कि राज्य शक्ति, शोभा के निकट या उपनिवेशों के रूप में प्रतिष्ठित भूमि प्राप्त कर बढ़ाई जा सकती है।¹ क्षतिपूर्ति किसी राष्ट्र के विभाजन के रूप में या अन्य राष्ट्र को भूमि पर अपना प्राधिकार स्थापित करने के रूप में एक सीमा व सर्वसाधारण तरीका है—क्षति मनुजन के लिए। यह १८वीं और १९वीं शताब्दियों में सर्वाधिक रूप से प्रचलित तरीका था। प्रो० मागनया का विचार है कि राजनैतिक समझौते जो राजनैतिक शक्तियों के फलस्वरूप होते हैं क्षतिपूर्ति या पारितोषिक के ही रूप हैं अतः क्षति-मनुजन के विद्यमान से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए १७१३ की Treaty of Vtrecht, जिसने स्पेन के उपनिवेशों के युद्ध का अन्त किया तथा पोलैंड का १७७२, १७९३ और १७९५ में विभाजन, १९०६ में Ethiopia का इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य प्रभावशाली भागों (Sphere of Influence) में विभाजन तथा १९०७ में ईरान का प्रभावशाली भागों में विभाजन व अन्य कई प्रकार के मानसे दिए जा सकते हैं।

शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण

(Armament and disarmament)

प्रो० मागनया, फामर, परकिन्स एवं अन्य विद्वानों का मत है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति से सज्जित होना पर सबसे अधिक जोर देता है और शस्त्रीकरण क्षति मनुजन स्थापित करने का एक प्रमुख माध्यम है।

नैदानिक दृष्टि से क्षति मनुजन का प्रभावशील और मरुत्वपूर्ण माध्यम है—निशस्त्रीकरण जिसके द्वारा राष्ट्र शक्तियों को बढ़ाने की होड़ को छोड़ कर शक्तियों की संख्या को कम करने की होड़ में मग जाते हैं। प्रो० फामर और परकिन्स का विचार है कि निशस्त्रीकरण की सम्मति निशस्त्रीकरण न होकर क्षति मनुजन है। नैदानिक दृष्टि से शक्ति के विलयन से ही शक्ति सम्पन्न प्रत्येक निशस्त्रीकरण के लिए दिए जा सकते हैं।

1. "Power may also be increased externally by acquiring additional territory either contiguous to the existing frontier or in colonial areas."
—Prof. Hartmann.

मध्यस्थता और अमध्यस्थता

(Intervention and Non-intervention)

इस विधि का प्रयोग शक्ति सन्तुलन करने वाले राष्ट्र द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता का अर्थ यह है कि सन्तुलनकर्ता राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के युद्धों और झगड़ों में भाग लेता है जिससे युद्ध के कारण शक्ति सन्तुलन अमन्तुलित न हो जाए। अमध्यस्थता का अर्थ है कि राष्ट्र समय पर स्थित शक्ति सन्तुलन से सम्मृष्ट है और शक्ति सन्तुलन को कायम रखने के लिए शक्तिप्रद साधनों का प्रयोग करता है।

मध्य राष्ट्र (The Buffer States)

शक्ति सन्तुलन की एक अन्य विधि है मध्य राष्ट्र। दो राष्ट्र एक मध्य राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए इसविधि राजी हो जाते हैं कि उत्तराभिपक्ष एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से शक्तिशाली बना देगा। मतः कोई भी राज्य उनका (मध्य राष्ट्र) दूसरे राज्य के समीप होना पसन्द नहीं करेगा। पामर और परकिन्स के विश्वानुसार दो घुटी वाली दुनिया (Bipolar world) में बिना मध्य क्षेत्र (Buffer zones) और उदासीन भूभागों (Neutral areas) के शक्ति सन्तुलन बड़ा कठिन है क्योंकि उन हालात में दो भागों में सीधी टक्कर होने की सम्भावना बनो रहती है।

उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान, बेल्जियम, होलैण्ड तथा स्वीट्जरलैण्ड के उदाहरण दिए जा सकते हैं।

बाँटो और शासन करो (Divide and Rule)

प्राचीनतम और प्रत्यधिक प्रयोग में आने वाली विधियों में से यह एक है जिसके द्वारा शक्ति सन्तुलन स्थापित किया जाता है। प्रो० मास्किन कहते हैं कि सन्तुलन दो प्रकार से स्थापित किया जा सकता है—प्रथम शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर बनाने के प्रयत्नों द्वारा तथा द्वितीय निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने के प्रयत्नों द्वारा। इसी विधि का नाम 'बाँटो और शासन करो' है। इसका प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा किया गया जिन्होंने अपने विरोधी राष्ट्रों को हार में पीछे धोड़ने का प्रयत्न किया। इन राष्ट्रों ने विरोधी राष्ट्रों को विभाजित कर या बँटा हुआ रख कर उनको अपनी तुलना में भागे नहीं बढ़ने दिया। इनके प्रमुख उदाहरण हैं फ्रांस और जर्मनी की नीतियाँ, इंग्लैंड की हेनरी फ्रंट के समय में यूरोप की नीति नीति तथा हम की यूरोप में नीति।

शक्ति सन्तुलन करने वाला राष्ट्र अर्थात् सन्तुलनकर्ता

(The Holder of the Balance)

शक्ति सन्तुलन पद्धति में तीन घंटा हो सकते हैं—दो घंटा के अन्तर्गत शक्ति सन्तुलन करना है तथा तृतीय घंटा यह राष्ट्र जो इन दो राष्ट्रों के मध्य शक्ति सन्तुलन करता है और जिसको सन्तुलनकर्ता (Balancer) के नाम से

वर्तमानकाल में शक्ति-सन्तुलन (The Balance of Power today)

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त ने उस युग में सफलतापूर्वक काम किया जब यूरोप में विभिन्न राज्यों की शक्ति में प्रथिक् सममानता न थी और नीतिवादी कुछ व्यक्तियों द्वारा ही नियन्त्रित होती थी। पाम की राज्य-त्रान्ति के पदवात, यूरोप में शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त के सफलतापूर्वक कार्य की सम्भावनाएं कम हो गईं, विशेष रूप से यूरोप के शक्ति सन्तुलन के विश्वव्यापी बनने से। पामर और परकिनस् (Prof. Palmer and Perkins) ने उन सत्त्वों का इस प्रकार वर्णन किया है, जिन्होंने इस सिद्धान्त को प्रभावहीन कर दिया है—

(१) नई शक्तियों का प्रभाव—राष्ट्रवाद, औद्योगीकरण, प्रजातन्त्र, जन शिक्षा, युद्ध की नई प्रणालियाँ, जनमत का बढ़ता हुआ महत्व, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, राष्ट्रों की प्राथिक् क्षेत्र में परस्पर निर्भरता, उपनिवेशों का अन्त—ये शक्ति सन्तुलन को अत्यन्त सरल तथा अत्यन्त कठिन नीति बना दिया है।

(२) वर्तमान युग में शक्ति की प्रवेहलना और सन्तुलनकर्ता के न होने से इस सिद्धान्त के लिए कार्य करना असम्भव बना दिया है। जैसा कि हमें ज्ञात है शक्ति सन्तुलन के लिए अनेक या बहुत राष्ट्र पद्धति और सन्तुलनकर्ता की आवश्यकता होती है, इससे बिना यह कार्य नहीं कर सकता।

(३) प्राकमणकारी राष्ट्र की शक्ति में विपक्षी राष्ट्र की तुलना में प्रत्यापी रूप से बुद्धि और युद्ध का रूप सम्पूर्ण युद्ध (Total war) होना—विमर्श सर्व है शक्ति सन्तुलन का प्रयत्न समर्थक भी शक्ति सन्तुलन को ठीक बनाने के लिए विश्वव्यापी संपर्क में भाग लेने से पूर्व हिचकिचायेगा।

(४) विचारधाराओं का बढ़ता हुआ महत्व—१९वीं शताब्दी में राजनीतिज्ञों की विपक्षियों की शक्ति के अनुमान लगाने के विशेष डकि थी, न कि विचारधारा सम्बन्धी। आजकल विभिन्न समझौते या सन्धियों राष्ट्रों के मध्य विचारधाराओं को आधार बनाकर किये जाते हैं।

(५) तुलनात्मक रूप में शक्तिशाली राष्ट्र और भी प्राथिक् शक्तिशाली राष्ट्र बनते जा रहे हैं जब कि दूसरी ओर कमजोर राष्ट्र प्राथिक् कमजोर होने जा रहे हैं।

इनके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के विषय में विरोध में अन्य बातें भी हैं।

(६) शक्ति सन्तुलन में पुनः सन्धियों और समझौतों निहित है। २०वीं सदी में कूटनीति ने प्रजातान्त्रिक हो जाने से इस प्रकार की युक्त सन्धियों असम्भव हो गई है। वर्तमान युग मार्शजनिक् और प्रजातान्त्रिक कूटनीति का युग है।

(७) दूसरे राष्ट्र की सम्भावित शक्ति का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है।

आज २०वीं सदी में शक्ति सम्बलन सरल तथा साधारण है क्योंकि अमेरिका तथा रूस ही आज की राजनीति के नेता बन हुए हैं तथा इंग्लैण्ड अब सम्बलनकर्ता का भाग अदा करने में असमर्थ है। अतः कुछ विख्यात विद्वान् व राजनैतिक शास्त्री शक्ति सम्बलन के सिद्धान्त को बेकार मानते हैं। उदाहरण के लिए Carl J. Friedrich और Quincy Wright का मत है कि तात्त्विक रूप से, अगर धर्पार्थ में नहीं, शक्ति सम्बलन का सिद्धान्त अश्वभावशील व अनामयित हो चुका है। कहींभी राइट इसे प्रजातन्त्र को विपरीत मानते हैं। उनका कहना है कि अगर प्रजातन्त्र को प्रोत्साहित करना है तो हमें शक्ति सम्बलन के सिद्धान्त को त्यागना हीगा। प्रो० मार्गन पाँच के अनुसार इसके निम्न तीन दोष हैं—(१) इसकी अनिश्चितता (Its uncertainty), (२) इसकी अवान्तरिकता (Its unreality) और (३) इसकी अपर्याप्तता (Its inadequacy)।

वह सत्य है कि शक्ति सम्बलन का सिद्धान्त इस युग में अपनी उपयोगिता और महत्ता खो चुका है तो भी इसको पूर्णतः बेकार कहना उचित नहीं और जैसा कि प्रो० पाम और परकिनम् कहते हैं—“जब तक अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में राज्य-राष्ट्र-द्रष्टाणी (Nations state system) प्रचलित है, शक्ति सम्बलन सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता रहेगा, चाहे इसे सिद्धान्त में किटना ही दोषों कहा जाय। मनी अवस्थाओं में वह कार्य करता रहेगा, चाहे प्रादेशिक अथवा विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सफल किया जाये।”¹

BIBLIOGRAPHY

- (1) International Relations • Palmer and Perkins
- (2) Politics Among Nations : Hans J. Margen than.
- (3) The Relations of Nations : Hartmann
- (4) Principles of International Politics • Prof. Lerebe
- (5) Introduction to International Relations • Schleicher.

1. “As long as the nations state system is the prevailing pattern of international society, balance of power politics will be followed in practice, however soundly they are damned in theory. In all probability they will continue to operate even if effective supra national grouping, on a regional or a world level, are formed”

—Prof Palmer and Perkins

स्वतंत्रता के बाद Dr Azikiwa प्रथम राष्ट्रपति और Abubkar Tafawa Balwa प्रथम प्रधान मंत्री। राष्ट्रपति एवं प्रधान मंत्री के पदों पर इस प्रकार सामान्य-सहमति से नाइजीरिया, प्रजातन्त्र की सफलता की प्रथम अग्नि परीक्षा सम्पूर्ण हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए इन दोनों नेतृत्वों में बड़ा संघर्ष की सम्भावना थी, जो सम्भवतः दो कबीलों के गृहयुद्ध में परिणित हो जाता, जैसा कि कांगो में हुआ।

नाइजीरिया में 'Northern People, Congress' (N P C) प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसके नेता प्रधान मंत्री Tafawa Balwa है। (Nation Council of Nigerica Citizens प्रमुख-विरोधी दल है। परम्परा-वादी N. P. C दल के विरुद्ध यह दल नए प्रगतिशील विचारों का समर्थक है। पूर्वी क्षेत्र के Ibo कबीले में इस दल का अधिक प्रभाव है। Northern Elements Progressive Union अन्य प्रगतिशील दल है। अन्य विकासोन्मुख देशों की तरह यहाँ भी दल मत-राजनीति धर्म, क्षेत्रीयता आदि पर आधारित है, जो राष्ट्रीय एकता में समय समय पर बाधक रहे हैं। दिसम्बर, 1964 के ग्राम चुनावों के दौरान एक ऐसी ही सम्पूर्ण सम्मेलन उत्पन्न हो गई थी, जबकि पूर्वी प्रांत के मुख्य मंत्री और क्षेत्रीय N. C. N. C. दल के नेता Dr. Okkara ने अपने राज्य की संलग्न करने का प्रश्न उठाया था। किसी तरह राष्ट्रपति Azikiwa ने N. P. C. और N. C. N. C. दल की मिली-जुली सरकार बनवाकर समस्या को टाला।

नाइजीरिया में नई बीड़ी में तीव्र-प्रगतिशील विचार पनप रहे हैं, जो पाश्चात्य-मूल्यों के स्थान पर समाजवाद और अफ्रीकावाद के अधिक निबट है। फिर भी निष्ठ भविष्य में ऐसी कोई भाषा नहीं देखती कि बहु देश वर्तमान-स्वरूप की छोड़कर Ultra Africanist या Socialist हो जायगा।

घाइवरी-कोस्ट — फरवरी 1960 में स्वतंत्रता प्राप्ति में पूर्व यह राष्ट्र फ्रांस का उपनिवेश था और हमसे मिन सेनीयाल टोनो आदि राज्य भी सम्मिलित थे। परन्तु स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के तत्कालीन नेता व घाइवरी कोस्ट के वर्तमान राष्ट्रपति की मान के प्रति उदारनीति के कारण टोनो राज्यों ने गुप्त हो जाना उचित समझा। प्रचुर साधन सम्पन्न घाइवरी-कोस्ट ने भी इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वहाँ प्रापिक-समृद्धता व प्राकृतिक साधन अधिक थे व उन्हें शिवायन की बि दूसरे राज्य उनमें हिस्सा बंटायेंगे।

राष्ट्रपति Houphouët Boigny पास की पद्धति पर धर्मशास्त्रिक सरकार चला रहे हैं। स्वयं ही प्रधान मंत्री भी हैं। Democratic Party of Ivory Coast (P.D.C.I.) यहाँ का एक मात्र राजनीतिक दल है। फिर भी दल के सदस्य शासन की चालोपना का पूरा अधिकार है। विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की काफी विशेषाधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। सतत दो तिहाई बहुमत से उसे सहायक बन सकता है।

राष्ट्रपति Boigny समाजवाद और धर्म अन्धविश्वास के सख्त विरोधी हैं। फिर भी नई बीड़ी में समाजवादी दृष्टिकोण को न बनने देने में वे सफल नहीं हो सके हैं।

साइरीरिया — साइरीरिया अफ्रीका के समस्त देशों से संलग्न प्रकार का एक देश है जो पाश्चात्य मूल्यों के आधार पर प्रजातन्त्र की संकल्प बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इतिहास का छोड़कर यही एक ऐसा देश है जो यूरोपीय दायित्व में मुक्त रहा।

समुक्त राज्य अमेरिका का सम्मेलन, इस देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए काफी सहायक रहा है। इस राज्य की आज़ाद करने वाले के अमरीका नीतिज्ञ हैं जो अधिक समय एवं गुप्तदृष्ट होकर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ का एक मात्र राजनीतिक दल 'The

True Whig Party और राष्ट्रपति Tubman उनकी समस्याओं का दृष्टिकोण समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वस्तुतः यहाँ के 20 लाख आदिवासियों के 20000 समस्याओं का दृष्टिकोण समझ का एक भाग बन गई है। परन्तु अब राष्ट्रपति Tubman कुछ क्षेत्रों में निम्नलिखित के बाद इन दो विभिन्न समझों का एकीकरण करने के लिए काटवट है। उन्होंने मंत्रिमंडल, न्यायपालिका और प्रशासनिक सहायकों में आदिवासियों के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की है। राष्ट्रपति दूरदर्शन से इन देशों की समस्याओं को देख रहे हैं, फिर भी वे अमेरिका की घोर मुश्किलों को कुछ सैनिक सहायता भी कर रहे हैं। फिर भी फ्रान्स एवं ब्रिटन आदि की घोर उदासीनता के कारण अन्य राष्ट्र उनकी समस्याओं में विचाराधीन नहीं हैं और कई बार दो अलग-अलग राष्ट्रों के बीच झगड़ों में उन्हें मध्यस्थ बनाया गया है।

प्रादेशिक राष्ट्रवादों राज्यों के सामान्य तत्त्व

उन विद्वानों से स्पष्ट है कि इन देशों पर प्रादेशिक का प्रभाव बहुत अधिक है। विज्ञान में इनकी नवीन समस्याओं को देखते हैं, फिर भी अनेकों समस्याओं पर इन्होंने पश्चिम की धार प्रभाव दिया है। आइबरी कोस्ट के राष्ट्रपति Bouigny मौलिक के मौलिक मान्यताओं की समीक्षा करते हो रहे हैं। परन्तु प्रजातन्त्र का जो मूल्य पश्चिमी देशों या हमारे देश में पहचाना जाता है, वह यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ नागरिकों का छोटा-बड़ा देशों में एक बन ही प्रमुख है। नागरिक, प्रेस की स्वतन्त्रता या अन्य मौलिक अधिकारों की सरकारें अपना कर्तव्य नहीं हैं। वास्तव में यहाँ की सामान्य जनता भी इन और से उदासीन है। जब तक नई विधित पीढ़ी तैयार नहीं हो जाती, प्रजातन्त्र का वास्तविक मूल्य अभी दूर ही होगा।

Ultra Africanism

विज्ञान की दृष्टि और प्राकृतिक व्यवस्था के प्रभाव में अनेकों समझ और सभ्यता की पुनर्जागरण करना अन्तर्गत अन्तर्जागरण का प्रमुख दृष्टिकोण है। अनेकों सदियों में विश्व के अन्य भागों से बड़ा हमारा महान्वेष रहा है। अन्तर्गत यहाँ के लोगों की भावना, स्वभाव एक विशिष्ट प्रकार का हो गए हैं। अन्तर्गत यह भावस्थिति है कि यदि अन्तर्गत का प्रादिक एवं औद्योगिक विकास करना है, प्रजातन्त्र स्थापित करना हो तो सामान्य जनता की इच्छाओं का, विचारों की समझ जान। इस प्रकार से उनका महान्वेष प्राप्त करके ही दृष्टा जा सकता है। अन्तर्गत Ultra Africanism नव-वा अन्तर्गत की सभ्यता व सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख ध्यान देते हैं। George W. Shepherd ने Ultra-Africanism के सामान्य तत्त्व (Common elements) बताए हैं—⁴

(1) राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही नव-राष्ट्रवाद के प्रभाव में मुख्य तत्त्व प्रादिक व सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना। इसके लिए अन्तर्गत प्रजा व बहुविध (Diversified) व्यवस्था का प्रोत्साहन देना।

(2) राज्य के द्वारा विभिन्न-क्षेत्रों में उद्योगों के स्वाधिक, उत्पादन और अनुचित विवरण की व्यवस्था और उनकी सहायता देना।

4. George W. Shepherd The Politics of African Nationalism (Frederick A. Praeger Publisher New York.) P. 65.

(3) जनता का विभाज्य प्राप्त करत हुए एक दलीय शासन पद्धति को स्वीकार करना। दल के सदस्य विभिन्न दृष्टिकोणों को समिन्धित करने की स्वतन्त्रता होगी पर तब मात्र राष्ट्रीय नीतियों के विशुद्ध दृष्टिकोण या आलोचना महत्त्व न होगी।

(4) उपनिवेशी दासता से मुक्ति के बाद बने राज्यों को एक बड़े संगठन में सम्मिलित होने के नियम प्रस्तुत करना। इस Pan African राजनीतिक संगठन के अंतर्गत अफ्रीकी लोगों को सम्पूर्ण धरातल महान सभ्यता और जातीय-व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना।

घाना — हम हिम्मा देना चाहिए कि हम अफ्रीकीयान स्वयं शासन स्थापन कर सकत हैं राष्ट्र को प्रगतिशील एवं स्वतन्त्र बनाए रख सकने हैं और राष्ट्रीय एकाता को सुरक्षित रखा सकते हैं। इस प्रकार के उत्तम जना एवं संलग्नता-संज्ञक व्यवस्था देने वाले घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा और उनका देग घाना राष्ट्र-अफ्रीकानिज्म और पान-अफ्रीकानिज्म के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने वालों में अग्रणी रहे हैं। 1957 में ब्रिटिश दासता से मुक्ति के बाद में घाना तटस्थता की नीति पर चलता हुआ अपने अफ्रीकी विश्वास में लगा है।

लंदन-रहून आफ इकनोमिक्स में निष्ठा प्राप्त राष्ट्रपति नक्रुमा मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। वे मार्क्स निष्ठावाद और वन सचय में विश्वास करते हैं। परन्तु वे साम्यवादियों के समाजवाद माने के हिमालयक साधनों में विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में राष्ट्रपति नक्रुमा इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि अफ्रीकी-शासनिक व सदन में प्रजासत्तम और मार्क्सवाद दोनों का संगोष्ण कर मिश्रित स्वरूप व्यवहार में लाया जाय।

इसीलिए विरासत की विभिन्न व्यवस्थाओं को पर करो के लिए एकीकृत क्रांती कृत शासन की व्यवस्था में ला रहे हैं। घाना का गवर्नर केवल Convention Peoples Party को मान्यता प्रदान करता है। नाव लेजीसलर पर एक्साइजन् नेतृत्व वग (बकीनों के सरदार) का कुछ भी विशेष अधिकार नहीं है। फलतः ये घाना की राजनीति में अनेकों बार असाधारण अवरोध उपस्थित करने का चेष्टा करता है।

घाना के राष्ट्रपति अपने आषकी अफ्रीका के नेता एवं पान-अफ्रीकानिज्म के प्रथम समर्थक घोषित करत हैं। 1961 में घाना की राजधानी अकरा में आयोजित Urganisation of African Union के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर कहा था यदि हमें नये-उपनिवेशवाद के खतुन में बचना है तो हम हमारा एक राजनीतिक संगठन बनाना होगा। बिना समुक्त राज्य अफ्रीका का निर्माण किए अफ्रीका विश्व में प्रतिष्ठित नहीं हो सगा।

तजानिया — अफ्रीका के तट पर स्थित अफ्रीका और ईशानिका राज्यों में मिल कर बना तजानिया का सचय में अफ्रीकी स्वतन्त्रता में पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था। यहां के राष्ट्रपति यरेक प्रारम्भ में पश्चिम की ओर अंकुश प्रतीत होते थे। परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के बाद उनके स्वरूप में गहरी अर्थ व Ultra Africanism की ओर झुके हुए हैं। उन्होंने अफ्रीकी वार व्यवस्था घोषणा की है कि कोई भी जो तजानिया की जीवन पद्धति का स्वीकार नहीं करता अच्छा हो कि यह इस देश को ही छोड़ दे।

राष्ट्रपति यरेक पश्चिमी प्रजातन्त्र की अफ्रीका के लिए एकदम अल्प बनाने हैं। उनका प्रजातन्त्र में सचय है —

(1) एक-इन व्यवस्था।

(2) विभिन्न विषयों पर दास विश्वास हो पर दम के अंग ही।

(3) प्रजातान्त्रिक शासन केन्द्रित है। इसमें सभी उत्तरदायीयों वनों पर निर्वाचित

प्रतिनिधि होंगे। वे राष्ट्रीय-गतिविधियों पर वाद-विवाद भी कर सकते हैं, पर निर्णय राष्ट्रध्यक्ष का मान्य होगा।

तत्कालीन तटस्थ रहकर अपना विकास करना चाहता है। जून 1965 में जीनी प्रधान मंत्री के स्वागत में दिए गए भाष में बोलते हुए उन्होंने अग्रतपत्र में मे चीन को चेतावनी देते हुए कहा था "हम हमारे मित्रों और दल को योही भी मुद्राओं के पीछे बेचने की तैयार नहीं होंगे। न ही हम किसी का हस्तक्षेप पसन्द करेंगे।"

गिनी — पश्चिमी अफ्रीका में एक छोटा सा देश होते हुए भी अपनी दृढ़ नीतियों के कारण राष्ट्रपति Sikou Toure ने अपने राष्ट्र का अफ्रीका के प्रतिष्ठित राष्ट्रों की श्रेणी में रख दिया है। 1958 में फ्रांस के राष्ट्रपति डी गाल की कड़ी घमस्त्रियों के आग्रह पर राष्ट्रपति तूरे ने फ्रांस का घग बनना स्वीकार नहीं किया और अंत में देश को स्वतंत्र करवाकर ही रहे। फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों की लड़ी सामोबनाओं और साम्यवाद के पिटू होने के आरोपों के बावजूद उन्होंने अपने देश को राष्ट्रपति तूरे ने अपने को नव उत्तमिष्य वाली राश्यों के चंगुल से बचाने की चप्टा की है।

अन्य अल्ट्रा-अफ्रीकनिस्ट देशों की भांति यहाँ भी एक-दलीय शासन है। राष्ट्रपति तूरे विरोधी-दलों के बारे में सबसे अधिक घमस्त्रिण्य व्यक्ति मान जाते हैं। अफ्रीका जैसे पिछड़े महाद्वीप में उनका विद्वान है, कि विरोधों केवल विरोध के लिए होता है। घम व जातीयता की मकीर्ण विचारधाराएँ शासन की नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। अतः विरोधी दलों को किसी भी तरह चुन देने की नीति की राष्ट्रपति तूरे स्पष्ट घोषणा करते हैं।⁵ जनता के लिए जनता को सरकार हो 'यह वे मानते हैं। पर एक दल में अपना विश्वास प्रकट कर भी जनता अपनी इच्छा व्यक्त कर सकती है। यही कारण है कि वहाँ केवल Democratic Party of Guinea को ही मान्यता प्राप्त है। गिनी का मवि-धान नागरिकों को निम्नल ग्याय पालिका व विभिन्न घम-बांति को मानने की स्वतंत्रता का आश्वासन देता है।

घाना के राष्ट्रपति नक्रमा के साथ मिलकर राष्ट्रपति तूरे ने अल्ट्रा-अफ्रीकनिस्ट के प्रसार में काफी योग दिया है।

अल्ट्रा अफ्रीकनिस्ट राष्ट्रों के सामान्य हतव — इन राष्ट्रों की प्रबल इच्छा है कि वे अफ्रीकी सभ्यता को महत्व प्रदान करते हुए देश में औद्योगिक विकास व समाजवाद नान के प्रयत्न करें। उनकी इस भावना की पश्चिमी और साम्यवादी राष्ट्र स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि तत्कालीन, गिनी आदि पश्चिम के कोप-माजिन बनते रहे व कई बार माविक-अड्डापता से बचते हुआ पड़ा। इस स्थिति का साम साम्यवादी उठाते हैं व साम्यवाद का प्रचार करते हैं।

5. "A year from now one won't walk into a town and meet a thousand idlers chafing from morning to night....If it is necessary to have a scaffold for counter-revolutionaries who still want to hold down this country, France had the Guillotine, Guinea shall have the scaffold."

Quoted by G. W. Shepherd : Op. cited (Page 99).

सैनिक शक्ति पर आधारित राष्ट्र

मिश्र, घरेलूतरिया आदि कुछ देश ऐसे हैं, जहाँ सैनिक साम्राज्यही है। अपने शासकों से सत्ता हथियान के बाद ये देश अपने आपकी प्रजातांत्रिक पद्धति पर दावने प्रयास कर रहे हैं। इनका मनन से अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, कि अफ्रीकी और अफ्रीकी-संस्कृति के बारे में इनकी नीतियाँ स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। योंसे तौर पर ये घट्टा, अफ्रीकनिस्ट होने का दावा करते हैं, पर मूझमन देखने पर इनका, विशेषकर मिश्र का, अन्दा-अफ्रीकनिज्म से असमाव स्पष्ट हो जाता है।

मिश्र — हम भी अफ्रीकी हैं' (We too, are Africans) कहने वाले नासर ने 1953 में अपने पूर्व सैनिक साम्राज्य General Naugib को पदच्युत शासन-मूत्र अपने हाथ में लिया था। 1956 में स्वेज नहर के एक पक्षीय राष्ट्रपरण घोषणा कर मिश्र का जनता का विश्वास प्राप्त करने में प्रपूर्व चातुर्य दिखाया था। घटना ने उम्ह मिश्र में ही नहीं अरब राष्ट्रों में भी प्रतिष्ठित नेता का स्थान प्रदान किया। इब्राहिम बिराघी नीति को आधार बनाकर राष्ट्रपति नासर अरब राष्ट्रों में अपनी बनाए हुए हैं व उनका फुलाव अरब देशों के संगठन की ओर ही है।

साथ ही राष्ट्रपति नासर अफ्रीका में भी अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं यहाँ भी अपने नेतृत्व की प्रतिष्ठित रखने के लिए उनका दावा है 'हम भी अफ्रीकी हैं। वस्तुतः मिश्र कुछ समय पूर्व तक अफ्रीकी होते हुए भी अफ्रीका की ओर से उदासीन था। प्राचीन सभ्यता व इतिहास के साथ ही सहारा के मध्यम में भी मिश्र अफ्रीका से चलन रहने देने में काफी योग दिया है। व मिश्र का सम्बन्ध तो अफ्रीकी की प्रेरणा एशिया व अरब राष्ट्रों से अधिक रहा है। अफ्री भी मिश्र में अपने प्रति घोरता की भावना व्याप्त है, जो उसे अफ्रीकी देशों से घिसने नहीं देती। परन्तु जब नष्ट ने अफ्रीकी राज्यों के साथ और अफ्रीकी-संस्कृति का नारा लगाया तो महत्वाकांक्षी अरब भी अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए अपने अफ्रीकी होने की दाव करने लगे व समय समय पर साम्राज्यवाद के विरुद्ध सपर्यन्त जनता को सत्तास्त्र से सहायता दी है।

स्वेज (हालांकि यह प्रश्न मुलक चुका है) और इब्राहिम ये दो प्रश्न ऐसे थे कि राष्ट्रपति नासर की पश्चिम का बटु आलोचक बना दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन-राम आदिक सहायता बन्द कर दी। व अफ्रीका ने भी काफी बटोरी की है। इसका फल व फल ने उठाने की कोशिश की है। हाल के अफ्रीकी-कुचकों से शिता लेकर अब इस की ओर अफ्रीकी का हाथ बढ़ा रहे हैं।

देश के अन्दर हालांकि सैनिक साम्राज्यही है फिर भी कुछ देशों में नासर-भावनाएं मौजूद हैं। राष्ट्रपति की हत्या के भी कई बार प्रयास किए गए। अफ्रीका 63 Moslem Brotherhood की धावाज उठाने वाले एक दल को नासर ने इसी घटना के सम्बन्ध में कुचलने का प्रयास किया है।

अफ्रीकीरिया — ये स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अफ्रीकीरिया प्रांत का उपनिवेश था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी यहाँ राजनैतिक स्थिरावस्था नहीं बनाए रखा जा सका। व कुछ ही समय बाद दो अविरोध नवा बेनबेता और बेनबेता में नेतृत्व का निर्णय हो गया। जनरल बूनेदीनि की सहायता में अफ्रीका में बेनबेता की मननना मिली

प्रधान मंत्री विष्णुन धीर रोडेगिया के प्रधानमंत्री श्मिय में एक ग्राही धापोन बनाने के बारे में समझौता हो गया था ^१ यह धापोन एक ऐसे मविधान की आधार तैयार करेगा जो रोडेगिया की जनता को माय होमा । इससे पक्षस्विय श्मिय द्वारा एक तरफा स्वाधीनता की घोषणा करने से रुकन हाने वाला सम्भावित मकट तब टल जाता । परन्तु 10 नवम्बर 1965 को श्मिय सरकार ने रोडेगिया की स्वतन्त्रता को एक तरफा ^२ कर दी ।

सफ़ीबी राष्ट्रवाद का स्वरूप —सफ़ीबी में राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों पर विचार करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि सतमाय पोटी किसी भी प्रकार के राष्ट्रवाद को अपना मकतो है पर कई पोटी में मकत उग्र व जातिवारी विचार जम ग रहे ^३ । इस पोटी में वस्तुतः सफ़ीबी सफ़ीबीज्म की भावना समर रही है । प्रजातन्त्र के स्वरूपों पर विश्वास या समर्थन करने के स्थान पर वे पोटी में धार्मिक व सामाजिक जाति माना चाहते हैं । सम्भावना यह है कि यदि उचित दिग्गम नहीं मिया तो कई पोटी हो जाय ।

प्रजातन्त्र और समविधान सम्झौता की नेतृत्व के सख्त में —सफ़ीबी-जनता के दृष्टिकोण का राष्ट्रीय-नेतृत्व कम धुरा धुरा उपयोग करने की कोशिश कर रहा है । सफ़ीबीज्म की मकम बनी समस्या यह है कि सफ़ीबीज्म देग दो या सफ़ीबी बचीना जागिया मिसकर बने हैं । भारत में साम्प्रदायिकता की भाँति यहाँ भी इन आँतों में सामानो विरोधी-भावनाएँ मरी जा मकती हैं । इनके स्थापक निरक्षरता के कारण—कुल की 12% सफ़ीबी जनता साक्षर है सफ़ीबीबासी राजनीतिक प्रचारी के सामानो में गिना हो जाना है । यही कारण है कि यहाँ समक्षीय-प्रजातन्त्र मकम नहीं रहा है ।

ऐसी दगा में यदि विभिन्न देग अपना धानरिक हकों में जमे रह तो धार्मिक विभाग की गति अवच्छेद हो सकती है । यही सम्भावनाओं पर विचार करत हुए सफ़ीबी प्रजातन्त्र को अपने रूप में अपना रहा है । प्रायः सफ़ीबी राष्ट्रों में मकता तब शक्ति के हाथ में है और विरोधी-दलों के लिए विरोध स्थान नहीं है । यूगांडा व प्रचिन मरी धारा में समय पूर्व विरोधी-पक्ष की उत्पत्ति मदर्भ में बहा या मविधान व विरोधी पक्ष को कुल दिया है मैं उनमें वह धनित नहीं बन रहा हूँ पर धान्तिविद्या यह है कि मविधान न उहे कुछ भी सुविधाएँ या धाशवासन नहीं दिग हैं ।

सफ़ीबी में सत्ता के केन्द्रीकरण व एक शक्ति के प्रभुत्व व धाश-धरता को सदन में अनुचित नहीं ठहरा मकती है पर समस्या तब उत्पन्न होती है जब दो या सफ़ीबी नेता सत्ता के लिए मकम करते हैं और स्वयं को जोरप्रिय बताते हैं । बागों में राष्ट्रपति शासकधुर व स्वर्गीय प्रधान मंत्री के बीच स औरिया में धनरता और धनरता व बीच हुए मधुपर्क मकते उदाहरण है । कुल मितानकर सुवीचन यह कि जनता में निवासन व धाधार पर नहीं सफ़ीबी संनिक मकम व धाधार पर दो विरोधी विचारों व मकता सत्ता दृष्टिकोण की कोशिश करत हैं । ऐसे मकम सफ़ीबी-मकता व सामाजिक धाश-धरता व मित बडे मकते हैं ।

Nationalism eager to be merged into Pan-Africanism

राष्ट्रपति नक्रुमा न 1960 में घाना के स्वतंत्र होने ही घनीकी राजनीतिक एकता (African Political Union) की मांगें लगाया है। उनका कहना है घनीकी ने उपनिवेशवादियों के हाथों एक जैसे दुख भरे हैं। सभी राष्ट्र पिछड़े हुए हैं और इसीलिए आर्थिक सहायता के सहाने नैव उपनिवेशवाद पुनः उत्पन्न जमाना चाहता है। अतः बिना एक संगठन स्थापित किए—जिस व समुक्त राज्य घनीकी पुकारते हैं—घनीकी स्वतंत्रता प्रसिद्ध नहीं बनाए रस सकता।⁷

राष्ट्रपति नक्रुमा व समर्थक गिनी के राष्ट्रपति Sekou Toure तद्विषय के राष्ट्रपति ग्यरेरे⁸ प्रादि हैं। 21 से 26 फरवरी 65 के बीच होने वाले घनीकी-एकता संघ के सम्मेलन में (36 राष्ट्रपतियों ने इसमें भाग लिया था) घाना न प्रस्ताव रखा था कि समुक्त राजा घनीकी की बार क्रमशः बढ़ने के लिए प्रथम चरण के रूप में सभी राज्यों की एक कार्यवाहिका समिति स्थापित की जाय। पर यह केवल 18 राज्यों ने इस प्रस्ताव को पक्ष में मत दिया। मनीषल, नाइजीरिया, नाइजीरिया प्रादि राज्यों ने इसका विरोध किया। विशेषकर पश्चिमी यमाव क्षेत्रों में यह गुदा व्यक्त की जाती है कि ऐसे संघ को प्रतिनिधिताही एवं घनीकी इच्छाओं की क्रियाविध के लिए मजबूत बना लेने। अतः घनीकी एकता संघ राज्य में परिचित होना असम्भव ही संघता है।

घनीकी और समुक्त राष्ट्रसंघ :—घनीकी देश ज्यों ज्यों स्वतंत्र होते जा रहे हैं, समुक्त राष्ट्रसंघ में घनीकी और एशियाई देशों का समुक्त स्वर अधिक शक्ति और प्रभाव मिल जाता जा रहा है। दक्षिणी घनीकी की प्राविष्ट-नाकेबन्दी की यात्रा, बागी में समुक्त राष्ट्रसंघ का बड़ा चरण उठाने के लिए बाध्य करना और सब दक्षिणी रोदे, यमा के मामले पर समुक्त राष्ट्रसंघ में प्रावाह उठाना प्रादि ऐसे उदाहरण हैं कि विभिन्न समुक्त राष्ट्र संघ में घनीकी देशों का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

परन्तु पश्चिम में इस बात को लेकर बड़ी शिंका है। उन्हें आशंका है कि कहीं आवावेध में बाहर घने शियाई राष्ट्र जन्मवादी में निर्णय न लेने लगे जाय। घनीकी व विचार न करने में सम्भव है कि कोई पक्ष अन्वविष्ट उन्निष्ठ हो जाय और विश्व शांति को खतरा उपस्थित हो जाय। 1962 में समुक्त राष्ट्र महा सभा में बोले हुए मेकिन्हा

7. मान-घनीकीनिष्ठ की व्याप्ति एवं स्वरूप की कोसिन लोपम ने इस प्रकार विवेचना की है : "Pan-Africanism has produced a language of its own which conditions the thinking and the politics of the entire continent. Emotion have been converted into ideas and ideas into slogans" by Colin Legum :

Pan Africanism' (Page & 111)

8. The weak and divided can never hope to maintain a dignified independence. We know that a black-rised Africa, even if gets independence, will in fact be an easy try to the forces of neo-colonialism"

Nyerere speaking in the Conference of African

States, 1961

पंचायती राज-एक आलोचनात्मक अध्ययन

(PANCHAYATI RAJ-A CRITICAL APPRAISAL)

—कमला बल्लभ शर्मा

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में लोक-प्रशासन केवल कुछ विशेष कारणों तक ही सीमित था—जैसे कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखना, कर (Tax) वसूल करना अथवा कुछ सामाजिक सेवायें प्रदान करना। द्वितीय महायुद्ध के समय से भी भारत का लोकप्रशासन पुलिस व्यवस्था तक ही रहा। दूसरे शब्दों में यह कहना व्यापक होगा कि संघीय राज ने भारत में प्रशासन के क्षेत्र में केवल वह व्यवस्था स्थापित की जो कि न्यूनतम सरकार (Minimum Government) एवं उन्मुक्त नागरिक जीवन के लिए ही पर्याप्त थी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् परिस्थितियाँ बदलने लगी तथा भारत में अब तक कभी था नहीं साधारण धर्म-व्यवस्था का विस्तृत होना प्रारम्भ हुआ। इस अवसर पर संघीय सरकार ने भारतीय समाज की नवीन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक बनने लगी। इस दिशा में कोई विशेष प्रगति न हो सकी। महायुद्ध के समाप्त होने से ही भारत में स्वतन्त्रता की लहर व्याप्त हो गई और १५ अगस्त १९४७ की दिमाज के साथ सत्ता का स्थानांतरण हुआ।

स्वतन्त्र भारत के नवीन संविधान ने भारत में स्वतन्त्रता, समानता, धार्मिक एवं न्याय जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सम्मिलित था, को प्राप्त करने के दृष्टिकोण का उद्घोष किया। यही नही संविधान ने भारतवर्ष में लोक-हितकारी राज्य की स्थापना के निश्चय में भी विश्वास व्यक्त किया। परन्तु प्रश्न यह था कि समाज में इन नवीन परिवर्तनों के प्रति उत्साह किस प्रकार जगाया जाय जिससे कि ये योजनायें सफल हो सकें। अतः जनता में चेतना जागृत करने के लिए सरकार ने सामुदायिक विकास योजना (Community Development Programme) के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारम्भ किया। अतः तो यह भी गई थी कि भविष्य में जनता इन

विकास योजनाओं में सक्रिय भाग लेकर सामाजिक कल्याण में सरकार का हाथ बंटा सकेगी। सामुदायिक विकास योजना के द्वारा देश में और विशेषकर गावों में नवीन प्रशासकीय ढांचे को सटा किया गया जिससे ग्रामीण जनता का बहुमुखी विकास सम्भव हो सके। इस प्रशासकीय ढांचे में खण्डों (Blocks) की स्थापना की गई और इनकी देख-रेख के लिए विकास अधिकारियों की नियुक्ति हुई।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कार्यक्रम ने जनता में सुधार की एक मांग पैदा की एवं वर्तमान दशाओं के प्रति तीव्र असन्तोष की भावना को जन्म दिया। किन्तु फिर भी ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए बनाई गई ये संस्थाएँ, इस जनता का कार्यक्रम बनाने में असमर्थ सिद्ध हुईं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जन सहयोग के द्वारा गावों का सामाजिक एवं प्राथमिक विकास करना था। सरकार का कार्य तो केवल सलाह देने एवं मार्ग दर्शन एवं ही सीमित था किन्तु ग्रामीण जनता ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हाथ नहीं बंटाया। अतः यह योजना जन जीवन की परिधि के बाहर ही रही। गांव वर्यों के सामुदायिक विकास सम्बंधी कार्यक्रम ने यह सिद्ध किया कि जहाँ न वही ऐसी त्रुटि अवश्य है, जिसे दूर करने के लिए धातुल-वृत्त परिवर्तन करना अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए गुजरात के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री वल्लभभाय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। इस समिति ने अपनी निवारिधियों में लोकतान्त्रिक विवेन्द्रीकरण (Democratic Decentralisation) की जो रूपरेखा रखी, उसने ग्राम्य प्रशासन में एक नये अध्याय का सूत्रपात किया है।

लोकतान्त्रिक विवेन्द्रीकरण का विचार

अतः १९५८ में वल्लभभाय मेहता समिति की रिपोर्ट के पुनस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में लोकतान्त्रिक विवेन्द्रीकरण की दिशा में इस विचार के कारण बहस उठाये गए कि विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति में सभी लोग हाथ बंटा देंगे, जब कार्यक्रमों के निर्धारण में उनका हाथ होगा। सामुदायिक विकास के प्रति जनभाषारण का निरालाहृ ही मेहता समिति के गठन का कारण था। दूसरे पक्षों में, १९५५ में ग्राम्य क्षेत्रों में प्रारम्भ किये गए विकास कार्यक्रम असफल रहे थे और इसका कारण यह मानकर कहा गया कि उनमें जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था। मेहता समिति ने इस दावा को दूर करने के लिए एक उपाय निश्चय और वह यह कि जनता स्वयं अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और बाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएँ तैयार करे और उन पर सरकारी मंजूरी मिल जाने के पश्चात् सरकार द्वारा वित्तिय और तकनीकी सहायता प्राप्त कर अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन योजनाओं को क्रियान्वित करे। एक ऐसा कार्यक्रम, जो जनता के दिन प्रतिदिन के

जीवन से घनिष्ठता से सम्बन्धित हो, और जिसका विधानत्रय भी जनता द्वारा हो किया जाय।

एतद् है कि पंचायती राज (Panchayati Raj) या प्रजातान्त्रिक विभेदशीकरण की एक विभागात्मक व्यवस्था द्वारा देश के ग्राम्य जीवन का एक नई चेतना मीचने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे कि राष्ट्रीय जनतन्त्र का आधार व्यापक और सुदृढ़ बन सके। पंचायती राज का प्राथमिक उद्देश्य प्रारम्भ है। लेकर प्रकृत तब विकास योजनाओं से जन साधारण को सम्बद्ध करना है। २६ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान के रूप में, देश के करोड़ों नागरिकों को अपना सामन बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का धर्म मिला था किन्तु लोकतान्त्रिक विभेदशीकरण की इस योजना के उद्घाटन में देश के करोड़ों निवासियों को अपने इलाके के विकास कार्यों में सीधे भाग लेने तथा अपना भविष्य स्वयं अपने हाथों से संभालने के भी व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। निस्संदेह हो यह एक ऐसी घटना है जिसका महत्व हम वर्तमान में पाते उसका प्रभावपूर्ण न सगे किन्तु गहरे विश्र में लोकतन्त्र का सारी स्वतन्त्र निर्धारित करने में इसका प्रभाव अवश्य रहेगा।

हममें सन्देह नहीं कि जब तक जनता को स्वयं धरने विकास की पूरी जिम्मेदारी न सौंपी जाय, सब तक वास्तविक प्रगति साक्षात् दुर्गम के समान है और न ही जातन्त्र की नींव की ही सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। विकास सभी सम्भव होगा जब कार्यरतों को जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डाली जाय और विकास के लिए कार्यक्रमों को पूर्ण रूपेण जनसाधारण का बनाया जाय। लेकिन बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या यह साजसजमान नहीं है कि विकास कार्यक्रमों की प्रयत्नता के मूल में एक भाव जनता के सहयोग की ही जमीन रही ? सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि लोकतन्त्र के दम के कारण तथा परिवर्तन के बाद कमरे में बनी योजनाओं के कारण विकास कार्यों में सहयोग नहीं मिल सका है और जनता के असफल रही है लेकिन अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डालने की मंशा के कारण हम सम्भावना को उभारे अज्ञानपूर्ण कर नजरअंदाज कर दिया कि योजनाओं धरने प्राप्त में भी गलत हो सकती है। किन्तु यह भी नहीं है कि उनमें से उत्तम योजना भी सफल नहीं हो सकती, यदि उसे जनसहयोग प्रदान न किया जाय और जनता का सहयोग भी उसे सभी प्राप्त हो सकता है जब कार्यक्रमों के निर्धारण एवं उनकी क्रियान्विति में जनता का हाथ हो। मन्त्रिय सरकार में सीधे भाग लेने की इस प्रक्रिया को ही पंचायती राज की मंशा दी गई है।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था

इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी अथर्वतन्त्र में बहुत ग्रामपंचायत बन ने हम बात पर बन दिया कि गाँव, ब्लॉक (Block) और जिले के स्तर पर सुसंगठित एवं निर्धारित प्रजातान्त्रिक संस्थाएँ (Democratic institutions) होनी चाहिए जिनके

द्वारा योजनाया तथा विकास के कार्यक्रमों को बतिसीन बनाया जा सके। लगभग सभी राज्यों ने (३१ मार्च सन् १९६२ तक) सिवा केरल और पश्चिम बंगाल के) इस पंचायती राज योजना को अपना लिया है। सन् १९६२ की इस तिथि तक देश के ५,३३,००० गांव और लगभग ६५% ग्रामीण जनता इस नवीन योजना के अन्तर्गत आ गई है जो निश्चय ही उत्साह वर्द्धक है।^१

मेहता रिपोर्ट में जो कतिपय सिफारिशें की गई हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी सिफारिश तीन स्तरीय योजना (Three tier system) की है जिसके अनुसार ग्राम स्तर, खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर निर्वाचित और संगठित प्रजासाम्यिक न्यायाधीशों की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। जिस तरह भारत में शक्ति एक स्थान अर्थात् केन्द्र में एकत्रित न रहकर विभिन्न राज्यों में बांट दी गई है उसी प्रकार शेष प्रांतीय शक्ति का भी भाग जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तर पर वितरित किया गया है जिससे जनता स्वयं अपना भला बुरा पहचान सके। समिति का मत था कि सरकार को अब अपने आपको कुछ बर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से असल हो जाना चाहिए एवं इसे उन संस्थानों को सौंप देना चाहिए जो कि विकास के कार्यों में संलग्न हों। इस तरह सरकार को केवल बड़ी-बड़ी योजनाओं मात्र तक ही अपने ध्यान को सीमित करना चाहिए।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम जिला स्तर पर एक जिला परिषद् होगी जो पुण्ड्र डिस्ट्रिक्ट बोर्डों (District Boards) का स्थान ले लेगी। इनका कार्य पंचायत समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना, उनके कार्यों को देख-रेख करना तथा उनके उपर नियन्त्रण रखना होगा। प्रत्येक खण्ड में एक पंचायत समिति स्थापित की गई है जो अपने क्षेत्र के कार्य के लिए योजना बनायेगी और अपने निर्वाचण में पंचायतों द्वारा उसे कार्यान्वित करवायेगी। पंचायत का मुख्य कार्य पंचायत समिति द्वारा निर्धारित नीतिको कार्यरूप में परिणित करना होगा। पंचायतों तथा पंचायत समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं को जितनी योजनाओं के साथ सम्बन्धित किया जायगा और बाद में ये योजनाएँ राज्य की

१. पंचायतों और उनके द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले गांवों के कुछ प्रांश इस प्रकार हैं—“The average number of villages per Panchayat varies from 22 in the case of Himachal Pradesh to 14 in the case of Madras Orissa has 20 villages on an average under a Panchayat. The average population of a Panchayat also varies from 755 in U. P. to 11,996 in Kerala. The average for the country as a whole is 2.6 Villages Per Panchayat with a population of about 1400.”

योजना का पंग बनैगी। इस प्रकार पंचायती राज की स्थापना द्वारा सच्चे ढंग से ग्राम स्वराज्य की ओर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है।

एक गाँव को या कई गाँवों को मिलाकर जो ग्राम पंचायत बनाई जायगी उसमें ८ या १० निर्वाचित सदस्य होंगे और एक प्रधान होगा जो सरपंच कहलायेगा। यह सरपंच ही गाँव का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी होगा। ग्राम पंचायत में सरपंच खण्ड स्तर पर पंचायत समिति बनाई गई है। पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों के सरपंच और कुछ विशेष हितों, जैसे खेती, हरिजन, आदिवासियों और स्त्रियों के विशेष प्रतिनिधि होंगे। इन विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को नामांकन करने का अधिकार पंचायत समिति के सदस्यों को होगा। विधान सभा के सदस्य पंचायत समिति के सहकारी सदस्य रहेंगे। इनके बाद जिला परिषद् में जिले की सब पंचायत समितियों के प्रधान, उन क्षेत्र विशेष के संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य, कुछ विशेष हितों जैसे हरिजनों, आदिवासियों, स्त्रियों और सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। जहाँ तक इन लोकतंत्रीय संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का प्रश्न है, ग्रामों के सम्बन्ध में योजनाएँ बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की मूल डग्राई ग्राम पंचायत होगी। पंचायत समिति या ग्राम संस्थाओं के कार्यों की देखभाल करेगी। इनके कार्यक्षेत्र में खेती के विषय सम्बन्धी सभी कार्य, मजदूरी, भूमि का उच्चार, मिर्बाई, पशुपालन, जनशक्ति का उपयोग, गाँवों की सफाई और स्वास्थ्य, मंदार व्यवस्था, उद्योग, आकरे एकत्रित करना, जंगलान एवं पानाम आदि की उन्नति के सभी विषय आ जाते हैं। यह आवश्यक है कि पंचायतों के द्वारा बनाई गई योजनाएँ, प्रांतीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के ढाँचे में बैठ सकें। जिला परिषद् को अधिकार होगा कि वह पंचायत समितियों के बजट का निरीक्षण करे। राज्य सरकार द्वारा जिसे वे लिए दिये गये अनुदान की उनमें बाँटे, उनमें कार्यक्रमों का निरीक्षण करे और उनमें समग्र स्थापित करे। लोकतन्त्रात्मकता के इस विशेषीकरण की योजना का मूल उद्देश्य यह है कि सब तरफ से ग्राम राज्य सरकार करती रही है उसमें जनता और उसके जिला एवं राज्य स्तर की प्रतिनिधि संस्थाएँ भी भाग लें और साथ ही विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले लोगों में अधिक से अधिक शिक्षा का भाव जागृत किया जाय।

संज्ञान्तिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण

पंचायती राज की संरचना (Concept) के अध्ययन एवं निर्माण के लिए दो मार्ग संभव दृष्टिकोण (Approaches) हो सकते हैं। प्रथम तो Normative मार्ग जहाँ एक पक्षाने एक स्वीकृत प्रकार की संरचना समझा जाय तथा द्वितीय Empirical मार्ग जहाँ हम वैज्ञानिक विज्ञान पर ही नहीं, बल्कि प्रयोगों (Experiment) पर

निर्भर रहे। एक स्वीकृत पैमाने एवं मापन को लेकर बने वाला राजनीतिक सिद्धान्त-वादी प्रणाली ही वापसा एवं आवाजाओं के अनुसार पंचायती राज के नमूने का निर्माण करेगा। किन्तु दूसरे ओर परीक्षण एवं प्रयोग पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति (Empirical) पंचायती राज की अवधारणा का अध्ययन उसके कार्यक्षेत्र में करेगा। उसका प्रयोग सदैव आदर्श एवं व्यवहार के बीच की दूरी को नापने का होगा। इसके साथ ही, वह उन प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डालेगा जो व्यवहार में पंचायती राज की अवधारणा को प्रभावित करती हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण पंचायती राज की वास्तविकता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं किन्तु इन्हें एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक मानना ही न्यायोचित होगा।

इस विषय पर प्रतिपादित किये गए दृष्टिकोणों में एक मुख्य दृष्टिकोण सर्वोदयी दृष्टिकोण है,¹ जिसे अधिक दृष्टे दृग् से श्री जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण कहकर परिभाषित किया जा सकता है। इस विचारधारा का जन्म सर्वप्रथम गांधीवादी विचारों में हुआ, जिसे द्वितीयांश भाषे के द्वारा एक नवीन समर्थन प्राप्त हुआ, किन्तु अब इस विचारधारा के सबसे मंगत एवं व्यवस्थित प्रवक्ता श्री जयप्रकाश नारायण हैं। इस विचारधारा का जन्म मसदीय सरकार की शासकीयता में हुआ है जो श्री नारायण के अनुसार भारत के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। श्री नारायण ने जिसमान मसदीय शासकीय के विकल्प (Alternative) के रूप में जिस समुदायवादी जनतन्त्र (Communitarian Democracy) का सुझाव दिया है वह केवल स्थानीय सरकार का भाव ही नहीं है बल्कि इसमें कुछ अधिक है। यह सम्पूर्ण भारतीय संविधान के लिए एक रचना मसदीय आदर्श (Structural Model) है जो नीचे से ऊपर की ओर गतिशील है जब तक कि एक पिरामिड के रूप में नये संविधान का उदय नहीं हो जाता। पंचायत इस त्रिकोणात्मक शासकीय (Pyramidal Structure) का महत्वपूर्ण आधार है। केवल यही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसके प्रतिरिक्त पंचायत की ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो ग्रामीण व्यक्तियों की एक सार्वजनिक संस्था होगी। श्री नारायण ने जिस प्रकार के समुदायवादी जनतन्त्र पर जोर दिया है, उसे शासकीय अनुसार दल पद्धति आधार पर निर्मित होता है, जहाँ एक मत के सिद्धान्त पर जोर दिया जायेगा। अतः स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार ग्राम सभा के सार्वजनिक चरित्र पर महत्व दिया गया है। कुछ अन्य तथ्य जिन पर भी यहाँ बतल दिया गया है इस प्रकार हैं—भारतीय संविधान के सूचनाधार भाषे के आधार स्वयं पंचायत का महत्व, पंचायत के प्राथमिक एवं स्वायत्त चरित्र पर जोर, ग्राम सभा के प्रति पंचायत का

1. Narayan J. P.—A plea for the Reconstruction of Indian Polity.

उत्तरदायित्व एवं पंचायत के चुनावों का दलबन्दी और राजनीति से क्या सम्भव दूर रखना आदि। श्री जयप्रकाश नारायण की इन नीतियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सते होते हैं जो पंचायती राज की व्यवस्था में मूलभूत हैं। उदाहरण के लिए पंचायती राज योजना में ग्राम सभाओं को क्या स्थान दिया जाय, क्या पंचायत को पंचायती राज इकाई को आधारभूत इकाई समझा जा सकता है, तथा क्या पंचायती राज को दल रहित आधार पर संगठित होना चाहिये, इत्यादि। *

स्थानीय सरकार (Local Government) की विचारणा स्वभाविक रूप से, ग्रामीणों के द्वारा स्वयं ही अपने मामलों की व्यवस्था किये जाने पर जाद देती है। इसका अर्थ हो जाता है कि पंचायतों का अधिक से अधिक स्वायत्तता, विचार विमर्श करने की शक्ति, नीति निर्धारण एवं अपने ज़ियान्त्रयन की शक्ति एवं ग्राम के लोगों की देखभाल तथा नियन्त्रण की शक्ति प्रदान की जाय जिसका प्रयोग वे राज्य स्तर के कम से कम नियन्त्रण की सीमाओं में रह कर कर सकें। जहाँ पर भी पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्त प्रकृति के महत्व पर बल दिया गया है यद्यपि ऊपर से कम से कम नियन्त्रण की आवश्यकता को भी नहीं भुलाया गया है। इन दृष्टिकोण के समर्थक पंचायती राज संस्थाओं के कार्यात्मक सेवाधिकार (Functional) को केवल परम्परागत सार्वजनिक कार्यों तक ही सीमित रखना नहीं चाहेंगे। कुछ समर्थक तो राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) और यहाँ तक कि राज्य अर्थ में बजट एवं व्यवस्था का भार भी पंचायतों को ही सौंपना चाहेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण नौकरशाही दृष्टिकोण * (Bureaucratic view point) कहा जा सकता है। इन दृष्टिकोण का आधार अपने मामलों की स्वयं व्यवस्था करने में अभिलिखित ग्रामीण जनता की योग्यता में विश्वास है। अतः यहाँ स्वाभाविक रूप से पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं प्रबंध करने के पहलू पर कम महत्व दिया जाता है। जहाँ तक इन संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का सम्बन्ध है, इन और दो छोर पकड़े जा सकते हैं—एक छोर अति को पहुँचा हुआ और दूसरा अतिशयित मध्य। अतिवादी (Extremist) पंचायती राज संस्थाओं को केवल एक संस्था के कार्य सौंपना समझ करेगे किन्तु संयतवादी इन संस्थाओं को कुछ शक्ति एवं उत्तरदायित्व सौंपे जाने — भी समर्थन करेंगे।

अन्तिम रूप में प्रसंगवादी एवं विकासवादी दृष्टिकोण (Contextual and Developmental view Point) के अनुसार पंचायती राज की प्राप्ति, प्रकृति एवं

1. Dey S. K. : Panchayati Raj— a Synthesis (Asia Publishing, 1961)

2. Mukerji B. : Community Development in India.

कार्य का निशाना होने हुए अनुभवों एवं घटनाओं के आधार पर किया जाना चाहिये। कुछ पूर्वगामी तथ्य भी दस्तवन्तराय भेदता द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। उनके अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता में अपने कार्यक्रमों की क्रिया-व्रति के लिए उ माह्र जनाने में अक्षयप मिद्ध हूमा है। प्रगर सामुदायिक विकास योजना के प्रतामन एवं ग्रामीण विकास याचनाओं को ग्रामीण स्तरों पर, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का मौप दिया जाय तो इन कमियों को दही मात्रा में दूर किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पंचायती राज अपने उद्देश्य एवं कार्यक्रमों में सामुदायिक विकास का विस्तार ही है। पंचायती राज संस्थाओं को विकास यंत्र (Development mechanism) के रूप में ही कार्य करना चाहिये, शक्ति को हथियाने के माधन के रूप में नहीं। पंचा और मरपंचों का प्रधान लक्ष्य जनता का मत प्राप्त करके केवल मात्र सत्ता को हथियाना ही नहीं होना चाहिये बल्कि उन्हें चाहिए कि वे अपने प्रमान उद्देश्य अर्थात् गावों के अनुमुखी विकास की दिशा में मरत प्रगमर रहें।

किन्तु एक दूसरे दृष्टिकोण में भी पंचायती राज की व्यवधारणा को देखा जा सकता है—वह है Empirical angle. यद्यपि यहा विश्लेषक की सोभाओं का भी दृष्टिगत रहना आवश्यक है। सर्वप्रथम दाव तो यह है कि पर्याप्त क्षेत्रीय अनुसंधानों (Field researches) के अभाव में सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पंचायती राज में अधिक क्षेत्रीय अनुसंधान नहीं किये जा सके हैं। इसके प्रतिरिक्त ये संस्थाएँ अभी शिशु अवस्था में ही हैं। बहुत थोड़े राज्यों में इन्हें कार्य करते हुए अभी ५ या ६ वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। कुछ अन्य राज्यों में तो इन्हें कार्य करने हुए और भी कम समय हुआ है पर फिर भी कुछ प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप में देखी जा सकती हैं। इस दृष्टि में हमारे सम्मुख पंचायती राज की तीन प्राकृतिया प्रकट होती हैं—राजनैतिक, सार्वजनिक एवं (Statutory) वैधिक। राजनैतिक प्राकृति हमारे जनरायी नेताओं द्वारा उनके भाषणों, वक्तव्यों एवं लेखों द्वारा राखी की जाती है। इसकी मुख्य विशेषता ग्रामीण जनता के द्वारा स्वयं ही अपने स्थानीय मामलों का प्रबन्ध है। पंचायती राज आवश्यक रूप से एक ग्रामीण स्थानीय सरकार का रूप ग्रहण कर लेती है। सार्वजनिक प्राकृति का निर्माण ग्रामीण जनता के द्वारा स्वयं ही किया जाता है। ग्रामीण जनता अधिकतरतः मरिजित एवं रुझित है इसमें सुन्देह नहीं, किन्तु फिर भी नये दातावरण से प्रभावित होकर वह अपनी आवश्यकताओं एवं माहाताओं के प्रति मरत दन रही है। अन्तिम रूप में पंचायती राज की एक वैधिक प्राकृति भी है जो आवश्यक रूप से नौकरवाही के द्वारा खडी की गई है। यहा पर अधिक जोर देना पर दिया जाता है, गक्ति पर नहीं। कर्तव्यों पर अधिक दन दिया जाता है अधिकारों पर नहीं।

पंचायती राज व्यवहार में

पंचायती राज मस्यौदे विवास करन के मन्त्र के रूप में इनकी विकसित नहीं हुई है जितनी शक्ति एवं सत्ता की हथियाने के मन्त्र के रूप में। वास्तव में इससे नये-नये नेताओं का विकास हुआ है। जो भी सरपंच बनवा पंच तीन चार बार अपने गाँव में चुन लिए जाते हैं व अपने आपकी सेवा समझने लगते हैं। वहीं बाद में जाकर सामान्य चुनावों व समय पाटिया का समर्थन पाकर अपने सदस्यों को जिताने में सहायता करते हैं। सरपंच और प्रधान की अपनी २ पंचायत और समिति में बड़ा दगा होती है जो कि एक मजि परिषद में प्रधान मन्त्री को। यह बराबर बात में प्रथम (First among equals) बन जाता है जो निश्चय ही पंचायती राज के विकास में नये हितकर है।

बैसे तो पंचायती राज भारतवर्ष में साम्य विचारों की जीवन शक्ति बनता जा रहा है।¹ धीरे धीरे अनेक नई जिम्मेदारियाँ उनसे कंधा पर डाली जा रही हैं किन्तु फिर भी ऐसी अनेक त्रुटियाँ हैं जिनके निराकरण व बिना किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करना संभव नहीं। अनिश्चित जनता, राजनीति के नेता की कमी, ग्रामीणों में निस्वार्थ सेवा भावना का अभाव, जानि एवं धर्म सम्बंधी अविश्वास, सामन्तो के प्रति अनादर एवं बफादारी, अलौकिक सामाजिक एवं पारिवारिक बंधन आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके हल पर ही पंचायती राज की सफलता और अन्त में प्रजातन्त्र का अविष्य निर्भर है। कुछ प्रतापकीय समस्याएँ भी प्रगति के मार्ग में रोड़े भरवाए हुए हैं। उदाहरण के लिए विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संस्था गमिनि हो या परिषद्। सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों का पारस्परिक सम्बन्ध भी प्रश्न सूचक बना हुआ है। जिला स्तरीय अधिकारियों से अनेकता की जाती है कि वे मित्र, दार्शनिक एवं सहायक के रूप में ग्रामवासियों के साथ कार्य करें किन्तु वास्तविकता यह है कि वे अधिकारीयण ग्रामवासियों का अपनी राय को देने का प्रयास करते हैं। जिना अधिकारियों का कार्य एक गिना की भाँति होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि वे ग्रामीणों में मनोविज्ञान की अनेक भाँति समझ सकें तो उन्हें नौकरगारी का बोस उठारना ही होगा जो उनके और ग्रामीणों के बीच गहरी खाई खाँदे हुए है। यह सही है कि यह मनोविज्ञान तान मल है जो समय के साथ साथ ही अनेक किन्तु फिर भी इन दिनों व युग बदल अवसर उठाए जा सकते हैं।

गाँवों में गुटबन्दी अपनी बरसता पर दिखाई देती है। पंचायतों में दो भागों में विभक्त हो गई हैं—प्रथम तो बहुमत से सम्बन्ध रखने वाला और द्वितीय व जो अल्प-

1 देखें "Study Team's Report on Panchayati Raj" (Rajasthan and Andhra) (Congress Party in Parliament) A. V. A. R. D. Report इत्यादि।

मन समूह के प्रत्यर्गत आती है। इसका स्पष्ट अर्थ हो जाता है कि लानों के वितरण में भेदभाव और दलबन्दी। उन बहुमत समूह का राजनीति के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जो एकाधिकारवादी स्वतंत्र एवं प्रवृत्ति का जन्म देता है। यह प्रवृत्ति जनता विरोधी एवं सामाजिक सुदृढ़ता का कमजोर बनाने का कारण है। अतः पंचायती राज से सम्बन्धित एक समस्या कुछ ऐसे नियंत्रण और सतुलन (Checks and Balances) का विकास करने की है जो इस प्रवृत्ति के प्रतिरोधक के रूप में कार्य कर सके। पंचायती राज मन्त्रालयों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी भी अर्थ में नीचे से योजना की प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं कि क्या नीचे से बनाई जाने वाली योजना हमारे केन्द्रीकृत राष्ट्रीय योजना की व्यवस्था के साथ किसी भी अर्थ में साथ चलने योग्य है? तथा नीचे से बनाई जाने वाली योजना की भारत गरीब विकासशील (Developing) देश में क्या कमजोरियाँ हैं एवं योजनाओं के निर्माण और क्रियान्विति में पंचायती राज मन्त्रालयों की किम भीमा तक सम्मिलित किया जाये।

अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन परिणाम

पंचायती राज के राजनीतिक परिणामों को दो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। प्रथम तो तात्कालिक, प्रत्यक्ष एवं सम्पत्तिलोचन परिणामों का अध्ययन हो सकता है तथा दूसरे उन प्रवृत्तियों तथा मुद्दों का अध्ययन हो सकता है जो ग्रामीण समुदाय के राजनीतिक जीवन पर अग्रगण्य एवं दीर्घकालीन प्रभाव डालती हैं। पिछले पांच वर्षों के अनुभव ने बताया है कि स्थानीय नेत्राधीन और पंचायती राजनीतिज्ञों ने मता की हासिल करने एवं एकाधिकार जमाने की प्रवृत्ति दिखाई है जिनका एक हिस्सा उन्हें पंचायती राज-व्यवस्था के प्रत्यर्गत प्रणत हो गया था। उन्होंने पंचायती राज मन्त्रालयों की विकास का मन बनाने के साथ-साथ सत्ता की हथियाने का माधन भी बना लिया है। ये नेत्रा अपने लिए महान का राजनीतिक स्थान ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि उन स्थान पर रहने से ही उन्हें शक्ति, शक्ति और सम्मान मिलता है। ये पंचायती नेत्रा प्रत्येक राज्य के ग्राम, ब्लॉक और जिले के स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान बन गए हैं। धीरे-धीरे इस Nucleus elite के बायों का क्षेत्र निम्न हो रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा विकास की मांग ने ग्रामीणों की उम्मीदों में योग दिया है जिसे कभी बड़ी हुई आशाओं की क्रांति (Revolution of Rising Expectations) कहा जाता है। यह तथ्य कि पंचायती संस्थाओं देश के जनतापरक के

लिए हैं एवं कल्याणकारी गतिविधियों को विपणन के दावा करनी हैं, आशाओं की उत्पत्ति करने के लिए पर्याप्त है। अगर यह सही भी जाय कि अज्ञान एवं परंपरागत मूल्य व्यवस्थाओं की कोई आशाएँ नहीं हैं किन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि 1959 के वर्ष की घटनाएँ एवं व्यक्तियों की आशाएँ एवं आकांक्षाएँ बर्दे हुनी पड़ी हैं। विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए राजनीतिक शक्ति को हार्मिज करने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। ऐसे अवसर भी देखे गए हैं जहाँ कुछ वर्ष पूर्व तक कोई भी व्यक्ति गूँगे कूँगे और घुस निँ अरो हुई पगडरिया के विषय में चिंतन नहीं करता था किन्तु जैसे ही पंचायत में कुछ करने का निश्चय किया, वे राजनीतिक बाध विवाद के विषय बन गए। पंचायती राज पर हानि के हुए अध्ययनों में कहा गया है कि राजनीतिक समस्या पर विवाद करके या निर्णय देते समय जो एक सामान्य प्रवृत्ति देखी गई है वह है शक्ति एवं अधिकारों की, वर्तमानों एवं उत्तरदायित्वों की अधिक महत्त्व देना।¹ किन्तु गांधी जी यह भी स्वीकार किया गया है कि जनता को अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के विषय में नई जानकारी मिली है। आज ग्रामस्थानी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और यह हम बात का प्रतीक है कि पंचायती राज ने नई-नई मांगों की जन्म देकर गाँवों में राजनीति का प्रवेश कराया है। आज ग्रामस्थानी उस कार्य का करने की तैयार नहीं हैं जिसे वे सहिष्णुता से करने चले आ रहे थे।² आमतौर पर जब भी पंचायतों में पंचायत समितियों के हाथ में विनाश कार्यों को शिथिल करने की शक्ति आई है गाँवों का बहुत कुछ कायापनट हो पाया है।³ पंचायती राज के माध्यम से जहाँ ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागृति आई है वहाँ उनमें आत्मविश्वास की भावना भी जागृत हुई है और अपनी स्थिति सुधारने के लिए सक्षम बनें न केवल कुछ बर सुझने की प्रवृत्ति भी उनमें पनपी है।⁴

राजनीतिक चेतना का विकास

पंचायती राज के पञ्चस्वरूप राजनीतिक चेतना की गति बर्दे हुनी अधिक बढ़ गई है। यह कथन जहाँ ग्रामीण जनता की राजनीतिक जागृति के विषय में सही है वहाँ वह सामाजिक नेतृता के विषय में भी सत्यता सही उतरता है। दूरवाट्ट और भेदभाव की दीवारों की पंचायती राज ने अटिभ धक्का दकर भूमिधस्ता किया है। बड़ी-बड़ी सी ऐसा देना गया है कि आज तक मजदूर और मीकर कहा जाने वाला व्यक्ति पंचायत प्रणाली पंचायत समिति की अध्यक्षता करता है। यह सामाजिक स्थिति नि गदेह महान है और

1 See Report of the Study Team on Panchayati Raj (1964) popularly known as Sadiq Ali Committee Report

2 Ibid.

3 Ibid.

केवल कानूनों के द्वारा यह संभव नहीं है। पंचायती राज मंत्र्याओं ने राजनीतिक चेतना का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन प्रतिनिधि मुद्रा कर (Tax) लगाने से हिचकिचाते रहे हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष कर से प्रतिनिधियों की लोक-प्रियता को धक्का लगता है। किन्तु पंचायत और पंचायत समितियों के सदस्यों ने इस प्रोर अपनी कर्तव्यनिष्ठा की ओर अधिक और ऐसी आशंकाओं की ओर कम ध्यान दिया है। अनेक पंचायतों ने अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि करने के लिए कर लगाये हैं एवं अपने साधनों में वृद्धि की है।

सारिकप्रली दल का मत

यह मनी मानि जानने हुए कि प्रधान और प्रमुख माने वाले सामान्य चुनावों में राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण रोल भूषा करेंगे, राज्य के नेता इनके व्यक्तिगत संदर्भ स्थापित करने में प्रयत्नशील हैं। यह माना जा सकता है कि ग्रामीण लोग आज अपनी ग्रामीण राजनीति के मसलों में अधिक रुचि लेते हैं चाहे वे हमसे अधिक अच्छी तरह परिचित न हों। सारिकप्रली प्रध्ययन दल (Sadiq Ali Study Team) ने राजस्थान में पंचायतों के कार्य-संचालन का अध्ययन करके कहा है कि गांव में व्यक्ति आज गिबरन रूप में अपने उद्योग के लिए अधिक जागरूक और चेतनाशील है। पंचायती राज ने जनता को सामाजिक सेवा का एक नया अवसर प्रदान किया है। इसके साथ ही जनता के मन में सरकारी अधिकारियों का डर समाप्त होने लगा है। जनता आपस में विकास प्रविष्टि (B. D. O) के पास जाकर अपनी समस्याओं को सुनवाती है। साबजन जो चुनाव होते हैं उनमें जनता काफी परिमाण में भाग लेती है। वह अब अपना वोट डालने जाती है तो नावती, गाती, उड़ती, कूदती दिखाई देती है। चुनाव उनके सामूहिक जीवन का एक अंग बन गए हैं। अपनी हानि में पंचायत के पंचायती चुनावों में एक ८९ वर्षीया अल्पवय वृद्धा अपना वोट डालने आई। किन्तु इस सब का एक अग्रकारण यह भी है जो निपचा-जतक है। पंचायती राज में राजनीति के प्रवेश कर देने में पंचायत समितियों और पंचायतों के बीच विरोधी भावनाओं और झगड़ों ने घर करना शुरू कर दिया है। प्राये दिन चुनाव नन्दियों मामलों को लेकर गाती-गाती, छुटकाती, मारपीट और कभी-कभी राजनीतिक कारणों से हत्या तक भी कर दी जाती है। इसके प्रतिरूप पाठशालाओं को पंचायतों के प्रशिक्षण कर दिया गया है जिसने जिसमें राजनीति प्रविष्टि हो गई है और आसपास उसा सामाजिक शिक्षा का स्तर और भी तेजी से गिरने लगा है।

सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध

एक सामान्य राजनीतिक घटना के रूप में यह देखा गया है कि शक्ति एवं

विकास के यन्त्र के रूप में पंचायती राज ने सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों के पारस्परिक सम्बन्धों को विट्ठेयपूर्ण बना दिया है। गैर सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी सरकार ने नाम पर सत्ता हथियाने का प्रयास करने हैं तथा सरकारी कर्मचारी कार्यक्षमता एवं प्रभावशाली विकास के लिए जनता पर प्रचण्ड प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। अपरिपक्व एवं कुशल के मध्य पाया जाने वाला यह असंतुलन विकासशील समाजों को जनताधिक राजनीति का एक सामान्य लक्षण है किन्तु पंचायती राज में यह असंतुलन दूर होना नजर आता है।

भूत और भविष्य

प्रश्न जो स्वाभाविक रूप में उठता है यह है कि साम्प्रदायिक विवेकीकरण लागू करने के पूर्व या म्यिगि धी समय क्या कोई उन्मूलनीय परिवर्तन हो सता है ? क्या मौलिक विधान बरोहो रूपों में धर्म के बावजूद पूर्वादिशा अधिक सुग्राह्य बन सता है ? यदि सच्चाई और ईमानदारी से इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढ जाय तो वे सकारात्मक हो मिलेंगे। सामान्यतः ग्राम एकाद उपज में गिरावट आई है और साधनहीन वास्तविकता की आर्थिक स्थिति में कोई उन्मूलनीय सुधार नहीं हुआ है। वास्तविकता की वास्तविकता के लिए आवश्यक सामग्री का अभाव है। मिचवाई की उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध करवाना तो दूर अन्य जिनो में सभी तक वेद जय का भी अभाव है। सुधरे हुए भोज, उर्वरक और लाद तथा मशीनें केवल साधन संपन्न वास्तविकता की ही सुलभ हैं। यदि विमान की बैलों की जोड़ी, भोज और मिचवाई के लिए जन उपलब्ध करवाया जा सके तो यह मेहनत करने में सभी प्रकार नहीं करेगा। सभी तक मान्यता पर हथि की आधुनिक रचना सरकार की निष्क्रियता और भीमो नीति का परिणाम है। ग्राम्य उद्योगों की स्थिति भी हथि से कोई बेहतर नहीं है। सर्वश्रेष्ठ के बावजूद सभी तक हथि पर साधारण उद्योगों की योजनाबद्ध ढंग में चलाने के लिए कोई टोन प्रयत्न नहीं लिए जा सके हैं। ग्राम विद्युतीकरण की योजनाओं सभी तक पूरी नहीं की जा सकी हैं। राज्य सरकार के सांसाध्यकारिक विकास कार्यक्रमों का विस्तार में उन्मूल करने पर स्पष्ट होता है कि जन साधारण का सहयोग न मिलने का आरोप निराधार है। पंचायती राज में हम मूल-भूत स्थिति में जिनो जादूई परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। तथा यह है कि ग्राम समाजों ने अपनी जो आवश्यकताएँ बताई उन्हें भी ठीक ढंग में योजना में स्थान नहीं दिया जा गया और स्थानीय साधन बढ़ाने के लिए साम्प्रदायिक विवेकीकरण संस्थाओं से गरीब जन साधारण पर अनाप-दानाप कर साग्र करने के लिए उन पर प्रादुर्भाव डाला गया। कच्चा समस्तुत करवाता में योजना की क्रियात्मकता में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

मेहना समिति की मितारियों का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरशाही (Bureaucracy) के प्रभाव को खत्म करना या साकि जन साधारण अपनी योजनाओं स्वयं बनाये

और उन्हें क्रियान्वित करे। लेकिन फिर भी यह सत्य है कि शनैः शनैः लोकतांत्रिक विवेकशक्ति संस्थाओं स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित होने लगी हैं। प्रायः शक्यता इन बातों की है कि पूरी सच्चाई के साथ संविधान की ४०वीं धारा में दिए गए निर्देशक के अनुरूप सही ढंग से ग्राम पंचायतों को आवश्यक अधिकार दिए जायें ताकि वे स्वशासित इकाइयों की तरह काम कर सकें। विकास कार्यों को तीव्र गति देने में ग्रामीणों की उदात्तता एकदम गलत दलील है क्योंकि ग्रामीणों तक योजनाओं को दाना और उन्हें क्रियान्वित करने में बौकराही ही १९५६ के पूर्व बाधक था और आज भी बाधक सिद्ध हो रही है।

इसमें मन्देह नहीं कि पंचायती राज का सद्यः गावों की दशा का सुधार करना, उनमें राजनीतिक और आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। गाव बानों की प्रसीम शक्ति का लाभ उठाने और उनमें नेतृत्व समता पैदा करने के लिए यह एक अच्छा संगठनात्मक सुधार है। इसमें न केवल भारत में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं बल्कि समान सामुदायिक विश्वास आन्दोलन जगत् के प्रतिनिधियों के हाथ में आया है। पंचायती राज का महत्व अभी समझा जा सकता है जब कि हम यह नतीजा प्राप्त जान लें कि गाव ही समस्त राष्ट्र की उत्थिति के नियामक हैं। पंचायती राज योजना की इन सकलताओं के बीच भाँकने हुए कुछ सतरे भी यद्यपि सामने आये हैं किन्तु फिर भी हमें प्राणावधि के माप भारत में लोकतन्त्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना करनी चाहिए।

भारत का प्रशासनिक ढांचा और इतिहास का प्रभाव

भारत में मन्त्रालय और प्रशासन का ढांचा दूसरे देशों से भिन्न, अपने ही प्रकार का है। यह अपने नये इतिहास और मन्त्रालय मन्त्रिणी से जनमा है। किसी सरकार को कोई व्यवस्था उपाय की तब तक चलने शुरू करने देना में बाध नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ, अमेरिका के लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रशासन है वह आयरलैंड का न भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशासन नहीं हो सकता। किसी अन्य व्यवस्था में प्रेरणा अवश्य ली जा सकती है। उस दृष्टि में यदि देखें तो भारतीय व्यवस्था पर ब्रिटिश मन्त्रालय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और भारतीय मन्त्रालय और प्रशासन का ढांचा बहुत कुछ ब्रिटिश व अनुकूल है यद्यपि इसे पूर्णतः ब्रिटिश के समान भी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि ब्रिटिश की भांति मन्त्रालय प्रणाली है परन्तु भारत की भांति नहीं है।

प्रशासकीय संगठन

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भारत सरकार का प्रशासकीय ढांचा अनेक मन्त्रालयों (Ministeries) में बँटा हुआ है। मन्त्रालय या विभाग का एक राजनीतिक प्रमुख होता है प्रमुख प्रत्येक विभाग एक मंत्री के अधीन होता है। वही विभाग की मुख्य नीति का निर्धारण करता है और उस विभाग के कार्य के लिए समस्त के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रियों की सहायता एक सचिव द्वारा की जाती है, जिसके नियन्त्रण में केन्द्रीय सचिवालय (Central Secretariat) का एक भाग होता है। सचिव (Secretary) विभाग का प्रशासकीय प्रमुख (Administrative Head) होता है और मन्त्रालय की परिधि के सम्बन्ध में सभी नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी सभी मामलों में मंत्री का प्रधान सलाहकार (Adviser) होता है। सचिव को किसी भी समस्या में सम्बन्धित तथ्य और धारणाओं के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। उसे यदि आवश्यकता हो तो मंत्री का सूचना, सलाह और चेतावनी भी देनी होती है। मंत्रियों द्वारा लिये जाने वाले नीति सम्बन्धी निर्णयों पर सचिव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। काम की प्रविष्टता के कारण, सचिव की सहायता के लिए संयुक्त सचिव (Joint Secretary), उपासचिव (Deputy Secretary), अधर सचिव (Under Secretary) तथा सभी सभी अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) भी होते हैं। सचिवालय के ये उच्च पद भारतीय प्रशासन सेवा (I A S) तथा प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवा (Central Services Class I) के सदस्यों में भरे जाते हैं। सचिवालय पुनर्गठन पर प्रस्तुत की गई रीडर रिपोर्ट (Wheeler Report) के अनुसार भारत सरकार के सचिवालय में स्टाफ की पूर्ति सीधी नहीं करते नही, बल्कि प्रथम (प्रथम श्रेणी) में पहले से ही काम कर रही अधिकारियों द्वारा की जाती चाहिये और दूसरे केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले और प्रथम (प्रथम श्रेणी) में काम करने वाले पदाधिकारियों को पदाधिकारी में नियमित बदलाव देनी चाहिये।" अतः यह प्रथम का सम्बन्ध है,

होती ही व्यवस्था है। उच्च मन्त्रिवाय अधिकारी राज्यों में बीम में पचोप वर्ष तथा प्रांतीय अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिये मन्त्रिवाय में प्राप्ति है।

कुछ समस्याएँ

अब हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे।

प्रत्यावधि (Short Tenure)

भारतीय प्रशासन अधिकारी भर्ती के पश्चात् राज्यों में नियुक्त कर दिये जाते हैं और फिर प्रशासकीय अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् मन्त्रिवाय में महत्वपूर्ण पदों को सम्भालते हैं। परन्तु प्रत्यावधि और केन्द्रीय मन्त्रियों की राज्यों में कार्यवाही के कारण केन्द्रीय मन्त्रिवाय अनुभव तथा दीर्घावधि की परम्परा न बचिती हो जाता है। अतः मन्त्रिवाय के कार्यभार को प्रबंधित तीन वर्ष में अधिक होनी चाहिये।

कार्य-मुनिश्चितता का अभाव

प्रशासन एक मशीन के सदृश है। यदि इसके सब भाग कुशलता (Efficiency) में कार्य करते हैं तो मशीन भी कुशलता से चलती है। इस मशीन के भाग व्यक्ति होने के कारण, परस्पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नफरत और झगड़ाचार को जन्म दे सकते हैं। अतः प्रशासन की मजबूती इस बात पर निर्भर है कि हर भाग के कार्य और कर्तव्य मुनिश्चित किये जायें और हर भाग अपने इन कर्तव्यों को कुशलता से पूरा करे। इनमें से प्रथम के न होने का अर्थ है संगठन की क्षमकता और दूसरे के न होने का अर्थ है पदवि या व्यक्तिगत तत्व (Personnel) की क्षमकता। दोनों ही स्थितियों का परिणाम है अनुकुशलता, अर्थात् प्रशासन के काम निम्नतर शक्ति न होना अथवा देरी में होना तथा भ्रष्टता।¹

इकाइयों में गलत संबंध

दा इकाइयों में गलत संबंध या एका इकाई में गलत कार्य प्रणाली भी अनुकुशलता को जन्म देती है। दोनों ही स्थितियों के अन्तर्गत उदाहरण दिये जा सकते हैं। एक इकाई द्वारा दूसरी पर प्रतिस्पर्धा के उदाहरण मन्त्रिवाय, कार्यपालिका विभाग, विधानमंडल, यश और मन्त्रि आदि के सम्बन्धों में देखे जा सकते हैं। इकाई के अन्तर्गत गलत कार्य होने के परिणामस्वरूप भी इकाई और सम्बन्धी दलों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं।²

प्रभावशाली हस्तक्षेप

विनाशप्रथम या गलत नीति के निष्पादन (Execution) में होता है, उसके निर्माण में नहीं। परन्तु गलत न मन्त्रिवाय और विनाशप्रथम के बीच टीका-संख्या का

1. A D Gopal's Report on Public Administration

2. Ibid

विकास नहीं हुआ है। "सबसे अधिक दोष का एक उदाहरण, जिसमें प्रशासन की योजनाएँ योजना के कार्यों का अनिवार्य करती हैं उन मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि मन्त्रिपरिषद् अथवा मन्त्रालय और उसके अन्तर्गत काम करने वाले विभागों के कार्य जाते हैं। दोनों के ही कार्यों की सीमाएँ स्पष्ट हैं—मन्त्रालय नीति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है और विभाग उस नीति के कार्यान्वयन (Implementation) के लिये परन्तु मन्त्रालय विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य को देखने के लिये उत्तरदायी रहता है कि यह निरन्तर उसके कार्यों में हस्तक्षेप करता है। परम्परागत विभागों के समस्त प्रेरणा समाप्त हो जाती है और अपने कार्य में व्यस्त रहने और उसमें काम करने के बजाय उसे अपना बाकी समय मन्त्रालय के प्रतिवेदन (Reports) प्रस्तुत करने में व्यस्त रहता रहता है। ऐसे मामलों पर उसे मन्त्रालय से आज्ञा मिलती होती है स्पष्टतः उसके अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। विभागों के काम को मन्त्रालय द्वारा किये जाने के प्रयत्न के परिणाम निश्चित रूप से अनुपपन्न और असफल के रूप में माने जाते हैं। काम में देरी होती है। काम अच्छी तरह नहीं हो पाता और जो काम मिलता है तो ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होता जिस जिम्मेदार ठहराया जा सके।"

विभागों के सम्मिश्रण

एक अन्य समस्या है विभिन्न विभागों का सम्मिश्रण। उदाहरणार्थ—(Revenue) और न्यायिक कार्य (Judicial) कार्यों का मिश्रण भारतीय प्रशासन की एक हानिकारक परम्परा है। "पूर्वम विभाग की गरीबी और एकीकरण करने की आवश्यकता है। इतिहासिक अधिकारियों को सादरता पूर्वक एकत्र करने के लिये तथा अभिन्न काम मन्त्रालय को कहा जाता है विनयन स्थानीय बोर्डों में।"

वित्तमन्त्रालय से सम्बन्ध

एक अन्य महत्वपूर्ण गणना यह होगी जिसमें प्रशासन में वित्तीयता की बढ़ावा है, यह है प्रशासनिक मंत्रियों और वित्त मन्त्रालय से संबंध। केन्द्र में वित्त मन्त्रालय के कार्यों और मन्त्रालय की स्पष्टता के अभाव की सिद्धांत प्रायः सुनने में आती है। यह कहा जाता है कि वित्त मन्त्रालय ने अपने काम में देरी देने की गरीबी अधिक केन्द्रित करती है और मन्त्रालय की छोटी-से छोटी रकम के लिये प्रशासनिक विभागों को वित्त मन्त्रालय का धुंधलका रहता है। अतः उचित

1. A. D. Gorwala—Report on Public Administration

2. "The Police department is asked to collect motor vehicles tax. Engineering officers have to do prosecution work for encroachment and collection of licence-fees specially in the Local Boards" (M. Ruthaswamy - Principles & Practice of Public Administration)

जाती है। योग्यता की जांच सुनी प्रतियोगिता द्वारा की जाती है, जिसमें व्यवस्थाएं स्वयं, निष्पक्ष एवं धर्म-मायित होकर काम करती हैं। सघन लोक सेवा आयोग (UPSC) IAS, IFS, IPS, आदि केन्द्रीय सेवाओं के निम्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इन "चयन के सिद्धांत के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि भारत में तत्काल वैसी ही निष्पक्षता बरनी जाती है जैसी कि किसी भी आधुनिक निम्न सेवा पद्धति में पाई जाती है परन्तु परीक्षा की विधियां अभी भी प्राच्य नहीं हैं और वे प्रयोगशील योग्यताओं के विषय में आधुनिक ज्ञान से पूर्णतः अवगत नहीं हैं।" परीक्षा-विधि संशोधन है, प्रयासयोग्य नहीं।¹ भरती में निष्पक्षता पर ज़रूर देना हूये गौरवान्वित है कि "यह अत्यन्त आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा (Psychological Tests) को महत्ता प्रदान की जाये और इनसे इनके योग्य परीक्षाओं का स्थापित हो सके। आधुनिक प्रशासकों के साथ होने वाली बातचीत उनके व्यापक अनुभव से सम्बन्धित होनी है तथापि वह उच्च गुणवत्ता मनोवैज्ञानिक परीक्षा का स्थान नहीं ले सकती जिससे उद्देश्य प्रत्यक्ष के माध्यम से तब ही प्राप्त हो सकेगा जहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक अनुकूलित दायता है।"²

पदोन्नति और प्रशिक्षण

शिक्षित मजदूरों को श्रद्धा और योग्यता के आधार पर पदोन्नति के व्यापक प्रयोग प्रदान किये जाते हैं तथा भविष्य निधि (Provident Fund) और पेंशन आदि के रूप में सेवा निवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) भी दिए जाते हैं। सरकारी नौकरों के सम्बन्ध में उनके पद की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। निम्न मजदूरों की दृष्टि से कि वे विभिन्न मजदूरों तथा परीक्षा काल (Probation Period) आदि की व्यवस्था होती है। इन प्रकार भारत में पदोन्नति के व्यापक प्रयोग, नौकरों की सुरक्षा तथा मजदूरों के द्वारा निम्न मजदूरों के मनोबल तथा कार्यक्षमता के स्तर को तब ही व्यवस्था की गई है।

राजनैतिक तटस्थता

निम्न मजदूरों को निष्ठा सरकार के प्रति होती है, जिसे वह के प्रति नहीं। भारत में मजदूरों और शिक्षित मजदूरों में वैसा ही संबंध पाया जाता है जैसा कि इंग्लैंड में। वारेन फिशर (Warren Fisher) ने इस संबंध को इन शब्दों में व्यक्त किया है।³ "मजदूरों का काम नीति निर्धारित करना है और जब एक बार नीति का निर्धारण कर दिया जाता है तो निम्न मजदूरों का यह निश्चय बर्तन्य हो जाता है कि यदि वे उस नीति से सहमत हो या नहीं, उसको मान्य करने के साथ अपना स्वयं का एक ही शक्ति तथा समान दायता के साथ क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। जबकि यह भी बर्तन्य हो जाता है कि वे, बिना

1. Paul H. Appleby : Public Administration in India-Report of a Survey.

2. A. D. Gorwala's Report on Public Administration.

समझने में और जनता को निरस्तार की दृष्टि से देने में । लोकतन्त्रीय स्वतन्त्र भारत में अब मिथि सेवा का यह रूप अस्माप्य ही नहीं, हानिदायक भी है । नीतरगाही को जन सहयोग से कार्य करना है । यदि नीतरगाही को लोकतन्त्रीय समाज की सेवा करनी है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके दृष्टिकोण तथा कार्य के तरीकों में आ परिवर्तन किया जाये ।

भारतीय प्रशासन के बमचारी प्रशासन में आज जो बुगझा विद्यमान है उनमें से मुख्य निम्नलिखित है—

सालकीताशाही

भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी आलोचना उसके कार्य की रूढ़ि प्रवृत्ति (Routine Nature) का कारण को जानी है । भारत में प्रशासन नियमा तथा विनियमों की बहुत ज्यादा बिता करता है, जो कई बार उसके कार्य को घात बढ़ाने को जगह बना जाता है । अधिकांश नियमों तथा विनियमों में अनिश्चय प्राप्त करने हैं और जब वे उन्हें लागू करते हैं, वे अपने व्यवसाय के ऐसे दर्जों से जा बचने की वांछ (रहित) तो करते हैं परन्तु उन्हें परोक्ष का पता नहीं रहता । इस प्रशासन में आलोचना काफ़ी उपस्थित होती है । भारत में सालकीताशाही या अनावश्यक प्रशासनिक देखे के कई कारण हैं । एक कारण है, बिना में प्राप्त होना वाली सभी पदवियों और पदोपदेशिकाओं का पात्र भेजने से पूर्व सहायता का समझ गया जाना । दूसरे, किसी मामले पर, निर्णय लिए जाने से पूर्व एक अधिा विभागों में विचार किया जाता । पटन की अपेक्षा अब दूरिपर मपगरी द्वारा बटन कम मामलों में निर्णय लिया जाता है । परिणामस्वरूप कार्य का बोझ मेकेंडार्य और उपाय ट मेकेंडार्य पर आ पड़ता है । अन्तिम और अन्य उच्च अधिाओं द्वारा निर्णय के अधीन जाने वाले मामलों में निरन्तर हस्तक्षेप भी साक्षीताशाही की प्रवृत्ति को बढ़ाता है ।

अत्याधिक कार्यकर्ता

जनता में प्रशासन के विरुद्ध बड़े आलोचनाएँ पायी जाती हैं । बहुत अधिक कार्य-कर्ताओं का जो बेईमान, अनुभव और साक्षीताशाही सरकार में तिस अथवा अनावश्यक कार्य-कर्ता हैं यह जानने के लिए विनृत अध्ययन की जरूरत है । अफसरों तथा निम्न वेतन और निम्न म्याद वाले बमचारी बहुत अधिक हैं जब कि उच्च स्तरों पर, गविस, सुपुन सगिस, उपमविस आदि के पद बहुत कम हैं । यह सामान्यतः किमी भी सिम्पूत मपगन के बारे में सत्य है किन्तु जहाँ अध्ययनता से अधिक कार्यकर्ता हो बहा कार्य का पुनर्भविष्य और भरण करण पर ये कार्यकर्ता कम रिये जा सक्त है ।

अकुशलता

भारतीय प्रशासन पर एक अन्य आरोप अकुशलता का लगाया जाता है । यह आरोप

मानाज्य जगता द्वारा भी नगारा जाता है। इनके कई कारण हैं। प्रथम तो हमारे यहां प्रमानाज्य निन्द्य और विविध क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या का अभाव है, जिससे प्रमान में अतिरिक्त, ना-फैदागार और देरी आदि उत्पन्न होती है। दूसरे, अनुमान का एक अन्य कारण समन्वय का अभाव होता भी है। निम्न, क्यों न अनुमान और उद्योग गति के लिए सत्ता का प्रत्यापन (Delegation) आवश्यक है किन्तु भारतीय प्रमान में अभाव है। हमारे यहां उच्च अधिकारी अपने पान अधिकारक मन्दा रखते हैं और अपने म निम्न पदाधिकारियों में उनका अधिकार रखते हैं। इन अधिकारों के कारण में उनके पिन गति में अनुमानता बढ़ती है। चौथे, सभी सभी अधिकार का अभाव या अभाव, जिनमें एक व्यक्ति को उच्च पदाधिकारियों के अधिकार का अभाव है, अनुमानता को जन्म देता है। तीसरी स्थिति में उसे एक से अधिक मिलता है कि 'ऐसा बग, 'य कि दूसरा बहता है' किता बन बने। उदाहरण के लिए, निम्न क्षेत्रों का एक ही अधिकार विभागों के निष्पादित अधिकारों में एक अधिकार प्राप्त जाता है और बिना विविध प्रक्रियाओं में दूसरे।

निम्नस्तर का मनोचल

यह भारतीय प्रमान की एक अन्य दुर्गति है। इनके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, पदोन्नति सामान्य और अनियमित के कारण उन न को गहरा अनुचित कारणों का भी जारी है। जति, मनुमान, अन् आदि अन्व के प्रभाव में योग्य व्यक्ति पीछे रह गते हैं और अयोग्य मान उठते हैं। उन निम्न व विरोध की नावनाहरी पैदा होता स्वभावित है। द्वितीय कारण है विविध स्तरों में उच्चतमस्तर को अन्व और निम्न न केने को प्रगति। उन्नी गहरा तीसरा कारण है मन्वारी और मेमिबिन् मेवनों का अन्व दिने जाना। इन मन्वारी में केंद्रीय वेतन आयोग ने कहा था कि "हमारे मन्वारी को अन्वित प्रगति को गढ़, उनमें पूर्ण निम्नता को मन्वारी, पर गहरा मन्वारी को अन्वित नीति के अन्वित प्रगति प्रगति होता है। यह उन निम्न मनोचल को निर्दिष्ट करता है जो अन्व प्रमान के लिए अन्वित के मन्वारी १।"

अप्रत्याचार

भारतीय प्रमान में अन्व को मन्वारी का दौर नन्वारी का रहा है वह है अनियमितता और अप्रत्याचार (Irregularity and Corruption) का प्रमान का जोर्द क्षेत्र इसमें मुक्त नहीं। उच्च स्तरों-मन्वारी और मन्वारी में ही अन्व अन्वित हो रहा है जो निम्नस्तर में जो कया अन्वित जो अन्व मन्वारी के अन्व अन्वितों में अनियमितता और पन्वितवाद (Favouritism) के अन्वों को प्रोत्साहन देते हैं। अन्व बिना अन्व को अन्वित अन्व है वही मन्वारी के विविध अन्वित प्रमान गने का रहे हैं।

1. "The evidence before us has disclosed absolute distrust, not to say despair on the part of most grades of public servants as to their receiving a fair response from the government to their representations." (Central Pay Commission 1957-59)

और जाँच मर्मितिया बिठाई जा रही हैं या यह सब हो चुका है या सोचा जा रहा है। केन्द्र और राज्य शान्त म उच्च पदाधिकारियों की यही स्थिति है। प्रमुखों और सरकारों धन का व्यक्तिगत खर्च के लिए दुष्प्रयोग बढ़ता जा रहा है।

सुधारों की आवश्यकता

हमारे भारतीय प्रशासन के कुछ मुख्य पट्टुप्रा और उनमें निहित दोषों का संश्लेषण विवेचन किया है। यदि भारतीय प्रशासन को भारत में वस्त्राणुकारी राज्य की स्थापना का महान कार्य करना है तो इसके लिए बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में भारत न जो उच्च उच्च अथवा सम्पूर्ण रूप से है उनके लिए प्रशासन की जांच और कुछ नतीजों और कुछ दीर्घकालीन सुधारों की अत्यन्त आवश्यकता है।

भर्तों में व्यक्तिगत गुणों की प्रमुखता हो जाय

समय-समय अधिकाधिकारी की भर्तों केवल संसक्ति आधार पर नहीं की जानी चाहिये, बल्कि चरित्र, उत्साह आदि व्यक्तिगत गुणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। आई ए ए., आई एन ए., आई एम ए. भर्तों होने वाला के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था का सुधार जाना चाहिये। इन समय में गोरवाला का मुताब है कि "आवश्यक अधिकाधिकारी और स्टाय सहित प्रशिक्षण, मगडन और कामगारों के निदेशों की नियुक्ति बन्दोबस्त सरकार का मुख्य कार्य देनी चाहिये। राज्या में भी बीच में केन्द्रीय के अधीन सेवान्ता होने चाहिये।" इस समय में ध्यान हमारे प्रशासन में विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पुनर्शिक्षण पाठ्यक्रमों (Refresher Courses) को अधिक आवश्यकता है।

अनावश्यक बिलम्ब मिटाया जाय

विभिन्न कार्यों में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि समय बचाने वाले साधनों का प्रयोग किया जाने और फाइलों का एक से दूसरी में प्रारम्भ आवश्यक स्थानांतरण समाप्त किया जाय। नतीजा का हस्तान्तरण देरी और लाजमीतावाही की सम्भावना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। अनावश्यक और बाधकताओं को त्याग कर प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार गुरुत्व निर्धारण करने की स्वतंत्रता देनी चाहिये। भर्तियों को प्रशासन में और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को अपने के निम्नतर अधिकारियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

कर्मचारी काम किये जायें

1. "The Central Government should appoint a Director of Training, Organisation and Methods with the necessary officers and other staff, the state too would be well advised to have organisation, methods and training sections, working directly under the Chief Secretary."

बहुत अग्रिम कर्मचारियों को पाये जाने का दोष प्रशासन के पुनर्गठन द्वारा दूर किया जा सकता है। किसी भी स्तर पर आवश्यकता से कम या अधिक कर्मचारियों का होना प्रशासन में देरी और अकुशलता को जन्म देता है।

कुशलता और दक्षता लाने के लिए सुझाव

संगठन में संशो पदों का उत्तरदायित्व और नया निश्चिन और विस्तृत स्पष्ट होने के साथ साथ प्राप्त में एक दूसरे के अनुपम भी होनी चाहिये। दूसरे, किसी भी पद पर नियुक्त कर्मचारी एवं में अधिक व्यक्तियों को आदेशों के अंतर्गत नहीं रहना चाहिये। श्रमोन्मत्त कर्मचारियों की आशाएं उनके ऊपर स्थित प्रमुख अधिकारियों द्वारा ही दी जानी चाहिये। तीसरे, विभाग के किसी भी प्रशासन के समस्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले श्रमोन्मत्त कर्मचारियों की सम्मति उसमें प्रविष्ट नहीं होनी चाहिये, जितना वा बह दृष्टि रूप में निर्धारण कर सकता हो। चौथे, अधिकारियों की अपनी सत्ता का इस्तेमाल और विकेंद्रीकरण करना चाहिये। पाचवें, कुशलता के लिए विभागों का इस प्रकार संगठित होना आवश्यक है कि उनमें उचित समन्वय रहे। विभाग के संचालक का प्रमुख कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह विभाग के अंतर्गत बड़े ममानों के कर्मचारीवर्ग तथा कार्यों में समन्वय स्थापित करे तथा सहयोग को प्रोत्साहित करे। अतः में, प्रशासकों को इस तथ्य का नहीं भूलना चाहिये कि जनता उनकी स्वामिनी है।

योग्यता और परिश्रम के आधार पर पदोन्नति और प्रोत्साहन

उच्चकोटि के मनोदलन के बिना इस सिद्धान्त का पालन आवश्यक है। भारत में अति-कालतः उच्चतर तथा मध्यम स्तर के पदों के लिये तो योग्यता पर जोर दिया जाता है और निम्न स्तर के पदों के लिये 'श्रेष्ठता और उपयुक्तता' (Seniority-cum-fitness) पर। सिद्धान्त यद्यपि हमारे यहाँ योग्यता पर ही बल देता है पर व्यवहार में श्रेष्ठता को अधिक बल दिया जाता है। राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के 'नूतन' प्रणाली ने बेज्बाय बेतन आयोग के समस्त कहा था - "इन दोनों सिद्धान्त का सम्मान इनका अनुसरण करने की अपेक्षा श्रेष्ठता और बल देने के रूप में ही अतिरिक्त दिया जाना है।" अतः वार्षिक सिद्धान्त का मूल्य अपॉ में प्राप्त होता चाहिये, देना मान्यता ने तो यही निश्चय की थी। कुशल और ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये अधिक पदक, मंडल आदि के रूप में पुष्कार भी दिये जा सकते हैं।

अष्टाचार का निवारण

आज भारतीय प्रशासन में सम्पूर्ण नवने प्रवृत्त नमस्वा अष्टाचार है। इनके निवारण के लिए नागरिकों के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करना चाहिये, जिससे कि श्राव के अनुचित मापनों को और प्रवृत्त न हो। रात्रनौतिक पदों पर अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारियों नियुक्त नहीं किये जाने चाहिये क्योंकि रात्रनौतिक पद प्राप्त करने के लिये वे पदाधिकारियों निर्णय करने वाले अपने अपने उच्च अक्षमता को छुग करने के लिये अनुचित कार्य करने लगते हैं। अष्टाचार

भाग्य में लौट प्रयास

और निरवगुणों के संघर्षों के लिये बहोर दण्ट की व्यवस्था होनी चाहिये। हाथ ही में केन्द्र सरकार द्वारा 'अष्टाचार निवारण समिति' की स्थापना की गई है परन्तु भावस्थ-का इन उपायों के द्वारा दृष्टानुसार कार्यवाही करने की है। इस सम्बन्ध में पौन एतन्वी के मुभाव इस प्रकार है —

“ऐसा मण्डनामर टाका उठाया जाता चाहिये जो पददानवाद और बेईमानी के प्रव-मन की वम में वम कर गये और पोष्यता और मच्चरिगता के प्रवर्धन के अधिनस्थित बड़ाया है। अनियमितताओं के प्रतिरोध के लिये मन्त्रालय और के प्रति जागरूकता प्रावधान है। पर सम्बन्ध सामान्य के स्वाभाविक गौरे वाक क्षेत्रों में सर्वोपरि माध्यामी और जागरूकता जरूरी है। इन क्षेत्रों में विराम नगरी, वास्तव्य, परमिटी प्रादि के लिये प्रांगण तथा जामूरी, परमिटी समझौते प्रादि के नाउन में मन्त्रिण कार्यवाहियों प्राणी हैं। निम्न वमन स्तर वाले कर्मचारियों में सामान्य नियमि कार्यव्यवहार रूप में प्रवृत्ति है। मेरा अनुमान है कि इसी लीग सामान्य अधिन ईमानदार हैं। दृष्टान्तों जो भी हैं वे गान्धीनिक अनुभव और समुचित मस्थानमर प्रवर्ध के प्रभाव की हैं।”

एतन्वी के उपरोक्त विचार बहुत कुछ सही हैं परन्तु हमारे विचार में भारतीय कर्म-चारियों की ईमानदारी के बारे में एतन्वी का अनुमान पूर्णतः उचित नहीं है। जनमन तो यह मानता है कि प्रायः बहुप्राता, अष्टाचार, अनियमितता, बेईमानी, रिक्वन्तरी प्रादि बुराईयाँ इसकी बड़ गई हैं कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिये जोष कमीशन निवृत्त करने की आवश्यकता है।

जहां तक वामन का सम्बन्ध है उसे वमन में लाया जा सकता है और उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन केवल वामन से अष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। हमने प्रत्येक को प्रमाण करवा होगा और निम्नलिखित पर हमें कार्य करने होंगे किन्तु देश में निम्नलिखित जीवन और प्रवृत्ति और प्रभावी प्रमाण की स्थापना की जा सके। समाज के 'महाजन' जो प्रायः के मन्त्री प्रादि हैं वे अपना व्यवहार सुद्ध करें। महाजन का जैसा व्यवहार होगा उसी के अनुसार समाज केगा क्या जलानारण उसी का अनुसरण करता है। राजनार्य, सर्वनार्य और समस्त सामान्य जीवन में कार्यवाही के लिये वामन के अनुसार ही देश का वर्तमान रूपित व्यवहार सुद्ध किया जा सकता है। यही अष्टाचार उन्मूलन का एक प्रभावी उपाय है।

देश में सुद्ध प्राप्त करने के लिये हाथ ही में समझ में एक मुभाव रखा गया कि राज्य मन्त्रालय को लोचनाना के अधिन में प्रमाण करने मय राजनीतिज्ञ दत्तो के स्तरों की एक ऐसी समिति नियुक्त करने चाहिये जो मय तथा विधान मन्त्रालय के मन्त्रियों के लिये एक प्रावधान गठित करे। यद्यपि सरकार श्री नन्दा के नेतृत्व में प्रमाण में दत्ता के उपायों के लिये प्रवृत्त है परन्तु यह विचार और विविध रूप में प्रवृत्त है।

मनियों के लिये आचरण महिना का निर्माण दिया जा चुका है। उसमें मन्देंह नहीं है किसी राष्ट्र के जीवन में अधिक महान् शक्ति का पद होना है जिसके उचित निर्वाह के लिये मनी का धुंध रहना बहुत जरूरी है। वही एक मार्ग है जिसके द्वारा वेप प्रभावना-यत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जा सकता है और आम जनता भी मुक्त की जाए सकती है। किन्तु विधायकों और मन्त्रियों का पद भी कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है। उन्हें अधिकार और सत्ता जम्हाई मिलनी चाहिए किन्तु जिन नीतियों और कानूनों के अनुसार कोई लोकतांत्रिक देश चलता है उसके अन्तिम निर्णायक वे ही हैं। यदि वे ही भ्रष्टाचार का शिकार होंगे तो ऐसे कानून नहीं बन सकेंगे जो जनता के मुख, मनोप और समृद्धि का आधार बन सकें। मन्त्रियों का चुनाव भी इसी में से होना है। अतः उन्हें धुंध रहने की व्यवस्था किये बिना मन्त्रियों से अप्रत्यक्ष आचरण को प्राप्ति देने की जा सकती है? इन निर्वाचित प्रतिनिधियों से राष्ट्र के अच्छे शुभचिन्तक बनने की आशा की जाती है परन्तु प्रायः इनमें से अधिकांश इन आशाओं को पूरा नहीं करने और म्याचों के कमीशन होकर अपने कर्तव्यों के प्रति न्याय नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप जिस विचार विनिमय पर देश का भविष्य आधारित होना है वही धुंध हो जाता है।

आचारसंहिता की आवश्यकता

आचरण महिनाओं, भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों, दण्ड-व्यवस्थाओं की घोषणाएँ मात्र ही समाज के आचरण को नहीं दिशा देकर भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकती। परन्तु ये सब व्यवस्थाएँ ऐसे अशुभ घटक हैं जिनके रहने में सामान्य कमचारियों में नैतिक देश के नायक-निर्माताओं तक की भ्रष्ट होने का अवसर कम मिलेगा और वे अपने कर्तव्य के प्रति अधिक न्याय कर सकेंगे। अतः हम क्षेत्र में केन्द्र सरकार, राज्या तथा जनता की अधिकार मजग और प्रवर्तनीय होना चाहिये नयी प्रभावना में इन सबके सुधारों का निवारण सम्भव है।

सिविल सेवकों में मंत्रियों और संसद-सदस्यों द्वारा विश्वास की आवश्यकता

सिविल-सेवकों को सभी सभी मन्त्रियों और मन्त्रियों के हाथ का विरोधाभास बनना जाना है। जब तक यह स्थिति दूर नहीं हो जाती स्वतन्त्र भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सफलता के लिये एक ठोस तथा सार्वजनिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सकता। समशील अविश्वाम के फलस्वरूप सिविल सेवकों ने प्राप्त स्वयं की सामान की दृष्टि कार्यक्रमों तथा प्रक्रियाओं का ही मौलिक तत्त्व है। उनके नज़र भारत के महान् उद्देश्यों को पूरा करने की उनकी समझ में भारी सभी हुई है। सिविल सेवा एक ऐसा यंत्र है जिससे द्वारा कोई भी सार्वजनिक कार्य बढ़ाया जा सकता है और यदि इसका प्रयोग अविश्वाम के साथ किया गया तो उसके द्वारा भी हम प्रभावकारी होंगे। सिविल सेवकों का अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व विनियमित करने की जरूरत है जिसमें वे मन्त्रियों के हाथ का विरोधाभास न रहें। उनके विभिन्न गुण का

संबंधों में प्रयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें बिना किसी भय के अपने प्रमुखों के सम्मुख सरकार के सामने पर ध्यान मत प्रकट करने के अवसर मिलें जायें।

एपलबी के मुद्दा

पॉल एपलबी ने भारतीय प्रशासन में सुधार के सम्बन्ध में कुछ मुद्दा दिये हैं जिनमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार हैं —

(१) सरकार द्वारा दियी योग्य मनी के प्रत्यक्ष अधीन सवर्ग और व्यवस्था व्यवस्था लागूगणन कार्यालय (Organisation & Management of Public Administration Office) की स्थापना की जानी चाहिये। सरकारों के अधीन प्रशासनिक पद्धतियों के सुधार के प्रस्तावों और अध्ययन के लिये ऐसा कार्यालय जरूरी है।

(२) बाहरी विभागों की टीम द्वारा और अधिक तथा विविध अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिये।

(३) लोक प्रशासन पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर से ध्यान केंद्रित करने के लिये सरकार की अधीनता में एक लोक प्रशासन संस्था (Institute of Public Administration) की स्थापना जिसका उद्देश्य साहित्य-वृद्धि द्वारा प्रशासनिक ज्ञान में कुशलता प्रदान करना है।

(४) लोक प्रशासन में वैश्वीय स्तर पर प्रोग्रामों का विभाग और लोकसेवा में वार्षिक प्रवेश के लिये विवेक भागों की स्थापना। उपरोक्त लोक प्रशासन मन्त्रालय की विभाग विद्यालय और सरकारों में नये और निरन्तर के परामर्श प्रदान और कार्यात्मक संबंध स्थापित करना चाहिये।

(५) सामुदायिक योजनाओं की बनाने और उनके मजबूत में लचीलता और निरन्तरता लाने के लिये प्रशासनिक दायित्व को मजबूत बनाना चाहिये।

(६) विभाग और सामाजिक कार्यों के भी क्षेत्रों में अन्तर-मन्त्रालय-हस्तक्षेपों को कम करना तथा सरकार के विभिन्न स्तरों पर समीक्षा (Reviewing) के तरीकों को सुधारना।

(७) पद सीढ़ियों में ऊपर और निम्न स्तरों पर विद्यमान विस्तृत दृष्टियों को कम करके प्रशासनिक पदमोपान को पूरा करना।

(८) सरकार के लिये कार्य करने वाले भी व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तृत वार्षिक वर्ग विकास योजनाओं (Personnel Development Programmes) की स्थापना।

(९) भारतीय प्रशासन नेकों के लिए अन्य देशों के भाग प्रशासन को देखने और उनके धारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। इनके अलावा अन्य देशों द्वारा

उत्पादित व्यावसायिक साहित्य का विस्तृत रूप में उपलब्ध होना भी उपयोगी होना और ऐसा होने पर ही यहाँ के प्रशासन अन्य न्यायो पर दृष्टिकोण पड़े जायेंगे।

(१०) भर्ती में सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिये और यहाँ में निरुक्त व्यक्तियों के विषये भी समय समय पर मैदानिक नैतिक प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिये।

(११) ए० और एम० डिग्रियों की स्थापना—ये केन्द्र और राज्य दोनों में हो सकते हैं।

(१२) Institute of Public Administration की स्थापना।

इनमें से अन्तिम तीन मुद्दाव क्रियान्वित किये जा चुके हैं।

इन उपरोक्त मुद्दों के क्रियान्वित पाँच एजेंसियों ने प्रशासन और योजना आयोगों के आदेशों के अनुसृत प्रशासनिक विद्याया के विषये भी मुद्दाव दिये हैं। उदाहरण है कि वर्तमान भारतीय समाज के दो मुख्य पहलु—प्रशासन तथा योजना—में राज्य की शक्ति के अभाव में प्रशासनिक विद्या के विकास का विषय आन्दोलन और प्रवर्धन है। प्रशासनिक शास्त्र प्रशासन का अर्थ केवल प्रशासनिक दृष्टि से चुने और उत्तरदायी नैतिकों के नियन्त्रण और निर्देशन में मात्र प्रशासन का होना ही नहीं है और न होना चाहिये। प्रशासन उस दृष्टि पर निर्भर है जिससे उत्तरदायित्व (Responsiveness) निश्चित किया जाता है। ऐसी सत्ताओं प्रशासनिक है जो उत्तरदायित्व को गृहीत करती हैं। वह प्रशासनिक पद्धति पूर्णतः उत्तरदायी नहीं बल्कि सत्ता है, जो नागरिकों के पक्षों से उत्तर न देने का शक्त दत्त या देरी में देने की क्षमता देती है। वह प्रशासनिक पद्धति भी प्रभावशाली नहीं है जो सत्ताशाली दलगत और सत्ताशाली व्यवस्था पर नागरिकों के प्रवेश पर बाधाएँ लगाती है या जो नागरिकों के विभिन्न स्तरों के मध्य सूत्रबद्ध बान्धन स्थापित करती है या जो नागरिक प्राधिकारों का सृजन नहीं समझती। जो पद्धति भाग लेने (Participation) के नाम पर उपाय के विभागों और मुद्दाओं को प्राप्त करती है वही सत्ते अर्थ में और अन्तिम भाषा में उत्तरदायी है।

बाह्य आयोग द्वारा जांच

समाज की परिवर्तनशीलताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन का पुनर्गठन होना चाहिये। निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र या क्षेत्रों की प्रवृत्ति के अनुसार एन बाह्य आयोग (Outside Commission) द्वारा सहायता के पुनः आगमन को उद्देश्य के रूप में बना लाना होगा। बाह्य आयोग अन्तिमों के कार्यकारी अधिकारियों (In-charge Officials) के नाम कीर्तनपूर्ण बालापरत में करने के विषयमात्र पर सहायक में विचार करेगा। यह क्षमता की जा सकती है कि निर्मा अथवा अन्तिम ऐजेंसियों के सुधार में बाह्य आयोग की निगरानी पर अतिरिक्त ध्यान दिया जायेगा। विभिन्न देशों में समय-समय पर पुनर्गठन आयोगों (Reorganisation Commission) की नियुक्ति की जाती है। उदाहरण के अभाव में दूसरे आयोग द्वारा प्रशासन का प्रशासन का। उत्तरदायित्व में भी इन मुद्दों में विशेषों की सहाय

की है और उन्होंने सरकार के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। सर्वप्रथम सन् १९४६ में ए० गांधीजी द्वारा 'सरकारी व्यवस्था के पुनर्गठन पर प्रतिवेदन (Report on the Re-organisation of Machinery on Govt.)' प्रस्तुत किया गया। इसके बाद १९४९ में गोखला तथा गुप्तजी ने भारतीय लोक प्रशासन पर दो प्रतिवेदन-प्रथम Report on Public Administration और Public Administration in India Report of a Survey प्रस्तुत किए। इन दोनों में हमारे प्रशासन के दोषों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया और भारतीय प्रशासकीय ढाँचे में परिवर्तन के अनेक सुझाव दिये गये जिनमें से अनेक को विद्यमान भी किया जा चुका है।

अब तक हुए प्रयास

भारत में १९४४ में गठित कया प्रशासकीय विभाग (O & M Division) की स्थापना हो गई। प्रशासनिक सुधारों में सुविधा के लिए इस विभाग का वर्तमान नाम पड़ोसी और सामुदायिक सेवा विभाग तथा यह ध्यान रखा है कि प्रशासनिक कार्यवाही समय के अनुरूप हो जायें और परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल रहें। केन्द्रीय सरकार में लोकप्रशासन के शासित करने वाले विभिन्न विभागों के मन्त्रीयमण्डल में अनेक विभागों का कार्य भी अन्तर्भूत कर दिया है। लोक प्रशासन के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 'Institute of Public Administration' को भी स्थापना की जा चुकी है। १४ फरवरी १९६० के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख में मन्त्रिपरिषद् द्वारा प्रस्तावित हुआ था कि "सुप्रसिद्ध भारत सरकार की प्रशासकीय मन्त्रियों के सुझावों के लिए दूरदर्शी महत्व के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनके बाद कहा गया कि सुझावों को अत्यन्त ही ध्यानपूर्वक ध्यान दिया जायेगा और उनमें से जो उपयोगी होंगे वे लिए जाएंगे। एक उच्च स्तर की समिति की शीघ्र ही स्थापना की जायेगी जो भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिवेशन में काम करेगी।" इस प्रकार समय समय पर भारत के प्रशासकीय ढाँचे का पुनर्गठन किया जाता रहा है।

निष्कर्ष

यद्यपि, एंग्रेजों के शासन में हमारा देश "Twelve Best Administered Countries of the World" में से एक है और कहा "उत्कृष्टतम शासन पर देशभारती" है फिर भी सरकार में अनेक स्थानों पर सुधार की आवश्यकता है। वर्ष १९४० में अखिल भारत के उद्घाटन के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य-योजना का समय रखा गया जब एक दूसरे और अच्छे चलन (वर्तमान शासन का

असिद महत्वपूर्ण होगा । इसके सिवाय व लिए आवश्यक है कि वह बौद्धिक और प्रणाली मूलक होने के साथ-साथ प्रशासन के ढांचे को भी प्रभावित कर सके ।”¹

BIBLIOGRAPHY

- 1 A D Gorwala Report on Public Administration
- 2 Paul H Appleby Public Administration in India—Report
of a Survey
- 3 Herbert Emmerich Essays on Federal Reorganisation
- 4 Ruthnathswamy Principles of Public Administration
- 5 Hyderabad Economy Committee Report

1 “ Average person working in an average way can not bring a wholly new day in India Very extra ordinary people must carry the hope of India into the manaeement of tasks enormously difficult and complicated Public Administration will grow in importance and significance in India Its growth shou'd be as much intellectual and methodolomical as it is physical ”

दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण

(स्वरूप, सम्भावना एवं समस्याएँ)

—गुरुपोतम नागर

घरने लखे धीर बठिन सपर्यं के बदलात एशिया के देसो को विदेशी साम्राज्य के आगनायो एजे से घरने-धारको निवाल कर स्वतन्त्रता की बायु में श्वास लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस स्वतन्त्रता को स्थिर एवं सुख बनाने रखने के लिए यह आवश्यक है कि अपने विकास कार्यों में वे देश मिलकर, सहयोगपूर्वक एक एक संगठन के रूप में अग्रसर हों। इसी कारण अनेक संघकोटि के विद्वानों को मान यह विचार प्रभावित करना आ रहा है कि दक्षिण-एशिया क्षेत्र को एक संगठन का रूप दे दिया जाये।

दक्षिण एशिया की इच्छायाँ—दक्षिण एशिया के इस क्षेत्रिय संगठन में विभिन्न देशों को शामिल किया जाय इसके बारे में विचारकों में मतभेद नहीं है। कुछ विद्वान इसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल तथा मलायक सीमित करते हैं जबकि दूसरे अफगानिस्तान और बर्मा को भी इसमें मिला लेते हैं। बर्मा को प्रायः दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं अफगानिस्तान को पश्चिमी एशिया के साथ समूह किया जाता है। इसी प्रकार भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राचुरिक राजनैतिक गुणों की दृष्टि से पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया से जोड़ा जाता है।¹ पाकिस्तान भी, क्योंकि 'सेन्ट्रो' तथा 'मिडो' का सदस्य है, पश्चिमी एशिया अथवा दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक भाग माना जाता है। मन मितना रहते हुए भी दक्षिण-एशिया को एक क्षेत्रीय संगठन का रूप देने वाले अधिष्ठित विचारक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, पञ्जाब, बर्मा एवं अफगानिस्तान को इस संगठन की इच्छायाँ मान कर बनते हैं।

क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता—दक्षिण एशिया के इन सभी राज्यों के सम्मुख मुख्य रूप से दो कार्य हैं—घरने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करना तथा देश का सर्वांगीण विकास।² जिस पराधीनता के बंधन से छुटकारा पाने के लिए इन राज्यों को अनेक संपूर्णों की सहायता पसी थी वह फिर से न आयाय हमरी रोकथाम के लिए रक्षात्मक संधियाँ एवं सैनिक शक्ति की भाँवर पर्याप्त होना आवश्यक है। किन्तु इन

1. Jawahar Lal Nehru's Speeches, 1947-49, P. 236.

2. "Confronted by many similar problems, and with a common interest in preserving and consolidating their newly won freedom, these Countries have a common stake in regional co-operation for common ends."

—Norman D. Palmer in forward of 'India and Regional Integration in Asia', by Sisir Gupta.

पावश्यकता की पूर्ति के लिए इन देशों के पास समुचित साधनों का प्रभाव है अतः इन सब को एक संगठन बना लेना चाहिए तथा एक होकर अपनी स्वतंत्रता के दुश्मनों का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। दूसरी समस्या है इन देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में उन्नति करने की। इस समस्या का समाधान भी इन देशों की परस्पर सहयोगपूर्ण नीति पर आधारित है। संगठन में शक्ति होती है। इस शक्ति का प्रयोग करके ये देश अपने आपको ऊँचा उठाकर प्रगतिशील राष्ट्रों की श्रेणी में रख सकेंगे।

क्षेत्रीय संगठन में सहायक तत्व—जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में मित्रता का आधार होता है निकट सम्पर्क, समान वृष्टि दृष्टि, एक-ही अभिरुचि, समान समस्याएँ, सदस्यों की समरूपता आदि आदि, ठीक उसी प्रकार दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय संगठन का रूप देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। इस क्षेत्र के देशों में वृष्टि-दृष्टि, राजनीति, संस्कृति, धर्म, स्तर, सदस्य आदि की समानता परिलक्षित होती है जिसके आधार पर यह सम्माननीय स्वीकार किया जाना है कि इन देशों के बीच परस्पर मैत्री एक सहयोग की म्यारता हो सकती है। क्षेत्रीय संगठन के अनुकूल विद्यमान तब निम्न प्रकार हैं—

(१) भौगोलिक एकत्व—इस क्षेत्र की द्वादश भौगोलिक दृष्टि में पर्याप्त निकट है। अफ़ग़ान की सीमाएँ एक दूसरे में मिली हुई हैं। यदि यहाँ और अफ़ग़ानिस्तान को एक छोटा रखें तो हम पायेंगे कि अन्य चारों देशों की सीमाओं में भारी निचटता एवं माश्रिफ़ है। यही कारण है कि इन देशों का जलवायु, मानसून, वर्षा की अवस्थाएँ तथा ख़न-महन आदि के बीच एक आधारभूत समानता प्राप्त होती है। यहाँ तथा अफ़ग़ानिस्तान को ऊँचे पहाड़ और गहरी खादों में भौगोलिक दृष्टि में विनाश कर दिया है किन्तु फिर भी ये देश पश्चिमी एशिया एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी उतने ही दूर हैं जितने दक्षिण एशिया में इनको समाहित किया जा सकता है।

(२) जीवन-यापन का धार्मिक तरीका—इस क्षेत्र के सभी देशों के नागरिकों का जीवन-यापन का तरीका किसी न किसी धर्म में प्रभावित है। सभी देशों में हिन्दू, मुसलमान, सिख, बौद्ध एवं ईसाई धर्मावलम्बी निवास करने हैं। भारत में हिन्दुओं को एक बड़ी समस्या निवास करनी है किन्तु बाघ की जंगल एवं बरोड मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं तथा अन्य धर्म भी अन्य समस्या में निवास करने हैं। यहाँ छोटी-छोटी समस्याएँ बटुमन हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों की समस्या अधिक है। पाकिस्तान एक धार्मिक राष्ट्र [Theocratic State] है। धर्महीन व्यक्ति का आधार है तथा राज्य के रूप एवं नीतियों पर धार्मिक शिक्षाओं का पर्याप्त प्रभाव है। यहाँ के मोर-जीवन में बौद्ध धर्म उनी प्रभाव निर्रोमा हुआ है जैसा कि भारत में मूल।

(३) ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गिकार—दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता में पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पदे में जकड़े हुए हैं। इन सभी राष्ट्रों की

दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण

समान रूप से विदेशी आनव एवं घोषण का निवार रहना पड़ा था। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी दृष्टियों में समान रूप में इनको चुनना गया था। ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ एवं रूप में इन राज्यों के शासन का मचानन कर रही थी। शिक्षा, धर्म, राजनीति, अधिवार आदि क्षेत्रों में घब्रोजो ने जो रूप भारत में अपनाया वही अन्य देशों में भी अपनाया गया। पाश्चात्य शिक्षा में रणो हुई एवं नवीन मन्त्रि सभी देशों में समान रूप में विकसित होने लगे। 'भूट डालो और राज्य बरों' की नीति का सभी देशों को बहुत फल बनना पड़ा। इन सभी समानताओं व आधार पर यह मानना प्रयोगिक न होगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के इन सभी देशों की प्रवृत्ति, स्तर एवं समस्याओं में एकस्यता होनी चाहिए। वे सभी एक ही रैली के चट्टे-चट्टे तथा एक ही रास्ते में डाली गई मूर्तियों के समान हैं। इन सभी देशों में शासन की बागडोर उन लोगों के हाथ में रही जिन पर पाश्चात्य सम्प्रदाय एवं संस्कृति का जल्लेखनीय प्रभाव है। 'जातीय' भाषा-गत एवं सांस्कृतिक अनेकता रहने हुए भी दृष्टिकोण की समानता इनमें पाई जाती है जिसके कारण सभी अनेकताओं महत्वहीन बन जाती हैं।¹ बाण्डुग सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों का यह भाव था कि "हम एशियावासी एक ही प्रकार के भ्रष्टाचार से पीड़ित रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी एक है। एशिया और अफ्रीका के हम लोग उपनिवेशवाद को लूट और भ्रष्टाचार के विचार हुए हैं और इस प्रकार गरीबी व पिछड़ेपन की स्थिति में रहने को मजबूर किये गये हैं। हमारी भाषा जन जन दवाई गई है, हमारी महत्वाकांक्षाओं को चुनला गया है और हमारा भाष्य दूसरों की दया पर निर्भर रहा है।"

(४) आर्थिक अर्थव्यवस्था—इन सभी देशों के सामने आर्थिक समस्याएँ समान रूप में उपस्थित हैं। पराधीनता के समय साम्राज्यवादी देशों द्वारा इन सभी देशों को समान रूप से घोषण का निवार बनना पड़ा था। आर्थिक क्षेत्र में परम्परा महयोग की नीति अपनाकर ये देश अपने विकास की रणि को संभव बनाने हैं। दल क्षेत्र का योजनायुक्त विकास किया जाय ता जल्दी ही आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकेगा है। उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में विमोक्षण तथा तयनीरी योग्यता का परस्पर आदान प्रदान किया जाय। इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विकास का स्तर समान नहीं है। प्रत्येक देश अपने स्रोतों का अधि से अधि प्रयोग उन क्षेत्रों में करना चाहता है जो उसकी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुकूल हैं तथा अधिक एवं सामाजिक दृष्टि में लाभदायक हैं। इस क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिसमें उत्पादन एवं तयनीरी योग्यता का परस्पर आदान प्रदान होता रहे। वॉरम्बो योजना के पीछे यही भावना कार्य कर रही है। भारत में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का निश्चय करने समय पूरे क्षेत्र की दृष्टि में मोचने का प्रयास किया

1. W. Henderson, "The Development of Regionalism in South-East", Vol IX, P. 464.

गया था। मोचा गया था कि गरीबों, जीवन-निर्वाह का निम्न स्तर तथा प्राथमिक शिक्षाएँ आदि गरीब प्रवृत्ति की समस्याएँ हैं। इन समस्याओं ने छुटकारा पाने में एक देश के साथी एवं अनुभव का दूसरे देश के लिए बड़ा उपयोग रहेगा।¹ भारत प्राथमिक दृष्टि से दक्षिण एशिया क्षेत्र का सर्वोच्च समर्थक रहेगा। यह इस दृष्टि से भारत के लिए लाभकारी रहेगा।²

(५) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शान्ति का समर्थन—दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित सभी राष्ट्रों का स्वायत्त यह भाव करता है कि विश्व में संपर्क एवं वननस्य न रहे। शान्ति एवं परस्पर सहयोग का बनावटगत हो वह उत्पन्न जनबाध है जिसकी उत्पत्ति में इन देशों का स्वतन्त्रता का नव विकसित पोषा बढकर प्राथमिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में विकास के फल और पुष्प प्रभृति कर सकता है। इस क्षेत्र के अधिकांश देश दोनों गुटों के बीच के संपर्क की भावना को कम करने दोनों में ही प्रच्छेद सम्बन्ध बनाने रखने के पक्षपाती हैं। भारत जैसे देश अस्तित्व के विद्वानों पर अपनी विदेश नीति को आधार करते हैं जिसका प्रमुख मध्य विश्व से युद्ध के सफल को दातना तथा अपने विकास कानों में सभी राष्ट्रों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना है। पाकिस्तान यद्यपि पश्चिमी संविधान संविधान का सदस्य हो चुका है किन्तु साम्यवादी गुट का सहयोग की वह अवस्था एवं तिरस्कार नहीं कर सकता।

संगठन के मार्ग की ओर किए गए प्रयास—इस क्षेत्र के देशों को एक दूसरे के अधिकाधिक समीप लाने की दिशा में पहले से ही अनेक प्रयास किये गये हैं। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ 'भौगोलिक' दृष्टि से निकट स्थित राष्ट्रों का एक ऐसे समूह से है जो इच्छाओं की सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से बनाया जाता है। इस समूह की शक्ति किसी व्यक्ति या राज्य दूसरे साधन द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार के एक समूह की जन्म देने के लिये इस क्षेत्र के देशों ने कई बार प्रयास किये हैं, अनेक सम्मेलन बुलाये गये तथा मितवर इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया गया। मई १९४७ में देहली में २२ मार्च में २ वर्षों तक एशियाई सम्मेलनों पर एक सम्मेलन बुलाया गया। इनमें एशिया के २४ देशों ने भाग लिया तथा एशिया की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जैसे एशिया में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, जातीय

1. "It has to be kept in mind that poverty, low standard of living and economic backwardness are problems of common interest, and the efforts and experiences in each country are bound to be of value to the others in the area faced with similar problems."

—India the Second Five Year Plan, New Delhi, 1956, P. 19-20.

2. "In any event, India's aversion to regional co-operation or integration in Asia is likely to be the least in the economic sphere."—Smt Gupta: India and Regional Integration in Asia, P. 105-6.

समस्याएँ, सामूहिक कार्य, वृद्धि एवं उद्योग आदि ।¹ इस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देने समय पण्डित नेहरू ने क्षेत्रीय सहयोग की महत्ता पर बड़ा ध्यान दिया था । इस सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में था कि एशियाई देशों के बीच सम्बन्धों के विकास का हमने शीर्षकोश किया । १९४५ में इण्डोनेशिया पर डचों द्वारा जो आक्रमण किया उसे एशिया बाहरी ने बड़ी गम्भीरता से लिया तथा इसे एशिया पर आक्रमण के रूप में माना । नई दिल्ली में इस समस्या पर विचार करने को सम्मेलन बुलाया गया । हममें करीब १३ देशों ने भाग लिया । सम्मेलन २० जनवरी १९४६ को बुलाया गया । इसके बाद बैंगलोर सम्मेलन (Bangalore Conference) बुलाया गया । भारत ने इस सम्मेलन में भाग लेने की जो धार्मिक रखी वह यह थी कि सम्मेलन केवल धार्मिक क्षेत्रों से ही अपना सम्बन्ध रहे । भारत को जब यह आश्वासन मिला गया कि सम्मेलन राजनैतिक मामलों पर विचार-विमर्श न करके केवल सामूहिक कार्यों से संबंध रहेगा तो भारत ने इसमें भाग लिया । १९३० में होने वाले इस सम्मेलन में करीब ९ देशों ने भाग लिया । इसमें सामूहिक क्षेत्र में सहयोग के प्रस्ताव पास किए गए । अगस्त, १९५४ में बोनम्बो में तथा, भारत, इण्डोनेशिया, बर्मा और पाकिस्तान जैसी कौलम्बो शक्तिपों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया । यह सम्मेलन मुख्यतः उपनिवेशवाद का विरोधी था । इस सम्मेलन में भारत-चीन स्थिति, हाइड्रोजन-बम का प्रश्न, अणुनिर्माण व मोरक्को के प्रश्न और सामान्यतः साम्यवाद के प्रश्न पर विचार किया गया । इस सम्मेलन के सदस्यों ने अलग अलग पहलुओं पर जोर दिया था । बर्मा ने साम्यवाद के सतरे में बचने के लिए अग्रिम सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, बर्मा ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने की मांग की, पाकिस्तान के अनुसार सम्मेलन को मुक्ततः बाइपोल समस्या पर ही विचार करना चाहिए था, पण्डित नेहरू ने इण्डो-पाकिस्तान तथा हाइड्रोजन के मसलों की महत्वपूर्ण माना जबकि इण्डोनेशिया एक अर्ध-स्वतंत्र-एशियाई सम्मेलन बुलाने की मांग पर जोर देने लगा था ।²

अगस्त १८ से २४, १९५५ तक एशिया तथा अफ्रीका के देशों का एक सम्मेलन वाशिंगटन (इण्डोनेशिया) में बुलाया गया । भारत सहित २९ एशियाई व अफ्रीकी देशों ने इसमें भाग लिया । इस सम्मेलन के परिणाम केवल अग्रणीयत्व ही न थे बल्कि आभा के विपरीत भी थे । हमने एशिया के देशों की विदेश नीति के बीच भारी अन्तरों की स्थापना की । पश्चिम समर्थक व विरोधी देशों के बीच का अन्तर बढ़ा । अग्रणीत्व की नीति पर धन देने वाले राष्ट्र भी कई राष्ट्रों की ओर घुटें गए । इस सम्मेलन ने चीन के मोरक्को की भारत की नीति पर बड़ाया । २४ अगस्त, १९५५ के न्यूयार्क दस्तावेज ने टिप्पणी की कि पण्डित नेहरू इस सम्मेलन की कार्यवाही की धरती इच्छा के अनुसार संघान्वित करने में समर्थ रहे । इस सम्मेलन में मुख्यतः आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक

1. Keesing's Contemporary Archives, 1947, P. 8362.

2. Keesing's Contemporary Archives, 1954, P. 13576.

नष्टयोग, मानवीय अधिकार व आत्म-निर्णय, परावर्त्यो व्यक्तियों की सम्मत्ता तथा विरव-गान्धि व नष्टयोग की सम्मत्ता पर विचार किया गया।

मई, १९५५ में १३ एग्जिडेंट देशों का एक सम्मेलन गिनता (नाम्न) में हुआ गया। इस सम्मेलन के विचार का प्रमुख विषय प्रमर्शजन सहायता का उपयोग, उपयोग में आने वाली कृत्रिमता एवं अन्य देशों प्रसार के आर्थिक प्रश्न थे। महा आता है कि इस समय प्रयोजन की हार्दिक इच्छा थी कि एग्जिडेंट में क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से प्राप्त हों। Harold Stassen इस सम्मेलन के प्रमुख प्रेरक थे। विलु प्रमर्श का आगाधों के अनुसार इस सम्मेलन के परिणाम प्राप्त न हो सके जैसा कि १३ मई के लुपार्क टाइम्स के सम्पादक का कथन है कि प्रमर्श का आगाधों की विचारों का कोई ऐसी योजना तैयार करेगी जिसमें आइजन्हावर फंड का नागरिक आधार पर उपयोग किया जा सके विलु गिनता सम्मेलन ने यह बताया कि एग्जिडेंट का कोई देश क्षेत्रीय योजना को स्वीकार नहीं करता, उल्टे करता है।

सितम्बर, १९६१ में पुन. एग्जिडेंट आर्थिक आयोगों का नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें क्षेत्रीय सहयोग की सम्मत्ताओं पर पुनर्विचार किया गया। इस सम्मेलन के जो सीधे उद्देश्य थे वे बारी छानित थे। इनकी प्राप्ति में यह सम्मेलन सफल रहा विलु क्षेत्रीय सहयोग के मूल मर्याद की प्राप्ति में यह कामयाब न हो सका। क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएँ—दक्षिण एग्जिडेंट का क्षेत्रीय एकीकरण करने के मार्ग में बाधाएँ हैं जिसका निराकरण किया बिना आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। इस क्षेत्र के देशों में अनेक निम्नतम विद्यमान हैं। क्षेत्र में एक मन का प्रभाव है, इस क्षेत्र के अनेक देश बाध्य शक्तियों द्वारा निर्मित एग्जिडेंट देशों की शक्तिशाली में बंधे हुए हैं। उनकी अपनी ही सम्मत्ताएँ हैं। इन क्षेत्र के देश राखनेतिर हृष्टि में स्थिर नया आगत में आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता में व्यवहार करने हैं। इन सब परिस्थितियों के हानि हुए क्षेत्रीय एकीकरण की कल्पना कुछ निराशा की प्रतीति होती है। इस बनना की निम्न के मार्ग में कुछ अन्य कृत्रिमता इस प्रकार है—

(१) इकाइयों की सममानता—इन क्षेत्र के देश नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक एवं अन्य गुणों में समान नहीं हैं। नेता व दलों जैसे छंटे व बन शक्ति वाले देश समान हैं, साथ ही भारत जैसे विद्यमान व शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र भी हैं। जैसा कि इन व्यक्तित्व जीवन में भी देखते हैं, मित्रता मर्याद दरार बाधा न हो होती है नहीं तो ऊँचता का भाव आगे दिया नहीं रह सकता। छंटे देशों को यह सच है कि बस देश क्षेत्रीय एकीकरण के नाम पर उन पर हाक न हो जब तक नहीं पुनः उनकी स्वायत्तता कोई छेद न ले। इनके अतिरिक्त भारत एक विशाल देश प्रत्यक्ष है विलु

1. "There is no friendship when nations are not equal, when one has to obey the other and one dominates the other."
—Jawahar Lal Nehru's Speeches, 1953-57, P. 290-1.

अमरीका की भांति यह आर्थिक व सैनिक क्षेत्र में अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया है कि अपना प्रभाव प्रयोग करके क्षेत्रीय सहयोग की स्थापना कर सके।

(२) आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता—आर्थिक दृष्टि से ये देश एक दूसरे के सहयोगी होने के स्थान पर प्रतिद्वन्द्वी हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों को बहुत कुछ आमान के सहारे ही जीवन निर्वाह करना होता है। इस दृष्टि से इन देशों के हितों में कई बार विरोध पैदा हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि यदि इस क्षेत्र का एकीकरण कर भी दिया जाय तो भी इन देशों के बीच इनके विचारों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। निश्चय ही एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के मार्ग की यह झुनझुन सीमा रेखा है।^१ मुद्रास्वर्तों में जब यह पुछा गया कि आप इटली या अमरीका जैसी बड़ी शक्ति में अपने की अपेक्षा आपस में मिल क्यों नहीं जाते तो उनका उत्तर था कि धूम्र और धूम्र और धूम्र मिल कर आर्थिक धूम्र के बराबर ही हो रहे हैं।^२ यह कथन इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि इस क्षेत्र के देशों के पास पर्याप्त साधनों का अभाव है। यदि एकीकरण भी हो जाय तो भी इनको बड़ी शक्तियों की सहायता की ओर तारना होगा।

(३) घरेलू झगड़े—इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के बीच किसी न किसी विषय पर संघर्ष होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर का झगड़ा एक घोरता-हीन युद्ध का कारण बन गया तथा दोनों देश सुन्दर के दो सिरों की स्थिति में आ गए जो कभी मिल सके बिना बचता नहीं की जा सकती। 'पाकिस्तान का भगदा अफगानिस्तान के साथ भी है, पानूनों की समस्या की लेकर। सजा और भारत के बीच सजा स्थित भारतीयों की लेकर कुछ मन मुटाव है।' इस मन-मुटाव व संघर्ष की स्थिति में इन देशों के एकीकरण की सम्भावना आगामी कुछ वर्षों में बिल्कुल नहीं सम्भावना की भांति आधारहीन है।

(४) राजनैतिक बाधाएँ—दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थित देशों के राजनैतिक रूपों में पर्याप्त भिन्नताएँ वर्तमान हैं। एक ओर बर्मा, पाकिस्तान आदि देश हैं जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध तानाशाही शासन में विस्तार करते हैं तथा इसी व्यवस्था में देश के आर्थिक (एक अन्य क्षेत्रों में) विभाग को परित्यजित करते हैं। समानता, स्वतन्त्रता आदि आदर्शों का इन देशों में कोई विशेष स्थान नहीं है। दूसरे ओर भारत जैसे देश हैं जो प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं और स्वतन्त्रता और समानता आदि आदर्शों की रक्षा के लिए धीमे प्रजातन्त्र के मार्ग को अपनाते में मजबूत नहीं करते।

1. "This indeed is a basic limitation on regional economic co-operation in Asia"

—P. S. Lokanathan. "Regional Co-operation in Asia," India quarterly, January March, 1951.

2. "Zero plus Zero plus Zero is after all equal to Zero."

— Prime Minister's Statement on Foreign Policy, 9 Dec., 1956.

इन देशों के राष्ट्रनीति-आदर्श भी भिन्न हैं। पाकिस्तान के बेनिट प्रजापत, भाग्य का समुदायक प्रजापत, मेसन की यथावत-व्यवस्था में कोई आधिक सम्बन्ध नकर नहीं आता। वर्तमान भारत-राष्ट्र-अर्थ में यह स्पष्ट हो गया कि आजादी और प्रजा-सत्तात्मक आदर्श साथ मिलकर नहीं रह सकते। एक दूसरे में भाग व फूट का सा नैर है। इस युद्ध में भारतीय जनता ने प्रजापत व धर्म-निष्ठतावादी अपने आदर्शों की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ की। युद्ध के दौरान डा० राधाकृष्णन् ने कहा था कि हमारा युद्ध प्रजापत व धर्म-निष्ठता के सिद्धान्तों के लिये है। हमारी विजय पर ही 'एशिया में प्रजापत का अविष्कार' निरंतर कहा है। नेपाल में लोकतन्त्र की स्थापना के लिये भारत की ओर से काफी प्रयत्न किया गया किन्तु कुछ वर्षों के अनुरोध परका यह अर्थ लगाया गया कि नागरिक नेतृत्व पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है।

(५) विदेशनीति में भिन्नता—इन क्षेत्र के सभी देशवासी एक प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण नहीं करते हैं। बड़े देशों पर इनकी विदेश-नीतियाँ भारत में स्वराज्य की भन्ना आती हैं। पाकिस्तान ने प्रारम्भ में ही वृद्धिवादी नीति का परिचायक कर दिया था। पाकिस्तान की विदेश नीति के दो प्रमुख तत्त्व प्रारम्भ में ही रहे हैं। (१) कश्मीर प्रश्न पर भारत को मुक्त करने के लिये वाय्य करना और कश्मीर को भारत से विच्छेद कर पाकिस्तान में मिलाव। (२) समस्त इस्लामी देश का नेतृत्व करना। ये दोनों तत्त्व सीधे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने हैं तथा दोनों देशों के बीच संघर्ष, मतभेद और यहां तक कि युद्ध का भी कारण बन गए हैं। नेपाल की विदेश नीति जैसा कि १९६२ में उन पर प्रकाश डालते हुए, टाकानासाद आचार्य ने बताया था, साम्यवादी चीन कम की नीति को अपना आदर्श मान कर बनी। बहने को तो भारत को यह विश्वास दिलाया गया कि नेपाल विश्व-शांति और-आतमसत्ता विरोधी भारत की नीति पर उनके चरण चढ़ने का अनुमति करने को तैयार है किन्तु अचानक में ऐसा नहीं किया गया। नेपाल और चीन ने साम्यवादी चीन के साथ सीमा-सम्बन्धी सम्मिलित की। इन सम्मिलितों में चीन का पक्ष कुछ और अधिक अर्थ प्राप्त करना न-होकर भारत को सीमा सुरक्षा देना था क्योंकि एशिया के अन्तर्गत पर सन्तुलनपूर्ण भारत की अभिप्राय चीन के एशिया का नेतृत्व करने के स्वयं को पुनः करने में बाधक थी। उक्त में साम्यवादी जाही सत्ता में मौजूद है और समय समय पर सरकार को नई समस्याओं में उत्पन्न का प्रदान करते रहते हैं। समित सिद्धान्तों अर्थ और नागरिक प्रजापतों की समस्या के कारण आया व युद्ध के बीच युद्ध के भाव हैं। अन्तर्निष्ठता और भारत की विदेश नीति अन्तर्निष्ठता की नीति है। ये देश जिन्हीं युद्ध या देश विदेश के साथ अपने आदर्शों वापना नहीं चाहते। साम्यवादी कम या नवने निष्ठतावादी पक्षों में सम्मिलित होने में मना कर दिया। भारत की इन अर्थियों का प्रारम्भ में ही विरोध किया रहा है। इन देशों

की यह नीति परिकरमान में जो वि सीएटो तथा सेन्टो का सन्धिय सदस्य है, मिश्र है। बर्मा भी तटस्थ नीति का अनुसरण करता हुआ साम्यवादी व बंर-साम्यवादी दोनों ही गुटों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास कर रहा है। इस मिश्रता के रहने हुये यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि कोई क्षेत्रीय मण्डल की स्थापना हो जायेगी।

अन्य समस्याएँ—क्षेत्रीय और क्षेत्रीय धर्मोक्तों की भाँति दक्षिण एशिया का क्षेत्र निर्धारित नहीं है। क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में चीन में प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्रीय जनता के मास्टरप्लान, शान्ति, जनतीय जीवन में कोई समानता नहीं है। इन देशों में परम्परागत भूस्वयं तथा अन्य स्वामि अधिकारों के अनुसार भी परम्परा निवृत्तता की अभिवृद्धि नहीं होती। इस क्षेत्र के वर्तमान बौद्धिक वर्ग की श्रद्धा भी एकीकरण की ओर नहीं है। योरोप की भाँति अफ्रीका के देशों का आकार एवं मा नहीं है। इस क्षेत्र में कोई देश इतना सक्तिमानो व समर्थ नहीं है कि जो अपनी आर्थिक शक्ति व सैनिक सामर्थ्य को क्षेत्रीय मण्डल के निर्माण में प्रयुक्त कर सके। यदि इस क्षेत्र के सभी देश मिल जायें तो भी किसी बड़ी शक्ति के आक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहेंगे। इस क्षेत्र के देशों में मजदूर के मापन अधिक सन्धिय नहीं है। राजनैतिक दल एवं प्रभावशाली समुदायों के बीच अधिक सम्बन्ध नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों के बुद्धिमान वर्ग में व्यावहारिक दृष्टि में समस्याओं पर विचार विनिमय नहीं होता। राजनैतिक व्यवस्था, मूल्य और विचारों की दृष्टि में इस क्षेत्र के देशों में पर्याप्त भिन्नता वर्तमान है। आर्थिक व सामाजिक आदर्शों में भी उनका ही अन्तर है। विदेशनीति के क्षेत्र में समानता, समझना और साम्यवादी-सोचों ही नीतियों में विस्वास करने वाले देश इस क्षेत्र में स्थित हैं। समानता में विस्वास रखने वाले देशों के विचारों में भी एकता नहीं है। राष्ट्रों के बीच परस्पर काफी मध्यम के तत्व वर्तमान हैं। क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि इस क्षेत्र के अधिराज्य राज्य हाल ही में राष्ट्र राज्य के रूप में उदित हुए हैं। इस स्थिति में यह सम्भव नहीं है कि राष्ट्र भक्ति के स्थान पर ये देश क्षेत्र मात्र चिन्तित कर सकें। आर्थिक क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण में होने वाले लाभों के प्रति छोटे देश समान रूप में जागरूक नहीं हैं। छोटे देशों को डर है कि बड़ी बड़े देशों की प्रयुक्त स्थापित न हो जाये। इन देशों की आर्थिक स्थिति मध्यमोत्तरी न होकर प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण है। नाथमियर पेफर का यह मत है कि विश्व राजनीति में एक प्रभावशाली द्वाद्वी के रूप में दक्षिण-पूर्वी एशिया नाम की कोई चीज नहीं है। यह तो स्वयं के उस स्थान पर स्थित है जहाँ कुछ समुदाय छोटी बहुत समानतायें रखते हुए पाल-पाल रह रहे हैं।¹

1. "In short South East Asia is not a region that can be conceived as an effective entity in world politics. It is a place in the globe where certain groups of people, holding little in common, live contiguous to one another."

—Nathaniel Peffer, "Regional Security in South East Asia", International Organisation, Aug. 1954.

क्षेत्रीय संगठन पर प्रभाव डालने वाले तत्व—अन्तर्राष्ट्रीय पटन पर अनेक ऐसी घटनाएँ पड़ी व परिवर्तन हुए जिन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को प्रभावित किया। साम्यवादी चीन का एशिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उदय ऐसा ही एक तत्व है। कोर्टे मो क्षेत्रीय संगठन बनाने समय, मुख्य प्रश्न यह आने लगा कि क्या चीन को इसमें सम्मिलित किया जाय ? यदि नहीं, तो एक बड़ी शक्ति के विरोध का भय था और यदि हाँ तो उसके प्रभाव बढ़ने का भय था। चीन के उदय ने इन क्षेत्रीय संगठनों के रूप को आदिष्ट व सामूहिक के स्वरूप पर सँतित बना दिया। यह रूप भाग्य की रचि के अनुकूल न था। चीन ने एशिया में अपना प्रभुत्व जमाना प्रारम्भ कर दिया। एशियन गैरसम्यक् राज्य सम्मेलन में ही चीन ने भाग्य के साथ शक्ति की प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ कर दी।¹ एशिया एवं अफ्रीका में अपना प्रभुत्व जमाने की दृष्टि में ही चीन ने भाग्य पर १९६० में आक्रमण किया। चीन ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध लड़ना कर इसकी शक्ति का स्थिति करना चाहा। दक्षिण एशिया के देशों के दिनों में चीन का एक हमला हो चिन उभरा गया व साम्यवाद के निरुद्ध भाये। चीन ने माठ माठ कर कश्मीर को हमला करने का पाकिस्तान को प्रेरणा प्रदान किया। उनसे पुनर्गठित भेड़ का कश्मीर में विद्रोह करने का प्रयत्न प्रभाव दिया और बाद में सम्यक् आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के आक्रमण के समय दक्षिण एशिया के देशों का जो एक गठन उसमें क्षेत्रीय संगठन की स्त्री-महो सम्भावनाओं पर भी आधारित कर दिया। पाकिस्तान ने भूमि-समन्वित राज्य भारत की विमान भूमि-गति की चीन की नीति ही है। भाग्य-आह समय में ही चीन ने भारत का आक्रान्ता बनार कर पाक के प्रति आ महासुनिपूर्ण खेला अनायास अपने भारत के दिन में पाकिस्तान के प्रति ख-मह गन्ध की भी माफ़ कर दिया।

दक्षिण-एशिया क्षेत्रीय संगठन के विकास—दक्षिण एशिया क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग की बाधाओं की देखभाल अनेक नेत्रों द्वारा यह मुनासब दिया जाता है कि भारत-पाक का एक मजबूत बना दिया जाय। इस उपन्यास की दृष्टि से भारत की दिशा में अग्रसर होती। यद्यपि इन मजबूत के निर्माण के मार्ग में भी अनेकों बाधाएँ हैं किन्तु इसमें होने वाले लाभ भी महत्त्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान इस मजबूत में बहुत लाभान्वित हो सकेगा। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच समुचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भारत के सहयोग की मांगी आवश्यकता है। भारत-पाक मजबूत के सुनवाई का मजबूत है कि शक्ति, सम्पत्ति, भाषा, धर्म, पश्चिम, पश्चिम निर्भरता, मजबूत-भाषा, आदि व सैनिक महाद्वारा पर निर्भरता अर्थात् दोनों को समानता किन्तु भारत व पाकिस्तान में पार-

1. "The Chinese had no wish to be tied to an organisation in which India was predominant. Their tactics at the Conference was to keep India's status within bounds. No more did the Indians wish to surrender any power to the Chinese."

—Lia, Warrar, Free India in Asia, P. 39

जाती है उसको इस क्षेत्र के बिन्ही दो देशों में नहीं पाई जाती। सदियों तर दोना ही देश का इतिहास एक दूसरे के सभ में समान स्तरों पर प्रवाहित हुआ है। देश के विभाजन द्वारा साम्यदायित समस्या को न गुनगाया जा गया और न ही इस क्षेत्र में स्थिरता की प्रतिष्ठापना की जा सकी।

भारत-पाक सभ के महत्व पर ये दोना ही देश सहमत थे किन्तु इस सभ के हार, व्यवहार आधार आदि के बारे में मतभेद नहीं रह गया। पाकिस्तान की वर्तमान विदेश एक स्वदेश नीति का ये रहन हुए इस सभ के पक्ष के कोई आधार नजर नहीं आता। यद्यपि भारत-पाक युद्ध के वर्तमान बवण्डर को रोकन के लिए सभ निर्माण कर बाड लयात का शुभास देने वालों की धन भी कमी नहीं है किन्तु इनको लगाने का गारा निमी के पास नहीं है। एत माधन पाकिस्तान न माचा था। काश्मीर में प्रिडोह पगते सर्वप्रथम उम अधिष्ठित किया जाय। बाद में जमना एत के बाद एक भारतीय दवावे की अने हाथ में ले लने के बाद दिनी के तान निने के निरने की बाद गितरा की छान दे दी जाय। इस मार्ग से पाकिस्तान भारत को घिटा कर पूरे उपमहाद्वीप पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था जगा कि अर्न्त में उपने पुराने भी कर चुके थे। पार की यह पान सजन न हो सकी। अरबी संनित शक्ति का बरौद करने, भारत मुनकी आन्दानस मनाने, अन्तर्राष्ट्रीय माध्याम से गान्धीयता करने के अनिर्ण यह कुछ भी न कर पाया। कमोचता और ताताभाती ये पाकिस्तानी नीति के दो पक्वार हैं जो अघित समय तर निरन्तरतर में उम स्थित रहने में अममर्ष हैं, निनारे पर पहुँचने का भी प्रदत ही नहीं उल्ला।

साम्यविश्वास तो यह है कि भारत-पाक सभ भी सम्भव नहीं है। इनके मार्ग में ये सभी वर्तमानदा हैं जिनका दक्षिण-एशिया एकीकरण के प्रलय में हम जान चुके हैं। इनके अनिर्ण आता देश विभाजन की १५ वर्ष का सम्या समय बीत चुका है। इस बीच दोना देश की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य स्थितियों में बहुत अन्तर आगया है। अनेक क्षण में यह समझा जाता है कि भारत-पाक को मिटाने का यदि कोई प्रयास किया गया तो सम्या परिणाम होगा अथवा हमलाओं की पुरातुति।¹

पाकिस्तान के अनिर्ण एत दुनरा छोटा क्षेत्र दक्षिण एशिया में है जिनके बारे में एंड्रोय लवीकरण के संभाव दिखे जात है। कहा जाता है कि हिमालय के निरन्तरों भाग नेपान बूटान और तिब्बत एत पश्चिम के सभ में अन्त आरत स्थिति करने।

1. Any attempt to reintegrate India and Pakistan might regenerate the kind of politics in the subcontinent which had led to mass violence and a collapse of sophisticated politics."—Sisir Gupta, *India and Regional Integration in Asia, 1964*, P. 109.

चाहते हैं कि बन्धुत्वनि ज्यों की त्यों बनी रहे ।¹

क्षेत्रीयता की पूर्ण आवश्यकताएँ होती हैं जैसा कि द्वाइया का एक सा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, साधना की बमो तथा बाजारा का अभाव आदि से पूरा आवश्यकताएँ दक्षिण एशिया क्षेत्र पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होती और इसलिए क्षेत्रीय एकीकरण एक अव्यावहारिक स्थिति है जो कुछ मध्यस्थता की प्राप्ति के लिए की गई है किन्तु निरापार है ।

(२) सरकार का विरोधी—किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय संगठन हा, वह निम्नय ही विश्व सरकार के साथ म एक बाजा का कार्य करेगा । क्षेत्रीय संगठन की द्वाइयो के सामने विश्व की ओर उन्ने अगले क्षेत्र का हिन प्रधान रहना और इन प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के जो दुष्परिणाम गिनाये जाते हैं वे सभी इस क्षेत्रीय एकीकरण की योजना पर भी उन्ने ही बरन उमसे सम्भोर रूप से लागू होने हैं । जी० डी० एच० कोन तथा बाल्टर निमैन ने इस प्रकार के क्षेत्रीय संगठना की विश्व सरकार की दिना म ही एक अगला कदम माना है किन्तु नेहरू ने इस प्रकार के विचारों की भूमों का प्रभाव स्वीकार किया उनका विचार था कि जब तक कि शक्तिशाली विश्व मध्य द्वारा ये क्षेत्रीय संगठन एकीकृत न हों वे इस विचार का समर्थन नहीं कर सकते । उन्ने मनातु-सार स्थानीय स्वायत्तता से पूर्ण इस प्रकार के बड़े राज्य का निर्माण करने विश्व की एवता व विश्व संगठन की सम्भावना का मिटाना एक भ्रमना पूर्ण कार्य है ।²

(३) मानवता के विरुद्ध—दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एकीकरण कुछ बिबान्तों के मनातुसार मानवता के मिटाना के विरुद्ध होगा । आज के अणु-युग में मनुष्य की शान्ति की आवश्यकता है । यह युद्ध की विभीषिताया से बचकर सम्पत्ता व मनुष्यता नाम निगान मिटा देने वाली प्रवृत्तिया से बच कर भाइयारे, मह-प्रतिक्रम, महयोग और शान्ति में जीवन यापन करने की दाह म है । इसीनिसे समय की आवश्यकता के अनु-सार मानवता विश्व सरकार की आवश्यकता करती है । किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय

1. "The Asia Conference showed that Asia would rather have things go on as they are then try any of those new fangled regional ideas"

—New York Times, 13 and 14 May, 1956

2. "For my part, I have no liking for a division of the world into a few huge supranational areas unless those are tied together by some strong world bond. But if the people are foolish enough to avoid world unity and some world organisation, each functioning as one huge state but with local autonomy, are very likely to take shape."

—J. S. Bright (ed.), Before and After Independence, New Delhi, 1950, P. 279.

भारत में राजकीय राजनीति (STATE POLITICS IN INDIA)

रमेश प्ररोडा

भारतीय संविधान को साधारणतया एक अर्धसंघीय (Quasi federal) संविधान की श्रेणी दी जाती है। परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण यद्यपि भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त विषे प्रायः १८ वर्ष तथा भारतीय संविधान को स्वीकृत हुए प्रायः १५ वर्ष पूरे हो चुके हैं किन्तु उसकी मूल्य प्रकृति के विषय में स्पष्ट निर्दिष्ट मत दिया जाना पड़ता है। सामान्य में संघीय संविधान भारत में एक राज्य संघीयता की भाँति माना विविधताओं में परिपूर्ण एक राष्ट्र है। महान् भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, एक सामाजिक विभिन्नताओं के हान हुए भी स्वतन्त्रता प्राप्त के अन्तर्गत ही भारत में एक राजनीति अपना एक स्थिरता का एक मूल्य सम्पदक हुआ है जिसकी ममानता एतिया और समीक्षा के अन्तर्गत नवजात राष्ट्र में मरतता में उपलब्ध नहीं होती, जबकि विविधता में एकता (Unity in Diversity) का ममान्यतादी सिद्धांत भारतीय सामाजिक ढाँचे की एक विशेषता है। उसकी श्रेणी ही एक स्पष्ट प्रमाणों का भारत की राजनीति प्रमाण करती है, विशेषकर वह राजनीति जिस प्राथमिक राजनीतिशास्त्री 'राजकीय राजनीति' (State Politics) कहते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्त के तुरन्त पदार्थ ही केन्द्रीय सरकार के राज्य मन्त्रालय (Ministry of States) ने मोह पुष्प मन्दाव अन्तर्भाषा १९५० के कुछ केन्द्र में भारत की ५६५ देशी विभागों के एकीकरण का प्रश्न हाथ में लिया और संविधान के अनुच्छेद ६ में राज्य (A States), ८ में राज्य (B States) और १० में राज्य (C States) देने। तुरन्त ही इन सूची का ममान्यता दिया गया। 'यूनाइटेड प्रोविन्स' (United Provinces) का नाम बदल कर 'उत्तर प्रदेश' रख दिया गया। 'पूँच बिहार' के स्थान पर 'विन्ध्य प्रदेश' की 'म' श्रेणी में रखा गया और 'अन्धप्रदेश निरोबार' श्रेणी को 'द' श्रेणी (D States) में स्थान दिया गया। इन राज्यों की कुछ मन्त्रालय उग ममान्यता कर २८ पर पदार्थ गई जबकि तत्कालीन मन्त्रालय राज्य के उत्तरी भाग को वाटनर सन् १९५३ में प्रथम भाषाई राज्य का निर्माण किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की विचारों के अनुसार १९५६ में भारतीय संविधान में मान्यता ममान्यता पारित हुआ

श्रीर नरसिम्हा १ नवम्बर १९१६ में भारत का मानविक मौखिक रूप में नया बनकर सामने आया। राज्यों को 'अ' 'ब' 'ग' श्रेणियों को समान कर समान स्तर के १४ नये राज्यों की स्थापना की गई। ४४ पुनर्गठन सुझाव, भाषाई राज्यों की स्थापना जैसे भारत के विभिन्न भागों में वन यह आन्दोलनों के फलस्वरूप प्रभाव में आया गया। उनका अर्थवाद केवल दम्पट नया पत्राव ही थे। जून १ मई, १९६० को गृहमन्त्री भारी एवं भारी भाषी जनता के आसानी विवादों और हिंसक आन्दोलनों के दबाव में आकर दम्पट राज्य के दो भाग (महागण्ड व गृहगण) कर दिए गये। बाद में १ दिसम्बर, १९६३ को लागू के एथर राज्य के रूप में दोन जिलों में भारत में राज्यों की संख्या १६ हो गई है। वर्तमान भारत में उन राज्यों के अतिरिक्त बिन्नी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुरी, मिजोर, पाँचगै, मेघा, दमन व दीव, छत्तीसगढ़ निगोवा द्वीप, मेकेश्वर, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश और तथा दादरा व नगर हवेली (कुल २) केन्द्र प्रशासन प्रदेश हैं।

भारतीय रूप में राज्यों का अर्थ स्थापन है, किन्तु केन्द्र की गता और महत्व निर्विवाद है। सर्वप्रथम दृष्टि में भारत एक नव है यद्यपि मध्य राज्य की परम्परागत महान् प्रकृति को परिष्कृत एवं समोचित करने वाली अनेक 'व्यवस्था' को अपने स्वीकृति है।^१ व्हेयर (Wheare) ने भारत को एक ऐसे एकात्मक राज्यों की श्रेणी में रखा है जिनमें मध्यमक राज्य के गौणत्व की विद्यमान है।^२

जिन्नी की मध्य में अधिकतर सर्वप्रथम प्रश्न केन्द्र व उनकी इकाइयों के भाग्य, कार्य एवं अधिकारों में अतिष्ठ रूप में उदभूत होते हैं। धार्मिक सविधानों के अन्तर्गत प्राप्त सभी में केन्द्रोत्तरा की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। भारत में भी केन्द्रीय सरकार की सुनिश्चित रूप में जितने ही अधिकार दिए गए हैं, और स्वतन्त्र प्रांत के बाद के १५ वर्षों में इन अधिकारों का उपयोग भी किया गया है।

मुद्रित अनेक राजनीति शास्त्री नामक डॉ० पानर के अनुसार, "भारत एक वैधानिक मध्य की अनेक एक प्रशासनिक मध्य का उदाहरण है जिसे ऊपर से पोसा गया है न कि नीचे से।"^३ वास्तव में भारत का नया संविधान सन् १९३५ के भारतीय

1. "The Republic of India is a federation, although it has many distinctive features which seem to modify the essentially federal nature of the State."—Palmer, Norman D. : The Indian Political System P. 94.
2. Prof. Kenneth Wheare classified India as "a unitary state with subsidiary federal principles rather than a federal state with subsidiary unitary principles." Quoted in Alan Gladhill, "The Republic of India," P. 92.
3. "India is an example of administrative rather than contractual federation. It was imposed from above, not from below." Palmer—Indian Political System, P. 95.

प्रधिनियम (Government of India Act, 1935) पर ही बानी गीमा तब प्रागर्तित है। इस कानून के निम्नान्त हमारे पूर्वनामक अध्याय के न कि भारतीय। गणिशाता केन्द्र की स्थापना की परम्परा इसी अधिनियम के अन्तर्गत होती गई। १९५० का भारतीय महासभा केन्द्र को अध्यायिक शक्ति देता है परन्तु केवल इसी एक कारण से दिल्ली सरकार की शक्ति बढ़ी हो एसी बात नहीं। १८ वर्षों की स्वतन्त्रता के अनुभवों ने इस प्रवृत्ति का पर्याप्त रूप में स्पष्ट किया है। प्रधान मन्त्री नेहरो के विशाल व्यक्तित्व का प्रभाव एवं कांग्रेस दल का उभयमुखी राज्यों में मुक्त हस्त के परम्परारूप केन्द्र की शक्ति में विद्यमान दृष्टि में आशाजनक वृद्धि हुई है। एक नया तथा एक दल की छत्रछाया में भारतीय सभ सङ्गठन रूप में ही केन्द्र का पर्याप्त शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो सका है। दूसरे माथ ही अध्यायिक नियोजन, सभासद सुधार, विनायक प्रणामन तथा विद्वानों, महत्वाकांक्षी तथा अन्य जनक स्पष्ट प्रभाव के परम्परारूप केन्द्र की बढ़ती हुई शक्ति और भी बढ़ी है। इन सभी महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक अवशिष्ट महत्त्वपूर्ण कारण यह रहा है कि राज्यों की अपने अध्यायिक साधना की प्राप्ति के बहुत बड़े भाग के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है।

केन्द्रीयकरण के इन सब तत्त्वों के मध्यम रूप में परवाना भी भारत में विकेंद्रीकरण की शक्तियाँ भी कम शक्तिशाली नहीं रही हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान पॉल एपेलबी भारतीय प्रणामन का अध्ययन करने समय इस बात पर अध्यायिक आश्चर्यचकित हुए थे कि भारत में एक केन्द्र की राष्ट्रीय योजनाओं की क्रियाशक्ति के लिये राज्यों पर कितना अधिक निर्भर रहना पड़ता है तथा नीति एवं प्रणामन के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों में केन्द्र राज्यों की तुलना में कितनी कम वास्तविक शक्ति रखता है।^१ अन्तर्गत की पुष्टि करते हुये डा० एपेलबी ने किया है कि भारतीय राज्यों में कांग्रेस दल की शीर्ष शक्तियों के गठन बढ़ जा रहे हैं और प्रांतीयता, प्रादेशिकता तथा भाषावाद आदि शक्तियाँ जहाँ पकड़ रही हैं जिनके आन्दोलनों में राष्ट्र की एकता के अस्तित्व को खतरा है। वास्तव में भारतीय सभ की महत्त्वपूर्ण समस्याएँ जैसा कि बैजामिन शोन्फेल्ड ने कहा है कि उन और ता वह मुक्त केन्द्र है जो कि देश की राजनीति एवं अध्यायिक समस्याओं को मुक्त सवे किन्तु दूसरी ओर प्रादेशिकता में उत्पन्न व सघर्ष हैं जिनमें सारा राष्ट्र सम्मिलित रूप से अस्त है।^२

१

1 Paul H Appelby, 'Public Administration in India Report of a Survey' (1953) pp 16-17.

2 "The problems which Indian federation faces stem from the needs of her people to have a central Government armed with sufficient powers needed to solve modern economic and political problems on one hand and the strong sentiments of regionalism found throughout the land" Benjamin N Schoenteld—Federalism in India (1960) p. 21.

श्री नेहरू ने कहा था—“कांग्रेस दल निर्बल है और अधिका निर्बल बनता जा रहा है। हमारी शक्ति अब केवल चुनाव है। यदि हम उस शक्ति से नहीं निकलते तो कांग्रेस दल समाप्त हो जाएगा।”¹ इस प्रत्यक्ष अवसर पर उन्होंने इस स्पष्ट कथन द्वारा कहा था कि कांग्रेस दल के आंदोलन की वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या है कि नगर, विधानसभा व प्रादेशिक स्तर पर कांग्रेस समिति का अनुशासन से कार्य कर रही है।²

वास्तव में यह सच है कि देश में प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का आंदोलन कम हुआ है। इसके प्रमुख कारण हैं—कांग्रेस सदस्यों का अलग-अलग वर्गों को न निभाना, उन जातों व मंडल के लोगों में विमुख रहना, आन्ध्र व प्रान्त के जीवन में फँस जाना, जन-मन में का निराशा, आन्धी घुट, शक्ति के लिए दंड-धुर तथा अन्ध-निष्ठा व अंध श्रद्धा प्राप्त। वास्तविकता में कुछ मात्र पर कांग्रेसी नेताओं व अन्धी श्रद्धा को चुनावों के विषे आन्दोलन का सहारा दिया जाना यह आन्दोलन किसी भी प्रकार में इस अवस्था को सन्तुष्ट नहीं कर सका है या कि अपने अधिकारों के विषे दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। प्रादेशिक स्तर व ईश्वर के कारण कांग्रेस के नेताओं का ध्यान अपने वास्तविक कार्य में हट कर मजबूत व गंभीर समस्याओं की ओर केन्द्रित हो गया है व इनके परिणामस्वरूप कांग्रेस की शक्ति व समर्थन का शीघ्र-शीघ्र विखण्डन हुआ है। राष्ट्र के सर्वोत्तर में उत्तम वातावरण के माध्यम से सचिवालय केन्द्रीय कांग्रेसी नेता अपने दल में हैं परन्तु उनकी मजबूत स्थानीय व प्रादेशिक स्तरों तक नहीं उतर सकी है। मई १९५७ के आम चुनावों में १९११-१२ की अंशदा सचिवालय राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस दल की स्थिति सुधरी, परन्तु राज्य विधानसभाओं में इस दल को २०० न भी अधिक सीटों में हाथ धोना पड़ा। १९५७ में आठ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व चुनावों में भी कांग्रेस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। मुख्य रूप से मध्यवर्ग व अधिकांश इस दल के अनुचिन्तक नहीं रहे और लोगों में भी गिरावट का ने इस दल को अपना मनपसंद बन दिया। यह बात निश्चित है कि राज्यों में कांग्रेस की शक्ति का आधार राष्ट्र के राज्याधीन कांग्रेसी नेता ही रहे। राज्यों की जनता ने अपने अंध कांग्रेसी नेताओं की श्रद्धाओं को चुनावों के समय नेहरू के नाम पर डूबा दिया, परन्तु ऐसा हर समय नहीं हुआ। १९६३ में मसानी, गोरिया एवं कानूनी कांग्रेस के निर्वाचनी नेताओं को हरा कर लोकप्रियता के विषे निर्वाचित हुए थे। परन्तु यह भी सच है कि १९६० के आम चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवारों ने नामपसंदी बड़े दलों

1. "The Congress Party is weak and getting weaker...Our strong point is the past. Unless we get out of our present mood, the Congress Party is doomed".
2. "If the Congress was losing respect and regard in the eyes of the people and getting a bad name, it was because of the inefficient functioning of the Congress Committees at the city, district and provincial levels".

के उच्चतमोक्ति में नेताओं को इंगित किया था। यह दृष्टि मिट्ट बरना है कि इन एवं व्यक्तिगत मंजूर पढ़ने इन का महत्त्व था घन था घन व्यक्तिगत का महत्त्व और भी अधिक हो गया है।

कारण इन की शक्ति बर्धन राज्या में समान नहीं रही। केवल, मध्य प्रदेश, उत्तीमा मनुपूर्व सम्बन्ध प्रान्त राजस्थान में इनके अपने उदाहरण बड़ा भी देखे हैं। इन उदाहरण बड़ा मंजूर हो जाता है कि कारणों की शक्ति अब उनमें ऐतिहासिक महत्त्व में नहीं चुनी हुई है वरन् उसी मरियवा एवं मगदोन में सम्पन्न होती जा रही है। यह भी निश्चित है कि अनेक मगदोन का प्रभाव भी कारणों की शक्ति पर पड़ा है। मगदोन व मगदोन में कारणों की मुख्य शक्ति का कारण इन राज्यों में अनेक नैतिक व मगदोन ही है। परन्तु जिन जिन राज्यों में कारणों में मगदोन की रही है, वही इन की शक्ति कम हुई है व उसी प्रतिष्ठा को भी धरता गया है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान, पंजाब, उत्तीमा गुजरात, मैसूर, केरल आदि राज्यों में इन इन को प्रान्तीय फूट के साथ में मर्यादित किया गया है। इन मर्यादों के जतना के समझ अपने पर इन के प्रति जनता की श्रद्धा निश्चित रूप में कम हुई है। प्रान्तीय मगदोन के कारण प्राशस्तिक नेता अपने मौखिक बर्धन की ओर उचित ध्यान व आवश्यक समय नहीं दे पाते। शक्ति विनाश के इन शक्ति पर में पूरा इन पैसा हुआ है और विरोधी के अहित के साथ-साथ इनके महत्त्व अपने इन का घटन भी कर बैठने हैं। ऐसे उदाहरण कई बार आये हैं जबकि चुनाव में अपने ही इन के एक उम्मीदवार के विरुद्ध एक प्रमुख कारणों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। अगस्त कारणों की एक नई जमाने मारे देन में उत्पन्न हो गई है। इनकी शक्ति पूर्णतः में जबकि विन्डोटेक कार्यवाह्य में ही सम्पन्न हो जाती है तो हमारी ओर 'मगदोन' कारणों की शक्ति इनकी दधाने में व इनमें सुरक्षित रहने में लपट हो जाती है। दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कारणों भी पदों के पीछे इन छोटे मर्यादों की उम्मीद रहे हैं और इन कारणों में कारणों का वैश्वीय उच्च बर्मान भी इन विरोधी का उम्मीद करने में आनन्द प्रमथ्य रहा है। दोनों गुटा के पीछे मर्यादों की शक्ति रहती है व इनकी भी अग्रगण्य करने का सर्व इन की शक्ति को पदाना बन जाता है। इन के अन्दर ही 'विन्डोटे' की स्थिति पंजाब व केरल में महा लक्ष पहुँच चुकी है कि इन दो राज्यों में 'शाय' (Shadow) कारणों इन इन में ही और केरल राज्य में सर्वोच्च कारणों हार का कारण भी कारणों की इसी प्रान्तीय फूट में देखा जा सकता है।

उक्त उदाहरणों के अलावा कारणों इन अपनी प्रतिष्ठा को इन कारण भी महा बँटा है कि यह महात्मा गांधी व अन्य महात्मा कारणों नेताओं के द्वारा दिये गये नैतिकता के उच्च धारकों का पालन नहीं कर सारा है। चुनाव में जानि, भाषा आदि भाषा के इन पर अपने कारणों महत्त्व प्रादेशिक व स्थायी स्तर पर चुनाव जीतते हैं। इन ती

यह है कि इनको चुनाव का प्रत्यागी (Candidate) बनाने समय इन बातों का भी ध्यान रखा जाना है। शक्ति के निम्ने धन का प्रयोग किया जाना तो कांग्रेस के साथ इन स्तरों पर जुड़ ही चुका है। इन्हीं कारणों से सामान्य जनता के हृदय को जीत सकने में यह दल आज पर्याप्त रूप में असफल रहा है। बेरन में मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन ने मित्र कर दिया था कि कांग्रेस दल अवसरवादी है और अब कांग्रेस आदमवाद का ज्वन नारा ही नहीं लगाने, बरन् व्यवहार में भी शक्ति की पुर्जारी बन चुकी है। आज शक्तिशाली व समर्थित विरोधी दल के अभाव में इस दल का सत्ता में च्युत नहीं किया जा सकता। नतीज तो यह है कि कांग्रेस को अपनी मौजिम उक्ति वम है, विरोधी दलों की भौतिक दुर्बलता अधिक होना ही इसकी शक्ति का स्रोत है।

कांग्रेस दल 'समाजवादी समाज की स्थापना' अथवा 'जनतन्त्रशासन समाजवाद' के प्रति निष्ठा का दावा करता है। दो साम्यवादी दलों के बीच प्रजा समाजवादी व समुक्त समाजवादी दल ऐसे हैं जो कि समाज में विकास लेकर चलने हैं। साम्य में कांग्रेस, समुक्त समाजवादी व प्रजा समाजवादी दलों के बीच मैदातिका मतभेद गण्य है। तीनों दलों के सभी प्रमुख सदस्य मूल रूप में कांग्रेसी ही थे। व्यक्तिगत रूप से लोगों ने ही मुख्यतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचान इन दलों को जन्म दिया। प्रजा समाजवादी व समुक्त समाजवादी यद्यपि लगभग एक ही दृष्टिकोण रखते हैं, परन्तु ये दोनों दल सगठनों में पृथक् हैं। राज्यों में इन दलों की शक्ति मृदु है। कुछ मोटों खाना या पाना ही इनके विषय की घटती बटती कहानी है। अपनी शक्तियों को पारम्परिक ढंग में समाप्त करने के फलस्वरूप यह दल कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं बन सके। प्रजा-समाजवादी दल जो कि विनी समय कांग्रेस का स्थान लेने के लिए प्रयत्न वन गमना जाता था, देश के बुद्धिजीवी शिक्षित समुदाय की सहानुभूति और समर्थन के बावजूद भी आगे न बढ़ सका। राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी, आदर्शों, सगठन व व्यावहारिक नीति के सम्बन्ध में विचारों के अंतर की कमी, भागीय राजनीति में अपने कार्य पत्र महान की सही प्रकार न समझना तथा आपत्ति व दल के आन्तरिक विद्रोह के समक्ष हुए मान बैठना ही प्रजा समाजवादी दल के ह्योन्मुख रहने के कारण रहे हैं।¹ इस दल की प्रमुख शक्ति बिहार, मध्यप्रदेश, मैसूर व उत्तर प्रदेश, केरल तथा उड़ीसा में है।

1. "The party's crisis have been those of the national leadership the party's inability to communicate effectively with the secondary echelons and the membership concerning the changes desired in ideology, organisation, and strategy, its failure to assess correctly, and adhere consistently to a given role in Indian politics, and its failure to maintain its own cohesion in the face of public adversity and party rebellion."—Thomas A. Rusch. "Dynamics of Socialist Leadership in India," in Park and Tinker, eds., *Leadership and Political Institutions in India*, pp. 204, 208.

समूह समाजवादी दल का प्रमुख शक्ति केन्द्र बिहार, मध्यप्रदेश, व उत्तर प्रदेश में देख जा सकते हैं। दादा दत्ता ॥ निम्नलिखित रूप में प्रजा समाजवादी दल की शक्ति अधित है। तृतीय घाम चुनावों में प्रजा समाजवादी दल ने राज्य विधानमण्डल की १४६ सीटें जीती जहाँ समाजवादी दल ने केवल ७१ सीटें पर जीता किया।

भारतीय राजनीति में एक नये अनुदार दल का जन्म सन् १९५६ में हुआ। इस वर्ष जनवरी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित गृहमंत्री कृषि से सम्बन्धित प्रस्ताव की प्रतिप्रिया स्वरूप यह दल जन्मा। कांग्रेस दल की समाजवादी नीतियों के विरोध के लिए हमने नया मोर्चा धारित। व्यक्ति की स्वतन्त्रता, निष्ठा, व्यवसाय, व उच्च प्रतिभागिता के सिद्धांतों पर आधारित इस दल का जन्म वास्तव में स्वतन्त्रता के १२ वर्षों के बाद व भारत में गर बिचित्र सी घटना थी। वैसे तो जनमत भी प्रारम्भ में ही ऐसे सिद्धांतों का पक्षपाती और प्रतिपादक रहा है, परन्तु गुप्त प्रचारण व अनुभवों नात्व के कारण यह दल कुछ राज्यों में गुप्त घुसने की भाँति राजनीतिगत शक्ति पर प्रकट हुआ है। स्वतन्त्र दल का शक्ति उन्ही प्रांतों में मिली जहाँ स्वतन्त्रता में पूर्ण राजाओं व सामन्तों का शासन था और जहाँ यह वर्ष अभी भी शक्तिशाली है। इस दल के समस्त वितीय साधनों के अभाव की समस्या उपस्थित ही नहीं हुई तथा पूँजी पतियों के सहयोग के कारण यह काफी शक्तिशाली बनना सफल गया। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मंगूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में हमने विधानमण्डल के लिए १०१२ प्रत्याशी लड़े किये, जिनमें से १६६ की विजय हुई। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में हमारा उत्साहजनक सफलता मिली। यह दल अपने परम्परावाद के आकर्षण के बावजूद भी जनता का उत्तम समर्थन प्राप्त नहीं कर सका है जितना कि इसका भय था। उनके पास एक निश्चित कार्यक्रम का अभाव तो है ही, किन्तु इसकी दुर्बलता का एक कारण तो १५ वर्षों में आग्रह होने वाली जन चेतना भी है। तृतीय घाम चुनावों के बाद यह दल अब कुछ-कुछ निष्क्रिय सा होने लगा है व यह आशा नहीं की जा सकती कि १९६७ के घाम चुनावों में यह पूर्व प्राप्त उच्च सफलता तो भी आस पड़ने लगेगी।

भारतीय समाज में यद्यपि एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, परन्तु साम्प्रदायिकता की समस्या यहाँ इस तत्वावधि के आरम्भिक वर्षों से ही देखी जा सकती है। हिन्दू मुस्लिम एकता के अन्तर्गत प्रकट के बावजूद भी यहाँ कई आदर्श एका जैसी धीरे धीरे स्थापित नहीं हो सकी है। आज के भारत में साम्प्रदायिक दलों की समस्या काफी है। वे एक-दूसरे के, अपनी सांस्कृतिक दृष्टि के सांस्कृतिक दृष्टि के लिए, की प्रयासशील रहे हैं।^१ इनमें से प्रमुख जनसमूह, हिन्दू महासभा व रामराज्य परिलक्षित हैं। जनसमूह का

1. These (communal) represent homogeneous political units only in the sense that each is concerned with the prerogatives of a single segment of Indian society—they are pressure groups seeking

सन् १९५१ में डा० आनामनाद मुक्ती द्वारा दृष्टा था । उनका मत था कि जनमत एक साम्प्रदायिक दल नहीं है । इसकी शक्ति प्रमुख रूप से मजदूरों, किसानों, मूलभूत राजनीतिज्ञों के व्यक्तिगत, पारिवारिक के विभिन्न व्यक्तिगत नीति के समर्थकों एवं प्रवृत्तियों आदि आदमियों के समर्थकों पर आधारित है । यद्यपि, व्यवहार में यह सिद्ध कर दिया है कि जनमत हिन्दू समाज की शक्ति का ही समर्थक है और भाग्य में 'हिन्दू राज्य' की स्थापना का स्वप्न दल रहा है । प्रथम ब्रिटिश आन-युक्तों में जनमत, हिन्दू समाज एवं समाजवाद परितः ही मुख्य महत्ता निती है । प्रथम आन युक्तों में जनमत न राज्य विधानसभाओं की केवल ३८ सीटें जीती थी जों १९५७ में बढ़ कर ५६ हो गईं । १९५७ के पचास जनमत की शक्ति में छात्रों का एक बृद्धि हुई और समाजवाद जैसे कारणों के दल में नागरिकों के युक्तों में उनके आनामनाद स्थापना प्राप्त की । सन् १९६० के आन युक्तों में राजनीति में ११६ सीटें प्राप्त की थी तथा प्रमुख रूप से यह समाजवाद, समाजवाद एवं समाजवाद में धारित विचारों द्वारा । अन्य राज्यों में समाज व विचार को छोड़ कर इसकी शक्ति नहीं के बराबर है । अन्य दो राज्यों की शक्ति का आधार भी साम्प्रदायिकता है, पञ्चम बृद्धि राज्य में जनमत को जनमत रूप में धारित महत्ता प्राप्त की है । अनिष्ट राजनीति-शास्त्री डा० पामर के मत में धर्म-निर्णय भाग्य में इस प्रकार के साम्प्रदायिक दलों का प्रभुत्व एवं विनाश निमित्त रूप में नागरिक एकता के हिन्दू दल का कारण बन सकता है ।^१

नागरिक राजनैतिक दलों में एक अन्य प्रमुख दल साम्प्रदायिक दल है, जिसका हाथ ही में धर्म-बोध आदमियों के समर्थकों के कारण विपन्न हो गया है । साम्प्रदायिक दल प्रमुख रूप से धार्मिक वर्ग एवं बुद्धिवादी वर्ग का समर्थन प्राप्त एक महत्वपूर्ण दल है । भाग्य जैसे एंटीवादी समाज में भी साम्प्रदायिक का जन्म एवं विकास बाध्यता में उस दल के व्यक्तिगत महत्ता का परिणामक है । जनसमान्यता तथा आनामनादों मार्गों के बीच दूरी दृष्टा यह दल आगम में ही धार्मिक स्थिति में गूँथा बना आया है । इसी दल में 'धर्म' व 'धर्म' शब्दों के होने के जनकी नीतियों में समर्थन पर परिवर्तन की होता रहा है । सन् १९६० में हिन्दुवाद के प्रवर्तन निमित्त में हिमानन्द आनामनाद इस दल की प्राग्निष्ठ नीतियों को स्पष्ट कर मरा । जनसमान्य

to secure for the cultural unit they represent a larger measure of prestige, power, wealth, and predominance of cultural patterns." Richard D. Lambert, "Hindu Communal Groups in Indian Politics, in Park and Tinker, eds, Leadership and Political Institutions in India, P. 211.

1. "They (Hindu Communal Organisations) are major threats to the unity of India, for they operate largely beneath the surface, and they have roots deep in traditional Indian society." Norman D. Palmer : Indian Political System, P. 203.

इस दल ने भारतीय व्यवस्था के अनुसार अपने घोषणा परिवर्तित किया। १९५१-५२ में भारतीय साम्यवादी दल ने प्रथम ग्राम चुनाव में एक संगठित दल के रूप में भाग लिया एवं एक राष्ट्रीय दल का स्वर पाया। तत्कालीन महामुख विदेशी दल के रूप में उभरा व कुछ प्रदेशों में इस दल की सफलता मिली वित्तियन मद्रास हैदराबाद व द्रावणकोर कोचीन में। पृथक् तेलगू भाषी राज्य के त्रिपे नर दल आन्दोलन की इसमें उत्साह प्रदान किया व जब १९५३ में आन्ध्र राज्य की स्थापना की गई तो विधान सभा में इसकी काफी प्रतिनिधित्व मिला। मार्च १९५५ के चुनाव में इस दल की बड़ा धक्का लगा जिसका प्रमुख कारण साम्यवादी दल में आन्तरिक मतभेद व सोवियत रुत द्वारा भारतीय तटस्थता की नीति को स्वीकार करना था। अप्रैल १९५६ की चौथी कांग्रेस के पालघाट अधिवेशन में भारतीय साम्यवादी दल न दा प्रस्ताव पास किये—पहला भारत सरकार की आन्तरिक व विदेशी नीतियों का समर्थन प्रदान करने से सम्बन्धित व दूसरा अन्य विरोधी दोनों सहयोग करने की नीति से सम्बन्धित। इस नीति को बुद्धिमानी से प्रयोग में लाया गया व १९५७ के दूसरे ग्राम चुनावों में चुनाव सधियों व अन्य साधनों से इस दल ने अपनी शक्ति देश में दुगुनी कर ली। केरल, पश्चिमी बंगाल व बम्बई में इसे काफी सफलता मिली। भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा में इसे प्रतिनिधित्व मिला। अप्रैल १९५७ में केरल में पाप स्वतन्त्र सदस्यों की सहायता से साम्यवादी दल द्वारा सरकार बनाई गई जो कि ३१ जुलाई १९५८ तक चली।

१९५८ से साम्यवादी दल का समर्थन व प्रतिष्ठा गिरने लगी। इसके मुख्य कारण थे—दल में आन्तरिक मतभेदों की तीव्रता, केरल का अनुभव, चीन का लिप्यत में दमन तथा भारतीय सीमा का असम्मान करना आदि। उपवादी सदस्य अब चीन-समर्थक होने जा रहे थे। चीन की शक्ति की वृद्धि के साथ व इस में उमारे मतभेद के साथ २ भारतीय साम्यवादी दल भी आन्तरिक रूप से विखण्डित होने लगे। १९६० में जब केरल में चुनाव हुये तो दल को केवल २७ सीटें मिली। यह दल की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात था। परन्तु १९६२ के ग्राम चुनावों में साम्यवादी दल फिर से शक्तिशाली दल के रूप में आया। दल ने आन्ध्रप्रदेश में ५१ व पश्चिमी बंगाल में ५० स्थान प्राप्त किये। अन्य सभी राज्यों में इसकी प्रतिनिधित्व मिला, परन्तु उत्तर-प्रदेश के अतिरिक्त जहाँ इसने १४ स्थान ही प्राप्त किये, इसकी शक्ति गीली ही रही। १९६२ में हुये चीनी आक्रमण के उपरांत साम्यवादी दल के प्रति भारतीय जनता में निष्ठा कम हो गई व साथ ही चीन-समर्थक व इस-समर्थक साम्यवादी गुटों का पारस्परिक विरोध समझा आ गया। भारतीय साम्यवादी दल दक्षिण-पश्चिमी व वाम-पश्चिमी दलों में विभाजित हो गया तथा केरल में १९६४ के चुनाव भी इन दो दलों द्वारा पृथक्-पृथक् लड़े गये। केरल में दोनों दलों में जनता से समर्थन प्राप्त किया, परन्तु आसानी से सफलता वामपक्षियों को मिली। वामपक्षी साम्यवादी दल ही अधिक शक्ति प्रजित करने

में मग्न रहा है। केरल व पश्चिमी बंगाल में इसी दल की शक्ति अधिक है। चीन समर्थन तथा राष्ट्र विरोधी होने के मशय में इन वर्ष कामगारियों को भारन रक्षा वातून के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया। इन परिस्थितियों में इस प्रवृत्ति की आशा की जा सकती है कि आगामी वर्षों में भारत में साम्यवादी दल अपनी फूट व नीतियों के कारण शीघ्रता से शक्ति अर्जित करने में सफल होगा। आंध्र, केरल व पश्चिमी बंगाल के अनिर्दिष्ट अन्य भागों में इस दल की स्थिति सुन्दरता में बहुत दूर है। यह दल एक अल्पसंख्यक भविष्य की आशा रख रहा है।

मुख्य मुख्य राजनैतिक दलों के अनिर्दिष्ट भारत में कुछ ऐसे प्रादेशिक व स्थानीय दल भी हैं जो कुछ प्रमुख व्यवस्था, साम्यवादियों, जाति अथवा किसी विशिष्ट हिन्दू के आधार पर जीवित हैं।

भारतीय अछूतों का प्रमुख राजनैतिक दल-अनुसूचित जाति मध (Scheduled Caste Federation) है जो महाराष्ट्र के महार अछूतों की शक्ति पर प्रभुत्वस्था आधारित है। दक्षिण के तामिल भाषी प्रदेश में, विमोचनवा मद्रास में, द्रविड आन्दोलन ने काफी मोक्ष-समर्थन प्राप्त किया है। यह आन्दोलन मुख्यतः तामिल जनता का आन्दोलन व अन्य उच्च जातियों के विरुद्ध सफल है। यह एक प्रकार से तत्कालीन उत्तरी भारत के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध विरोध है। तामिल-जातियों का राजनैतिक संगठन, 'द्रविड मुन्नेत्र कळगम्' है। इस दल ने समय-समय पर साम्यवादियों के साथ गठबन्धन भी किया परन्तु १९५७ में जब DMK की अपनी शक्ति बढ़ी तो इनने साम्यवादियों का समर्थन नहीं किया कतलः साम्यवादियों को मद्रास राज्य में आधार बना। ब्राह्मण-विरागी, हिन्दु विरोधी, उत्तर विरोधी व आर्य विरोधी अन्धधार्मिकों के मन्तव्य DMK की पृथक् द्रविडमन्तव्य की मांग का समर्थन तामिलनाडु के गैर-ब्राह्मण करने हैं। लोकप्रियता के कारण कांग्रेस विरोधी अन्य दलों को मद्रास में इनने काफी पीछे छोड़ दिया है। १९६० के तृतीय आम-चुनावों में इस दल ने मद्रास राज्य विधान सभा में ५० स्थान प्राप्त किये। स्थानीय लोकप्रियता सुदृढ़ होने के कारण व ऐतिहासिक कारणों में इस दल का भविष्य अमरुक्षित नहीं कहा जा सकता।

पन्जाब में सिक्खों का राजनैतिक व सामाजिक संगठन सिक्खोवाणी असाही दल के रूप में स्थित है। यह दल पृथक् सिक्ख राज्य व अब 'पन्जाबी सूबे' की मांग करता है। सिक्खों में यह दल अल्पसंख्यक लोकप्रिय है। पन्जाब में १९६० के आम चुनावों में इनने १२ स्थान जीते। मद्रास व केरल के कुछ भागों में मुस्लिम लीग सक्रिय है। १९६० के केरल के चुनावों में इनने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा व विधान सभा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अतिरिक्त कामगारी दलों में विमान मजदूर मन्तव्य प्रमुख है। पश्चिमी व दक्षिणी भारत के कुछ भाग में ऐसे कुछ शक्ति प्राप्त हैं (विशेषतया महाराष्ट्र में)। बिहार के आदिवासीयों के समर्थन पर आधारित जंग-संग दल है। १९६० में नागालैण्ड के पृथक् राज्य की स्थापना के पश्चात् भी नागा

विरोधी अपने छोटे-से दल के द्वारा अधिकांश अधिकारों की माल कर रहे हैं।

ग्राम चुनावों में भारत के राजनीतिज्ञ दलों ने चुनावों व सरकार बनाने के लिये समय-समय पर काफी आसानी गठबन्धन किये हैं। यह खपिया गठबन्धन पर आश्रित होने के कारण आसानी से टूट सकता है। कांग्रेस को हराने के लिये कांग्रेस विरोधी दल व दलितगुणपी दल का गठबन्धन कई बार हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी १९५५ में आंध्र व १९६० में केरल में साम्यवादियों के विरुद्ध स्वयं में विभिन्न दलों के गठबन्धन किया। साम्यवादिकता-विरोधी कांग्रेस दल का साम्यवादीक मुन्निम लोग के गठबन्धन बुद्धिवादियों की निन्दा का विषय बना। दो अन्तर्दलीय रूप में महत्वपूर्ण गठबन्धन १९५७ में देवने में आये जबकि पृथक् महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों की स्वायत्ता की समस्याएं देन वाले सभी विरोधी दलों ने कर्नाट प्रान्त में कांग्रेस का बड़ा विरोध किया। संयुक्त महाराष्ट्र समिति व महा गुजरात जनता परिषद् ने आतंकीय सफलता प्राप्त की। इन आन्दोलनों व फलस्वरूप भी १९६० में पृथक् राज्य-गुजरात व महाराष्ट्र भी बने। इसमें सिद्ध होता है कि एक राज्य की जनता अपनी इच्छा को राजनीतिक प्रतिनिधित्व द्वारा व्यक्त कर सकती है। राज्य बनने के बाद यह विरोधी दल तबतक विघटित हो गये। १९६२ के ग्राम चुनावों में फिर से कांग्रेस ने अपनी खाई छुई शक्ति प्राप्त कर ली।

विधान देश में विविधता होता स्वाभाविक है। राजनीति दलों का बाहुल्य भारतीय राजनीति जीवन की एक विशेषता है। एक स्वयं दल पद्धति (Party System) भी जन्म नहीं ले सका है और आशा नहीं कि निकट भविष्य में ऐसा हो सके। भारत में कांग्रेस दल की शक्ति इतनी अधिक रही है कि भारत को कई व्यक्ति 'एक-दलीय राज्य' (One Party State) कहते हुये भी नहीं हिचकते।^१ संसदीय सभा में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। परन्तु कई राज्यों में कांग्रेस को काफी अधिक विरोध का सामना भी करना पड़ता है। आंध्र, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व केरल में इस दल की स्थिति निर्धन है। राजस्थान में अन्य दलों व निर्दलीय सदस्यों को आवणित करने ही कांग्रेस की शक्तिशाली बनाया गया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की कम स्थिति प्राप्त है वहां भी विरोधी दलों के आसपास रहने के कारण उसे सरकार बनाने में कोई भय नहीं रहता। महाराष्ट्र में कांग्रेस को १९६२ के ग्राम चुनावों में २६४ में से २१५ स्थान मिले, राजस्थान में १७६ में से ५८, मध्य प्रदेश में २८८ में से १४२ स्थान मिले थे। कांग्रेस की शक्ति सभी राज्यों में गमन नहीं है और न ही किसी भी दल की स्थिति किसी भी राज्य में नियमित रूप से बढ़ रही है। केरल जैसे जनगण प्रेमी राज्य को आज राजनीति दलों के बाहुल्य का मूल्य चुकाना पड़ रहा है। कांग्रेस की स्थिति राज्यों में समुचित है परन्तु बंग म सुदृष्टि होने के बारे में नैतिग हारिजन (Selie Harrison) का विचार है कि 'बंग राज्य

सम्बन्धों के पहलू पर दृष्टि रखते हुये भारतीय संविधान में परिवर्तन करना क्या उचित नहीं रहा ? १९५७ से १९५९ तक के दौरान प्रशासन में उत्पन्न समस्याओं के सुदन में हैमिन्स का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रतीत होता है ।

वर्तमान परिस्थितियों के समय समस्त जनता का भी मानवहादुर शास्त्री के पीछे एकत्र हो जाना हमारे नेहरू-युग की स्मृति का तानी कर देना है । नेहरू राष्ट्रीय-एकता के प्रतीक थे । उनकी मृत्योपरांत, भारत का जैसा नयातन वास्तविक चित्र खींचा जाता था, वैसी दशा विचित्रमात्र भी न हुई । परन्तु नष्टश्री के अभाव में राज्यों की अपनी शक्ति बढ़ाने की भावना को पूरा करने का प्रवृत्त प्रवण्य मिला है । स्वतन्त्रता के स्वरूप में शास्त्री द्वारा संघर्ष का परिचय देने में राष्ट्र-निवासियों के हृदय में खोये नेतृत्व को फिर से पान करने का सन्तोष हुआ है । कुछ समय में हम स्वः से उठे उठ गये हैं व राष्ट्र हित का ध्यान सर्वोपरि हो चुका है । कामराज के कुछ निवेदन में कांग्रेस की शक्ति के बढ़ने की भासा है व ऐसा अनुमान किया जाता है कि सम्भवतः १९६७ के आम-चुनाका के बाद भारतीय राजनीतिक दलों की स्थिति में परिवर्तन आवे । कांग्रेस की शक्ति बढ़ना व उसका सुधार होना राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिरता के लिये शुभ है । एक सुख जनतन्त्र को आवश्यकता होती है—मुझे हुये विरोधी दलों की, जिसका भारत में अभाव है । ऐसे प्रयत्न होने चाहिये कि राजनीतिक दलों की शक्त के बाहुल्य पर रोच लगे व जनताविक शक्ति का भारतीय आदर्शों व परिस्थितियों के अनुसार मुधरे हुये सगल बनाये जायें जो जनता को विफल दे सकें । जातीयता, प्रथाचार, स्वकीयता, प्रादेशिकता, सृष्टिकता की प्रभुत्व दमनक राजनीति में भारतीय राजनीतिक दलों की दिक्कत कर प्रतामक, दोन परम्पराओं को अन्न देने का प्रयत्न करना चाहिये जिन पर जनतन्त्र का अविश्य निर्भर रहता है करना भारतीय राजनीतिक दन जनतन्त्र के लिये एक अनुपात बन कर रह जायेंगे ।

1. "Thus the great issue before Indian leaders is whether the present constitution, drafted at a time when a national party system seemed to be in the making, will be adequate to a new time in which the interplay of national parties makes way for the new contest between the central power and regionally based political forces." Selig Harrison : *India the Most Dangerous Decades*, p. 246.